



सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड
डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)
एक मिनी रब कंपनी (कैट - I)

सतत् रूप से विकसित भारत की ओर अग्रसर



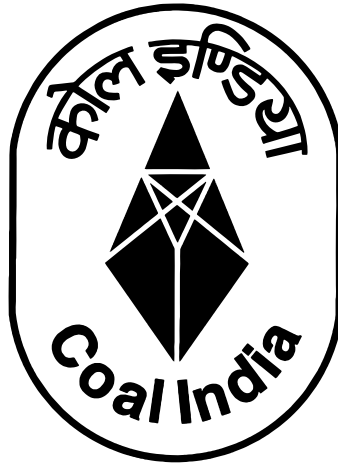
वर्षों का जश्र



वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2024-25

50^{वाँ} वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

2024-25



सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)

एक मिनी रत्न कंपनी (कैट-1)

आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित

गोन्दवाना प्लेस, काँके रोड

राँची - 834008

CIN : U14292 JH1975 GOI 001223

वेबसाइट: www.cmpdi.co.in

विजन

बढ़ते भू-संसाधन के क्षेत्र तथा सम्बद्ध व्यवसायिक क्रियाकलापों में वैश्विक बाजार का नेतृत्व करना।

मिशन

प्रमुख परामर्शदाता के रूप में भारत तथा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी कोयला, गवेषण, खनन, अभियंत्रण तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में संपूर्ण परामर्शी सेवा प्रदान करना।

सीएमपीडीआईएल की प्रबंधन नीति

कोयला एवं अन्य खनिज संसाधन के गवेषण तथा खान आयोजन, डिजाइन, सम्बद्ध अभियंत्रण तथा प्रबंधन प्रणाली में परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रमुख परामर्शदाता के रूप में सीएमपीडीआईएल विस्तृत भू-संसाधन क्षेत्र तथा अन्य व्यावसायिक क्रिया-कलापों में बाजार में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है।

हम निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं:-

1. पर्यावरण, सूचना सुरक्षा तथा ऊर्जा उपलब्धि पर सम्यक (यथोचित) ध्यान देते हुए अपने परामर्श एवं अन्य सहायता सेवाओं की गुणवत्ता में सतत सुधार लाना।
2. उत्पन्न अपशिष्ट में लगातार (दृढ़तापूर्वक) कमी लाकर, पुनः उपयोग कर तथा उसके कुछ भाग को पुनर्चक्रित (रिसाइक्लिंग) कर; हमारे कार्यों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम कर पर्यावरण को संरक्षित करना।
3. गुणवत्ता, पर्यावरण, ऊर्जा तथा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना।
4. व्यापार निरंतरता बनाए रखने के लिए खतरों (जोखिम) तथा व्यवधानों से अपनी सूचना संपदा (परिसम्पत्ति) को बचाए रखना तथा सूचना सुरक्षा कार्यनिष्पादन में सतत सुधार लाना।
5. कानूनी एवं अन्य सभी प्रयोज्य (लागू) आवश्यकताओं (अपेक्षाओं) का अनुपालन।

कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डरों के लिए सामान्य नोट

सीएमपीडीआईएल का वार्षिक लेखा विवरण जाँच के लिए मुख्यालय में रखा रहेगा तथा कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी शेयर होल्डर के माँगने पर जानकारी देने के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	2024-2025 के दौरान प्रबन्धन	01
2.	12.08.2025 के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्य	02
3.	निगमित सूचना	03
4.	50वें वार्षिक आम बैठक की सूचना	04
5.	अध्यक्ष का वक्तव्य	07
6.	उपलब्धि: एक नजर में	20
7.	वित्तीय पर्यवेक्षण एवं सांख्यिकी	21
8.	निदेशक-मंडल की रिपोर्ट	23
9.	निदेशक-मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट	134
10.	सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण-पत्र	148
11.	निगमित शासकीय अनुपालन प्रमाण-पत्र	149
12.	सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर	158
13.	सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर	201
14.	धारा 143 (6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ तथा प्रबंधन का उत्तर	211
15.	निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट	216
16.	लेखे का अंकेक्षित विवरण साथ नकद प्रवाह विवरण	219
17.	लेखे पर टिप्पणी	230

31.03.2025 को निदेशक मंडल की स्थिति

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक



श्री मनोज कुमार

कार्यकारी निदेशक



श्री शंकर नागाचारी



श्री अजय कुमार

अंशकालिक सरकारी निदेशक



श्री मुकेश अग्रवाल



श्री मारापल्ली वेंकटेश्वरलु

कंपनी सचिव



श्री अभिषेक मुंधरा

वर्ष 2024-2025 के दौरान प्रबंधन

कार्यकारी निदेशक

श्री मनोज कुमार	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (04.10.2021 से)
श्री शंकर नागाचारी	:	निदेशक (तकनीकी) (02.09.2022 से)
श्री अजय कुमार	:	निदेशक (तकनीकी) (26.10.2022 से)
श्री सतीश झा	:	निदेशक (तकनीकी) (01.09.2023 से 19.12.2024 तक)
श्री अच्युत घटक	:	निदेशक (तकनीकी) (01.10.2023 से 23.01.2025 तक)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री मुकेश अग्रवाल	:	निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड (17.10.2024 से)
श्री मारापल्ली वेंकटेश्वरलू	:	निदेशक (टी/एनए) कोयला मंत्रालय (01.01.2025 से)
डॉ. बी. वीरा रेड्डी	:	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड, (24.02.2022 से 31.08.2024 तक)
श्री अजितेश कुमार	:	निदेशक (पी&एस-I, पी&एस-II/एनए), कोयला मंत्रालय (27.12.2023 से 31.12.2024 तक)

कंपनी सचिव

श्री अभिषेक मुंधरा	:	वरीय प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी (18.02.2016 से)

12.08.2025 तक की स्थिति के अनुसार बोर्ड के सदस्य

कार्यकारी निदेशक

श्री मनोज कुमार	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री शंकर नागाचारी	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री अजय कुमार	:	निदेशक (तकनीकी)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री मुकेश अग्रवाल	:	निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता
श्री मारापल्ली वेंकटेश्वरलू	:	निदेशक (टी/एनए) कोयला मंत्रालय

कंपनी सचिव

श्री अभिषेक मुंधरा	:	वरीय प्रबंधक (वित्त) / कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

निगमित सूचना

पंजीकृत कार्यालय

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड,
गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची - 834 008 (झारखंड), भारत
सीआईएन: U14292 JH1975 GOI 001223
वेबसाइट: www.cmpdi.co.in

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
इंडियन बैंक
पंजाब नेशनल बैंक

बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
बैंक ऑफ बड़ौदा
यूको बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
कोटक महिंद्रा बैंक
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

लेखा परीक्षक

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स केसी टाक एंड कंपनी, रांची

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स मेहता एंड मेहता, मुंबई

कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिटर

मेसर्स मेहता एंड मेहता, मुंबई

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स विजेन्द्र शर्मा एंड कंपनी

डिपॉजिटरी

मेसर्स नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड
मेसर्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

आईएसआईएन

आईएनई 05एचवी01019, 17.05.2025 तक

आईएनई 05एचवी01027, दिनांक 17.05.2025 से (इक्विटी शेयरों का विभाजन 1000/- रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य से 2/- रुपये प्रति शेयर तक)

50वीं वार्षिक आम बैठक के लिए सूचना

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के सभी शेयरधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 50वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 को सुबह 10:00 बजे पंजीकृत कार्यालय, रांची में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी: -

(क) सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च 2025 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते के साथ-साथ भारत के सांविधिक लेखा परीक्षक और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और निदेशकों की रिपोर्ट पर विचार करने और उसे अपनाने के लिए।
2. अक्टूबर 2024 में कंपनी के इक्विटी शेयरों पर 150.00 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करने और कंपनी के इक्विटी शेयरों पर 150.00 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश की घोषणा करने, इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश के रूप में कुल 300 करोड़ रुपये की घोषणा करना।
3. श्री अजय कुमार (डीआईएन: 09774347), पूर्णकालिक निदेशक, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के नाते, खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना।

(क) विशेष कार्य:

1. निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।
2. एक सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, संशोधन के साथ या उसके बिना पारित करना:
3. "यह निर्णय लिया जाता है कि दिनांक 08.08.2025 को आयोजित निदेशक मंडल की 296वीं बैठक में स्वीकृत एम/एस शोम एंड बनर्जी (लागत लेखा परीक्षक) को वित्तीय वर्ष 2025-26 से लेकर वित्तीय वर्ष 2027-28 तक लागत लेखा परीक्षण हेतु प्रतिवर्ष ₹5,00,000/- (रुपये पाँच लाख मात्र) तथा लागू कर देय होंगे, साथ ही वास्तविक यात्रा व्यय एवं अन्य विविध खर्च की प्रतिपूर्ति कुल शुल्क के 50% तक की सीमा के अंतर्गत की जाएगी, जिसे विधिवत् अनुमोदित किया जाता है।"

नोट:-

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपनी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितम्बर, 2024 तथा इस संबंध में जारी अन्य परिपत्रों (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" कहा गया है) के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, 30 सितम्बर, 2025 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीसी या ओएवीएम") की सुविधा के माध्यम से वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एजीएम के लिए स्थल माना जाएगा।
2. चूंकि यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की

नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसार, सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने और मतदान करने हेतु नियुक्त किया जा सकता है। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए लिंक कंपनी के अधिकृत ई-मेल आईडी से पर्याप्त समय पूर्व उपलब्ध कराया जाएगा तथा बैठक में सम्मिलित होने की सुविधा निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले उपलब्ध होगी और बैठक के निर्धारित समय से 15 मिनट पश्चात तक खुली रहेगी।
4. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीडमपीडीआईएल) के शेयरधारक, निदेशक एवं लेखा परीक्षक (जिसमें सचिवीय लेखा परीक्षक भी सम्मिलित हैं) बैठक में उपस्थित होने और/या मतदान करने के अधिकारी होंगे अथवा वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से भी बैठक में उपस्थित होकर तथा/या मतदान कर सकते हैं। वे केवल बैठक में विचार किए गए विषयों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने हेतु cosecretary.cmpdi@coalindia.in पर ई-मेल भेजकर मतदान कर सकेंगे।
5. सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के अनुसार अल्प सूचना पर बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

निदेशक मण्डल के आदेश से
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के लिए



(अभिषेक मुंधरा)
कंपनी सचिव

दिनांक: 08.08.2025

स्थान: राँची

वितरण:

1. सभी शेयरधारक।
2. कंपनी के सभी निदेशक गण।
3. कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक।
4. कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक।
5. कंपनी का लागत लेखा परीक्षक।
6. महाप्रबंधक (वित्त) / सीएफओ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

आइटम नं. बी (1): निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

सीएमपीडीआईएल के निदेशक मंडल ने 08.08.2025 को आयोजित अपनी 296वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक लागत लेखापरीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश के बाद मैसर्स शोम और बनर्जी की नियुक्ति को मंजूरी दी। 5,00,000/- रुपये प्रति वर्ष की फीस के साथ यात्रा और जेब खर्च की प्रतिपूर्ति कुल शुल्क (लागू कर) के 50% तक सीमित है। कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा मंजूरी देने की आवश्यकता है।

कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार संकल्प में रुचि या चिंतित नहीं हैं।

बोर्ड ने सदस्यों के अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश की।

निदेशक मंडल के आदेश से
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के लिए



(अभिषेक मुंधरा)
कंपनी सचिव



अध्यक्ष का वक्तव्य

श्री मनोज कुमार

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारक,

सीएमपीडीआईएल की 50वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि की निदेशक मंडल की रिपोर्ट, अंकेक्षित (आडिट) लेखे की रिपोर्ट के साथ-साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं समीक्षा पहले ही कंपनी के शेयरधारकों को दी जा चुकी है।

1.0 विकास की रूप-रेखा:

संपूर्ण भारतीय खनन उद्योग को एक ही छत के नीचे विस्तृत प्लानिंग सेटअप के रूप में सीएमपीडीआई की स्थापना का विचार एवं प्रस्ताव मूलतः 1972 में पोलैंड के विशेषज्ञों वाले संयुक्त अध्ययन दल द्वारा आया। इसके बाद सीएमपीडीआई की स्थापना 1 नवम्बर, 1975 को की गई।

आपकी कंपनी द्वारा कोयले के गवेषण, खान आयोजन एवं अभिकल्पन, पर्यावरण अभियांत्रिकी, कोयले का परिष्करण एवं उपयोग, संबंधित अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) सेवाएँ, सूचना एवं संचार, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, सुदूर संवेदन, क्षेत्र सेवा आदि में कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों को घरेलू परामर्श सेवाएँ देती रही है। कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के ग्राहकों को भी इसी प्रकार की सेवाएँ दी जा रही है। कुछ हद तक धात्विक खनन उद्योग को भी आयोजना एवं सम्बद्ध सेवाएँ दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई गैर-सीआईएल ब्लॉक, कोयला आधारित गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधन यानि सीबीएम, सीएमएम यूसीजी शेल गैस से संबंधित इसी प्रकार की सेवाएँ कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भी दे रहा है।

सीएमपीडीआईएल के गठन के बाद के वर्षों के दौरान बड़ी खुली खान तथा भूमिगत खान परियोजना के लिए संयुक्त प्लानिंग कार्य करने हेतु पूर्ववर्ती यूएसएसआर के जिप्रोशाख्त, पोलैंड के कोपेक्स तथा ब्रिटेन के ब्रिटिश माइनिंग कन्सल्टेंट जैसे उन्नत (अग्रणी) कोयला खनन वाले देश के संस्थानों के साथ द्विपक्षीय समझौते के जरिए अपने योजनाकारों एवं अभियंताओं की विशेषज्ञता का स्तर बढ़ाया गया। सीएमपीडीआई के कार्मिकों की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाने के अतिरिक्त, कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला सुविधा की स्थापना के द्वारा महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा का निर्माण किया गया। इन सब उपायों से सीएमपीडीआई एक ही छत के नीचे खनिज एवं खनन के क्षेत्र में संपूर्ण समाधान करने वाला अद्वितीय कंपनी बन गया है। इसके अलावा, कंपनी अपनी सेवाओं और सुविधाओं को उत्कृष्टता के स्तर तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि व्यावसायिक वातावरण के बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल

बनाए रखा जा सके। यह कथन इस तथ्य से भी पुष्ट होता है कि कंपनी 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण प्रौद्योगिकियों, उच्च उत्पादकता वाली ड्रिल मशीनों के साथ-साथ कार्यस्थल के कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से गवेषण की गति को बढ़ाने में सक्रिय रूप से शामिल रही है, साथ ही गवेषण और खनन उद्योग से संबंधित नवीनतम सॉफ्टवेयर के उपयोग के अलावा पर्यावरण सुविधाओं, खान सर्वेक्षण, कोयले की विशेषता के साथ-साथ आईएसओ मानकों की शुरुआत से संबंधित उपकरणों को भी जोड़ा गया है।

सीएमपीडीआईएल के प्रमुख क्रिया-कलापों में से एक ड्रिलिंग की क्षमता, जिससे भावी कोयला उत्पादन की आवश्यकता के लिए कोल ब्लॉक के अनुमान करने में मदद मिलती है, लगभग 2 लाख मीटर प्रतिवर्ष (2004-05 में 2.02 लाख मीटर से 2007-08 में 2.09 लाख मीटर) के आस-पास थी तथा बिक्री लगभग 150 से 200 करोड़ रुपये (2004-05 में 151 करोड़ रूपए तथा 2007-08 में 196 करोड़ रूपए) थी। ड्रिलिंग में योगदान सिर्फ विभागीय संसाधन का ही था। 11वीं योजना के प्रारंभ में यह विचार आया कि संसाधनों को तेजी से प्रमाणित करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर, खासकर गवेषण के क्षेत्र में सीएमपीडीआई की भूमिका में काफी वृद्धि करने की जरूरत होगी। तद्वसार, विभागीय क्षमता को बढ़ाने के अलावा एमईसीएल सहित अन्य एजेंसियों की ड्रिलिंग क्षमता का उपयोग कर संपूर्ण ड्रिलिंग क्षमता में वृद्धि करने पर बल दिया गया तथा निजी एजेंसियों को ड्रिलिंग कार्य का कुछ भाग आउटसोर्स कर ड्रिलिंग शुरू किया गया। इसी के साथ-साथ सीएमपीडीआई की कोयला कोर जाँच की क्षमता भी बढ़ायी गयी। कुल मिलाकर स्वदेशी तथा आयातित उपकरण के जरिए अन्य प्रयोगशालाओं जैसे पर्यावरण, सीबीएम, खनन प्रौद्योगिकी आदि की क्षमता को भी बढ़ायी गयी है।

इसके बाद प्रशासकीय मंत्रालय यानि कोयला मंत्रालय भी सीएमपीडीआई की गवेषण क्षमता बढ़ाने के लिए एक योजना लेकर आया, जहाँ वर्ष 2015-16 तक विभागीय ड्रिलिंग क्षमता 4 लाख मीटर सहित 15 लाख मीटर तक बढ़ाई जानी थी। सीएमपीडीआई ने पूर्व के वर्ष में की गई ड्रिलिंग की तुलना में वर्ष 2016-17 में 13 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कर 11.26 लाख मीटर, वर्ष 2017-18 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 13.66 लाख मीटर, वर्ष 2018-19 में 13.60 लाख मीटर ड्रिलिंग तथा 2019-20 में 12.94 लाख मीटर ड्रिलिंग तथा 2020-21 में 12.48 लाख मीटर 2021-22 में 7.91 लाख मीटर तथा 2022-23 में 6.85 लाख मीटर ड्रिलिंग कर लिया। 2021-22 और 2022-23 में ड्रिलिंग उपलब्धि में कमी मुख्य रूप से गैर-सीआईएल और प्रमोशनल ब्लॉकों में गवेषण के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए फंड में कमी के साथ-साथ सीआईएल ब्लॉकों में कम मीटररेज उपलब्धता के कारण थी।

हालाँकि, अक्टूबर 2022 में, EFC ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान यानी 2025-26 तक कोयला और लिग्नाइट में गवेषण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को जारी रखने की सिफारिश की। परिणामस्वरूप, सीएमपीडीआईएल 2023-24 में पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 26% की वृद्धि दर्ज करते हुए लगभग 8.625 लाख मीटर ड्रिलिंग तथा 2024-25 में 17% की वृद्धि दर्ज करते हुये लगभग 10.12 लाख मीटर ड्रिलिंग हासिल कर सका। आने वाले वर्षों में भी इस वृद्धि के बरकरार रहने की संभावना है।

वर्ष 2021-22 से एनएमईटी (राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट) के वित्तपोषण के माध्यम से ड्रिलिंग को बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। कोयला ब्लॉकों (जी2/जी3/जी4) में अन्वेषण के लिए कुल 23 प्रस्तावों को एनएमईटी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इनमें से 16 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 4 प्रगति पर हैं और 3 को सरेंडर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एनएमईटी वित्तपोषण के तहत, बॉक्साइट अन्वेषण के तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और तीनों परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। बेस मेटल्स (Cu, Pb और Zn) में अन्वेषण के लिए एक परियोजना भी पूरी हो चुकी है, जबकि बेस मेटल और मैग्नेटाइट में अन्वेषण के लिए अन्य 2 परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं। इसके अलावा, एनएमईटी वित्तपोषण के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए डीजीओ, उड़ीसा द्वारा ग्रेफाइट के अन्वेषण के लिए 2 ब्लॉक भी दिए गए हैं।

2024-25 में भूकंपीय सर्वेक्षण गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। सीएमपीडीआई ने 2024-25 में लगभग 438 लाइन किमी 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण किए, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष-दर-वर्ष 87% की प्रभावशाली वृद्धि हुई, जिसमें विभागीय संसाधनों का उपयोग करके लगभग 300 लाइन किमी 2डी सर्वेक्षण शामिल थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 31 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट, 33 परियोजना रिपोर्ट, 90 भूजल मॉडलिंग (जीडब्ल्यूएम) रिपोर्ट, 88 व्यापक जल विज्ञान रिपोर्ट, 26 ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट (जल विज्ञान भाग) और 26 अन्य रिपोर्ट सहित कुल 230 रिपोर्ट

तैयार की गई। विभागीय रूप से तैयार की गई भूजल मॉडलिंग (जीडब्ल्यूएम) रिपोर्टों की संख्या पिछले वर्ष की 10 रिपोर्टों से बढ़कर 2024-25 में 44 रिपोर्ट हो गई। इन-हाउस रिपोर्टिंग में इस उल्लेखनीय वृद्धि ने जीडब्ल्यूएम रिपोर्ट तैयार करने के लिए आउटसोर्सिंग पर निर्भरता को प्रभावी रूप से कम कर दिया है।

अपनी सेवाओं का विविधीकरण और ग्राहक आधार का विस्तार सीएमपीडीआईएल का निरंतर फोकस क्षेत्र है। लक्षित संभावित ग्राहकों के साथ एक-एक करके मीटिंग, प्रासंगिक सेमिनार/प्रदर्शनियों में भाग लेने, विदेशी प्रदर्शनियों में भागीदारी बढ़ाने और सोशल मीडिया के माध्यम से सीएमपीडीआईएल की पहुँच बढ़ाने के लिए सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ सहयोग ने भी सही समाधान प्रदान करने वाले एक भरोसेमंद संगठन के रूप में सीएमपीडीआईएल की देश भर में पहुँच बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है।

हमारे ग्राहकों को समय पर कुशल और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके इन सभी प्रयासों को और पुष्ट किया जा रहा है। हमारी श्रमशक्ति का निरंतर पुनर्कोशल और अपस्किंग, नवीनतम उपकरणों और सॉफ्टवेयरों का अधिग्रहण और टीम को उच्च दक्षता और जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए प्रेरित करना इन प्रयासों को बनाए रखने के लिए प्रमुख जोर देने वाले क्षेत्र हैं।

विविधीकरण के साथ-साथ, निकट भविष्य में समग्र रूप से कोयला क्षेत्र के हित के लिए कंपनी की विशिष्टता को संरक्षित रखा जाएगा।

2.0 वित्तीय प्रदर्शन:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने 2102.76 करोड़ रुपये का निवल कारोबार किया है, जिसमें 882.14 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ- 20.83 करोड़ रुपये (समग्र) की अन्य व्यापक आय शामिल है। 31.03.2025 तक आपकी कंपनी की पूंजी रिजर्व को छोड़कर निवल संपत्ति बढ़कर 2041.85 रुपये (32.18 करोड़ रुपये की ओसीआई सहित) हो गई है। वित्तीय वर्ष के दौरान, प्रति शेयर आय एक साल पहले 3524.02 रुपये (1000/- रुपये अंकित मूल्य वाले 14,28,000 इक्विटी शेयरों पर गणना की गई) से बढ़कर 4670.24 रुपये (1000/- रुपये अंकित मूल्य वाले 14,28,000 इक्विटी शेयरों पर गणना की गई) हो गई है।

3.0 ड्रिलिंग और सेस्मिक सर्वेक्षण का प्रदर्शन:

जैसा कि भाग 1.0 में बताया गया है, सीएमपीडीआई ने 10 लाख मीटर के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के मुकाबले लगभग 10.12 लाख मीटर ड्रिलिंग हासिल की, जिसमें विभागीय ड्रिल के माध्यम से लगभग 4.64 लाख मीटर की ड्रिलिंग शामिल है, जिसकी उत्पादकता लगभग 635 मीटर/ड्रिल/महीना है। सीएमपीडीआई ने 2024-25 में लगभग 438 लाइन किमी 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण भी किए, जिसके परिणामस्वरूप साल-दर-साल 87% की प्रभावशाली वृद्धि हुई, जिसमें विभागीय संसाधनों का उपयोग करके लगभग 300 लाइन किमी 2डी सर्वेक्षण शामिल थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% की वृद्धि को दर्शाता है।

21 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से लगभग 270 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए विस्तृत अन्वेषण के माध्यम से लगभग 7.5 बिलियन टन कोयला संसाधनों को प्रमाणित श्रेणी में जोड़े जाने का अनुमान है। इसके अलावा, 9 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से लगभग 208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए क्षेत्रीय गवेषण के माध्यम से लगभग 7.4 बिलियन टन नए कोयला संसाधनों (संकेतित और अनुमानित श्रेणियों में) को जोड़े जाने का अनुमान है। इसके अलावा, लगभग 166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए 1 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के माध्यम से संकेतित श्रेणी में अनुमानित 75 मिलियन टन लिग्नाइट संसाधनों को भी जोड़े जाने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2024-25 में, सीएमपीडीआई ने झारखंड राज्य में बॉक्साइट के लिए 1 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के माध्यम से विभिन्न ग्रेडों के लगभग 65 मिलियन टन शुद्ध इन-सीटू बॉक्साइट संसाधन और 19 मिलियन टन शुद्ध इन-सीटू एल्युमिनस लेटराइट संसाधन की स्थापना की है। ब्लॉक में TiO_2 और V_2O_5 की भी रिपोर्ट की गई है।

4.0 परियोजना रिपोर्ट:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुल 33 कोयला परियोजना रिपोर्ट (पीआर) तैयार की गई हैं, जिनमें ओपनकास्ट परियोजनाओं के लिए 19 पीआर और भूमिगत परियोजनाओं के लिए 14 पीआर शामिल हैं। गैर-सीआईएल खदानों के लिए दो ओपनकास्ट पीआर तैयार की गई हैं, अर्थात् (i) मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड के लिए रोहने कोल ब्लॉक, नॉर्थ करनपुरा कोलफील्ड्स (8 मीट्रिक टन) के लिए डीपीआर और (ii) मेसर्स एनएलसी इंडिया लिमिटेड के लिए नॉर्थ धादू (पश्चिमी भाग) कोयला खदान, नॉर्थ करनपुरा कोलफील्ड्स (4.5 मीट्रिक टन) के लिए डीपीआर।

गेवरा (एसईसीएल) की विस्तार परियोजना रिपोर्ट 70-85 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की है, जिससे यह भारत में नियोजित सबसे बड़ी कोयला खदान बन गई है। सीआईएल के लिए नियोजित अन्य मेगा परियोजनाओं में जयंत डिप-साइड एक्सपेंशन ओसी (38 मीट्रिक टन प्रति वर्ष), एनसीएल; बैतरणी ईस्ट ओसी (20 मीट्रिक टन प्रति वर्ष), एमसीएल; मदननगर ओसी एमडीओ मोड (रीकास्ट) (12 मीट्रिक टन प्रति वर्ष), एसईसीएल और अशोका-करकटा वेस्ट नॉर्थ ओसी (10 मीट्रिक टन प्रति वर्ष), सीसीएल शामिल हैं।

ईसीएल की रंगमती-ए भूमिगत परियोजना की योजना 3.80 मीट्रिक टन प्रति वर्ष के लिए बनाई गई है जिसे एक बड़ी भूमिगत खदान माना जा सकता है। इसके अलावा, ईसीएल के भानोरा पश्चिम (0.50 मीट्रिक टन प्रति वर्ष) के लिए भूमिगत, हाईवॉल और ओपनकास्ट कार्य पद्धति वाली एक मिश्रित खदान की भी योजना बनाई गई है।

5.0 प्रयोगशालाओं का उन्नयन:

सीएमपीडीआईएल में सभी प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ा दी गई है। भू-रासायनिक प्रयोगशाला मैनुअल/अर्ध-स्वचालित नमूना तैयारी इकाइयों, समीपस्थ विश्लेषक, अंतिम विश्लेषक, बम कैलोरीमीटर, राख संलयन तापमान रेंज विश्लेषक, एचजीआई उपकरण आदि से सुसज्जित है। प्रयोगशाला एक्स-रे प्रतिदीप्ति प्रणाली (एक्सआरएफ) सुविधा से भी सुसज्जित है जो राख और अन्य धातु ऑक्साइड का विश्लेषण करने में सक्षम है। तरल और ठोस नमूनों में पारा (एचजी) सामग्री का निर्धारण करने के लिए प्रत्यक्ष पारा विश्लेषक उपलब्ध है। कोयले के कोकिंग गुणों का निर्धारण करने के लिए स्वेलिंग सूचकांक, एलटीजीके, प्लास्टोमीटर जैसे उपकरण भी उपलब्ध हैं। हाल ही में, प्रयोगशाला को एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर (एक्सआरडी) प्रणाली से सुसज्जित किया गया है जो अज्ञात नमूनों में खनिजों की उपस्थिति, खदान धूल के नमूनों में मुक्त सिलिका का विश्लेषण करने में सक्षम है।

प्रयोगशाला में हाल ही में गैर-कोयला नमूने (बेस मेटल) तैयार करने की इकाई भी स्थापित की गई है, जिसमें वांछित नमूना आकार की आवश्यकताओं के नमूने तैयार करने के लिए वाइब्रेटरी कप मिल्स और स्वचालित जॉ क्रशर शामिल हैं। गैर-कोयला के लिए खनिज पहचान सुविधा की स्थापना की दिशा में, सीएमपीडीआई रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइजिंग रिसर्च माइक्रोस्कोप के साथ रॉक कटिंग और पॉलिशिंग यूनिट की खरीद की प्रक्रिया में है। साथ ही, दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) और ट्रेस धातुओं की गुणात्मक और मात्रात्मक पहचान के लिए, एक पूरी तरह से चालू आईसीपी-एमएस (इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा-मास स्पेक्ट्रोमेट्री) प्रयोगशाला सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला पेट्रोग्राफिक अध्ययन करने के लिए उन्नत पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप से सुसज्जित है जिसमें कोयले के नमूनों की मैकेरल सामग्री (कोयला प्रकार) और परावर्तन प्रतिशत (रेंक/परिपक्वता) निर्धारित की जाती है। कोक बनाने में मिश्रण के रूप में दिए गए कोयले की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोग्राफिक अध्ययन अनिवार्य है।

सीएमपीडीआईएल, आरआई-VII, भुवनेश्वर में एक रासायनिक विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। कोयला कोर प्रसंस्करण क्षमता को और बढ़ाने के लिए, 2025-26 की अवधि के लिए विभिन्न कोयला क्षेत्रों से अन्वेषण ब्लॉकों के कोयला कोर के विश्लेषण के लिए कोयला परीक्षण निजी प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है।

कोल कैरेक्टराइजेशन प्रयोगशाला को 12 अलग-अलग "परीक्षण क्षेत्रों में" अपनी सुविधाओं के लिए मानक आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार एनएबीएल प्रमाणन से मान्यता प्राप्त है। पेट्रोग्राफी लैब में पेट्रोग्राफर्स को कोयला और जैविक पेट्रोलॉजी की अंतर्राष्ट्रीय समिति आईसीसीपी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

कोयला और खनिज तैयारी (सीएमपी) प्रयोगशाला को 4 अलग-अलग क्षेत्रों में "परीक्षण" के क्षेत्र में अपनी सुविधाओं के लिए मानक आईएसओ/आईईसी 17025:2017 "परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं की क्षमता के लिए सामान्य आवश्यकताओं" के अनुसार एनएबीएल प्रमाणन के साथ मान्यता प्राप्त है। इस तरह के मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा मान्यता को परीक्षण परिणामों की पारस्परिक स्वीकृति की सुविधा के लिए एक आवश्यक कदम माना जाता है।

एनएबीएल ने सीएमपीडीआईएल मुख्यालय की गैर-विनाशकारी परीक्षण (एनडीटी) प्रयोगशाला को गैर-विनाशकारी परीक्षण के क्षेत्र में अपनी सुविधाओं/दायरे के लिए आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के आधार पर मान्यता जारी रखी। सीएमपीडीआईएल के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में उचित उपकरणों और संसाधनों के साथ एनडीटी सेल स्थापित किए गए हैं। क्षेत्रीय संस्थानों की प्रयोगशालाओं को भी एनएबीएल मान्यता दिलाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय संस्थान VI, सिंगरौली में एनडीटी प्रयोगशाला को अप्रैल 2023 में मान्यता दी गई भाई।

सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची स्थित पर्यावरण प्रयोगशाला को परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा 170 मापदंडों के लिए आईएसओ/आईईसी 17025:2017 मानकों के अनुसार पुनः मान्यता दी गई। यह मान्यता 24 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी। प्रयोगशाला को व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) आईएस/आईएसओ 45001:2018 के अनुसार भी मान्यता प्राप्त है। इसी तरह, आरआई-I, आसनसोल; आरआई-II, धनबाद; आरआई-IV, नागपुर; आरआई-V, बिलासपुर; और आरआई-VII, भुवनेश्वर की पर्यावरण प्रयोगशालाओं को भी आईएसओ/आईईसी 17025:2017 मानकों के तहत एनएबीएल मान्यता प्राप्त है।

सीएमपीडीआईएल के पास सीबीएम और शेल गैस के विशिष्ट विश्लेषण की सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला है। इन सेवाओं में गैस विशोषण परीक्षण, अधिशोषण आइसोथर्म परीक्षण, गैस संरचना विश्लेषण, रॉक इवल पायरोलिसिस, कुल कार्बनिक कार्बन (टीओसी), हीलियम पोरसिटी और पारगम्यता परीक्षण, खान वायु नमूना विश्लेषण आदि शामिल हैं।

खनन प्रौद्योगिकी (एमटी) लैब को परीक्षण सुविधाओं के क्षेत्र में मानक आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार 05.01.2024 से एनएबीएल प्रमाणन के साथ पुनः मान्यता दी गई है। खनन प्रयोगशाला में उपलब्ध भौतिक-यांत्रिक गुण (पीएमपी) परीक्षण सुविधाओं में असीमित संपीड़न शक्ति, तन्य शक्ति, कतरनी शक्ति, लोचदार स्थिरांक (यंग मापांक, पॉइसन अनुपात), थोक घनत्व, त्रिअक्षीय संपीड़न शक्ति (संलग्नता और आंतरिक घर्षण का कोण), प्रोटोडाकोनोव शक्ति सूचकांक (पीएसआई), पॉइंट लोड इंडेक्स, स्लेक स्थायित्व सूचकांक (एसडीआई), रॉक क्वालिटी डेजिग्रेडेशन (आरक्यूडी), आदि शामिल हैं। लैब रॉक मास रेटिंग (आरएमआर), सपोर्ट डिज़ाइन, कैवेबिलिटी इंडेक्स और स्ट्रेटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान (एससीएमपी) अध्ययन के निर्धारण की सुविधाएं प्रदान करती है। इसमें भूमिगत और खुली खदानों से प्राप्त चट्टानों/कोयले के पीएमपी परीक्षण के लिए कोर नमूने तैयार करने के लिए कोर ड्रिलिंग मशीन की सुविधा भी है। इस परीक्षण के परिणाम का उपयोग भूमिगत पिलर स्थिरता और खुली खदान की ढलान स्थिरता के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किया जाता है।

6.0 श्रमशक्ति का नियोजन:

गवेषण, आयोजना एवं अभिकल्पन (प्लानिंग एंड डिजाइन) के साथ-साथ संबद्ध अभियंत्रण सेवाओं में श्रमशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान सीएमपीडीआई में स्थानान्तरण और भर्ती के द्वारा 68 अधिकारियों को पदस्थापित किया गया है। इसी प्रकार भर्ती/अनुकम्पा के आधार पर नौकरी/अन्य अनुषंगी कंपनियों से स्थानांतरण के द्वारा 24 कर्मचारियों को पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा सीएमपीडीआईएल में खदान योजना के वर्तमान और भविष्य के कार्यभार को पूरा करने के लिए अन्य सहायक कंपनियों से योग्य श्रमशक्ति के स्थानान्तरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

7.0 जियोमेटिक्स सेवाएँ

सीएमपीडीआईएल 2008 से ही उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले उपग्रह डेटा के आधार पर नियमित आधार पर सीआईएल खदानों की

सैटेलाइट डेटा आधारित भूमि सुधार निगरानी कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में, कुल 114 परियोजनाओं की भूमि सुधार निगरानी सफलतापूर्वक पूरी की गई, जिसमें 5 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) से अधिक उत्पादन करने वाली 75 ओपनकास्ट परियोजनाएँ (कोयला + ओबी) श्रेणी शामिल हैं, जिनकी वार्षिक आधार पर निगरानी की जाती है और 5 एमसीएम (कोयला + ओबी) श्रेणी से कम उत्पादन करने वाली 39 खदानें/क्लस्टर, जिनकी निगरानी सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों के तहत चरणबद्ध तरीके से तीन साल के अंतराल पर की जाती है, शामिल हैं। वर्ष के दौरान छह कोयला क्षेत्रों के वनस्पति आवरण का मानचित्रण भी किया गया।

1 एमटीवाई से अधिक उत्पादन करने वाली सभी ओसी खदानों, आउटसोर्स और विभागीय दोनों, की ओबीआर माप और 1 एमटीवाई से कम उत्पादन करने वाली ओसी खदानों (केवल किराये के पैच) की वार्षिक माप पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है।

सीएमपीडीआईएल कोयला मंत्रालय के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान, गांधीनगर (बीआईएसएजी-एन) के साथ पीएम गति शक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर एमओसी पेज के विकास में समन्वय और सुविधा प्रदान कर रहा है।

सीएमपीडीआईएल, गांधीनगर के भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) के सहयोग से कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली के सुचारू संचालन को सुनिश्चित कर रहा है तथा संबंधित मोबाइल ऐप खनन प्रहरी को अद्यतन रख रहा है।

सीएमपीडीआईएल ने स्थलाकृतिक मानचित्रण, कोयला खदान अग्नि मानचित्रण, वनस्पति आवरण मानचित्रण, बस्तियों का मानचित्रण, वृक्षारोपण ऊंचाई आकलन और खनन से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए ड्रोन/यूएवी आधारित सर्वेक्षणों का संचालन किया है। वर्ष के दौरान निष्पादित कुछ प्रमुख परियोजनाओं में राजस्थान और बिहार राज्य में रेत पट्टों के रेत पुनःपूर्ति अध्ययन, कोयला मंत्रालय के लिए नीलामी ब्लॉकों के फ्लाई-श्रू वीडियो तैयार करने के लिए ड्रोन आधारित सर्वेक्षण शामिल हैं। नीलामी के तहत कोयला ब्लॉकों के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया।

8.0 कोल वाशरी की स्थापना में सहायता:

सीएमपीडीआई ग्रीनफील्ड कोयला वाशरियों के लिए वैचारिक रिपोर्ट तैयार करने से लेकर कार्य देने (अवार्ड आफ वर्क) एवं उसके बाद ड्राईगों की संवीक्षा तथा वर्तमान वाशरियों के रूपान्तरण/आधुनिकीकरण तक तकनीकी सेवा देता है। इन सेवाओं में विस्तृत प्रयोगशाला अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर)/संकल्पनात्मक रिपोर्ट (सीआर) तैयार करना, बोली प्रक्रिया प्रबंधन, अनुबंध दस्तावेज़ तैयार करना, परियोजना निष्पादन के दौरान चित्रों की जांच के बाद कार्य सौंपने में सहायता और ट्रायल रन, पीजीटी आदि में सहायता शामिल है।

वर्ष के दौरान, कई प्रमुख रिपोर्ट और अध्ययन पूरे किए गए, जिनमें मौजूदा 2.6 मीट्रिक टन क्षमता वाली केदला वाशरी (सीसीएल) के जीर्णोद्धार के लिए विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट और बलराम खान (एमसीएल) के लिए 15 मीट्रिक टन क्षमता वाली वाशरी की स्थापना के लिए मसौदा व्यवहार्यता रिपोर्ट शामिल है। नई वाशरियों के लिए निविदा जारी करने के लिए सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा अपनाई गई विभिन्न बोली अवधारणाओं की जांच करने के लिए समिति की रिपोर्ट तैयार की गई। कोयला वाशरियों की निष्क्रिय क्षमता के उपयोग के उपायों का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए एक रिपोर्ट भी कोयला मंत्रालय द्वारा निदेशक (तकनीकी), सीआईएल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार की गई थी।

एमसीएल में रिजैक्ट आधारित बिजली संयंत्र के साथ-साथ गैर-कोकिंग कोयला वाशरी की स्थापना की संभावनाओं पर एक अवधारणा नोट तैयार किया गया था, जिसके आधार पर "एमसीएल में एकीकृत कुल्दा-गर्जनबहाल गैर-कोकिंग कोयला वाशरी की स्थापना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी" के लिए कार्य आदेश दिया गया है।

9.0 पर्यावरणीय सेवाएँ:

2024-25 के दौरान, 48 रिपोर्टें यानी 19 ड्राफ्ट ईआईए/ईएमपी/परिशिष्ट ईआईए/ईएमपी (पर्यावरण प्रभाव आकलन/पर्यावरण प्रबंधन योजनाएँ) और 29 फॉर्म-I/फॉर्म-IV/फॉर्म-VI तैयार किए गए और आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, हसदेव, जयंत और रांची में स्थित आठ पर्यावरण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सीआईएल की 303 परियोजनाओं/क्लस्टरों/प्रतिष्ठानों की पर्यावरण निगरानी की गई। सीएमपीडीआईएल द्वारा कुछ विशेष कार्य जैसे कि वहन क्षमता अध्ययन, खदान की पारिस्थितिक निगरानी, पुनर्ग्रहण स्थलों के जैव विविधता मूल्यांकन अध्ययन, रेत पुनःपूर्ति अध्ययन, एसटीपी और ईटीपी का डिजाइन भी किया गया।

कोयला क्षेत्र में ओवर बर्डन (ओबी) के लाभकारी उपयोग पर एचपीईसी रिपोर्ट, सीआईएल द्वारा विकसित इको-पार्कों की प्रभावशीलता की मूल्यांकन रिपोर्ट, और डी-कोयला भूमि के पुनः उपयोग के लिए एसओपी का विकास, आदि पर रिपोर्टें तैयार की गईं और कोयला मंत्रालय के लिए एसडीसी के तहत प्रस्तुत की गईं।

एमसीएल, सीसीएल, एसईसीएल, एनसीएल और बीसीसीएल की विभिन्न खदानों के लिए विशेष अध्ययन जैसे वैज्ञानिक मृदा नमी संरक्षण (एसएमसी) योजना, शीर्ष मृदा प्रबंधन और मृदा अपरदन योजना; ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन अध्ययन रिपोर्ट, कार्बन पृथक्करण अध्ययन रिपोर्ट, नदी पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता अध्ययन रिपोर्ट और प्रदूषण न्यूनीकरण अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गईं और प्रस्तुत की गईं।

इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल ओपनकास्ट/भूमिगत खनन, थर्मल, सीबीएम और कोल वॉशरी क्षेत्रों सहित खनिजों के खनन के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई), नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) परामर्श संगठन के रूप में अपनी मान्यता जारी रखे हुए है, ताकि ईआईए अध्ययनों के लिए सीआईएल और भारत भर में फैले अन्य संगठनों को अपनी सेवाएं प्रदान की जा सकें। सीएमपीडीआईएल ईआईए और ईएमपी की तैयारी के लिए भारत में सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त सलाहकार संगठन (एसीओ) है और इसके पास 80 से अधिक अनुमोदित विशेषज्ञ हैं।

10.0 कोयला आधारित ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत:

सीएमपीडीआईएल, सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के लिए कोल बेड मीथेन (सीबीएम) और कोयला गैसीकरण जैसे कोयला आधारित अपरंपरागत संसाधनों के विकास में लगी हुई है। सीआईएल लीजहोल्ड क्षेत्रों में वर्तमान में तीन सीबीएम ब्लॉक विचाराधीन हैं: 1) झरिया सीबीएम ब्लॉक- I (झरिया कोलफील्ड), 2) रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (रानीगंज कोलफील्ड), 3.) झरिया सीबीएम ब्लॉक- II (झरिया कोलफील्ड)।

झरिया सीबीएम ब्लॉक-I (बीसीसीएल लीजहोल्ड क्षेत्र) को राजस्व साझेदारी के आधार पर सीबीएम के निष्कर्षण के लिए मेसर्स प्रभा एनर्जी लिमिटेड (पीईएल) को दिया गया है। ब्लॉक वर्तमान में अन्वेषण चरण में है। न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) के तहत 5 अन्वेषण कोरहोल की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। झरिया सीबीएम ब्लॉक-II (बीसीसीएल) के लिए परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट को अक्टूबर, 2024 में बीसीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (ईसीएल) और झरिया सीबीएम ब्लॉक-II (बीसीसीएल) को सीबीएम के निष्कर्षण के लिए सीबीएम डेवलपर के चयन के लिए निविदा देने का प्रस्ताव है।

भारतीय भू-खनन स्थितियों में भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए एक अनुसंधान एवं विकास पायलट परियोजना को सीएमपीडीआईएल, ईसीएल और एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजी इंक (ईईटीआई), कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। सीएमपीडीआईएल और ईसीएल प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियां हैं और ईईटीआई, कनाडा उप-कार्यान्वयन एजेंसी है। अनुसंधान एवं विकास पायलट परियोजना के परिणाम कोयला संसाधनों के उपयोग के लिए स्वच्छ मार्ग प्रदान कर सकते हैं।

11.0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ:

सीएमपीडीआईएल कोयला मंत्रालय और सीआईएल के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान के तहत वित्तपोषित अनुसंधान गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है। विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों/संगठनों द्वारा किए जा रहे विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यों के समन्वय के अलावा, सीएमपीडीआईएल अपनी अच्छी तरह से स्थापित प्रयोगशालाओं के साथ कोयला/लिग्नाइट खनन उद्योगों के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कोयला अन्वेषण; कोयला आधारित गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों जैसे कोल बेड मीथेन (सीबीएम), कोल माइन मीथेन (सीएमएम), कोयला गैसीकरण, शेल गैस मूल्यांकन का विकास; कोयला लाभकारीकरण और उपयोग; खदानों में उत्पादन, उत्पादकता और सुरक्षा में सुधार; खदान पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा; कोयले और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का वैकल्पिक उपयोग; नवाचार और स्वदेशीकरण आदि में अनुसंधान कर रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में, कई शोध परियोजनाओं ने काफी लाभ अर्जित किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन में सुधार, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ, बेहतर संसाधन पुनर्प्राप्ति और पर्यावरण की सुरक्षा हुई है। जबकि कुछ शोध परियोजनाओं ने उद्योग पर प्रत्यक्ष रूप से ठोस प्रभाव डाला है, वहीं कुछ अन्य हैं जिन्होंने खदान नियोजन, डिजाइन और तकनीकी सेवाओं को मजबूत किया है जो कि संचालित खदानों और भविष्य की खनन परियोजनाओं दोनों के लिए आवश्यक हैं।

2024-25 के दौरान, 18 शोध परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ये पूर्ण हो चुकी शोध परियोजनाएं निम्नलिखित से संबंधित हैं: "भूमिगत कोयला खदानों में उपयोग किए जाने वाले पिट बॉटम बफर के लिए ड्रॉप टेस्ट सुविधा का डिजाइन और विकास"; "भूमिगत कोयला खदानों में विद्युत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में वेंटिलेशन फैन पवन ऊर्जा रिकवरी प्रणाली का डिजाइन और तैनाती"; "मॉडलिंग और सिमुलेशन विश्लेषण के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड के तहत कोकिंग कोल वाशरी के प्रदर्शन में सुधार पर अध्ययन"; "कार्बन मूल्यों की वसूली के लिए कोकिंग कोल वाशरी के मिडिलिंग्स और फाइन्स का प्रभावी उपयोग"; "खनिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए घुटने और रीढ़ की हड्डी के स्मार्ट सुरक्षात्मक उपकरणों का डिजाइन और विकास"; "सिंगरौली कोयला खदानों में आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क [एएनएन], प्रोबेबिलिस्टिक न्यूट्रल नेटवर्क [पीएनएन] और क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री [कार्ट] मॉडल के माध्यम से पार्टिकुलेट मैटर और गैसीय प्रदूषकों की सांद्रता का पूर्वानुमान "बायो-कोगुलेंट का उपयोग करके कोयला वाशरी अपशिष्टों से बारीक कणों को अलग करना और उनकी पुनर्प्राप्ति"; "कोयला खदानों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर (वीआरएमएस) का विकास"; "हाईवॉल खनन व्यवहार्यता आकलन और लेआउट डिजाइन"; "विशाल प्रकृति की नींव मिट्टी को स्थिर करने और इष्टतम ओवरबर्डन डंप ऊंचाई को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए उपयुक्त जमीन सुधार प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए भू-तकनीकी पहलुओं से संबंधित फोरेंसिक जांच"; "कोयला उद्योग के लिए सीएमपीडीआई में 5 जी उपयोग केस टेस्ट लैब की स्थापना"; "सीओ₂ कैप्चर के लिए झरझरा अधिशोषक विकसित करने के लिए कोयला गैंग का उपयोग"; "बढ़ी हुई कोलबेड मीथेन रिकवरी और कार्बन पृथक्करण की संभावनाओं के लिए कोयला भंडार का जलाशय लक्षण वर्णन और संख्यात्मक मॉडलिंग", "कोयले का बायोमेथेनाइजेशन" "बकेट व्हील एक्सकेवेटर में प्रयुक्त बॉटम रोलर्स की असामयिक विफलताओं की रोकथाम तथा उनके जीवन को बढ़ाना" और "भारत में कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए इष्टतम रणनीति पर अध्ययन"।

भारत और विदेश में अनुसंधान संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों और कोयला/लिग्नाइट उत्पादक कंपनियों के साथ निरंतर बातचीत की जा रही है ताकि उन्हें सीआईएल के दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए लाभकारी आवश्यकता-आधारित अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सीआईएल अपनी पहुंच बढ़ाने और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में भारत और विदेश में अधिक विश्व स्तरीय वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों को शामिल करने का इरादा रखता है ताकि वह आत्मनिर्भर बनकर देश की आकांक्षाओं को पूरा कर सके।

सीएमपीडीआई में कोयला और ऊर्जा अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र (नासर), चरण-1 की स्थापना की गई है। चरण-1 में सीएमपीडीआई रांची में मौजूदा बुनियादी ढांचे और अनुभवी श्रमशक्ति का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि

चरण-II में एक प्रसिद्ध शहर में एक स्थायी अनुसंधान एवं विकास केंद्र का निर्माण किया जाएगा जो वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए सुसज्जित होगा। यह केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, खनन, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ कोयला समाधानों में अत्याधुनिक तकनीकों और ज्ञान साझाकरण के एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। नासर के प्रमुख उद्देश्यों में कोयला और ऊर्जा क्षेत्रों में अनुसंधान प्रयासों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना और उद्योग के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान परिणामों का समय पर अनुप्रयोग सुनिश्चित करना शामिल है। केंद्र नई खोजों के लिए बौद्धिक संपदा को सुरक्षित करने और उन्नत, डिसरप्टिव तकनीकों को विकसित करने के लिए उद्योग और विदेशी हितधारकों के साथ सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

विभिन्न अनुसंधान संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे ऊर्जा क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय अनुसंधान परियोजनाओं एवं पहलों के माध्यम से अपने प्रतिभा पूल से विशेषज्ञों एवं युवा वैज्ञानिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें, ताकि कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्त पोषण किया जा सके।

पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा प्रबंधन और डिजिटलीकरण, कार्बन उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा, एआई और आईओटी का उपयोग, अपशिष्ट से धन सृजन, अन्वेषण में नई तकनीकों की तैनाती आदि के क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू करके अनुसंधान एवं विकास पहलों के विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है।

वर्तमान में, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी-आईएसएम, धनबाद, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, वाराणसी, आईएससी, बीएचयू, वाराणसी, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मंडी, एनआरएससी, हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (जेएनसीएसआर), बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केंद्र (जेएनएआरडीडीसी) नागपुर, टीसीआईएल, नई दिल्ली, सीएमईआरआई, दुर्गापुर, एनएमएल, जमशेदपुर, सीआईएमएफआर, धनबाद, वीएनआईटी, नागपुर, एससीसीएल, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (एसआईएस), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली, ड्यूक विश्वविद्यालय, यूएसए, सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया, न्यू कैसल विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया, वॉल्लोन्गो विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से 41 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं।

सीएमपीडीआईएल ने 6 चिन्हित समस्याओं के लिए "मेक इन इंडिया" पहल के अंतर्गत कोयला गैसीकरण के क्षेत्र में स्टार्ट-अप और अनुसंधान संगठनों को बढ़ावा देने/प्रोत्साहित करने के लिए "कोयला गैसीकरण पर हैकार्थॉन" का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

12.0 निगमित सामाजिक दायित्व तथा सस्टेनेबिलिटी:

सीएमपीडीआईएल अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ-साथ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति के तहत अपने आस-पास के समुदायों और आम जन जीवन के कल्याण और उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। पिछले कुछ वर्षों में सीएमपीडीआईएल ने सीएसआर के तहत अपने मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थानों और ड्रिलिंग कैंपों के आसपास के समुदायों के विकास और उत्थान के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण और स्वच्छता, बुनियादी ढांचे आदि के क्षेत्रों में विभिन्न पहल की हैं। सीएमपीडीआईएल ने लक्ष्य से अधिक खर्च करके अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित की है।

वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसआर के तहत की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में झारखंड के आदिवासी ब्लॉकों की लड़कियों को जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल कौशल विकसित करना; टाटा कैंसर केयर फाउंडेशन (टीसीसीएफ) द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कैंसर का पता लगाने के लिए रांची कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र (आरसीएचआरसी), रांची में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचितों को सहायता प्रदान करना; आसनसोल, पश्चिम बंगाल के 15 सरकारी स्कूलों की छात्राओं को प्रशिक्षण और आसान निपटान के साथ सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच के माध्यम से स्वस्थ मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देना; झारखंड को अंधेपन से मुक्त बनाने की दिशा में झारखंड के धनबाद जिले के 2 ब्लॉक

(पूर्वी टुंडी और गोविंदपुर) में मुफ्त नेत्र जांच और गतिशीलता सहायता शिविर का आयोजन करना और हजारीबाग, झारखंड के सरकारी स्कूल के छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए छह खाद्य वितरण वाहन प्रदान करके बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए समर्थन करना टीबी और अन्य बीमारियों से पीड़ित गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिए रामकृष्ण मिशन टीबी सेनेटोरियम, तुपुदाना, रांची को आवश्यक चिकित्सा उपकरण/यंत्र प्रदान करना ; छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सीआईएमएस), बिलासपुर (सीजी) को चिकित्सा उपकरण प्रदान करना और स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), ओडिशा में विकलांग रोगियों, उपस्थित लोगों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए कैंटीन/कैफेटेरिया भवन का प्रावधान करना।

13.0 प्रबंधन प्रणाली मानक में परामर्शी सेवा:

सीएमपीडीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में प्रबंधन प्रणाली मानकों के कार्यान्वयन के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है और विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों जैसे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 45001, आईएसओ 50001, आईएसओ/आईईसी 27001, आईएसओ 37001 आदि के अनुप्रयोग के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। हम प्रणाली की स्थापना और दस्तावेजीकरण, प्रलेखित प्रणालियों के प्रति जागरूकता, प्रशिक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षक प्रशिक्षण, लेखा परीक्षा सहायता, कार्यान्वयन, प्रमाणन सहायता के साथ-साथ इन प्रबंधन प्रणाली मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रमाणन के बाद सहायता में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं।

सीएमपीडीआईएल को अपने सभी क्षेत्रीय संस्थानों के साथ आईएसओ 9001: 2015 मानक की आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएसओ 9001:2015 - गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के लिए लाइसेंस दिया गया है। सीएमपीडीआईएल का वर्तमान आईएमएस मैनुअल आईएसओ 9001- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ/आईईसी 27001- सूचना प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं को संबोधित करता है। सीएमपीडीआईएल मुख्यालय, रांची ने आईएसओ 37001:2016 - रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली को भी लागू और प्रमाणित किया है।

सीआईएल मुख्यालय, कोलकाता को सीएमपीडीआईएल के मार्गदर्शन और समर्थन में भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 50001:2018 प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

मार्च 2025 तक, सीआईएल की तीन सहायक कंपनियाँ यानी ईसीएल, एनसीएल और एमसीएल एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018) के लिए प्रमाणित हैं। एनसीएल को सीएमपीडीआईएल के परामर्श मार्गदर्शन के तहत आईएसओ/आईईसी 27001- सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए भी प्रमाणित किया गया है।

14.0 कोल इंडिया लिमिटेड के अतिरिक्त अन्य कम्पनियों को परामर्श सहायता:

सीएमपीडीआईएल ने अपनी सेवाओं के विविधीकरण और सीआईएल के बाहर ग्राहक आधार में वृद्धि की दिशा में अपना प्रयास जारी रखा है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार (केन्द्रीय और राज्य) के साथ-साथ निजी एजेंसियां भी शामिल हैं।

पिछले छह वित्तीय वर्षों में इसने संख्या और मूल्य दोनों ही दृष्टि से कार्यों का सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त किया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएमपीडीआईएल ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ग्राहकों को ₹252.32 करोड़ के 213 प्रस्ताव भेजे, जो साल-दर-साल (वाईओवाई) 50% की वृद्धि को दर्शाता है।

कंपनी ने सीआईएल के बाहरी क्लाइंट्स से ₹144.44 करोड़ मूल्य की 151 कंसल्टेंसी जॉब्स हासिल कीं, जो कि 42.84% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। साथ ही, सीएमपीडीआईएल ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बाहरी जॉब्स से ₹53 करोड़ से अधिक का राजस्व सफलतापूर्वक अर्जित किया है।

सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल के बाहर अपने ग्राहक आधार का काफी विस्तार किया है, वित्त वर्ष 2024-25 में 50 से अधिक नए ग्राहक जोड़े हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में सीएमपीडीआईएल के प्रमुख बाहरी ग्राहकों में एनटीपीसी, डब्ल्यूबीपीडीसीएल (पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड), राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, टीपीजीसीएल (टीएसजीईएनसीओ), बिहार सरकार, रूंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, बुल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, सीईएससी लिमिटेड और विभिन्न वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक मालिक शामिल हैं।

15.0 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाएँ

सीएमपीडीआईएल ने 'कोयला गैसीकरण पर हैकथॉन' और 'आरएंडडी पर हैकथॉन' पर वेबसाइट विकसित की है। इसने सीएमपीडीआई के नेटवर्क आईटी संसाधनों तक पहुंच को कुशलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए केंद्रीकृत प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता प्रबंधन और सुरक्षा नीतियों के कार्यान्वयन के लिए 'डायरेक्टरी सर्विसेज एंड डोमेन कंट्रोल' भी पेश किया है।

16.0 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं:

पहले चरण में, सीआईएल द्वारा 382.5 एमटीवाई क्षमता वाली 33 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं शुरू की गईं, जिसमें सीएमपीडीआईएल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रिकॉर्ड समय में सभी परियोजनाओं के लिए एनआईटी प्रस्तुत की। 15 परियोजनाएं पहले ही चालू हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

एफएमसी-II में 57 एमटीवाई क्षमता वाली 8 एफएमसी परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें से सभी 8 परियोजनाओं के लिए अंतिम एनआईटी प्रस्तुत की गई है। एफएमसी-III में 324 एमटीवाई क्षमता वाली 17 एफएमसी परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें से सीएमपीडीआईएल 9 परियोजनाओं की एनआईटी तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन 9 परियोजनाओं में से 5 परियोजनाओं के लिए अंतिम एनआईटी प्रस्तुत की गई है और 4 परियोजनाओं की एनआईटी तैयारी के अधीन है। एफएमसी के चौथे चरण में 74 एमटीवाई क्षमता वाली 14 परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें से सीएमपीडीआईएल 9 परियोजनाओं के लिए एनआईटी तैयार करेगा। दो परियोजनाओं के लिए एनआईटी प्रस्तुत की गई है और अन्य 7 को सीआईएल समयसीमा के अनुसार तैयार किया जाएगा।

सीएमपीडीआईएल ने एमओसी और सीआईएल के निर्देशानुसार 22 निर्माणाधीन एफएमसी परियोजनाओं के लिए तीसरे पक्ष से गुणवत्ता ऑडिट कराया है और अपनी रिपोर्ट संबंधित सीआईएल सहायक कंपनियों को सौंप दी है।

17.0 वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉक की नीलामी:

कोयला मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी में सीएमपीडीआईएल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नीलामी के लिए पेश किए जाने वाले कोयला ब्लॉकों की पहचान करने में, सीएमपीडीआईएल ने सतह की बाधाओं, भू-तकनीकी कारकों के अध्ययन, संभावित बोलीदाताओं की राय एकत्र करने आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोयला मंत्रालय द्वारा नीलामी के विभिन्न चरणों के लिए चुने गए कोयला ब्लॉकों के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा खदान डोजियर और खदान सारांश प्रस्तुत किए गए थे। इसके अतिरिक्त, इन सभी कोयला ब्लॉकों के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा निविदा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण इनपुट डेटा भी कोयला मंत्रालय को उपलब्ध कराया गया था। कोयला मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक नीलामी के 10 वें दौर तक 109 कोयला ब्लॉकों के लिए वेस्टिंग ऑर्डर जारी किए गए हैं।

18.0 कोयला खदानों में 5जी अनुप्रयोग

सीएमपीडीआईएल ने मेसर्स टीसीआईएल, नई दिल्ली के सहयोग से लैब स्केल 5जी कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) के साथ एक समर्पित "5जी सीओई यूज केस टेस्ट लैब" की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य कोयला क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी परिदृश्य को आगे बढ़ाना है। 5जी यूज केस टेस्ट लैब कोयला उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए विभिन्न 5जी-आधारित अनुप्रयोगों के विकास, परीक्षण और अनुकूलन के लिए एक परीक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता है।

इसके अलावा, सीएमपीडीआई ने अमलोहरी ओपनकास्ट माइंस, एनसीएल, सिंगरौली में "ओपनकास्ट कोल माइंस में एकीकृत वॉयस, वीडियो और डेटा संचार के लिए 5जी कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन)" शीर्षक से एक आरएंडडी परियोजना शुरू की है, जिसमें स्केलेबल 5जी आधारित उपयोग मामलों के साथ पूर्ण खदान पैमाने पर 5जी सीएनपीएन की तैनाती की जा रही है।

19.0 कोयला ई-नीलामी प्लेटफार्म का विकास

इससे पहले, कोयले की ई-नीलामी केवल बाहरी एजेंसियों जैसे एमएसटीसी और एमजंक्शन द्वारा की जा रही थी। इसके बाद, सीआईएल के निर्देशों के अनुसार, सीएमपीडीआई ने सिंगल विंडो मोड एग्रेस्टिक (एसडब्ल्यूएमए) योजना 2022 के अनुसार कोयले की नीलामी के लिए कोयला ई-नीलामी मंच विकसित किया है। पोर्टल का विकास और इसके संशोधन एनआईसी, मीटीई, भारत सरकार द्वारा किए गए हैं, जो इस परियोजना के लिए हमारे प्रौद्योगिकी भागीदार हैं। पोर्टल का औपचारिक उद्घाटन 03.10.2023 को सचिव, एमओसी, भारत सरकार द्वारा किया गया और सीएमपीडीआईएल ने कोयले के लिए ई-नीलामी आयोजित करना शुरू कर दिया है।

मार्च 2025 तक 7000 से अधिक बोलीदाताओं ने कोयला ई-नीलामी पोर्टल में अपना पंजीकरण कराया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, सीएमपीडीआईएल ने 88 मिलियन टन से अधिक कोयले के लिए सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के लिए 150 ई-नीलामी सफलतापूर्वक आयोजित की है। एसडब्ल्यूएमए कोयला ई-नीलामी योजना में एक बड़ा बदलाव हुआ है और संशोधित योजना के अनुसार कोयला नीलामी आयोजित करने के लिए नीलामी योजना में किए गए परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए पोर्टल का विकास किया जा रहा है। दिसंबर 2024 से सीएमपीडीआईएल के पोर्टल में ई-नीलामी बंद कर दी गई है। संशोधित योजना के अनुसार नीलामी आयोजित करने के लिए पोर्टल जल्द ही तैयार हो जाएगा।

20.0 मान्यता एवं पुरस्कार:

भारत सरकार ने सीएमपीडीआईएल के योगदान और प्रासंगिकता को मान्यता दी और इसे सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार उनके ओ/एम संख्या 11/36/97-वित्त दिनांक 09-10-1993 में मिनी रत्न (श्रेणी- I) का दर्जा दिया। डीपीई के निर्देश सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नीतिगत उद्देश्य के रूप में लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) को बढ़ी हुई स्वायत्तता और शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल प्रदान करने का प्रावधान करते हैं। सीएमपीडीआईएल का प्रभावशाली प्रदर्शन 2007-08 से लगातार उत्कृष्ट एमओयू (सीआईएल और सीएमपीडीआईएल के बीच) रेटिंग प्राप्त करने में परिलक्षित होता है (2010-11, 2018-19 और 2020-21 को छोड़कर जब इसे 'बहुत अच्छा' के रूप में रेट किया गया था)।

21.0 कॉर्पोरेट प्रशासन:

भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशा-निर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का सीएमपीडीआईएल द्वारा अनुपालन किया गया है। निदेशकों की रिपोर्ट में

कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक अलग खंड जोड़ा गया है और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों से कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र निदेशकों की रिपोर्ट में संलग्न है।

22.0 सीएमपीडीआईएल का सूचीबद्ध:

हमारी कंपनी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। तदनुसार, मई 2025 में कंपनी को एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया है और एनएसई और बीएसई दोनों पर सूचीबद्ध करने के लिए ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल कर दिया गया है।

23.0 आभारोक्ति:

ये सभी उपलब्धियाँ आपकी कंपनी के सामूहिक प्रयास, श्रमिक संगठनों (जेसीसी) तथा ऑफिसर्स असोसिएशन के सदस्यों द्वारा अनवरत सहयोग के साथ-साथ कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए सहयोग से प्राप्त हो सकीं हैं। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की संलिप्तता, समर्पण तथा कंपनी में उपलब्ध विशेषज्ञता भावी कार्य के प्रति समर्पण दिलासा का बड़ा स्रोत होगा। विश्वास है कि हम भविष्य में और ऊँचाई प्राप्त करने का प्रयास जारी रखेंगे तथा पहले की तरह हर स्तर पर समर्पित प्रतिबद्धता तथा उपलब्धियों के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए शेयर होल्डर की आकांक्षों को पूरा करेंगे।

मैं सभी शेयर होल्डर, कोयला मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों, ग्राहकों एवं विक्रेताओं (वेन्डरों) को उनकी हार्दिक सहायता तथा अनवरत सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

स्थान: राँची

दिनांक: 12.08.2025



(मनोज कुमार)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

सीएमपीडीआई लिमिटेड प्रदर्शन: एक अवलोकन

आकड़े करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	2024-25 (अंकेक्षित)	2023-24 (अंकेक्षित)	2022-23 (अंकेक्षित)
विवरण			
सेवाओं की बिक्री (निबल बिक्री)	2102.76	1732.69	1386.09
अन्य आय	74.77	37.49	12.69
कुल आय	2177.53	1770.18	1398.78
कुल खर्च	1295.39	1037.34	1031.83
पी बी टी	882.14	732.84	366.95
पी ए टी	666.91	503.23	296.66
कुल ब्लॉक	246.95	246.75	243.8
चालू परिसम्पत्तियां	2400.6	1889.96	1598.5
चालू देयताएं	553.48	477.5	599.21
कार्यशील पूंजी	1847.12	1412.46	999.29
नियोजित पूंजी*	2048.97	1595.48	1214.17
इक्विटी पूंजी	142.8	142.8	142.8
भंडार और अधिशेष	1899.05	1448.81	1074.85
नेट वर्थ **	2041.85	1591.61	1217.65
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	40.36	43.93	29.61
ईपीएस***	4670.24	3524.02	2077.45

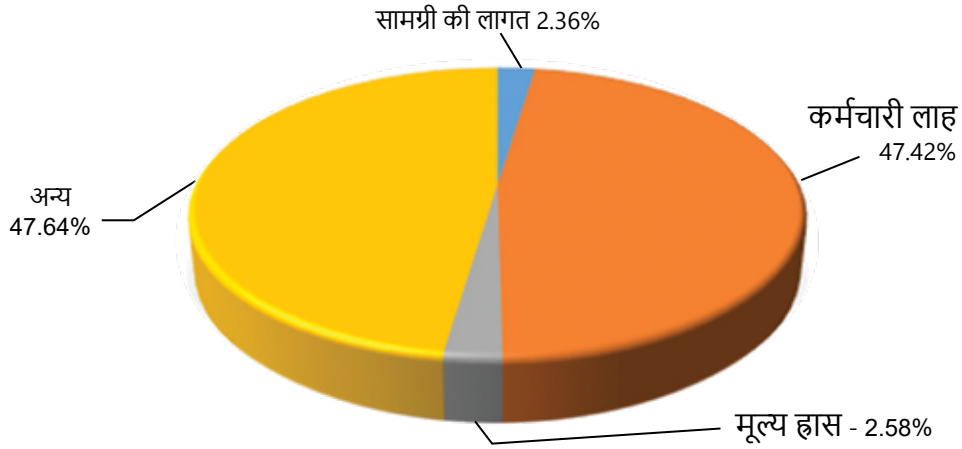
* नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता

** निवल मूल्य = इक्विटी शेयर पूंजी + रिजर्व और पूंजी रिजर्व को छोड़कर अधिशेष

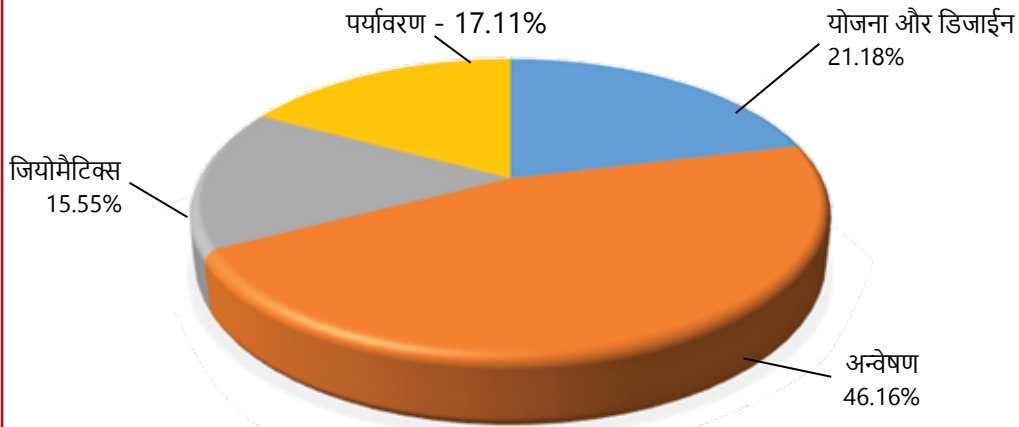
*** प्रति शेयर आय कुल बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या 1428000 पर आधारित है

सीएमपीडीआईएल का वित्तीय अवलोकन

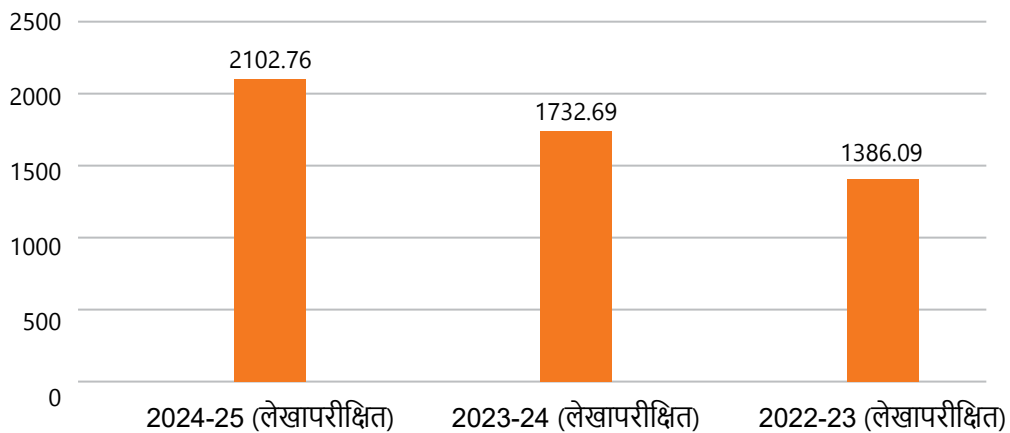
व्यय विवरण वित्त वर्ष (2024-25)



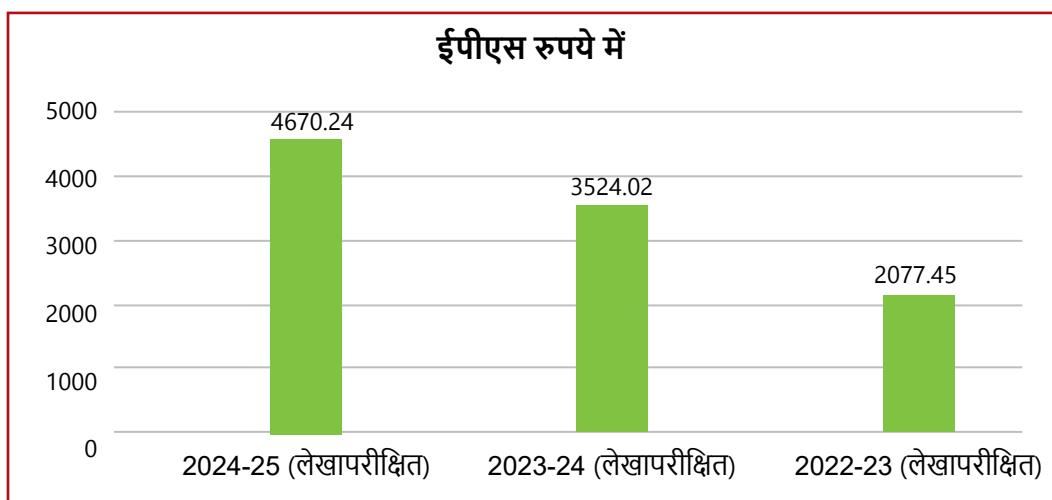
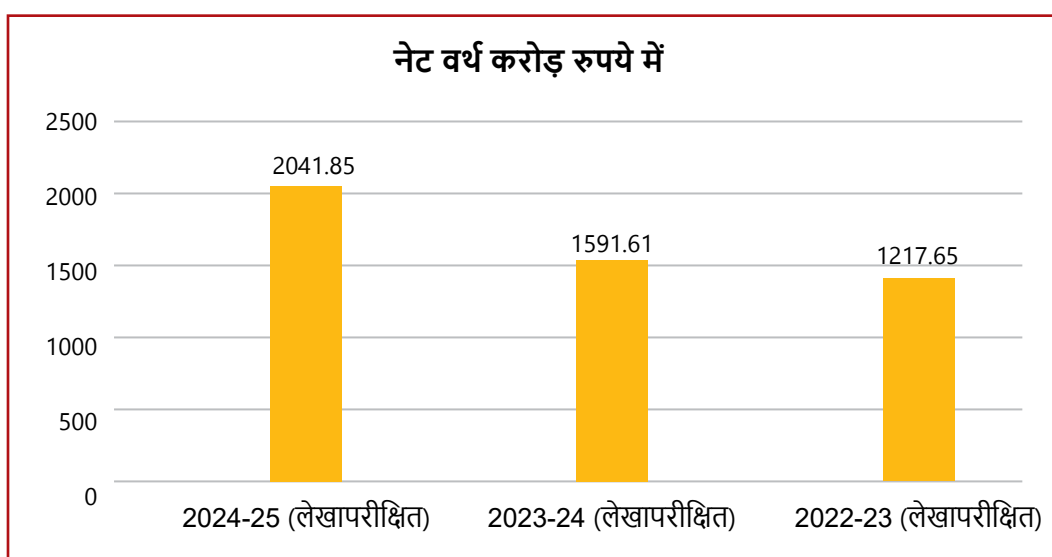
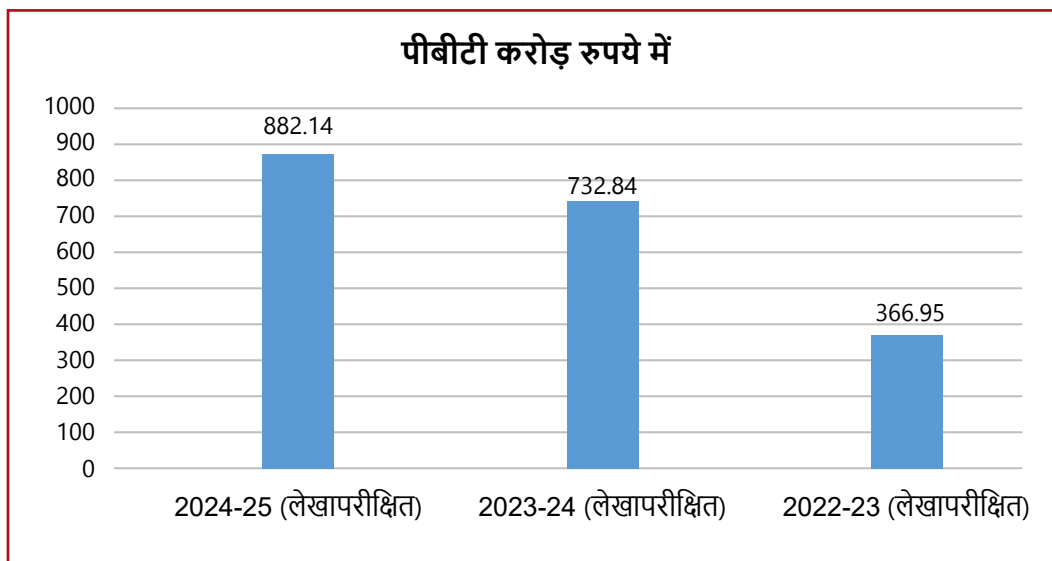
बिक्री ब्यौरा वित्त वर्ष (2024-25)



सेवाओं की बिक्री (शुद्ध बिक्री) करोड़ रुपये में



सीएमपीडीआईएल का वित्तीय अवलोकन



निदेशक-मंडल का प्रतिवेदन

सेवा में,

अंशधारक

मुझे निदेशक-मंडल की ओर से 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिसाब-किताब तथा उस पर सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित आपकी कंपनी के क्रिया-कलाप पर आधारित 50 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

भाग-क

1.0 निगमित पर्यवलोकन:

आपकी मिनी रत्न (कैट-1) कंपनी ने गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची स्थित अपने मुख्यालय तथा आसनसोल, धनबाद, राँची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली तथा भुवनेश्वर स्थित सातों क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कार्य जारी रखी। सातों क्षेत्रीय संस्थानों को क्षेत्रीय संस्थान-1 से क्षेत्रीय संस्थान-7 तक का नाम दिया गया जो कोल इंडिया लिमिटेड की 7 संगत अनुषंगी कोयला उत्पादक कंपनियों जैसे ईसीएल (क्षे.सं.-1), बीसीसीएल (क्षे.सं.-2), सीसीएल (क्षे.सं.-3), डब्ल्यूसीएल (क्षे.सं.-4), एसईसीएल (क्षे.सं.-5), एनसीएल (क्षे.सं.-6) तथा एमसीएल (क्षे.सं.-7) को अपनी समर्पित सेवाएँ देती रही हैं।

सीआईएल, मुख्यालय, एनईसी तथा गैर सीआईएल ग्राहकों जैसे एनटीपीसी लिमिटेड, ओडीसी कोल एंड पावर लिमिटेड (ओसीपीएल), गुजरात इन्डस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (जीआईपीसीएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड, अल्ट्राटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आदि को परामर्श सेवाएँ मुख्यतः सीएमपीडीआईएल मुख्यालय के द्वारा दी गई। इन परामर्श सेवा के अलावा सीएमपीडीआईएल ने कोयला मंत्रालय की विशेषज्ञता वाला कार्य का भी संचालन किया है।

वित्त वर्ष 2024-25 में सीएमपीडीआईएल ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से परे अपने परामर्श पदचिह्न का विस्तार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो निष्पादित परियोजनाओं की संख्या और दिए गए अनुबंधों के कुल मूल्य दोनों में मजबूत वृद्धि प्रदर्शित करता है। यह प्रगति सीएमपीडीआई

के विविधीकरण की ओर रणनीतिक बदलाव और विभिन्न क्षेत्रों में बाहरी ग्राहकों के साथ बढ़ती हुई सहभागिता को दर्शाती है। आउटरीच बढ़ाने, अनुकूलित समाधान और गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण पर जोर देने के परिणामस्वरूप कंपनी के सक्रिय प्रयासों ने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिया और एक विश्वसनीय परामर्श भागीदार के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वित्त वर्ष 2024-25 में प्रमुख उपलब्धियाँ और पहल इस प्रकार हैं:

- **सेवाओं का विविधीकरण:** सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल से परे अपनी परामर्श सेवाओं में विविधता लाना जारी रखा है, जिसका लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, सरकारी संस्थाओं (केंद्र और राज्य दोनों) और निजी एजेंसियों को लक्षित करना है। पिछले सात वित्तीय वर्षों में, सीएमपीडीआईएल ने मात्रा और मूल्य दोनों के लिहाज से कार्यों का सबसे बड़ा हिस्सा हासिल किया है।
- **ऑफर और कार्यों में वृद्धि:** सीएमपीडीआईएल ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ग्राहकों को ₹252.32 करोड़ मूल्य के 213 ऑफर भेजे, जो साल-दर-साल (वाईओवाई) 50.57% की वृद्धि को दर्शाता है। कंपनी ने सीआईएल के बाहर से ₹144.44 करोड़ मूल्य के 151 कंसल्टेंसी कार्य हासिल किए, जो वाईओवाई में 42.84% की वृद्धि को दर्शाता है।
- **सफल कार्य समापन:** सीएमपीडीआईएल ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बाहरी बिक्री के कुल ₹58.32 करोड़ मूल्य के 121 कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए। कुछ प्रमुख ग्राहक एनटीपीसी, अडानी, राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट, टीएचडीसी, टीपीजीसीएल, नाल्को, डब्ल्यूबीपीडीसीएल, वेदांता लिमिटेड, मेघालय के निजी खनिक, रूंगटा संस, एनएलसी, ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी, एपीएमडीसी आदि थे।
- **ग्राहक आधार का विस्तार:** सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल के बाहर अपने ग्राहक आधार का काफी विस्तार किया है, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 30 से अधिक नए ग्राहक जोड़े हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएमपीडीआईएल ने नाल्को,

टीएचडीसी, एनएलसी आदि जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के साथ नए असाइनमेंट के लिए रणनीतिक समझौते किए हैं। कोयला परीक्षण के क्षेत्र में सिम्फर के साथ एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ है, जिससे हमारी क्षमता में वृद्धि होगी और ऐसे अन्य रणनीतिक समझौता ज्ञापन पाइपलाइन में हैं, जिनमें हमारे व्यापार मॉडल और सेवाओं को समृद्ध करने की क्षमता है। इन सहयोगों का उद्देश्य तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाना और टिकाऊ खनन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। सेवा डोमेन में विविधता लाने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अतिरिक्त तकनीकी साझेदारियाँ पाइपलाइन में हैं।

विभिन्न सेमिनारों, प्रदर्शनियों और प्रौद्योगिकी एक्सपो में भागीदारी बढ़ाकर सीआईएल के बाहर हमारी दृश्यता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। सीएमपीडीआईएल ने ग्राहकों के साथ एक-एक करके बैठकों के माध्यम से व्यवसाय विकास के लिए अपने प्रयास भी बढ़ाए हैं। यह विस्तार सीआईएल के बाहर परामर्श क्षेत्र में सीएमपीडीआई की बढ़ती प्रमुखता को उजागर करता है, जिसमें व्यवसाय की मात्रा और ग्राहक विविधता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

1.1 प्रदत्त प्रमुख सेवाएँ:

• भू-वैज्ञानिक गवेषण एवं ड्रिलिंग:

विश्वसनीय भू-वैज्ञानिक तथा भू-अभियंत्रण आँकड़ा तैयार करने तथा खनन परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्व-स्थाने कोयला भंडार के मूल्यांकन के उद्देश्य से क्षेत्रीय तौर पर गवेषित ब्लॉकों का विस्तृत भू-वैज्ञानिक गवेषण, मल्टी प्रोब भू-भौतिक लागिंग के जरिए भू-भौतिक सर्वेक्षण, हाई रिजोल्यूशन शैलो सीममिक सर्वेक्षण, जल भू-वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कोल बेड मिथेन संसाधनों की पहचान।

• परियोजना आयोजन एवं डिजाइन:

भूमिगत और खुली खदानों, कोयला क्षेत्रों, कोयला और खनिज लाभकारीकरण और उपयोग संयंत्रों, कोयला हैंडलिंग संयंत्रों, कार्यशालाओं और अन्य सहायक इकाइयों और बुनियादी ढांचे सुविधाओं के मास्टर प्लान के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत

परियोजना रिपोर्ट और विस्तृत इंजीनियरिंग चित्र तैयार करना, जिसमें निवेश निर्णयों के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजना रिपोर्टों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन शामिल है।

• अभियान्तिकी सेवाएँ:

खानों, परिष्करण तथा यूटिलाइजेशन प्लांट्स, कोल हैंडलिंग प्लांट्स, विदूत आपूर्ति प्रणाली, वर्कशॉप एवं अन्य इकाइयाँ, वास्तुशिल्पीय प्लानिंग एवं डिजाइन के लिए सिस्टम और सब-सिस्टम का विस्तृत डिजाइन

• अनुसंधान एवं विकास:

कोल इंडिया की आरएंडडी द्वारा निधित आरएंडडी योजना और कोयला मंत्रालय द्वारा निधित सभी एसएंडडी योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सेवा दे रहा है। सीएमपीडीआईएल, अपने बल पर परिष्करण, खनन, यूटिलाइजेशन, पर्यावरण गवेषण आदि के क्षेत्र में एप्लायड रिसर्च और विकास का कार्य भी शुरू किया है।

• प्रयोगशाला सेवाएँ:

पूरी तरह आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला खान की गैसों की गुणवत्ता का पूर्ण विश्लेषण, वायु, ध्वनि, कोयला कोर नमूनों, कोयले की धोवन क्षमता गुण-निर्धारण, संस्तर का भौतिक यांत्रिक शक्ति, पेट्रोग्राफी अध्ययन, गैर विध्वंसक परीक्षण आदि सेवाएँ दे रही है।

• पर्यावरणिक सेवाएँ:

पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी, क्षेत्रीय संस्थानों एवं मुख्यालयों के जरिए इसका कार्यान्वयन, घरेलू सीपीसीबी अनुमोदित प्रयोगशालाओं में वायु, जल, ध्वनि नमूनों का विश्लेषण, खान बंदी योजना बनाना तथा खान बंदी की मॉनिटरिंग करना, ओबी एवं हाई वाल का ढाल स्थायित्व अध्ययन, खानों की पर्यावरणिक वहन (कैरिंग) क्षमता तथा नदी तटीय इकोसिस्टम का अध्ययन, पूरे सीआईएल की खानों के लिए भू-उपयोग मॉनिटरिंग हेतु सुदूर संवेदी उपग्रह डाटा का प्रयोग, आदि।

- सूचना प्रौद्योगिकी
- मानव संसाधन विकास
- विशेषीकृत सेवाएँ

- ❖ रिमोट सेंसिंग सहित जियोमेटिक्स
- ❖ खानों में संवातन (वेंटिलेशन) एवं गैस सर्वेक्षण
- ❖ नियंत्रित विस्फोटन
- ❖ नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
- ❖ खनन इलेक्ट्रानिक्स
- ❖ खान की क्षमता का मूल्यांकन
- ❖ खान समर्थन डिजाइन, रॉक मास रेटिंग (आरएमआर)
- ❖ गैर विनाशकारी परीक्षण
- ❖ प्रबंधन प्रणाली परामर्श
- ❖ कोयला एवं ओबीआर की माप

1.2 वित्तीय कार्य परिणाम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने कर पश्चात 666.91 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया। कंपनी के वित्तीय परिणाम नीचे दिये गये हैं:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त होने वाला वर्ष	31.03.2024 को समाप्त होने वाला वर्ष
कुल बिक्री	2102.76	1732.69
अन्य कमाई	74.77	37.49
कुल खर्च	1295.39	1037.34
कर देने से पूर्व लाभ	882.14	732.84
कर व्यय	215.23	229.61
कर पश्चात लाभ (ए)	666.91	503.23
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)*	(20.83)	(13.73)
आयकर जिसे लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा	(5.24)	(3.46)
कुल अन्य व्यापक आय (बी)	(15.59)	(10.27)
कुल व्यापक आय (ए)+(बी)	651.32	492.96

1.3 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) का प्रबंधन कंपनी के प्रदर्शन और दृष्टिकोण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों को कवर करते हुए अपनी चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

1.3.1 सीएमपीडीआईएल के प्रमुख उद्देश्य :

1. भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, जल विज्ञान और पर्यावरण संबंधी डेटा सृजन सहित कोयला और खनिज अन्वेषण में परामर्श सहायता प्रदान करना।
2. इष्टतम खनन योजना के लिए भूवैज्ञानिक मूल्यांकन के उच्च स्तर का विश्वास प्रदान करते हुए अन्वेषण और व्यवहार्यता रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार करना।
3. संसाधनों की उत्पादकता में सुधार करके आंतरिक संसाधनों के उत्पादन को अनुकूलित करना, अपव्यय को रोकना और निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त बाह्य संसाधन जुटाना।
4. कोयला खदानों, कोयला लाभकारीकरण और उपयोग संयंत्रों आदि के लिए परियोजना नियोजन और डिजाइनिंग।
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के अंतर्गत कोयला क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना, समन्वय करना और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करना।
6. कोयला खनन और संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी), पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और खदान बंद करने की योजना तैयार करना।
7. भूमि सुधार निगरानी, पर्यावरण डेटा सृजन, वनस्पति आवरण मानचित्रण, कोयला खदान अग्नि मानचित्रण, कोयला क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर स्थलाकृतिक मानचित्रण, टीपीएस और वाशरी स्थानों के चयन सहित बुनियादी ढांचे की योजना आदि के लिए रिमोट सेंसिंग सेवाओं का विस्तार करना।

8. सीआईएल की सहायक कोयला उत्पादक कंपनियों को क्षेत्र और प्रयोगशाला सेवाएं प्रदान करना।
9. सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के अलावा बाहरी संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

1.3.2 सीएमपीडीआईएल के कार्यों का संक्षिप्त विवरण:

सीएमपीडीआईएल के सभी कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

क. भूवैज्ञानिक गवेषण और सहायता सेवाएँ - सीएमपीडीआईएल का यह मुख्य कार्य अपनी स्थापना के बाद से खनिज भंडारों के लिए निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करता है:

- गवेषण की योजना और कार्यान्वयन;
- निवेश और दोहन निर्णयों के लिए संसाधन मूल्यांकन और दस्तावेज़ीकरण; तथा
- कोयला और गैर कोयला नमूनों के लिए संबंधित क्षेत्र परीक्षण और प्रयोगशाला सहायता।

ख. योजना, डिजाइन और सहायता सेवाएँ - स्थापना के बाद से सीएमपीडीआईएल का एक अन्य मुख्य कार्य होने के नाते, खनन, लाभकारीकरण, उपयोग और अन्य बुनियादी ढांचे और इंजीनियरिंग परियोजनाओं के निर्माण और संचालन के लिए निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

- संकल्पनात्मक/पूर्व-व्यवहार्यता/व्यवहार्यता अध्ययन, परियोजना रिपोर्ट, और बुनियादी और विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइनों का निर्माण और/या मूल्यांकन;
- इंजीनियरिंग एवं अन्य संबंधित परामर्श सहायता; तथा
- कोयला और गैर कोयला नमूनों के लिए संबंधित क्षेत्र परीक्षण और प्रयोगशाला सहायता।

ग. पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं - 1992 से प्रस्तावित, ये सेवाएं खनन और खनिज उद्योग को उनकी

योजना और संचालन के दौरान पर्यावरण प्रबंधन के लिए सर्वांगीण सहायता प्रदान करती हैं, जिसमें खदान बंद करने की योजना, प्रयोगशाला और परीक्षण सहायता, नदी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन, मृदा और नमी संरक्षण अध्ययन आदि शामिल हैं।

घ. जियोमैटिक्स सेवाएँ - 2001 से प्रस्तावित, निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं:

- खनन पट्टे और वन सीमा के लिए विभेदक जीपीएस सर्वेक्षण, ओबीआर/कोयला जांच माप, यूजी खानों का सहसंबंध सर्वेक्षण, आदि।
- कोयला खदान अग्नि मानचित्रण, खुली खदानों के भूमि पुनर्ग्रहण निगरानी, कोयला क्षेत्रों के भूमि उपयोग/वनस्पति आवरण मानचित्रण आदि सहित सुदूर संवेदन अध्ययन।
- स्थलाकृतिक सर्वेक्षण,
- उपग्रह डेटा और जीआई के आधार पर थर्मल पावर स्टेशनों का स्थल चयन
- ड्रोन आधारित सर्वेक्षण और मानचित्रण सेवाएँ

ड. मानव संसाधन विकास - 1976 से प्रस्तावित, इसमें बाजार के ग्राहकों, विशेष रूप से खनिज और खनन क्षेत्र में तकनीकी, प्रबंधकीय और प्रबंधन-प्रणाली से संबंधित प्रशिक्षण शामिल है।

च. प्रबंधन प्रणाली सेवाएँ - 1997 से प्रस्तावित, ये सेवाएँ विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों, जैसे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएस 18001, एसए 8000, आईएसओ 50001, आईएसओ 27001 और आईएसओ 37001 के निर्माण, दस्तावेज़ीकरण, कार्यान्वयन और प्रशिक्षण के लिए परामर्श और समर्थन की पूरी श्रृंखला को कवर करती हैं। सीएमपीडीआईएल को, इसके सभी क्षेत्रीय संस्थानों के साथ, नए संशोधित आईएसओ 9001:2015 मानक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस दिया गया है।

छ. विशिष्ट सेवाएं - खानों में वेंटिलेशन और गैस

सर्वेक्षण, नियंत्रित ब्लास्टिंग, नए विस्फोटकों का प्रदर्शन मूल्यांकन, खनन इलेक्ट्रॉनिक्स, खान क्षमता मूल्यांकन, चट्टान और कोयले के भौतिक यांत्रिक गुण (पीएमपी) परीक्षण, खान समर्थन डिजाइन, रॉक मास रेटिंग (आरएमआर), स्ट्रेटा नियंत्रण और निगरानी योजना (एससीएएमपी) अध्ययन, गैर-विनाशकारी परीक्षण, सीआईएल और एमओसी के लिए ऐप्स और पोर्टलों का विकास आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञ परामर्श सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।

1.3.3 उद्योग संरचना और विकास

वैश्विक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, चल रहे संघर्ष और व्यापार नीति जोखिम वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते रहते हैं। फिर भी, वैश्विक आर्थिक वृद्धि काफी हद तक मध्यम बनी हुई है।

2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2024 और 2025 के लिए क्रमशः 3.2 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। अगले पाँच वर्षों में, वैश्विक वृद्धि औसतन 3.2 प्रतिशत के आसपास रहने की उम्मीद है, जो ऐतिहासिक मानकों के हिसाब से मामूली है। जबकि समग्र वैश्विक दृष्टिकोण स्थिर बना हुआ है, विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि अलग-अलग है।

भारतीय अर्थव्यवस्था और वास्तविक जीडीपी स्थिर विकास पथ पर अग्रसर है। वित्त वर्ष 25 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। चूंकि देश आने वाले वर्षों में अपनी आर्थिक वृद्धि दर में तेजी लाने का लक्ष्य रखता है, इसलिए घरेलू कॉर्पोरेट और वित्तीय क्षेत्रों में मजबूत बैलेंस शीट की वजह से उसे मदद मिल रही है। लेकिन, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पलायन का रुझान देखा जा रहा है। इसलिए, अगले दो दशकों में वृद्धि दर के औसत को बढ़ाने के लिए विनियमन प्रोत्साहन के माध्यम से जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करना होगा। आगे की ओर देखते हुए, वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की आर्थिक संभावनाएं संतुलित हैं। विकास के लिए

बाधाओं में भू-राजनीतिक और व्यापार अनिश्चितताएं और संभावित कमोडिटी मूल्य में उतार-चढ़ाव शामिल हैं।

भारत में खनन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कोयला खनन और बिजली उत्पादन आठ प्रमुख उद्योगों में से दो हैं और साथ मिलकर भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में लगभग 12% का योगदान देते हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए उनके महत्व की पुष्टि करता है। इसके अलावा, भारत का लॉजिस्टिक्स उद्योग, स्पंज आयरन उद्योग, एल्युमीनियम उद्योग और कई अन्य उद्योग भारत के घरेलू कोयला उद्योग पर निर्भर हैं। कोयला खनन अक्सर स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, नौकरियों के सृजन के माध्यम से, स्थानीय बुनियादी ढाँचे में सुधार - जैसे सड़क नेटवर्क और पानी की आपूर्ति, और स्थानीय आबादी को स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान करने की अनुमति देकर प्रोत्साहन देता है। भारत का कोयला क्षेत्र देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण रोजगार वृद्धि को भी बढ़ावा देता है। कोयला क्षेत्र की सफलता का श्रेय कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), निजी खिलाड़ियों और 350 से अधिक कोयला खदानों में लगभग 5 लाख खदान श्रमिकों के अथक प्रयासों को दिया जाता है। इसलिए, भारत के लिए कोयला क्षेत्र का महत्व, न केवल देश के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में, बल्कि इसके द्वारा निभाई जाने वाली सामाजिक-आर्थिक भूमिका के रूप में भी, नकारा नहीं जा सकता।

भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया भर में इसका कोयला भंडार 5वां सबसे बड़ा है। भारत के कोयला उत्पादन अनुमान आने वाले वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान घरेलू कोयला उत्पादन 1047.68 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया। 781.07 मिलियन टन के उत्पादन के साथ सीआईएल का इसमें प्रमुख योगदान रहा, जिसके 2027-28 तक जल्द से जल्द 1000

मिलियन टन के स्तर तक बढ़ने की उम्मीद है। पिछले पांच वर्षों के दौरान घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, देश बढ़ती कोयले की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर हो रहा है। कोयले की मांग 2030-2040 के दशक में चरम पर पहुंचने का अनुमान है, जबकि उत्पादन संभावित रूप से 2035 के आसपास चरम पर होगा और राष्ट्रीय कोयला उत्पादन 1.50 बिलियन टन के स्तर पर पहुंच जाएगा।

कम से कम अगले एक या दो दशक तक भारत में बिजली उत्पादन में कोयला सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना रहेगा। हालांकि गैर-नवीकरणीय क्षेत्र के लिए निवेश बढ़ रहा है, लेकिन कोयले के लिए योगदान की आवश्यकता अभी भी निरपेक्ष रूप से अधिक है। बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य ने भी हर देश को उन संसाधनों पर निर्भरता के बजाय यथासंभव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है जो उनके पास नहीं हैं। कोयले पर भारत की निर्भरता महत्वपूर्ण बनी हुई है क्योंकि यह राष्ट्रीय ऊर्जा मिश्रण में 55% का योगदान देता है और कुल बिजली उत्पादन का 74% से अधिक ईंधन प्रदान करता है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सीओपी 26 में दी गई पंचामृत प्रतिबद्धता में यह बात शामिल है कि कोयला क्षेत्र पर कोयले के वैकल्पिक उपयोगों की तलाश करने का दबाव होगा क्योंकि ताप विद्युत क्षेत्र पर जोर कम हो सकता है। सीएमपीडीआईएल इस संबंध में कोयले के वैकल्पिक उपयोग को विकसित करने, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करने और कोयला कंपनियों को उनके व्यवसायों में विविधता लाने के लिए परामर्श प्रदान करने के अवसरों की तलाश कर सकता है ताकि वे भविष्य के लिए तैयार हो सकें।

सरकार ने महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें 2030 तक देश की स्थापित ऊर्जा क्षमता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से विकसित करना शामिल है। यद्यपि नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत के ऊर्जा मिश्रण में कोयले का उचित हिस्सा बना रहेगा और सीएमपीडीआई को

वैकल्पिक टिकाऊ कोयला उपयोग, कम कार्बन और टिकाऊ कोयला खनन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करनी होगी।

गोंडवाना कोलफील्ड्स (43) और तृतीयक कोलफील्ड्स (19) का कुल अनुमानित बेसिन क्षेत्र लगभग 67032 वर्ग किलोमीटर आंका गया है, जबकि 01.04.2023 तक देश का कुल अनुमानित कोयला क्षेत्र लगभग 32902 वर्ग किलोमीटर था। कुल अनुमानित कोयला क्षेत्र में से, मापा गया कुल क्षेत्रीय अन्वेषण लगभग 20448 वर्ग किलोमीटर था और लगभग 12454 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए छोड़ दिया गया है। तृतीयक कोलफील्ड्स का कुल बेसिन क्षेत्र लगभग 1352 वर्ग किलोमीटर आंका गया था, जिसमें से कुल लगभग 834 वर्ग किलोमीटर को अनुमानित कोयला क्षेत्र माना गया था।

सरकार के निर्देशानुसार, सीएमपीडीआईएल पूरे देश में 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षणों पर विशेष ध्यान देते हुए क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण गतिविधियाँ कर रहा है। इसका उद्देश्य त्वरित कोयला दोहन के लिए सबसे आशाजनक कोयला-असर वाली संपत्तियों की पहचान करना और उनका चित्रण करना है। इस पहल का उद्देश्य संभावित बोलीदाताओं के लिए कोयला ब्लॉकों की उपलब्धता में तेजी लाना है, जिससे देश के कोयला संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके।

कोयला ब्लॉकों की पहचान एक सुपरिभाषित मानदंड के आधार पर नीलामी के लिए की जा रही है, ताकि तेजी से और सतत संसाधन विकास सुनिश्चित किया जा सके। खनन पट्टा (एमएल) जी1 स्तर पर खोजे गए ब्लॉकों के लिए प्रस्तावित है, जबकि प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस-सह-खनन पट्टा (पीएल-सह-एमएल) क्षेत्रीय रूप से खोजे गए ब्लॉकों (जी2 और जी3 स्तर) के लिए माना जाता है। पर्यावरण संबंधी विचार जैसे कि इको-सेंसिटिव ज़ोन (ईएसजेड) के साथ ओवरलैप, वन क्षेत्र, महत्वपूर्ण सतही बाधाएँ जैसे कि आवास, बुनियादी ढाँचा और अन्य प्रतिबंध नीलामी में डालने से पहले ध्यान में रखे जाते हैं, ताकि सफल बोलीदाताओं के लिए सुचारू परिचालन तत्परता सुनिश्चित हो सके।

वर्ष 2025-26 के लिए 11.0 लाख मीटर ड्रिलिंग का

लक्ष्य तथा 450 लाइन किमी के 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के माध्यम से डाटा अधिग्रहण का प्रस्ताव किया गया है, जिसका उद्देश्य कम बोरहोल घनत्व के साथ भौतिक ड्रिलिंग के साथ अन्वेषण में 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण पर जोर देना है।

सीआईएल के 1 बीटी कोयला उत्पादन लक्ष्य के लिए अन्वेषण और नियोजन अभ्यास पूरा हो चुका है, लेकिन भविष्य में उत्पादन को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए सीआईएल को सीएमपीडीआई से निरंतर आधार पर तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी। यह सीएचपी, वाशरी आदि सहित बुनियादी ढांचा सुविधाओं के लिए भी सही होगा। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के अन्य कोयला उत्पादकों द्वारा भी सीएमपीडीआईएल की विशेषज्ञ सेवाएं मांगी जाती हैं। सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल के अलावा एनटीपीसी, जीएमडीसी, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, एनटीपीसी, एससीसीएल, जीएमपीएल, टाटा स्टील, जेपीएल, टीएचडीसी, यूसीआईएल, एनएलसीआईएल, डब्ल्यूबीपीडीसीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, आईएमपीपीएल, एमपी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, आईसीवीएल और विभिन्न वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक मालिकों जैसी अन्य कंपनियों के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं।

कोयला आधारित वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों जैसे कोल बेड मीथेन (सीबीएम), भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) के विकास के लिए सीएमपीडीआई की पहल नए व्यावसायिक अवसर प्रदान कर सकती है। सीएमपीडीआई 10 वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से प्रमोशनल/क्षेत्रीय/विस्तृत अन्वेषण के तहत सीबीएम और शेल गैस विशिष्ट डेटा तैयार कर रहा है और कोयला मंत्रालय के लिए सीबीएम डेटा बैंक बना रहा है।

सीएमपीडीआई सीबीएम विकास से संबंधित परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है, जिसमें सीबीएम विशिष्ट डेटा उत्पादन, कोयला अभिलक्षण अध्ययन, गैस प्रारंभिक रूप से स्थान पर (जीआईआईपी) मूल्यांकन, जलाशय सिमुलेशन और व्यवहार्यता अध्ययन शामिल हैं।

सीएमपीडीआईएल, सीआईएल क्षेत्रों अर्थात् ईसीएल,

बीसीसीएल और एसईसीएल में सीबीएम परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में कार्य करता है। बीसीसीएल लीजहोल्ड क्षेत्र के अंतर्गत झरिया सीबीएम ब्लॉक-1 वर्तमान में अन्वेषण चरण में है।

कोयला गैसीकरण सीएमपीडीआईएल के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। सीएमपीडीआईएल मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी ईसीएल और उप-कार्यान्वयन एजेंसी एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजीज इंक (ईईटीआई), कनाडा के साथ संयुक्त रूप से भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए एक अनुसंधान एवं विकास पायलट परियोजना को लागू कर रहा है। अनुसंधान एवं विकास पायलट परियोजना के परिणाम कोयला संसाधनों के उपयोग के लिए स्वच्छ मार्ग प्रदान कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, कोयला क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उभरता हुआ क्षेत्र भी सीएमपीडीआईएल के लिए अतिरिक्त अवसर प्रस्तुत कर रहा है, जो आने वाले वर्षों में और बढ़ेगा। इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल ने यह सुनिश्चित करने के लिए पहल की है कि उसके प्रयास शीर्ष और निचले स्तर पर सराहनीय रूप से परिलक्षित हों, और तदनुसार, हाल के दिनों में बिक्री और पीबीटी में काफी वृद्धि हुई है।

यद्यपि यह आशा की जाती है कि भारत में कोयला ईंधन अपनी प्रधानता बनाए रखेगा तथा कम से कम निकट भविष्य में स्थानीय आबादी के लिए किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने के लिए एकमात्र यथार्थवादी विकल्प बना रहेगा, तथापि सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का बड़े पैमाने पर दोहन करने की प्रतिबद्धता, समानांतर रूप से, कोयला क्षेत्र के भविष्य के विकास को प्रभावित करेगी। यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी26) के 26 वें सत्र में भारत ने भारत की जलवायु कार्रवाई के पांच अमृत तत्व (पंचामृत) प्रस्तुत किए, अर्थात् (i) 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता तक

पहुँचना, (ii) 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना, (iii) अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी, (iv) 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत की कमी, और (v) 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना। इसके अलावा, अद्यतन एनडीसी प्रतिबद्धता 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन CO₂ समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का वादा करती है कोयला खनन के लिए मंजूरी, ग्रीन लॉबिस्टों का दबाव और भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक प्रयास दिन-प्रतिदिन कठिन होते जा रहे हैं। सीएमपीडीआईएल को कोयला क्षेत्र के लिए कम कार्बन, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य और सामाजिक रूप से समावेशी खदान नियोजन के लिए कोयला कंपनियों को तकनीकी सहायता प्रदान करनी होगी।

सीएमपीडीआईएल के लिए अन्वेषण राजस्व का एक प्रमुख स्रोत रहा है। निरंतर विकास सुनिश्चित करने और भविष्य की आय बढ़ाने के लिए, सीएमपीडीआई सक्रिय रूप से एक विविधीकरण रणनीति पर काम कर रहा है जो कोयले से आगे तक फैली हुई है। इस दृष्टिकोण में हमारी अन्वेषण गतिविधियों को गैर-कोयला क्षेत्रों में विस्तारित करना शामिल है, साथ ही हमारी सेवा पेशकशों की सीमा को भी व्यापक बनाना शामिल है - सबसे खास बात, 2डी भूकंपीय सर्वेक्षणों का इन-हाउस निष्पादन। इन पहलों का उद्देश्य हमारी शीर्ष और निचली दोनों लाइनों को मजबूत करना है। इस रणनीतिक बदलाव के हिस्से के रूप में, और एनएमईटी फंडिंग के समर्थन से, सीएमपीडीआई ने तीन स्वीकृत बॉक्साइट अन्वेषण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके अलावा, बेस मेटल एक्सप्लोरेशन (तांबा, सीसा और जस्ता) पर केंद्रित एक परियोजना पूरी हो गई है। दो और अन्वेषण परियोजनाएं, एक बेस मेटल के लिए और दूसरी मैंग्रेटाइट के लिए, वर्तमान में प्रगति पर हैं। इसके अलावा, एनएमईटी फंडिंग के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए डीजीओ, उड़ीसा द्वारा ग्रेफाइट के अन्वेषण के लिए 2 ब्लॉक भी दिए गए हैं।

इसके अलावा, योजना और डिजाइन, जियोमैटिक्स और पर्यावरण सेवाओं आदि जैसी अन्य सेवाओं से राजस्व बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। ये सेवाएँ महत्वपूर्ण विकास के अवसर प्रस्तुत करती हैं और हमें अपने ग्राहकों को व्यापक समाधान प्रदान करने की अनुमति देती हैं। इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल उभरते बाजार के रुझानों को भुनाने और अपने ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष हाइड्रोजियोलॉजिकल सेवाओं को सक्रिय रूप से प्राथमिकता दे रहा है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और सीएमपीडीआईएल के व्यवसाय क्षेत्र में गतिशीलता लाने के लिए, उत्पादकता में और सुधार के माध्यम से अन्वेषण क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करना यथार्थवादी होगा, विशेष रूप से, 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण और अन्य भू-भौतिकीय विधियों के व्यापक उपयोग, जहां भी आवश्यक हो, मौजूदा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का उन्नयन और आधुनिकीकरण, जनशक्ति उपयोग और कार्यकारी जनशक्ति प्रेरण को युक्तिसंगत बनाना, कोयले के अलावा खनिज, खनन और संबद्ध इंजीनियरिंग क्षेत्रों के नए क्षेत्रों में विविधीकरण, मूल्य के संदर्भ में बाहरी नौकरियों (गैर-सीआईएल) की मात्रा में वृद्धि, कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग के माध्यम से ड्रिलिंग और इन्वेंट्री नियंत्रण सहित कोर क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी प्रणाली की स्थापना, कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी की स्थापना आदि।

1.3.4 उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई रणनीति :

खनिज, खनन और संबद्ध क्षेत्रों में सीएमपीडीआईएल के ज्ञान और बाजार स्थान की गहराई के साथ, यह अपने कॉर्पोरेट उद्देश्यों को साकार करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों और व्यवसाय योजना को अपना रहा है:

- (i) (I) जहां तक संभव हो, भौतिक ड्रिलिंग के स्थान पर 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से अन्वेषण क्षमता को बढ़ाना आदि।
- (II) कोयला के अलावा खनिज, खनन और संबद्ध

- (III) राजस्व में बाहरी ग्राहकों के लिए बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि,
- (IV) देश के भीतर और बाहर, दोनों जगह रणनीतिक साझेदारों के साथ गठजोड़,
- (V) मौजूदा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का उन्नयन और आधुनिकीकरण,
- (VI) परिचालन दक्षता और कार्य गुणवत्ता में वृद्धि,
- (VII) कॉर्पोरेट संस्कृति और आंतरिक प्रणालियों में सुधार,
- (VIII) कोयला उद्योग के लिए निरंतर योजना और विशेषीकृत समर्थन सुनिश्चित करने के लिए श्रमशक्ति उपयोग और अधिकारियों के प्रेरण को युक्तिसंगत बनाना,
- (IX) बेहतर लागत नियंत्रण उपाय और निगरानी, और
- (X) कोयला आधारित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के विकास हेतु सेवाएं प्रदान करना।

1.3.5 सामर्थ्य और कमजोरी

सामर्थ्य

- सीएमपीडीआईएल एक बहु-विषयक संगठन है, शायद अपनी तरह का एक ऐसा संगठन है, जो खनन से पहले, खनन कार्य के दौरान और खनन कार्य के बाद की लगभग सभी सेवाएँ एक ही छत के नीचे प्रदान करता है।
- भारत में विस्तृत कोयला अन्वेषण पर प्रभुत्व। सीएमपीडीआईएल को भारतीय ग्राहकों के बीच सबसे पसंदीदा सलाहकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, साथ ही इसे सरकारी 'प्राथमिकताएँ' भी प्राप्त हैं।
- रणनीतिक रूप से स्थित क्षेत्रीय संस्थानों के साथ, यह कोयला मंत्रालय के साथ-साथ कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों को डोर-स्टेप सेवा प्रदान करने में सक्षम है। कोयला युक्त क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में सीएमपीडीआईएल की 'अखिल भारतीय' उपस्थिति है।

- सीएमपीडीआईएल को कोयला ब्लॉक, कोयला भंडार, कोयला गुणवत्ता आदि से संबंधित एक बड़े, प्रामाणिक डेटा-बेस का गौरव प्राप्त है, जो कोयला क्षेत्र में उपलब्ध विशाल संसाधनों के ज्ञान तक पहुँच प्रदान करता है।
- इसके पास बहु-विषयक कुशल श्रमशक्ति का एक बड़ा प्रतिभा बैंक है।
- एकीकृत कोयला अन्वेषण परियोजनाओं को क्रियान्वित करने, 85 एमटीवाई ओपनकास्ट खदान और 5 एमटीवाई भूमिगत खदान तक की व्यक्तिगत परियोजना क्षमता के साथ खनन परियोजना रिपोर्ट की योजना बनाने, बड़ी संख्या में अवसंरचना-सुविधाओं आदि का समृद्ध अनुभव है।
- इसके पास कोयला अन्वेषण के लिए सबसे बड़े बुनियादी ढांचे में से एक है, जिसका भौगोलिक विस्तार 8 राज्यों में है, प्रयोगशाला सुविधाएँ, बेसलाइन डेटा उत्पादन क्षमता आदि।

कमजोरी

- कंपनियों और कोयला मंत्रालय पर अत्यधिक निर्भरता।
- कुशल अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उच्च दर।
- धीमी गति से विविधीकरण अर्थात् मुख्यतः कोयला उद्योग तक सीमित।

1.3.6 अवसर और चुनौतियाँ

अवसर

- कोयले की मांग बढ़ने की संभावना है और 2030 के मध्य तक यह चरम पर पहुँच सकती है, जिससे सीएमपीडीआईएल की सेवाओं के लिए संभावनाएं पैदा होंगी।
- सरकार द्वारा सार्वजनिक एवं निजी दोनों कंपनियों को कोयला ब्लॉकों की नीलामी/आबंटन से सीआईएल के बाहर सीएमपीडीआईएल के लिए बाजार अवसर पैदा हुए हैं।
- कोयला क्षेत्र में आईटी के अनुप्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता

- गैर-कोयला क्षेत्र में विविधीकरण
- सीबीएम/सीएमएम/ यूसीजी/ अन्य गैर-परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के दोहन के क्षेत्र में सेवाओं का विस्तार।
- सीआईएल कोयले के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी विविधीकरण के प्रयास कर रही है। सक्रिय कदमों के माध्यम से पहचाने गए क्षेत्रों में अपने क्षितिज का विस्तार करने का अवसर मिलेगा।

चुनौतियाँ

- भारतीय कोयला क्षेत्र 100% एफडीआई के साथ उदारीकरण की ओर बढ़ रहा है। कोयला क्षेत्र को और अधिक खोलने से अन्य घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय परामर्श सेवा प्रदाताओं से बाजार में प्रतिस्पर्धा हो सकती है।
- पिछले कुछ वर्षों में, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास बढ़ने की संभावना है, जिससे यह सस्ता हो सकता है, जिससे कुछ हद तक सीएमपीडीआई के पारंपरिक व्यवसाय को खतरा पैदा हो सकता है।
- वन क्षेत्र में उत्खनन पर प्रतिबंध तथा कानून-व्यवस्था की समस्या के कारण ड्रिलिंग प्रभावित हो रही है। इन क्षेत्रों में परिचालन।
- एक प्रमुख मानव संसाधन संचालित कंपनी होने के नाते, वर्तमान उच्च आयु प्रोफ़ाइल भविष्य में हानिकारक साबित हो सकता है। विशेषज्ञ श्रमशक्ति कम होती जा रही है, क्योंकि इसके कई अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञ सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

1.3.7 मूल्य निर्धारण

परामर्श सेवाओं से राजस्व कोल इंडिया की सहायक कंपनी सीएमपीडीआईएल द्वारा सीमित: गवेषण, खान योजना/परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरण योजनाओं और अन्य इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए परामर्श सेवाओं से उत्पन्न राजस्व की पहचान विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के लिए अपनाए गए मूल्य निर्धारण फार्मूले पर आधारित है।

1.3.8 विपणन नीति

सीएमपीडीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मांगे जाने पर सभी संभावित क्षेत्रों में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, सीएमपीडीआईएल सीआईएल के बाहरी ग्राहकों से भी काम लेने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां भी ऐसे बाहरी परामर्श कार्य किए जा सकते हैं, महत्व और रणनीतिक मूल्यों पर उचित विचार किया जाता है।

1.3.9 दृष्टिकोण और तैयारी

सीएमपीडीआई ने पिछले कुछ वर्षों में ड्रिलिंग गतिविधियों और उत्पादकता में लगातार वृद्धि का रुख दिखाया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-2012) के दौरान, ड्रिलिंग 2007-08 में 2.09 लाख मीटर से बढ़कर 2011-12 में 4.98 लाख मीटर हो गई, जबकि विभागीय ड्रिलिंग उत्पादकता प्रति ड्रिल प्रति माह 374 मीटर से बढ़कर 416 मीटर हो गई।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-2017) में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिसमें 2016-17 तक 11.26 लाख मीटर तक ड्रिलिंग की गई और उत्पादकता बढ़कर 583 मीटर प्रति ड्रिल प्रति माह हो गई। यह क्षमता और दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित प्रयास को दर्शाता है।

2017-2025 की अवधि के दौरान, सीएमपीडीआई ने 2017-18 में 13.66 लाख मीटर की अपनी उच्चतम ड्रिलिंग आउटपुट हासिल की, जबकि विभागीय उत्पादकता में सुधार जारी रहा, जो 2024-25 में प्रति माह प्रति ड्रिल 635 मीटर के शिखर पर पहुंच गया। विभागीय ड्रिल का आधुनिकीकरण, नई उच्च क्षमता वाली मैकेनिकल और हाइड्रोस्टैटिक ड्रिल को शामिल करना, उच्च उत्पादकता के परिणामस्वरूप उच्च प्रदर्शन वाले बिट्स की शुरुआत, नवीनतम मड तकनीक को अपनाना, ड्रिलिंग सहायक उपकरण और जनशक्ति की प्रभावी व्यवस्था सीएमपीडीआईएल की ड्रिलिंग क्षमता को बढ़ाने की कुंजी रही है।

2022-23 के दौरान केवल 6.85 लाख मीटर की ड्रिलिंग की जा सकेगी, खास तौर पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत अन्वेषण के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा फंड

में कटौती के कारण। हालांकि, अक्टूबर 2022 में, EFC ने 15 वें वित्त आयोग चक्र यानी 2025-26 तक कोयला और लिग्नाइट में अन्वेषण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को जारी रखने की सिफारिश की। नतीजतन, सीएमपीडीआई 2023-24 में लगभग 26% की वृद्धि के साथ लगभग 8.62 लाख मीटर ड्रिलिंग और 2024-25 में लगभग 17% की वृद्धि के साथ लगभग 10.12 लाख मीटर ड्रिलिंग हासिल कर सकता है। कोयले में आगे अन्वेषण करने की तात्कालिकता को देखते हुए, केंद्रीय क्षेत्र योजना/एनएमईटी के तहत फंडिंग जारी रखने की आवश्यकता होगी।

21 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से लगभग 270 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए विस्तृत अन्वेषण के माध्यम से लगभग 7.5 बिलियन टन कोयला संसाधनों को मापित (प्रमाणित) श्रेणी में जोड़े जाने का अनुमान है। इसके अलावा, 9 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से लगभग 208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए क्षेत्रीय (प्रचार) अन्वेषण के माध्यम से लगभग 7.4 बिलियन टन नए कोयला संसाधनों (संकेतित और अनुमानित श्रेणियों में) को जोड़े जाने का अनुमान है। इसके अलावा, लगभग 166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए 1 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के माध्यम से संकेतित श्रेणी में अनुमानित 75 मिलियन टन लिग्नाइट संसाधनों को भी जोड़े जाने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2024-25 में, सीएमपीडीआई ने झारखंड राज्य में बॉक्साइट के लिए 1 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के माध्यम से विभिन्न ग्रेडों के लगभग 65 मिलियन टन शुद्ध इन-सीटू बॉक्साइट संसाधन और 19 मिलियन टन शुद्ध इन-सीटू एल्युमिनस लेटराइट संसाधन की स्थापना की है। ब्लॉक में टीआईओ₂ और वी₂ओ₅ की भी रिपोर्ट की गई है।

भारत सरकार ने अन्वेषण की गति को कम करने और लागत कम करने के लिए ड्रिलिंग के लिए बोरहोल की संख्या कम करने के साथ-साथ 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी की शुरूआत पर जोर दिया है। सीएमपीडीआईएल ने अन्वेषण की विभिन्न भूभौतिकीय सर्वेक्षण तकनीकों जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकियों का गहन उपयोग करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि ड्रिलिंग की समय लेने वाली प्रक्रिया पर

निर्भरता कम हो और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने में उनका उपयोग किया जा सके। इससे भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने में तेजी आएगी और ब्लॉकों के भूवैज्ञानिक मॉडल में बेहतर विश्वास पैदा होगा।

2024-25 में भूकंपीय सर्वेक्षण गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। सीएमपीडीआई ने 2024-25 में लगभग 438 लाइन किमी 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण किए, जिसके परिणामस्वरूप 87% की प्रभावशाली वृद्धि हुई, जिसमें विभागीय संसाधनों का उपयोग करके लगभग 300 लाइन किमी 2डी सर्वेक्षण शामिल थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% की वृद्धि दर्शाता है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 90 ग्राउंड वाटर मॉडलिंग (जीडब्ल्यूएम) रिपोर्ट, 88 व्यापक हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट, 26 ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट (हाइड्रोलॉजिकल भाग) और 26 अन्य रिपोर्ट सहित कुल 230 रिपोर्ट तैयार की गईं। विभागीय रूप से तैयार किए गए ग्राउंड वाटर मॉडलिंग (जीडब्ल्यूएम) रिपोर्टों की संख्या पिछले वर्ष की 10 रिपोर्टों से बढ़कर 2024-25 में 44 रिपोर्ट हो गई। इन-हाउस रिपोर्टिंग में इस पर्याप्त वृद्धि ने जीडब्ल्यूएम रिपोर्ट तैयार करने के लिए आउटसोर्सिंग पर निर्भरता को प्रभावी रूप से कम कर दिया है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 450 लाइन किमी के 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा अधिग्रहण के साथ-साथ 11.0 लाख मीटर ड्रिलिंग का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुल 33 परियोजना रिपोर्ट (पीआर) तैयार की गई हैं, जिनमें ओपनकास्ट परियोजनाओं के लिए 19 पीआर और भूमिगत परियोजनाओं के लिए 14 पीआर शामिल हैं। गैर-सीआईएल खदानों के लिए दो ओपनकास्ट पीआर तैयार की गई हैं, अर्थात् (i) मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड के लिए रोहने कोल ब्लॉक, उत्तरी करनपुरा कोलफील्ड्स (8 मीट्रिक टन) के लिए डीपीआर और (ii) मेसर्स एनएलसी इंडिया लिमिटेड के लिए उत्तरी धादू (पश्चिमी भाग) कोयला खदान, उत्तरी करनपुरा कोलफील्ड्स (4.5 मीट्रिक टन) के लिए डीपीआर।

गेवरा (एसईसीएल) की विस्तार परियोजना रिपोर्ट 70-85 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की है, जिससे यह भारत में नियोजित सबसे बड़ी कोयला खदान बन गई है। सीआईएल के लिए नियोजित अन्य मेगा परियोजनाओं में जयंत डिप-साइड एक्सपेंशन ओसी (38 मीट्रिक टन प्रति वर्ष), एनसीएल; बैतरणी ईस्ट ओसी (20 मीट्रिक टन प्रति वर्ष), एमसीएल; मदननगर ओसी एमडीओ मोड (रीकास्ट) (12 मीट्रिक टन प्रति वर्ष), एसईसीएल और अशोका-करकटा वेस्ट नॉर्थ ओसी (10 मीट्रिक टन प्रति वर्ष), सीसीएल शामिल हैं।

ईसीएल की रंगमती-ए भूमिगत परियोजना की योजना 3.80 मीट्रिक टन प्रति वर्ष के लिए बनाई गई है, जिसे एक बड़ी भूमिगत खदान माना जा सकता है और ईसीएल के भानोरा पश्चिम (0.50 मीट्रिक टन प्रति वर्ष) के लिए भूमिगत, हाईवॉल और ओपनकास्ट कार्य पद्धति वाली एक मिश्रित खदान की भी योजना बनाई गई है।

सीएमपीडीआईएल में सभी प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ा दी गई है। कोयला अभिलक्षण प्रयोगशाला को 12 विभिन्न क्षेत्रों में "परीक्षण" के क्षेत्र में अपनी सुविधाओं के लिए मानक आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार एनएबीएल प्रमाणन से मान्यता प्राप्त है। हाल ही में, प्रयोगशाला को एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर (एक्सआरडी) प्रणाली से सुसज्जित किया गया है जो अज्ञात नमूनों में खनिजों की उपस्थिति, खदान धूल के नमूनों में मुक्त सिलिका का विश्लेषण करने में सक्षम है। प्रयोगशाला एक्स-रे फ्लोरोसेंस सिस्टम (एक्सआरएफ) सुविधा से भी सुसज्जित है जो राख विश्लेषण और अन्य धातु ऑक्साइड करने में सक्षम है। प्रयोगशाला ने गैर कोयला नमूने (बेस मेटल्स) तैयार करने की इकाई स्थापित की है जिसमें वांछित नमूना आकार की आवश्यकताओं के लिए नमूना तैयार करने के लिए वाइब्रेटरी कप मिल्स और स्वचालित जॉ क्रशर शामिल हैं जो सीएमपीडीआई में अपनी तरह की पहली इकाई है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (आरईई) और ट्रेस धातुओं की गुणात्मक और मात्रात्मक पहचान के लिए, प्रयोगशाला पूरी तरह से चालू आईसीपी-एमएस (इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा-मास स्पेक्ट्रोमेट्री) प्रयोगशाला सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

यह प्रयोगशाला गैर-कोयला के लिए खनिज पहचान सुविधा की स्थापना के लिए परावर्तित प्रकाश ध्रुवीकरण अनुसंधान माइक्रोस्कोप के साथ-साथ रॉक कटिंग और पॉलिशिंग इकाई की खरीद की प्रक्रिया में है। पेट्रोग्राफी लैब में पेट्रोग्राफर्स को कोयला और कार्बनिक पेट्रोलॉजी (आईसीसीपी) की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रमाणित किया गया है।

कोयला एवं खनिज तैयारी (सीएमपी) प्रयोगशाला को एनएबीएल प्रमाणन से भी मान्यता प्राप्त है, ऐसे मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त होना परीक्षण के परिणामों की पारस्परिक स्वीकृति की सुविधा के लिए एक आवश्यक कदम माना जाता है। एनएबीएल ने गैर-विनाशकारी परीक्षण के क्षेत्र में सीएमपीडीआईएल मुख्यालय की एनडीटी प्रयोगशाला को मान्यता जारी रखी। उचित उपकरण और संसाधनों के साथ सीएमपीडीआईएल के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में एनडीटी सेल स्थापित किए गए हैं। क्षेत्रीय संस्थानों की प्रयोगशालाओं को भी एनएबीएल मान्यता दिलाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय संस्थान VI में एनडीटी प्रयोगशाला को भी अप्रैल 2023 में मान्यता दी गई। सीएमपीडीआईएल के पास सीबीएम और शेल गैस विशिष्ट विश्लेषण के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला है।

सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची स्थित पर्यावरण प्रयोगशाला को परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा 170 मापदंडों के लिए आईएसओ/आईईसी 17025:2017 मानकों के अनुसार पुनः मान्यता दी गई। यह मान्यता 24 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। प्रयोगशाला को व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) आईएस/आईएसओ 45001:2018 के अनुसार भी मान्यता प्राप्त है।

2024-25 के दौरान 48 रिपोर्टें यानी 19 ड्राफ्ट ईआईए/ईएमपी/परिशिष्ट ईआईए/ईएमपी (पर्यावरण प्रभाव आकलन/पर्यावरण प्रबंधन योजनाएँ) और 29 फॉर्म-I/फॉर्म-IV/फॉर्म-VI तैयार किए गए, और आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, हसदेव, जयंत और रांची में स्थित आठ पर्यावरण

प्रयोगशालाओं के माध्यम से सीआईएल की 303 परियोजनाओं/क्लस्टरों/प्रतिष्ठानों की पर्यावरण निगरानी की गई। कुछ विशेष कार्य जैसे वहन क्षमता अध्ययन, खदान की पारिस्थितिक निगरानी, सुधार स्थलों के जैव विविधता आकलन अध्ययन, रेत पुनःपूर्ति अध्ययन, एसटीपी और ईटीपी का डिजाइन भी सीएमपीडीआईएल द्वारा किए गए। कुछ विशेष अध्ययन जैसे वैज्ञानिक मृदा नमी संरक्षण (एसएमसी) योजना, शीर्ष मृदा प्रबंधन ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन अध्ययन रिपोर्ट, कार्बन पृथक्करण अध्ययन रिपोर्ट, नदी पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता अध्ययन रिपोर्ट और प्रदूषण न्यूनीकरण अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई और प्रस्तुत की गई। सीएमपीडीआई ईआईए और ईएमपी की तैयारी के लिए भारत में सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त सलाहकार संगठन (एसीओ) है और इसके पास 80 से अधिक अनुमोदित विशेषज्ञ हैं।

सीएमपीडीआईएल 2008 से ही उच्च रिजॉल्यूशन सैटेलाइट डेटा के आधार पर नियमित आधार पर सीआईएल खदानों की सैटेलाइट डेटा आधारित भूमि सुधार निगरानी कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में, कुल 114 परियोजनाओं की भूमि सुधार निगरानी सफलतापूर्वक पूरी की गई, जिसमें 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) श्रेणी से अधिक उत्पादन करने वाली 75 ओपनकास्ट परियोजनाएँ शामिल हैं, जिनकी वार्षिक आधार पर निगरानी की जाती है और 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) श्रेणी से कम उत्पादन करने वाली 39 खदानें/क्लस्टर, जिनकी निगरानी सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों के तहत चरणबद्ध तरीके से तीन साल के अंतराल पर की जाती है। वर्ष के दौरान छह कोयला क्षेत्रों के वनस्पति आवरण का मानचित्रण भी किया गया।

सीएमपीडीआईएल ने टोपोग्राफिकल मैपिंग, कोयला खदान अग्नि मानचित्रण, वनस्पति आवरण मानचित्रण, बस्तियों का मानचित्रण, वृक्षारोपण ऊंचाई आकलन और खनन से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए ड्रोन/यूएवी आधारित सर्वेक्षणों का संचालन शुरू किया है। इसके अलावा, 1 एमटीवाई से अधिक उत्पादन करने वाली सभी ओसी खदानों, आउटसोर्स और

विभागीय दोनों का ओबीआर मापन और 1 एमटीवाई (केवल किराए के पैच) से कम उत्पादन करने वाली ओसी खदानों का स्थलीय लेजर स्कैनर का उपयोग करके वार्षिक माप पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। कोयला मंत्रालय के लिए लगभग 40 नीलामी ब्लॉकों के लिए फ्लाई-श्रू वीडियो तैयार करने के लिए ड्रोन आधारित सर्वेक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया। नीलामी के तहत कोयला ब्लॉकों के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

वर्ष के दौरान मौजूदा केदला वाशरी (2.6 मीट्रिक टन प्रति वर्ष), सीसीएल के जीर्णोद्धार के लिए विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट और एमसीएल में बलराम खदान के लिए 15 मीट्रिक टन प्रति वर्ष वाशरी की स्थापना के लिए मसौदा व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नई वाशरियों की निविदा जारी करने के लिए सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा अपनाई गई विभिन्न बोली अवधारणाओं की जांच करने के लिए समिति की रिपोर्ट तैयार की गई। कोयला वाशरियों की निष्क्रिय क्षमता के उपयोग के उपायों का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई और उसे कोयला मंत्रालय को सौंप दिया गया। एमसीएल में रिजेक्ट आधारित बिजली संयंत्र के साथ-साथ नॉन-कोकिंग कोल वाशरी की स्थापना की संभावनाओं पर एक अवधारणा नोट तैयार किया गया, जिसके आधार पर "एमसीएल में एकीकृत कुल्दा-गर्जनबहाल नॉन-कोकिंग कोल वाशरी की स्थापना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने" के लिए कार्य आदेश दिया गया है।

सीएमपीडीआईएल ने कोयला आधारित गैर-परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के वाणिज्यिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ वाणिज्यिक और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है। सीएमपीडीआईएल लगातार कोल बेड मीथेन (सीबीएम) और कोल गैसीफिकेशन जैसे कोयला आधारित गैर-परंपरागत संसाधनों के विकास के लिए काम कर रहा है। सीएमपीडीआईएल सीबीएम के विकास के लिए ईसीएल, बीसीसीएल

और एसईसीएल के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) है।

सीआईएल लीजहोल्ड क्षेत्रों में तीन सीबीएम ब्लॉक अर्थात् झरिया सीबीएम ब्लॉक-1, रानीगंज सीबीएम ब्लॉक और झरिया सीबीएम ब्लॉक-11 वर्तमान में विचाराधीन हैं। झरिया सीबीएम ब्लॉक-1 (बीसीसीएल लीजहोल्ड क्षेत्र) को राजस्व साझाकरण के आधार पर सीबीएम के निष्कर्षण के लिए मेसर्स प्रभा एनर्जी लिमिटेड (पीईएल) को दिया गया है। ब्लॉक वर्तमान में अन्वेषण चरण में है। न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) के तहत 5 अन्वेषण कोरहोल की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। झरिया सीबीएम ब्लॉक-11 (बीसीसीएल) के लिए परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट को अक्टूबर, 2024 में बीसीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। सीबीएम निष्कर्षण के लिए सीबीएम डेवलपर के चयन के लिए रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (ईसीएल) और झरिया सीबीएम ब्लॉक-11 (बीसीसीएल) को निविदा देने का प्रस्ताव है।

भारतीय भू-खनन स्थितियों में भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए एक अनुसंधान एवं विकास पायलट परियोजना को सीएमपीडीआईएल, ईसीएल और एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजी इंक (ईईटीआई), कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। सीएमपीडीआईएल और ईसीएल प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी हैं और ईईटीआई, कनाडा उप-कार्यान्वयन एजेंसी है। अनुसंधान एवं विकास पायलट परियोजना के परिणाम कोयला संसाधनों के उपयोग के लिए स्वच्छ मार्ग प्रदान कर सकते हैं।

सीएमपीडीआई कोयला मंत्रालय और सीआईएल के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान के तहत वित्त पोषित अनुसंधान गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है। विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों/संगठनों द्वारा किए जा रहे विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यों के समन्वय के अलावा, सीएमपीडीआईएल अपनी अच्छी तरह से स्थापित प्रयोगशालाओं के साथ कोयला/लिग्नाइट खनन उद्योगों के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान भी कर

रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, इनमें से कई शोध परियोजनाओं ने परिचालन में सुधार, सुरक्षित कार्य स्थितियों, बेहतर संसाधन पुनर्प्राप्ति और पर्यावरण की सुरक्षा के परिणामस्वरूप काफी लाभ दिया है। जबकि कुछ शोध परियोजनाओं ने सीधे उद्योग पर एक ठोस प्रभाव डाला है, वहीं कुछ अन्य हैं जिन्होंने खदान नियोजन, डिजाइन और तकनीकी सेवाओं को मजबूत किया है जो परिचालन खदानों और भविष्य की खनन परियोजनाओं दोनों के लिए आवश्यक हैं।

सीएमपीडीआई द्वारा भारत और विदेशों में अधिक से अधिक विश्व स्तरीय वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों को आर&डी गतिविधियों में शामिल करने के प्रयास जारी हैं ताकि यह आत्मनिर्भर बनकर देश की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। उसी के अनुरूप, सीएमपीडीआई में कोयला और ऊर्जा अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र (नासर), चरण-1 की स्थापना की गई है। चरण-1 में सीएमपीडीआई रांची में मौजूदा बुनियादी ढांचे और अनुभवी जनशक्ति का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि चरण-11 चरण में प्रसिद्ध शहर में एक स्थायी आर&डी केंद्र का निर्माण होगा जो वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए सुसज्जित होगा। यह केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, खनन, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ कोयला समाधानों में अत्याधुनिक तकनीकों और ज्ञान साझाकरण के एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। नासर के प्रमुख उद्देश्यों में कोयला और ऊर्जा क्षेत्रों में अनुसंधान प्रयासों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना और उद्योग के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान परिणामों का समय पर अनुप्रयोग सुनिश्चित करना शामिल है। केंद्र नई खोजों के लिए बौद्धिक संपदा को सुरक्षित करने और उन्नत, विघटनकारी तकनीकों को विकसित करने के लिए उद्योग और विदेशी हितधारकों के साथ सहयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा प्रबंधन और डिजिटलीकरण, कार्बन उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा, एआई और आईओटी का उपयोग, अपशिष्ट से

धन सृजन, अन्वेषण में नई तकनीकों की तैनाती आदि के क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू करके अनुसंधान एवं विकास पहलों के विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है। वर्ष के दौरान, 18 शोध परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से 41 चल रही शोध परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

सीएमपीडीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में प्रबंधन प्रणाली मानकों के कार्यान्वयन के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है और विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों जैसे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 45001, आईएसओ 50001, आईएसओ/आईईसी 27001, आईएसओ 37001 आदि के अनुप्रयोग के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। सीएमपीडीआईएल को अपने सभी क्षेत्रीय संस्थानों के साथ आईएसओ 9001:2015 - गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस दिया गया है। हमारे मार्गदर्शन और समर्थन के तहत, सीआईएल मुख्यालय, कोलकाता को आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 50001:2018 के लिए प्रमाणन मिला है और सीआईएल की तीन सहायक कंपनियों यानी ईसीएल, एनसीएल और एमसीएल को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018) के लिए पुनः प्रमाणित किया गया है।

कोयला मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी में सीएमपीडीआईएल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोयला मंत्रालय द्वारा नीलामी के विभिन्न चरणों के लिए चुने गए कोयला ब्लॉकों के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा खदान डोजियर और खदान सारांश प्रस्तुत किए गए थे। इसके अतिरिक्त, इन सभी कोयला ब्लॉकों के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा निविदा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण इनपुट डेटा भी कोयला मंत्रालय को उपलब्ध कराया गया था। कोयला मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक नीलामी के 10 वें दौर तक 109 कोयला ब्लॉकों के लिए वेस्टिंग ऑर्डर जारी किए गए हैं।

सीआईएल के निर्देशों के अनुसार, सीएमपीडीआई ने सिंगल विंडो मोड एग्रीस्टिक (एसडब्ल्यूएमए) योजना 2022 के अनुसार कोयले की नीलामी के लिए कोयला ई-नीलामी मंच विकसित किया है। पोर्टल का विकास और इसके संशोधन एनआईसी, मीटीई, भारत सरकार द्वारा किए गए हैं, जो इस परियोजना के लिए हमारे प्रौद्योगिकी भागीदार हैं। पोर्टल का औपचारिक उद्घाटन 03.10.2023 को सचिव, एमओसी, भारत सरकार द्वारा किया गया और सीएमपीडीआईएल ने कोयले के लिए ई-नीलामी आयोजित करना शुरू कर दिया है। मार्च 2025 तक, 7000 से अधिक बोलीदाताओं ने कोयला ई-नीलामी पोर्टल में अपना पंजीकरण कराया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, सीएमपीडीआई ने 88 मिलियन टन से अधिक कोयले के लिए सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के लिए 150 ई-नीलामी सफलतापूर्वक आयोजित की है दिसंबर 2024 से सीएमपीडीआईएल के पोर्टल पर ई-नीलामी बंद कर दी जाएगी। संशोधित योजना के अनुसार नीलामी आयोजित करने के लिए पोर्टल बहुत जल्द तैयार हो जाएगा।

सीएमपीडीआईएल ने मेसर्स टीसीआईएल, नई दिल्ली के सहयोग से लैब स्केल 5जी कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) के साथ एक समर्पित "5जी सीओई यूज केस टेस्ट लैब" की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य कोयला क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी परिदृश्य को आगे बढ़ाना है। 5जी यूज केस टेस्ट लैब कोयला उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए विभिन्न 5जी-आधारित अनुप्रयोगों के विकास, परीक्षण और अनुकूलन के लिए एक परीक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता है।

इसके अलावा, सीएमपीडीआई ने अमलोहरी ओपनकास्ट माइंस, एनसीएल, सिंगरौली में "ओपनकास्ट कोल माइंस में एकीकृत वॉयस, वीडियो और डेटा संचार के लिए 5जी कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन)" शीर्षक से एक आरएंडडी परियोजना शुरू की है, जिसमें स्केलेबल 5जी आधारित उपयोग मामलों के साथ एक पूर्ण खदान पैमाने 5जी सीएनपीएन की तैनाती की जा रही है।

1.3.10 सीएमपीडीआईएल और सीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, सीएमपीडीआईएल अपनी होल्टिंग कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश करती है, ताकि सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश के अनुसार गैर-अनुपालन के लिए नकारात्मक अंकन के साथ कुछ अनुपालन मापदंडों के साथ भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन के लिए विभिन्न पैरामीटर सेट किए जा सकें। उपलब्धियों को 1 से 5 के पैमाने पर ग्रेड किया गया था; 'उत्कृष्ट' ग्रेड 1.0 से 1.5 और 'खराब' ग्रेड 4.51 से 5.0 वित्त वर्ष 2014-15 तक। वित्त वर्ष 2009-10 के लिए, सीएमपीडीआईएल को 1.00 (उत्कृष्ट) की उच्चतम समझौता ज्ञापन रेटिंग दी गई थी और वित्त वर्ष 2014-2015 के दौरान, इसे सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा उत्कृष्ट (1.002) रेटिंग दी गई थी, जो सभी सीपीएसई में तीसरी सर्वश्रेष्ठ थी और इसके सिंडिकेट में सर्वश्रेष्ठ थी सीएमपीडीआईएल को 2007-08 से 2021-22 तक उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग प्रदान की गई है, तीन वर्षों को छोड़कर जब यह बहुत अच्छा था, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए "उत्कृष्ट रेटिंग" के साथ एमओयू का प्रदर्शन मूल्यांकन सीआईएल, कोलकाता में अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

1.3.11 जोखिम और चिंताएँ

- हमारे राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों से प्राप्त होता है। सीआईएल से हमारी सेवाओं की मांग में कोई भी गिरावट हमारे व्यवसाय, परिचालन के परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- हमारे व्यापारिक लेन-देन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकारी संस्थाओं या एजेंसियों के साथ होता है, जिससे हमें विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें अतिरिक्त नियामक जांच और प्राप्तियों के विलंबित संग्रह शामिल हैं।
- हमारे राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी भूवैज्ञानिक अन्वेषण और संसाधन मूल्यांकन

सेवाओं से प्राप्त होता है। हमारी भूवैज्ञानिक अन्वेषण और संसाधन मूल्यांकन सेवाओं की मांग में कोई भी गिरावट हमारे व्यवसाय, परिचालन के परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

- प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हमारी वर्तमान प्रौद्योगिकियों को अप्रचलित बना सकता है। ऐसी स्थितियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने, नवाचार करने और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने में हमारी ओर से कोई भी विफलता हमारे व्यवसाय, परिचालन के परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- हमारा व्यवसाय जनशक्ति प्रधान है। काम बंद होने, हमारे कर्मचारियों द्वारा वेतन की बढ़ती मांग या न्यूनतम वेतन में वृद्धि से हमारा व्यवसाय प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है, और यदि हम व्यावसायिक रूप से आकर्षक शर्तों पर नए कर्मचारियों को नियुक्त करने में असमर्थ हैं।
- यदि हम वरिष्ठ प्रबंधन, योग्य और कुशल कार्मिकों की भर्ती करने और उन्हें बनाये रखने में असमर्थ हैं, तो हमारा व्यवसाय और हमारे व्यवसाय को संचालित करने या बढ़ाने की हमारी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- हम अपने कर्मचारियों के कल्याण, लाभ और प्रशिक्षण को नियंत्रित करने वाले कई श्रम कानूनों और विनियमों के अधीन हैं। वेतन और प्रशिक्षण लागत में कोई भी वृद्धि हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- हम अपने उपकरण और मशीनरी के बुनियादी ढांचे पर निर्भर हैं, जो रखरखाव, उन्नयन और एकीकरण से जुड़े व्यवधान, क्षति, विफलता और जोखिमों के अधीन है। हमारे उपकरण और मशीनरी के बुनियादी ढांचे को प्रभावी ढंग से बनाए रखने या अपग्रेड करने में कोई भी विफलता हमारे व्यवसाय, संचालन के परिणामों,

वित्तीय स्थितियों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

- ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा के उभरने के कारण हमें अपनी सेवाओं की मांग में कमी का जोखिम उठाना पड़ रहा है। स्थायी ऊर्जा समाधानों की ओर महत्वपूर्ण बदलाव से हमारे व्यवसाय, परिचालन के परिणामों, वित्तीय स्थितियों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- बदलते कानून, नियम और विनियम तथा कानूनी अनिश्चितताएं, जिनमें कर कानूनों का प्रतिकूल अनुप्रयोग भी शामिल है, हमारे व्यवसाय, संभावनाओं और परिचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

1.3.12 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

- सीएमपीडीआईएल के पास कारोबार के सुचारू और कुशल संचालन के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं तथा यह प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है।
- सुचारू निर्णय लेने के लिए शक्तियों का व्यापक हस्तांतरण मौजूद है।
- एकरूप अनुपालन के लिए खातों की तैयारी हेतु विस्तृत दिशानिर्देशों का लगातार पालन किया जाता है।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के अनुपालन पर नजर रखने के लिए लेखापरीक्षा समिति का गठन किया जाता है।
- आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स/कॉस्ट अकाउंटेंट फर्मों द्वारा की जाती है।
- प्रमुख नियंत्रणों की पहचान करने तथा आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा डिजाइन किए गए प्रमुख नियंत्रणों की परिचालन दक्षता के पर्यवेक्षण हेतु आंतरिक नियंत्रण ढांचा विकसित किया गया है।
- व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई गई है और उसका पालन किया जा रहा है।

- कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में तथा जोखिम प्रबंधन के संबंध में सीआईएल के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीएमपीडीआईएल में बोर्ड स्तर के सदस्य की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

1.3.13 मानव संसाधन में ठोस विकास

सीएमपीडीआईएल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसके कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी और लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और कर्मचारियों के लिए 5 साल में एक बार और अधिकारियों के लिए 10 साल में एक बार तय किए जाते हैं। सीएमपीडीआईएल अपने कर्मचारियों, मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों, अन्य अधिकारियों और प्रबंधन प्रशिक्षुओं को निरंतर प्रशिक्षण और विकास के अवसर भी प्रदान करता है। इसके अलावा, कंपनी भारत के बाहर बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करती है। इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट रिपोर्ट के प्रासंगिक हिस्से में शामिल है।

1.3.14 परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

कंपनी की कुल आय में मुख्य रूप से सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों और अन्य कंपनियों को दी गई परामर्श सेवाओं से आय, अन्य आय और अर्जित ब्याज शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 की कुल आय पिछले वर्ष के 1770.18 करोड़ रुपये के मुकाबले 2177.53 करोड़ रुपये है, इस प्रकार 23.01% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल व्यय 1037.34 करोड़ रुपये के मुकाबले 1295.39 करोड़ रुपये है, जिसके परिणामस्वरूप 24.88% की वृद्धि हुई है।

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और आस्थगित कर व्यय या संशोधित आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार गणना की गई क्रेडिट शामिल है। वर्तमान करों के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम के अनुसार भत्ते और छूट के लिए अनुमानित कर देयता के आधार पर मान्यता प्राप्त है इन्हें बैलेंस शीट की तारीख तक लागू कर दरों और कर विनियमों का

उपयोग करके मापा जाता है। कर दरों में परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभाव को दर में परिवर्तन के संबंधित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण में मान्यता दी जाती है।

आगे ले जाने वाले नुकसानों के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह निश्चित रूप से निश्चित है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को प्राप्त किया जा सकता है। कर से पहले का लाभ पिछले वर्ष के 732.84 करोड़ रुपये की तुलना में 882.14 करोड़ रुपये है, जिसमें 149.30 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। कर के बाद का लाभ पिछले वर्ष के 503.23 करोड़ रुपये की तुलना में 666.91 करोड़ रुपये है, जिसमें 163.68 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

1.4 सीएमपीडीआईएल का वित्तीय अवलोकन

वर्ष के दौरान कंपनी ने 666.91 रुपए का कर पश्चात लाभ कमाया। पिछले तीन वर्षों के कार्य परिणामों का सारांश इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	सीएमपीडीआईएल का प्रदर्शन		
	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
1. कर पूर्व लाभ (रुपए करोड़ में)	366.95	732.84	882.14
2. कर पश्चात लाभ (रुपए करोड़ में)	296.66	503.23	666.91
3. कारोबार (रुपए करोड़ में) (शुद्ध बिक्री)	1386.09	1732.69	2102.76
4. कर पूर्व लाभ से कारोबार (%)	26.47	42.29	41.95
5. प्रति शेयर आय (₹.)	2077.45	3524.02	4670.24

1.4.1 सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा सचिवीय अंकेक्षक रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई प्रत्येक अर्हता, आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी पर बोर्ड द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या टिप्पणियां, रिपोर्ट के **परिशिष्ट-IV** के रूप में संलग्न हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रबंधन द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, रिपोर्ट के **परिशिष्ट-V** के रूप में संलग्न है।

1.4.2 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 186 के अनुसार कंपनी को दिए गए ऋण, किए गए निवेश अथवा की गई गारंटी अथवा उपलब्ध कराए गए सिक्कुरिटी तथा ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्कुरिटी में रेसिपिएंट द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्कुरिटी के उद्देश्य के पूरे विवरण को वित्तीय विवरण में सदस्यों के लिए प्रकट करना चाहिए।

किसी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी को कोई ऋण नहीं दिया गया, निवेश नहीं किया गया या गारंटी नहीं दी गई अथवा सिक्कुरिटी मुहैया नहीं कराई गई। इसका ब्यौरा वित्तीय विवरण में दिया गया है।

1.4.3 कंपनी मामले की स्थिति

कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के मुकाबले 142.80 करोड़ रुपये है। पूंजी आरक्षित राशि 18.87 करोड़ रुपये है, सामान्य आरक्षित राशि 103.28 करोड़ रुपये है और पी/एल खाते में अधिशेष 1795.77 करोड़ रुपये (ओसीआई सहित) है और शेयरधारकों के फंड में पूरी तरह से 2041.85 करोड़ रुपये है। गैर चालू देनदारी 87.47 करोड़ रुपये और चालू देनदारी 553.48 करोड़ रुपये है।

कंपनी की शुद्ध अचल संपत्ति 246.95 करोड़ रुपये, आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध) 21.94 करोड़ रुपये, अन्य गैर-वर्तमान संपत्ति 13.31 करोड़ रुपये और वर्तमान संपत्ति 2400.06 करोड़ रुपये है।

परिचालन और अन्य आय से कुल राजस्व 2177.53 करोड़ रुपये रहा तथा सभी व्यय और करों को पूरा करने के बाद शुद्ध लाभ 666.91 करोड़ रुपये रहा। प्रति शेयर आय (प्रति शेयर 1000 रुपये अंकित मूल्य) 4670.24 रुपये रही।

1.4.4 31 मार्च, 2025 तक पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2024-25
भूमि एवं भवन	0.29	8.47
संयंत्र और मशीन	26.31	15.29
कार्यालय उपकरण	1.72	0.66
फर्नीचर	3.07	3.05
दूरसंचार	0.02	0.58
वाहन	1.87	1.81
सॉफ्टवेयर	1.52	2.08
ईआरपी विकासाधीन	-	-
कुल	34.80	31.94

1.4.5 लाभांश की घोषणा

निदेशक मंडल ने 20 अक्टूबर 2024 को आयोजित अपनी 284वीं बैठक में 30 सितंबर 2024 तक के वित्तीय परिणामों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹150 करोड़ के अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी, जो ₹1,000 के 14,28,000 इक्विटी शेयरों पर ₹1,050.42 प्रति इक्विटी शेयर था, जो कर के बाद चालू वर्ष के लाभ और लाभ एवं हानि खाते में संचित अधिशेष में से भुगतान किया गया था।

इसके अलावा, 30 अप्रैल 2025 को आयोजित अपनी 290वीं बैठक में, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹150 करोड़ के अंतिम लाभांश की सिफारिश की (एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन), जो वर्ष के दौरान कंपनी के समग्र वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर ₹1,000 के 14,28,000 इक्विटी शेयरों पर ₹1,050.42 प्रति इक्विटी शेयर है।

1.4.6 31.03.2025 के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन:

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई भी भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धता कंपनी के उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, तथा रिपोर्ट की तारीख के बीच नहीं हुई है।

1.5 निगमित शासन

कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी कंपनी के प्रबंधन, उसके बोर्ड, उसके शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के बीच संबंधों का एक समूह है। यह एक सैद्धांतिक प्रक्रिया और संरचना प्रदान करता है जिसके माध्यम से कंपनी के उद्देश्य, उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन और प्रदर्शन की निगरानी की प्रणाली भी निर्धारित की जाती है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमाणपत्र की रिपोर्ट और लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण रिपोर्ट के **परिशिष्ट-III** के रूप में संलग्न है।

1.6 कंपनी का दर्शन

निगमित शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन, पारदर्शिता, इंटीग्रिटी, विश्वसनीयता, गोपनीयता, नियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व, डिसक्लोजर और रिपोर्टिंग जो नियम, अधिनियम विनियमन और दिशा-निर्देश का पालन करता हो, को सुनिश्चित करना है।

कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, कंपनी के पास एक अच्छी तरह से परिभाषित नीति ढांचा है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- निदेशकों तथा वरीय प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता (कोड आफ कंडक्ट)
- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आंतरिक ट्रेडिंग के संरक्षण के लिए आचार संहिता
- विसिल ब्लोअर पालिसी
- जोखिम प्रबंधन योजना

1.7 निदेशक मंडल

कंपनी का कार्य व्यापार निदेशक मंडल द्वारा चलाया जाता है। कंपनी के निदेशकों की संख्या समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। निदेशकों के लिए क्वालिफिकेशन शेयर को रखने की जरूरत नहीं होती है। राष्ट्रपति द्वारा चेयरमैन, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक और गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति आदेश के अनुबंध एवं शर्तों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते, बैठक, शुल्क आदि दिए जाते हैं।

क) निदेशक मंडल का आकार

कंपनी के आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के संदर्भ में हमारे निदेशक मंडल में कम-से-कम दो (2) निदेशक और पन्द्रह (15) निदेशक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक कार्यकारी निदेशक/कार्यकारी अथवा सरकारी अंशकालिक निदेशक या गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक हो सकते हैं।

ख) निदेशक-मंडल का कोटिवार गठन:

31 मार्च, 2025 के अनुसार सीएमपीडीआईएल के निदेशक मंडल में 5 निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित तीन (3) पूर्णकालिक निदेशक दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं। कार्यकारी अध्यक्ष श्री मनोज कुमार इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

पहले नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों का पद समाप्त होने के बाद कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी की जानी है। इस प्रकार बोर्ड की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों का पालन केवल स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर किया जा सकता है।

31 मार्च, 2025 को निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है:

I. पूर्णकालिक निदेशक

क) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

1. श्री मनोज कुमार

ख) कार्यकारी निदेशक

1. श्री शंकर नागाचारी
2. श्री अजय कुमार

II. अंशकालिक सरकारी निदेशक

1. श्री मुकेश अग्रवाल
2. श्री मारापल्ली वेंकटेश्वरलू

ग). आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या और तिथि

निदेशक मंडल कंपनी का सर्वोच्च निकाय है जो कंपनी के समग्र कार्यों की देखरेख करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 11 (ग्यारह) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं।

क्रम सं.	बैठकों की संख्या	दिनांक	दिन	बैठक का स्थान
1.	277 वां	25.04.2024	गुरुवार	रांची
2.	278 वां	24.05.2024	शुक्रवार	रांची
3.	279 वां	25.06.2024	मंगलवार	रांची
4.	280 वां	22.07.2024	सोमवार	रांची
5.	281 वीं	23.08.2024	शुक्रवार	रांची
6.	282 वीं	13.09.2024	शुक्रवार	रांची
7.	283 वीं	01.10.2024	मंगलवार	रांची
8.	284 वीं	20.10.2024	रविवार	रांची
9.	285 वां	19.01.2025 और 20.01.2025	रविवार और सोमवार	मैसूरु, कर्नाटक
10.	286 वीं	24.02.2025	सोमवार	रांची
11.	287 वीं	25.03.2025	मंगलवार	रांची

घ). बोर्ड बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक	उनके कार्यावधि में हुई बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड की बैठक में उपस्थिति की संख्या	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
कार्यकारी निदेशक				
1.	श्री मनोज कुमार	11	11	हाँ
2.	श्री शंकर नागाचारी	11	9	हाँ
3.	श्री अजय कुमार	11	10	हाँ
4.	श्री सतीश झा	8	8	हाँ
5.	श्री अच्युत घटक	9	9	हाँ
अंशकालिक सरकारी निदेशक				
6.	श्री मुकेश अग्रवाल	4	4	-
7.	श्री मारापल्ली वेंकटेश्वरलु	3	3	-
8.	डॉ. बी. वीरा रेड्डी	5	5	हाँ
9.	श्री अजितेश कुमार	8	8	हाँ

क्रमांक 6 को 17.10.2024 से कोल इंडिया लिमिटेड से सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया

क्रमांक 7 को 01.01.2025 से कोयला मंत्रालय से सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

क्रमांक 8 को 24.02.2024 से 31.08.2024 तक कोल इंडिया लिमिटेड से सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया

क्रमांक 9 को 27.12.2023 से 31.12.2024 तक कोयला मंत्रालय से सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

ड़). 31 मार्च, 2025 के अनुसार रूचि का प्रकटीकरण ।

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	जिस कंपनी के लिए वे इच्छुक हैं	रूचि की प्रकृति यानि अध्यक्ष, निदेशक प्रबंधक एवं सचिव
कार्यकारी निदेशक			
1.	श्री मनोज कुमार	शून्य	-
2.	श्री शंकर नागाचारी	1. कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा 2. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	1. निदेशक 2. निदेशक
3.	श्री अजय कुमार	शून्य	-
अंशकालिक सरकारी निदेशक			
4.	श्री मुकेश अग्रवाल	1. कोल इंडिया लिमिटेड 2. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड 3. सीएलयूवीपीएल	1. निदेशक एवं शेयरधारक 2. निदेशक 3. निदेशक
5.	श्री मारापल्ली वेंकटेश्वरलु	शून्य	-

च). बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की गई जानकारी

बोर्ड के पास कंपनी के भीतर किसी भी जानकारी तक पूरी पहुंच है। बोर्ड को दी गई जानकारी में शामिल हैं:

- ♦ पूंजीगत और राजस्व बजट।
- ♦ कंपनी के त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- ♦ कंपनी के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा।
- ♦ भारी मशीनों की उपलब्धता एवं उपयोग की आवधिक समीक्षा।
- ♦ लागू कानूनों के अनुपालन पर आवधिक रिपोर्ट।
- ♦ वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।
- ♦ लेखापरीक्षा समिति, सीएसआर समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।
- ♦ बड़े ठेकों/समझौतों को देना
 - अन्य कंपनियों में निदेशक पद और उनके द्वारा ग्रहण किए गए पद के बारे में निदेशकों की रुचि का खुलासा
 - स्वतंत्र निदेशक द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा।
 - श्रमशक्ति बजट.
 - कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

1.8 निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल :



श्री मनोज कुमार

(डीआईएन: 09225497)

वर्ष 1986 में आईआईटी-बीएचयू, वाराणसी से खनन इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1990 में प्रथम श्रेणी के खदान प्रबंधक का योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। उन्होंने वर्ष 1986 में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के कोरबा क्षेत्र से कोयला उद्योग में अपना करियर शुरू किया। और यूजी और ओसी दोनों खानों के क्षेत्र स्तर पर काम करने का

व्यापक अनुभव है।

वह 1998 में सीएमपीडीआईएल में शामिल हुए और उन्होंने यूजी और ओसी खान योजना में काम किया और भारत की सबसे बड़ी कोयला खदानों जैसे गेवरा, कुसुमुंडा और दीपका खानों की योजना बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हें सीएमपीडीआईएल के तीन क्षेत्रीय संस्थानों के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में 9 साल का प्रशासनिक अनुभव भी है, जहां उन्होंने एनसीएल, एसईसीएल और सीसीएल के लिए भविष्य का रोडमैप बनाने में मदद की।

वह सीएमपीडीआईएल के सीबीएम/सीएमएम क्लियरिंग हाउस के एचओडी भी थे और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सीआईएल के सीबीएम ब्लॉकों की पहली दो परियोजना रिपोर्टों को मंजूरी दी। उन्हें वर्ष 2019 में कोल इंडिया स्तर पर सर्वश्रेष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सम्मानित किया गया था।

उन्होंने आधिकारिक क्षमता में पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान का दौरा किया और वैश्विक खनन प्रथाओं का अनुभव किया।

दिनांक 04.10.2021 से वे सीएमपीडीआईएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं।



श्री मुकेश अग्रवाल

(डीआईएन: 10199741),

श्री मुकेश अग्रवाल ने 17 अक्टूबर 2024 से सीएमपीडीआईएल के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक

निदेशक का पदभार ग्रहण किया। वे कॉर्पोरेट वित्त, रणनीतिक योजना और वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक के शानदार करियर के साथ आए हैं। एक अनुभवी वित्त पेशेवर, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के फेलो सदस्य और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक, श्री मुकेश अग्रवाल अपने मूल क्षेत्र में विश्लेषणात्मक दृढ़ता के साथ गहन कार्यात्मक विशेषज्ञता का संयोजन करते हैं। उनकी योग्यताओं ने उन्हें दूरसंचार, अवसंरचना, खनन और विद्वत् उत्पादन जैसे क्षेत्रों में वित्तीय कार्यों का नेतृत्व और रूपांतरण करने में सक्षम बनाया है।

वह वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड में निदेशक

(वित्त) के पद पर कार्यरत हैं। सीआईएल में नियुक्ति से पहले, वह कोयला मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) में कार्यकारी निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यरत थे।

इस पद पर रहते हुए, उन्होंने संगठन के वित्तीय ढांचे को सुदृढ़ बनाने, वित्तीय समेकन, डिजिटल परिवर्तन और नीति अनुकूलन की पहलों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कोयला आधारित सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर संयुक्त उद्यम, नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) में मुख्य वित्तीय अधिकारी का पद भी संभाला, जहाँ उन्होंने महत्वपूर्ण वित्तीय संचालन और परियोजना वित्त मामलों की सटीकता और रणनीतिक दूरदर्शिता के साथ देखरेख की।

श्री मुकेश अग्रवाल की प्रमुख दक्षताओं में वित्तीय डोमेन का एक विस्तृत दायरा शामिल है—कॉर्पोरेट लेखांकन, लागत नियंत्रण, कोषागार और निधि प्रबंधन, कराधान, बजट और पूर्वानुमान, वैधानिक अनुपालन, वित्तीय संचालनों का डिजिटलीकरण और उद्यम जोखिम प्रबंधन। उन्होंने उद्यम-व्यापी ईआरपी एकीकरण का नेतृत्व किया है और तकनीक-सक्षम वित्तीय पारदर्शिता और रीयल-टाइम रिपोर्टिंग की दिशा में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के वित्त क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विचारक, श्री मुकेश अग्रवाल को मैक्रो-स्तरीय नीति सोच के साथ परिचालन विवरण को मिश्रित करने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता है। परियोजना प्रबंधन और वित्तपोषण के अलावा, उन्होंने योजनाओं को आकार देने, मूल्य निर्धारण और नियामक ढाँचे तैयार करने और राष्ट्रीय ऊर्जा और बुनियादी ढाँचे के लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय संसाधनों को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कोल इंडिया लिमिटेड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट (सीएमपीडीआई) में अपनी भूमिका से परे, श्री मुकेश अग्रवाल हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) में अध्यक्ष का पद भी संभालते हैं। वे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) और कोल लिग्राइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड सहित सीआईएल की कई प्रमुख सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निदेशक के पद पर

हैं। उनके बोर्ड स्तर के जुड़ाव कोयले और बिजली क्षेत्रों के बारे में उनकी सूक्ष्म समझ को दर्शाते हैं।

परिचालन गहराई और रणनीतिक परिप्रेक्ष्य के दुर्लभ मिश्रण के साथ, श्री मुकेश अग्रवाल सीएमपीडीआईएल की वित्तीय संरचना को मजबूत करने और इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।



श्री मारापल्ली वेंकटेश्वरलू

(डीआईएन: 10059799),

कोयला मंत्रालय में निदेशक (तकनीकी) हैं। कोयला मंत्रालय में निदेशक (तकनीकी) के रूप में अपनी

नियुक्ति से पहले, वे सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) में विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। उन्होंने वर्ष 1996 में कोठागुडेम स्कूल ऑफ माइंस, उस्मानिया विश्वविद्यालय से खनन में बी.टेक किया और वर्ष 2000 में डीजीएमएस से प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किया। उन्होंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पर्यावरण अध्ययन में पीजी डिप्लोमा भी किया है। उन्होंने कोयला खनन के विभिन्न क्षेत्रों में 25 से अधिक वर्षों तक सिंगरेनी कोलियरीज में काम किया है, जिसमें अन्वेषण, खान नियोजन, मशीनीकृत भूमिगत और खुली खदानें, अनुसंधान और विकास, रणनीतिक योजना और विपणन शामिल हैं उन्हें 01.01.2025 से सीएमपीडीआईएल के बोर्ड में सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।



श्री शंकर नागाचारी

(डीआईएन: 09729657)

के पास इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) से माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री (1988), इग्नू से मार्केटिंग मैनेजमेंट

में एमबीए और आईआईएम रांची से एग्जीक्यूटिव एमबीए है। उन्होंने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के कन्हान क्षेत्र में अंबारा कोलियरी से अपने पेशेवर सफर की शुरुआत की और भूमिगत और ओपनकास्ट खनन परिचालन दोनों में नेतृत्व की प्रमुख भूमिकाएँ निभाईं। माइन मैनेजर से लेकर एरिया जनरल मैनेजर तक के पदों पर पहुँचते हुए, उन्होंने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) और

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में कोयला उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उनके गतिशील नेतृत्व में, एसईसीएल के बैकुंठपुर और सोहागपुर क्षेत्रों को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हुए, जो परिचालन उत्कृष्टता और सुरक्षा मानकों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

सीएमपीडीआईएल में निदेशक (तकनीकी/सीआरडी) के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका के अलावा, श्री नागाचारी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। वे कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड (सीआईएल) के बोर्ड में कार्यरत हैं, जो मोजाम्बिक में कोयला परियोजनाओं को विकसित करने के लिए स्थापित कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

इससे पहले, उन्होंने 14 जनवरी 2024 से 27 जनवरी 2025 तक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में निदेशक (तकनीकी - परियोजना और योजना) के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला था।

वह अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) और भारतीय खनन, भूवैज्ञानिक एवं धातुकर्म संस्थान (एमजीएमआई) के आजीवन सदस्य हैं, तथा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) के आजीवन फेलो सदस्य हैं।

अपने विशाल तकनीकी ज्ञान, नेतृत्व कौशल और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ, श्री शंकर नागाचारी सीएमपीडीआईएल और व्यापक कोयला उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र के रणनीतिक विकास और वृद्धि में सार्थक योगदान देने के लिए उपयुक्त हैं।



श्री अजय कुमार
(डीआईएन: 09774347)

सीएमपीडीआईएल में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले, उन्होंने एनटीपीसी

लिमिटेड, सीएमपीडीआईएल क्षेत्रीय संस्थान-V, बिलासपुर, सीएमपीडीआईएल और सीसीएल में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

श्री अजय कुमार ने 1989 में आईआईटी (आईएसएम)-धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और उसी वर्ष, श्री कुमार ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के एनके एरिया से अपना करियर शुरू किया। श्री कुमार ने वर्ष 1993 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक का योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किया।

श्री कुमार ने आधिकारिक क्षमता में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया और इन देशों में कोयला खदानों और भूमिगत कोयला गैसीकरण की कार्य पद्धतियों पर ज्ञान प्राप्त किया।

श्री कुमार ने अमेरिका और स्विट्जरलैंड में आयोजित जीएमआई सम्मेलन में भी भाग लिया है।

श्री कुमार के पास ओपन कास्ट माइन प्लानिंग और माइन डेवलपमेंट में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है, जिससे सीएमपीडीआईएल के साथ-साथ संपूर्ण कोयला खनन उद्योग को लाभ होगा।



डॉ. बी. वीरा रेड्डी
(डीआईएन 08679590)

1 फरवरी 2022 से सीआईएल के निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण कर लिया है।

इससे पहले वह 01.01.2020

से 31.01.2022 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) संचालन थे। उन्होंने वर्ष 1986 में कोठागुडेम स्कूल ऑफ माइन्स, उस्मानिया विश्वविद्यालय से माइनिंग में बी.टेक किया और वर्ष 1990 में डीजीएमएस द्वारा प्रथम श्रेणी प्रबंधक योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किया। उन्होंने वर्ष 2000 में कोठागुडेम स्कूल ऑफ माइन्स, उस्मानिया विश्वविद्यालय से माइन प्लानिंग में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी भी पूरा किया है। श्री रेड्डी वर्ष 1987 में एससीसीएल में शामिल हुए और उन्हें कोयला खनन, योजना, खरीद और संचालन में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) संचालन के रूप में शामिल होने से पहले उन्होंने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के अद्रियाला लॉगवाल परियोजना क्षेत्र के महाप्रबंधक के रूप में काम किया।

उन्हें 24.02.2022 से 31.08.2024 तक सीएमपीडीआईएल के बोर्ड में आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।



श्री अजितेश कुमार
(डीआईएन: 08765626)

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सर्विस एक्जामिनेशन 2005 के जरिए चयनित सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग (ग्रुप-ए) सेवा के 2006 बैच से हैं। उन्होंने अपने बी-टेक (इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग) की डिग्री गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंत नगर (उत्तराखंड) से ली।

उन्होंने 2008 में सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी आथरिटी, नई दिल्ली में ज्वाइन किया और 2016 तक हाइड्रोइलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट के विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन भी किया। वर्ष 2016 में उनकी नियुक्ति हिंडस-ऑन-एक्सपोजर टू वापर प्लांट आपरेशन के लिए टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसीएल) के लिए हुई और टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट, उत्तराखंड के पावर हाउस में पदस्थापित रहे।

वर्ष 2017 में सीईए से लौटने के पश्चात् उनकी पदस्थापना पावर सिस्टम प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग डिवीजन में हुई जहाँ उन्हें वे राष्ट्रीय महत्व के टेरिफ आधारित बिडिंग स्कीम और अन्य ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के तहत ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट से संबंधित मामले देखने का कार्य दिया गया।

वर्तमान में, वे कोयला मंत्रालय में निदेशक (पी एंड एस-I / पी एंड एस-II / एनए) के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने 13.01.2020 से 26.12.2023 तक सीएमपीडीआईएल के बोर्ड में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्हें 22.02.2023 से सीसीएल के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 27.12.2023 से 31.12.2024 तक सीएमपीडीआईएल के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है।



श्री सतीश झा (डीआईएन: 10299809)

ने 1990 में नागपुर विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियरिंग की डिग्री और 1998 में आईएसएम, धनबाद से औद्योगिक इंजीनियरिंग और प्रबंधन में एम.टेक की डिग्री प्राप्त की है। श्री झा आईआईटी-बीएचयू, वाराणसी से माइन प्लानिंग में पीएचडी भी कर रहे हैं।

श्री झा ने 1990 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से जूनियर एक्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में अपना करियर शुरू किया। श्री झा ने ज्यादातर कोयला उत्पादक कंपनियों जैसे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की विभिन्न भूमिगत और खुली खदानों में खान प्रबंधक से लेकर जीएम (कॉर्पोरेट प्लानिंग) और क्षेत्रीय महाप्रबंधक तक विभिन्न पदों पर काम किया है।

निम्नलिखित कार्यों में श्री झा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:

- 1) 1996 में झरिया कोयला क्षेत्र की व्यापक जल प्रबंधन योजना।
- 2) लॉन्गवॉल और शॉर्टवॉल संचालन का प्रबंधन।
- 3) नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ड्रैगलाइन खदानें।
- 4) एनसीएल की अमलोहरी परियोजना में "ओबी टू एम-सैंड प्लांट" की स्थापना और कमीशनिंग।

लॉन्गवॉल और शॉर्टवॉल संचालन के सफलतापूर्वक प्रबंधन के लिए 2003 में श्री झा को "एसईसीएल सम्मान" पुरस्कार भी मिला। श्री झा ने अपनी आधिकारिक हैसियत से जापान और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है।

श्री झा के भूमिगत खदानों और खुली खदानों दोनों में 33 वर्षों के व्यापक अनुभव से न केवल सीएमपीडीआईएल बल्कि पूरे कोयला उद्योग को लाभ होने की उम्मीद है।

उन्हें 01.09.2023 से सीएमपीडीआईएल के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले उन्होंने एनसीएल में विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है।



श्री अच्युत घटक (डीआईएन

08923591) ने 1989 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, रायपुर से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की

और 1993 में प्रथम श्रेणी माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी प्राप्त किया। उन्होंने 1989 में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में अपना करियर शुरू किया और 19 वर्षों तक वहाँ सेवा की, जिनमें से अधिकांश मशीनीकृत भूमिगत खदानों में कार्यरत रहे।

अगस्त 2008 के बाद, उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय, कोलकाता में परियोजना निगरानी और कॉर्पोरेट योजना जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्य किया।

उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख भूमिकाएँ निभाई:

- 1) कोयला खनन परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड में पहली बार एमएस-प्रोजेक्ट का उपयोग।
- 2) कोल इंडिया लिमिटेड की 1 बीटी योजना के लिए रोडमैप तैयार करना।
- 3) कोल इंडिया लिमिटेड की भूमिगत विज्ञान योजना का निर्माण और कार्यान्वयन।
- 4) सीआईएल के विज्ञान 2047 का निर्माण और एमओसी के विज्ञान 2047 दस्तावेज़ की तैयारी में सहायता।

अपनी आधिकारिक हैसियत से, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और अमेरिका का दौरा किया है। भूमिगत खनन और परिचालन योजना में उनके व्यापक अनुभव से न केवल सीएमपीडीआई, बल्कि सीआईएल को भी भविष्य में भूमिगत खनन में अपने परिचालनों को स्थानांतरित करने में लाभ होने की संभावना है।

उन्हें 01.10.2023 से 23.01.2025 तक सीएमपीडीआईएल के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया था।

1.9 क). अंकेक्षण समिति:

लेखापरीक्षा समिति का प्राथमिक कार्य वित्तीय रिपोर्ट, वित्त, लेखांकन और कंपनी की लेखापरीक्षा, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा करके निदेशक मंडल को अपनी निगरानी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करना है।

लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा करती है, सांविधिक लेखापरीक्षकों से मिलती है और उनके निष्कर्षों, सुझावों और अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा करती है तथा कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रमुख लेखांकन नीतियों की समीक्षा करती है।

ख). सन्दर्भ की शर्तें :

अंकेक्षण समिति के सन्दर्भ की शर्तें विषय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार है तथा भारी उद्योग मंत्रालय तथा पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग द्वारा जारी किये गए सीपीएसईएस के कारपोरेट-गवर्नेंस पर आधारित दिशा-निर्देश के अनुसार है।

अंकेक्षण समिति के सन्दर्भ की शर्तें अन्य बातों के साथ-साथ संगठन के सभी व्यावसायिक पहलुओं को कवर करेगा।

- i. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।
- ii. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का नियतकालिक पुनरीक्षण।
- iii. शासकीय अंकेक्षण तथा सांविधिक अंकेक्षण की रिपोर्ट का पुनरीक्षण।
- iv. मानक पारामीटरों के साथ-साथ संचालनीय कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण।
- v. परियोजनाओं तथा अन्य पूंजीगत योजनाओं का पुनरीक्षण।
- vi. आंतरिक अंकेक्षण उपलब्धि/अवलोकन का पुनरीक्षण।
- vii. आनुपातिक तथा प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण

कार्य का विकास।

viii. बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए मुद्दों सहित किसी भी विषय का विशेष अध्ययन/जाँच।

ग). अंकेक्षक समिति का कार्य क्षेत्र:

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र/भूमिका इस प्रकार है:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना तथा वित्तीय संरचनाओं का प्रकटीकरण, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है।
2. ऑडिट फीस को निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अनुशंसा करना।
3. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गए अन्य सेवाओं के लिए अंकेक्षक, सांविधिक अंकेक्षकों के भुगतान का अनुमोदन करना है।
4. विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना।

क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) और 134(5) के संदर्भ में शामिल किए जाने वाला डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सबिलिटी स्टेटमेंट में शामिल होने वाले अपेक्षित मामले।

ख) लेखा नीतियों तथा प्रैक्टिसेस में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसका कारण।

ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय पर आधारित आकलन से जुड़े मुख्य लेखा प्रविष्टि (इन्ट्री)।

घ) अंकेक्षण निष्कर्ष से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं (प्रयोज्य नियम, अधिनियम तथा कंपनी नीतियाँ) का अनुपालन।

च) किसी भी संबंधित पार्टी मामलों का

प्रकटीकरण (डिस्कलोजर) तथा

(छ) मसौदा अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यता।

5. अनुमोदन हेतु बोर्ड में प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
6. आंतरिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
7. आंतरिक अंकेक्षण विभाग, ऑफिशियल होलिंग डिपार्टमेंट का स्टाफिंग तथा वरीयता रिपोर्टिंग संरचना कवरेज एवं आंतरिक अंकेक्षण की आवृत्ति सहित, यदि कोई हो तो आंतरिक अंकेक्षण कार्य की उपयुक्तता की समीक्षा करना।
8. कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा उससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई हो तो आंतरिक अंकेक्षण तथा/अथवा अंकेक्षक के साथ विचार विमर्श करना।
9. ऐसे मामले जहाँ संदिग्ध, धोखाधड़ी अथवा अनियमितता अथवा आर्थिक प्रकृति के (मेटिरियल नेचर) के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता है तथा बोर्ड को रिपोर्टिंग करने के मामले में आंतरिक अंकेक्षकों/अंकेक्षकों एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच की उपलब्धियों की समीक्षा करना।
10. अंकेक्षण की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के बारे में तथा इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट ऑडिट विचार-विमर्श, ऑडिट कामनसेंस के पहले सांविधिक अंकेक्षण के साथ विचार-विमर्श करना।
11. व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म की क्रियाशीलता की समीक्षा करना।
12. सी एंड ए जी ऑडिट के अंकेक्षण अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
13. स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के बीच सम्पर्क हेतु खुला मंच उपलब्ध कराना।
14. कंपनी के सभी संबंधित पार्टी मामलों की समीक्षा

करना तथा अनुमोदित करना। इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण समिति एक सदस्य को नामित कर सकता है, जो इन्स्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में वर्णित पार्टी ट्रांजेक्शन से संबंधित पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

15. कवरेज, अनावश्यक प्रयास में कमी तथा सभी आडिट संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल की संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु ऑडिट प्रयासों के स्वतंत्र ऑडिटर समन्वयन के साथ पुनरीक्षण करना।
16. कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं संबंधित उपलब्धियों तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों की अनुशंसाएँ तथा प्रबंधन प्रत्युत्तर के साथ अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए अथवा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण के दौरान सामना की गई कठिनाइयों, महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ एवं आंतरिक अंकेक्षक सहित इसका दायित्व प्रबंधन पर भी है।
17. अपेक्षित सूचना की अधिकता या क्रिया-कलापों की संभावना पर किसी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण कार्य के दौरान पायी गई किसी कठिनाइयों तथा पूर्व के अंकेक्षण की अनुशंसाओं की स्थिति सहित विवेच्य वर्ष के दौरान महत्वपूर्व निष्कर्षों के लिए प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षण तथा स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ विचार-विमर्श करना तथा समीक्षा करना।
18. डिपोजिटर्स, डिर्वेचर धारकों, शेयर होल्डरों (घोषित लाभांश के नन पेमेंट के मामले में) को भुगतान में पर्याप्त त्रुटि के कारणों का पता लगाना।
19. पब्लिक अंडरटेकिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट (कोपू) पर गठित कमेटी की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई का अनुसरण कर समीक्षा करना।
20. अंकेक्षण कमेटी के विचाराधीन विषयों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को सम्पादित करना।

घ) अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ:

अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ निम्नलिखित के अनुरूप होगी:

1. विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधियों की जाँच करना।
2. किसी भी कर्म से सूचना माँगना।
3. बाह्य कानूनी तथा व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
4. यदि विचार करना आवश्यक हो तो संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
5. व्हिसिल ब्लोअर्स की रक्षा करना।
6. अंकेक्षकों की स्वतन्त्रता पर बल देते हुए हितों के टकराव को रोकना।
7. आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।

ड) अंकेक्षण समिति द्वारा सूचना की समीक्षा:

अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करेगी:

- i. वित्तीय स्थिति तथा कार्य के परिणामों पर प्रबंधन के साथ मिलकर विचार-विमर्श तथा विश्लेषण।
- ii. प्रबंधन द्वारा सुपुर्द पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण।

- iii. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा जारी कमियों पर आंतरिक नियंत्रण का पत्र/प्रबंधन का पत्र।
- iv. आंतरिक नियंत्रण की कमजोरियों से संबंधित आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट।
- v. मुख्य आंतरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा पदच्युति को अंकेक्षण समिति के समक्ष रखना तथा,
- vi. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाणन/घोषणा।

1.10 गठन:

लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं और इसका नेतृत्व एक सरकारी अंशकालिक निदेशक करता है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1	श्री मुकेश अग्रवाल	अध्यक्ष	सरकारी अंशकालिक निदेशक
2	श्री मारापल्ली वेंकटेश्वरलु	सदस्य	सरकारी अंशकालिक निदेशक
3	श्री शंकर नागाचारी	सदस्य	कार्यकारी निदेशक
4	श्री अजय कुमार	सदस्य	कार्यकारी निदेशक

ऑडिट कमेटी की बैठक में जीएम (वित्त), विभागाध्यक्ष (आईएडी) और सांविधिक लेखा परीक्षकों को आमंत्रित किया जाता है। सीएफओ स्थायी आमंत्रित व्यक्ति है और कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। समिति को आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग ऑडिट कमेटी की बैठक आयोजित करने और संचालन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

बैठक एवं उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 25.04.2024, 25.06.2024, 22.07.2024, 23.08.2024, 13.09.2024, 01.10.2024, 20.10.2024, 20.01.2025, 24.02.2025 और 25.03.2025 को क्रमशः 10 (दस) बैठकें आयोजित की गईं। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों द्वारा भाग लेने का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक के नाम	उनके कार्यावधि के दौरान आयोजित अंकेक्षण समिति की बैठकों की संख्या	अंकेक्षक समिति की बैठक में उपस्थिति की संख्या
कार्यकारी निदेशक			
1.	श्री शंकर नागाचारी	10	08
2.	श्री अजय कुमार	03	02
3.	श्री सतीश झा	07	07
अंशकालिक सरकारी निदेशक			
4.	श्री मुकेश अग्रवाल	03	03
5.	श्री मारापल्ली वेंकटेश्वरलु	02	02
6.	डॉ. बी. वीरा रेड्डी	04	04
7.	श्री अजितेश कुमार	07	07

1.11 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

बोर्ड ने 30.12.2015 को आयोजित अपनी 191 वीं बोर्ड बैठक में सीएमपीडीआईएल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया।

क) गठन

दिनांक: 09.06.2020 को आयोजित 234वीं बोर्ड की बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1	श्रीमती अलका पांडा	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
2	डॉ. कृष्ण चंद्र पांडे	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
3	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
4	श्री मुकेश चौधरी	सदस्य	सरकारी अंशकालिक निदेशक
5	श्री एस.के.गोमस्ता	स्थायी आमंत्रित	कार्यकारी निदेशक

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा विभागाध्यक्ष (कार्मिक एवं प्रशासनिक) समिति के नोडल अधिकारी होंगे, जो समिति को सभी सेवाएं प्रदान करेंगे।

ख) बैठक एवं उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

1.12 अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 तक निदेशकों का पारिश्रमिक :

कंपनी के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सभी पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों के नियम और शर्तें तथा पारिश्रमिक कंपनी/कोल इंडिया लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं।

क) कार्यकारी निदेशक

वित्तीय वर्ष अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 के लिए कंपनी के कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:
(आंकड़ा रुपये में)

नाम	पद का नाम	सकल वेतन और महंगाई भत्ते	भत्ते (मूल भत्ते का 35% + अन्य भत्ते)	एचआरए	सीएमपीएफ नियुक्ता का अंशदान (पीएफ + पेंशन और सीआईएल)	अवकाश नकदीकरण	पीआरपी एडवांस / पीआरपी	उपहार	चिकित्सा के खर्च	उपहार कार्ड	कुल
श्री मनोज कुमार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	42,94,028.85	10,24,967.30	-	12,88,208.66	-	27,60,219.00	-	77,349.00	15,000.00	94,59,772.81
श्री एस. नागाचारी	निदेशक (टी)	41,62,647.31	9,93,582.92	-	12,48,794.19	3,48,243.90	25,70,325.14	-	80,321.37	15,000.00	94,18,914.83
श्री अजय कुमार	निदेशक (टी)	41,61,795.25	9,93,416.20	-	12,48,538.58	6,63,074.72	11,78,736.00	-	67,082.70	15,000.00	83,27,643.45
श्री सतीश झा	निदेशक (टी)	30,39,558.70	7,30,849.00	-	9,11,867.61	-	20,36,368.00	-	54,357.00	15,000.00	67,88,000.31
श्री अच्युत घटक	निदेशक (टी)	33,09,499.50	7,93,232.95	-1,81,399.50	9,92,849.85	-	18,64,258.00	-	2,278.00	15,000.00	67,95,718.80
TOTAL		1,89,67,529.61	45,36,048.37	-1,81,399.50	56,90,258.88	10,11,318.62	1,04,09,906.14	-	2,81,388.07	75,000.00	4,07,90,050.19

ख) अंशकालिक सरकारी निदेशक

सीएमपीडीआईएल द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है:-

1. श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (वित्त) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के नामित निदेशक हैं और उनका पारिश्रमिक कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा भुगतान किया जा रहा है।
2. श्री मारापल्ली वेंकटेश्वरलू, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। उनका पारिश्रमिक कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।

1.13 वार्षिक आम बैठकें:-

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	2021-22 47वीं वार्षिक आम बैठक	2022-23 48वीं वार्षिक आम बैठक	2023-24 49वीं वार्षिक आम बैठक
बैठक की तिथि	21.07.2022	21.07.2023	05.07.2024
समय	04:00 अपराह्न	10:45 पूर्वाह्न	03:00 अपराह्न
कार्यक्रम का स्थान	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची, झारखंड - 834008	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची, झारखंड - 834008	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची, झारखंड - 834008
विशेष संकल्प	शून्य	शून्य	शून्य

1.14 असाधारण आम बैठक

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित असाधारण आम बैठक का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
तारीख	शून्य	शून्य	शून्य
समय			
कार्यक्रम का स्थान			

1.15 प्रकटीकरण (डिसक्लोजर):

• भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन:

कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों या वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है, जिससे कंपनी के हितों में व्यापक रूप से टकराव की संभावना हो।

सम्बद्ध पार्टी सहित किसी संविदा या व्यवस्था के संबंध में वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक में कोई एजेंडा पेश नहीं किया गया।

संबंधित पार्टी के लेन-देन संबंधि नीति के अनुसार किसी भी दो सरकारी कंपनी तथा नियंत्रक कंपनी एवं उसकी अनुषंगी कंपनी के बीच लेन-देन में छूट है।

धारा 188(1) के तहत पार्टी से संबंधित या अरेंजमेंट को **परिशिष्ट- VI** में संलग्न किया जाता है।

• कंपनी द्वारा नियमों/कानून के अनुपालन का विस्तृत विवरण:

कंपनी, कंपनी पर लागू विभिन्न कानूनों के अनुपालन की निगरानी कर रही है और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन, किसी भी प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर लगाए गए जुर्माने, प्रतिबंध के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट कंपनी के संज्ञान में नहीं लाई गई है।

- **व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसार अंकेक्षण समिति तक पहुँच:**

यह नीति कर्मचारियों को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध, धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सूचना प्रबंधन को तथा लेखा परीक्षा समिति को देने का अवसर प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।

व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसार किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया है तथा वर्ष के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

- **कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देशों का अनुपालन**

निदेशक मंडल, अंकेक्षण समिति, प्रकटीकरण, कोड आफ कंडक्ट इत्यादि के संबंध में इन दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है। तथापि, पारिश्रमिक समिति, अनुषंगी कंपनियों, प्रशिक्षण नीति इत्यादि पर दिशा-निर्देशों का अनुपालन कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा किया जाता है, इसका अनुपालन सीएमपीडीआईएल द्वारा भी किया जाता है। कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पूर्णकालिक कंपनी के अंकेक्षक से एक प्रमाण-पत्र इसके साथ **परिशिष्ट-III** में संलग्न है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान और डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशक की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति के लिए कोयला मंत्रालय जो नियुक्ति प्राधिकारी है को इससे अवगत करा दिया है।

- **इन्टीग्रीटी पैक्ट एवं आईईएम**

कंपनी के पास अपने व्यापारिक लेन-देन, संविदा, प्राप्ति प्रक्रिया में प्रबंधन में पादर्शिता संवृद्धि पर जोर देते हुए इंटिग्रीटी पैक्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल

इंडिया (टीआईआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया हुआ है। इस समझौता संलेख (एमओयू) के अंतर्गत कंपनी अपने सभी प्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) तथा वर्क कांटेक्ट कार्यों में इंटिग्रीटी पैक्ट कार्यान्वित करने हेतु वचनबद्ध है। दो स्वतंत्र बाह्य मोनिटर्स केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से ही टीआईआई द्वारा नामजद व्यक्ति इसकी गतिविधियों का मॉनीटर करते हैं। इन्टीग्रेटी पैक्ट ने ट्रस्ट स्थापित कर स्थापना प्रणाली एवं प्रक्रिया को सशक्त किया है तथा जिसे सीवीसी का पूरा समर्थन प्राप्त है।

- **सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण**

कंपनी के अध्यक्ष तथा महाप्रबंधक(वित्त)/सीएफओ द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को “सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण” प्रदान कर दिया है जिसे डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट के **परिशिष्ट-II** के रूप में लगाया गया है।

- **निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता (कोड आफ कंडक्ट):**

कंपनी के निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे सभी संबंधित व्यक्तियों के मध्य परिचालित कर दिया गया है, तथा कंपनी के इंटरनेट पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक तथा वरीय प्रबंधन कार्मिक ने कंपनी के आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है।

- **किए गए खर्च का ब्यौरा:**

लेखा पुस्तकों में ऐसे व्यय की कोई भी मद नहीं दर्शाई गई है, जो व्यवसाय के उद्देश्य से न हो, तथा ऐसे व्यय भी नहीं दर्शाए गए हैं, जो व्यक्तिगत प्रकृति के हों तथा निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हों, तथा कंपनी के लेखा परीक्षक ने ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं दी है।

• राष्ट्रपति का निर्देश:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीएमपीडीआईएल के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रेसिडेंसियल निर्देश जारी नहीं किया गया है।

1.16 संचार के साधन:

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट आम बैठक तथा डिसक्लोजर अपने वेबसाइट, कार्यालयी पत्रिका **"गोंदवाना भारती"**, **"माइन्टेक"**, प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा स्थानीय दैनिक के माध्यम से अपने शेयर होल्डरों के साथ संप्रेषण करती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्ट एवं कंपनी का तिमाही परिणाम तथा महत्वपूर्ण घटनाओं को कंपनी की वेबसाइट यानि www.cmpdi.co.in पर उपलब्ध करा दिया गया। कंपनी से संबंधित अद्यतन जानकारी तथा घोषणाएँ कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। कंपनी की उपलब्धियों से आम लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है।

1.17 लेखापरीक्षण आपत्ति

कंपनी का हमेशा यह प्रयास रहता है कि वह बिना किसी शर्त के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करे।

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की टिप्पणियों को परिशिष्ट-VII में संलग्न किया गया है।

1.18 बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण:

कंपनी के व्यवसाय से संबंधित सभी मामले, इसके संबंधित जोखिम तथा कंपनी की भावी रणनीति आदि के सार (संक्षिप्त विवरण) से निदेशक-मंडल को पूर्णतः अवगत करा दिया जाता है।

सभी कार्यकारी निदेशक संबंधित क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता तथा अनुभव के आधार पर संबंधित कार्य क्षेत्र के प्रमुख होते हैं। वे कंपनी के बिजनेस माडल तथा जोखिमों से अवगत होते हैं। अंशकालिक निदेशक भी कंपनी के बिजनेस मॉडल से पूर्णतः वाकिफ होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को निगमित शासन के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया जाता है। सभी सरकारी निदेशकों की कोल इंडिया लिमिटेड की पॉलिसी के अनुसार भारत और विदेश दोनों के लिए स्पॉन्सर किया जाता है। कंपनी में नव-नियुक्त निदेशकों को कंपनी के कंस्टीच्यूशन, विजन एवं मिशन स्टेटमेंट, मुख्य क्रिया-कलाप, बोर्ड की प्रक्रिया/पद्धति, रणनीतिक दिशा-निर्देश के विस्तृत प्रजेन्टेशन, विचार-विमर्श आदि के माध्यम से पूर्णतः अवगत कराया जाता है।

1.19 व्हिसिल ब्लोअर नीति

कंपनी के कर्मचारियों के नैतिक आचरण को सशक्त करने तथा विभिन्न हितधारकों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए सीएमपीडीआईएल में 2011-12 में व्हिसिल ब्लोअर नीति लागू की गई तथा दिनांक 8.11.2011 को आयोजित 163वीं बैठक में बोर्ड को इससे अवगत करा दिया गया। यह नीति वास्तविक या संदिग्ध अनैतिक आचरण, कंपनी की आचार संहिता के साथ धोखाधड़ी या इसके उल्लंघन के मामले को प्रबंधन के पास रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर प्रदान करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) और (10) सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 22 के अनुसार कंपनी ने **"व्हिसिल ब्लोअर नीति"** तैयार की थी। यह प्रतिशोध या उत्पीड़न से कर्मचारियों को बचाने में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है।

तथापि, इस नीति के अंतर्गत व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए खराब कार्य निष्पादन या कदाचार, जो व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए स्पष्टीकरण से अलग हो, के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई को इसके तहत संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

1.20 जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन दिनांक: 02.02.16 को आयोजित सीएमपीडीआईएल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर की 192वीं बैठक में किया गया तथा दिनांक: 29.01.2024 को आयोजित बोर्ड की 274वीं बैठक में इसे पुनर्गठित किया गया।

क. गठन:

जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं, जिसकी अध्यक्षता कार्यकारी निदेशक करते हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1	श्री शंकर नागाचारी	अध्यक्ष	कार्यकारी निदेशक
2	श्री अजय कुमार	सदस्य	कार्यकारी निदेशक
3	श्री अच्युत घटक	सदस्य	कार्यकारी निदेशक

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और महाप्रबंधक (उत्खनन/एस एंड टी) समिति को सभी सेवाएं प्रदान करने वाली समिति के नोडल अधिकारी होंगे।

ख. बैठक एवं उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांक: 18.12.2024 को एक बैठक हुई। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थित सदस्य निम्नलिखित हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	बैठक में उपस्थिति
1	श्री शंकर नागाचारी	अध्यक्ष	1
2	श्री अजय कुमार	सदस्य	1
3	श्री अच्युत घटक	सदस्य	1

1.21 इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाव के लिए आंतरिक प्रक्रिया और आचार संहिता:

होल्लिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम और कोल इंडिया लिमिटेड की प्रतिभूतियों से निपटने के लिए आंतरिक प्रक्रिया और आचार संहिता को अपनाया है, जिसका उद्देश्य अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के आधार पर किसी अंदरूनी व्यक्ति द्वारा सीआईएल के शेयरों की खरीद और / या बिक्री को रोकना है। यह संहिता (केस) सीएमपीडीआईएल द्वारा भी अपनाई गई है। इस संहिता के तहत वैसे इनसाइडरों को डिजिग्रेटेड कर्मचारी का नाम दिया गया है, जो ट्रेडिंग बिन्टों के बंद होने के दौरान सीआईएल के शेयरों से डील करने से रोके जाते हैं। विहित सीमा से अधिक प्रतिभूति डील करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। जैसा कि संहिता में परिभाषित है, सभी डिजिग्रेटेड कर्मचारी को नियमित रूप से संबंधित जानकारी प्रकट करना आवश्यक है। इस कोड के लिए कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नामित किया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आंतरिक प्रक्रिया तथा आचार संहिता को भी सीएमपीडीआईएल के वेब साइट के इन्ट्रानेट पर डाल दिया गया है।

1.22 निदेशकों की जवाबदेही

आगामी वित्तीय वर्ष आरंभ होने के पहले डीपीई दिशा-निर्देश में दिए गए प्रावधान के अनुसार सीएमपीडीआईएल के प्रबंधन तथा कोल इंडिया/कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौता के अंतर्गत यह कंपनी वर्ष के प्रारंभ में सेट किए गए टारगेट को हासिल करने के लिए वचनबद्ध है तथा इसमें निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वर्ष के अंत में सीएमपीडीआईएल के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना निहित है। यह “फाइव प्वाइंट स्केल” तथा “क्राइटेरिया वेट” की पद्धति को अपनाकर कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप “कम्पोजिट स्कोर” की गणना की जाती है। “कम्पोजिट स्कोर”, कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से डीपीई तथा प्रशासनिक मंत्रालय को अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है।

समझौता ज्ञापन सिस्टम दक्षतापूर्वक काम करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वित्तीय एवं गैर-वित्तीय दोनों प्रकार के (डायनेमिक, क्षेत्र विशिष्ट तथा उद्यम विशिष्ट पारामीटर) पारामीटरों की विविधता है। इस प्रक्रिया से दीर्घकालीन उद्देश्य तथा संपूर्ण विकास प्राप्त करने में अधिक मदद मिलती है। संपूर्ण प्रक्रिया से स्टेक होल्डरों के प्रति पारदर्शिता तथा उत्तदायित्व भी सुनिश्चित किया जाता है।

1.23 निगमित शासन के अनुपालन की त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति

अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को सीपीएसई द्वारा रिपोर्ट करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति का विकास किया गया है। इसके अनुपालन में सीएमपीडीआईएल द्वारा कोयला मंत्रालय को नियमित रूप से तथा समय पर तिमाही रिपोर्ट भेजी जाती रही है।

1.24 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधान के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2025 को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित हैं:

श्री मनोज कुमार	:	सीईओ
श्री शंकर नागाचारी	:	निदेशक
श्री अजय कुमार	:	निदेशक
श्री सुदीप दासगुप्ता	:	सीएफओ
श्री अभिषेक मूंधरा	:	कंपनी सचिव

1.25 सीएमपीडीआईएल में सीएसआर पहल

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तथा सस्टेनेबिलिटी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण के अनुकूल ढंग से कार्य, जो पारदर्शी तथा नैतिक हो, करने के लिए अपने स्टेक होल्डरों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता है। सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी क्षमता निर्माण, सामुदायिक अधिकारिता, समावेशी, सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, तथा समाज के सीमांत तथा अर्ध-सुविधायुक्त तबकों की उन्नति आदि पर विशेष जोर देता है। कंपनी ने दिनांक: 27.02.2014 को मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन तथा डीपीई की गाइड लाइन और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 तथा उसके तहत बने नियम के अनुसार स्वयं की सीएसआर नीति बनाई है।

सीएसआर और संधारणीयता, खनन उद्योग के लिए न केवल जोखिम लाती है, बल्कि अवसरों के एक समूह का भी सृजन करती है। सीएसआर और संधारणीयता कंपनियों को संचालन के लिए अपना सामाजिक लाइसेंस सुरक्षित करने में मदद कर सकती है, और संधारणीय विकास में सार्थक तरीके से योगदान दे सकती है। सीएमपीडीआईएल दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक संचालन में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करके सीएसआर और संधारणीयता के प्रति व सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सीएमपीडीआईएल में दो स्तरीय निर्णय लेने वाली समितियाँ गठित की गई हैं।

अपने व्यापार की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखकर, सीएमपीडीआईएल ने वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी क्रिया-कलाप प्रारंभ किया है, जिसे रिपोर्ट के भाग “ख” में देखा जा सकता है।

1.26 वार्षिक रिटर्न

कंपनी का वार्षिक रिटर्न हमारे वेबसाइट लिंक <https://www.cmpdi.co.in/annualrpt.php> पर उपलब्ध है।

1.27 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय और आऊटगोः.

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय और आऊटगो को निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है (परिशिष्ट- I)।

1.28 बोर्ड की समिति तथा निदेशकों के कार्य-निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन:

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 की धारा 134(3) (पी) और नियम 8 के अनुसार, किसी सूचीबद्ध कंपनी और प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी के मामले में, जिसकी

चुकता शेयर पूंजी 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, जिसकी गणना पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में की गई है, उसे अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में एक विवरण शामिल करना होगा, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि बोर्ड द्वारा उसके स्वयं के तथा उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के निष्पादन का किस प्रकार औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया गया है।

सीएमपीडीआईएल की चुकता शेयर पूंजी 142.80 करोड़ रुपये है और यह एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है तथा किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए कंपनी को अपने बोर्ड, समिति और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण बोर्ड द्वारा अपने और समितियों तथा व्यक्तियों के प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया गया। हालाँकि, वार्षिक मूल्यांकन उस नीति के आधार पर किया जाएगा जिसे कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के लिए तैयार किए जाने की उम्मीद है।

भाग: ख

वार्षिक प्रदर्शन अवलोकन

1.0 भूवैज्ञानिक गवेषण और ड्रिलिंग

- वित्त वर्ष 2024-25 में, सीएमपीडीआईएल ने झारखंड राज्य में एक बॉक्साइट ब्लॉक में ड्रिलिंग के साथ-साथ सीआईएल, गैर-सीआईएल, प्रमोशनल, एनएमईटी और कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने कोयला गवेषण प्रयासों को जारी रखा।

सीआईएल ब्लॉकों में अन्वेषण का उद्देश्य सीआईएल की सहायक कंपनियों की परियोजना नियोजन और उत्पादन सहायक आवश्यकताओं में सहायता करना था। गैर-सीआईएल और परामर्शदात्री ब्लॉकों में उद्देश्य इच्छुक हितधारकों और डेवलपर्स को कोयला ब्लॉकों की नीलामी और आवंटन प्रक्रिया का समर्थन करना था। इसके अतिरिक्त, प्रमोशनल और एनएमईटी-वित्तपोषित गवेषण प्रयास नए पहचाने गए, पहले से अनदेखे क्षेत्रों तक सीमित थे, जिसका उद्देश्य बाद में विस्तृत गवेषण करना और इन ब्लॉकों को भविष्य की नीलामी या आवंटन के लिए तैयार करना था।

- सीएमपीडीआईएल ने पिछले कुछ वर्षों में ड्रिलिंग प्रदर्शन और उत्पादकता में लगातार वृद्धि दिखाई है। 2007-08 में ड्रिलिंग 2.09 लाख मीटर से बढ़कर 2011-12 में 4.98 लाख मीटर हो गई, जबकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभागीय उत्पादकता 374 मीटर प्रति ड्रिल प्रति माह से बढ़कर 416 मीटर हो गई। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह प्रवृत्ति जारी रही, जो 2016-17 में 11.26 लाख मीटर तक पहुंच गई, जबकि उत्पादकता बढ़कर 583 मीटर प्रति ड्रिल प्रति माह हो गई। 2017-18 में, सीएमपीडीआई ने 13.66 लाख मीटर की अपनी अब तक की सबसे अधिक ड्रिलिंग की। हालांकि केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कम फंडिंग के कारण 2022-23 में ड्रिलिंग घटकर 6.85 लाख मीटर रह गई, लेकिन 2023-24 में यह

8.62 लाख मीटर (26% वृद्धि) और 2024-25 में 10.12 लाख मीटर (17% वृद्धि) हो गई, जिससे विभागीय उत्पादकता प्रति माह प्रति ड्रिल 635 मीटर पर पहुंच गई। ये उपलब्धियां उपकरणों के आधुनिकीकरण, उच्च प्रदर्शन वाली ड्रिलिंग तकनीकों को अपनाने और बेहतर संसाधन प्रबंधन के माध्यम से संभव हुई हैं। इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना और एनएमईटी के तहत निरंतर समर्थन महत्वपूर्ण है।

सीएमपीडीआईएल के 60 विभागीय ड्रिलों में से 26 ड्रिल हाइड्रोस्टैटिक और 34 ड्रिल मैकेनिकल हैं।

1.1 2024-25 में ड्रिलिंग प्रदर्शन :

- सीएमपीडीआईएल ने 59 सीआईएल, गैर-सीआईएल, प्रमोशनल और कंसल्टेंसी ब्लॉकों में विस्तृत और क्षेत्रीय गवेषण के लिए अपने विभागीय संसाधनों को तैनात किया। इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल ने अन्य 6 सीआईएल खदानों में उत्पादन समर्थन ड्रिलिंग भी की है। एमईसीएल ने समझौता ज्ञापन के तहत कुल 44 सीआईएल, गैर-सीआईएल, प्रमोशनल, एनएमईटी और कैप्टिव ब्लॉकों में अपने संसाधनों को तैनात किया, जिसमें 4 लिग्नाइट ब्लॉक और 1 बॉक्साइट ब्लॉक शामिल हैं। डीजीएम असम और डीजीएम नागालैंड ने 3 प्रमोशनल ब्लॉकों में संसाधनों को तैनात किया। इसके अलावा, नौ संविदा एजेंसियों को भी 30 सीआईएल, गैर-सीआईएल, प्रमोशनल और एनएमईटी ब्लॉकों में गवेषण के लिए संसाधन तैनात किए गए थे।
- 2024-25 में, सीएमपीडीआईएल ने अपनी संविदात्मक और एमओयू एजेंसियों के साथ मिलकर 136 ब्लॉकों में गवेषणात्मक ड्रिलिंग की, जिसमें 131 कोयला ब्लॉक, 4 लिग्नाइट ब्लॉक और 1 गैर-कोयला ब्लॉक शामिल थे। ये ब्लॉक 15 राज्यों में फैले हुए थे और विभिन्न कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रों में वितरित किए गए थे, जो देश भर में व्यापक संसाधन मूल्यांकन के लिए सीएमपीडीआईएल की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

136 ब्लॉकों में से: 45 सीआईएल ब्लॉक थे, 42 विस्तृत गवेषण के लिए गैर-सीआईएल ब्लॉक थे, 32 क्षेत्रीय गवेषण के लिए प्रमोशनल ब्लॉक थे, 8 निजी/परामर्श ब्लॉक थे, 4 एनएमईटी-वित्त पोषित कोयला ब्लॉक थे, 4 लिग्नाइट ब्लॉक थे (2 गैर-सीआईएल और 2 प्रमोशनल), और बॉक्साइट का 1 गैर-कोयला ब्लॉक एनएमईटी वित्त पोषण के तहत खोजा गया था।

98 ब्लॉकों में विस्तृत गवेषण किया गया तथा 38 ब्लॉकों में क्षेत्रीय गवेषण किया गया।

इसके अतिरिक्त, सीआईएल की 6 अन्य खदानों में भी उत्पादन सहायता ड्रिलिंग का कार्य किया गया।

2024-25 में अन्वेषण ब्लॉकों का राज्यवार वितरण इस प्रकार था: छत्तीसगढ़ (27), मध्य प्रदेश (30), महाराष्ट्र (21), झारखंड (20), पश्चिम बंगाल (10), ओडिशा (9), असम (8), नागालैंड (4), मिजोरम (1), और तेलंगाना (1) कोयला गवेषण के लिए। लिग्नाइट के लिए, राजस्थान (3) और तमिलनाडु (1) ने गवेषण ब्लॉकों की मेजबानी की। इसके अतिरिक्त, झारखंड में एक गैर-कोयला ब्लॉक की खोज की गई।

प्रमुख कोयला क्षेत्रों में कोयला ब्लॉकों के वितरण में शामिल हैं: वर्धा घाटी (17), सोहागपुर (12), मांड-रायगढ़ (10), सिंगरौली (10), रानीगंज (9), उत्तरी करणपुरा (8), पेंच-कन्हान-तवा घाटी (8), राजमहल-बीरभूम (7), सोनहत (7), कोरबा (5), आईबी घाटी (5), मकुम (4), कैम्पटी (4), तालचेर (4), और मिकिर हिल्स (4)। अन्य कोयला क्षेत्रों के अलावा बिश्रामपुर, तातापानी-रामकोला और औरंगा से भी छोटा योगदान मिला, जिनमें से प्रत्येक में 2 ब्लॉक थे।

सीएमपीडीआईएल ने एनएमईटी के वित्तपोषण के तहत राजस्थान के बीकानेर और नागौर क्षेत्रों तथा तमिलनाडु के रामनाद में स्थित चार लिग्नाइट ब्लॉकों के साथ-साथ झारखंड में एक गैर-कोयला ब्लॉक में भी गवेषण कार्य किया।

ड्रिलिंग प्रदर्शन के संदर्भ में, सीएमपीडीआईएल ने वित्त वर्ष 2024-25 में 10.115 लाख मीटर की प्रभावशाली ड्रिलिंग उपलब्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि सीएमपीडीआईएल के मजबूत परिचालन ढांचे, ड्रिलिंग उपकरणों के आधुनिकीकरण और केंद्रीय क्षेत्र योजना और एनएमईटी के तहत निरंतर वित्त पोषण सहायता को दर्शाती है।

2024-25 में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग का समग्र प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

(आंकड़े लाख मीटर में)

एजेंसी	वित्त वर्ष 2024-25 में ड्रिलिंग प्रदर्शन			पिछले वर्ष की उपलब्धि: वित्त वर्ष 2023-24	वृद्धि (%)
	लक्ष्य (एमओयू)	उपलब्धि	उपलब्धि (%)		
I. विभागीय (सीआईएल, गैर-सीआईएल, प्रचारात्मक और परामर्श)					
I. विभागीय	4.200	4.638	110%	4.317	7%
II. आउटसोर्सिंग (सीआईएल, गैर-सीआईएल, प्रमोशनल, कंसल्टेंसी और एनएमईटी)					
राज्य सरकार	0.012	0.023	194%	0.022	7%
एमईसीएल-एमओयू	3.375	3.594	106%	2.837	27%
टेंडरिंग	2.413	1.860	77%	1.449	28%
कुल आउटसोर्सिंग:	5.800	5.477	94%	4.308	27%
सकल योग	10.000	10.115	101%	8.625	17%
2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण (लाइन किमी)	400.00	437.95	109%	234.57	87%

गवेषण कार्यों में आउटसोर्स और विभागीय ड्रिलिंग गतिविधियों दोनों में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा:

लगातार स्थानीय बाधाओं के कारण कई ब्लॉकों में आउटसोर्स किए गए गवेषण प्रभावित हुए। इनमें झारखंड में आरागुंडी, बटुका, मंदार, पिपरवार फेज-1 के उत्तर, रायडीह, लालमटिया ए एंड बी के डिपसाइड और धामनीपहाड़ ब्लॉक, छत्तीसगढ़ में गंगापुर और तौलीपाली ब्लॉक और राजस्थान में नागुरदा ईस्ट लिग्नाइट ब्लॉक शामिल हैं। इन मुद्दों के कारण पूरे साल देरी और परिचालन में व्यवधान हुआ।

कपासडांगा में 2 दिन के ठहराव के कारण दिसंबर 2024 के दौरान आरआई-1 क्षेत्र में विभागीय ड्रिलिंग प्रभावित हुई। भरकटा ब्लॉक (पश्चिम बंगाल) में स्थानीय प्रशासनिक मुद्दों के कारण विवाद उत्पन्न हुआ।

इसके अतिरिक्त, आरआई-III क्षेत्र (झारखंड) में स्थानीय बाधाओं के कारण 2024-25 में ड्रिलिंग कार्यों के 31 दिनों के बंद होने से विभागीय गतिविधियां गंभीर रूप से बाधित हुई।

इन सबके बावजूद, विभागीय ड्रिलिंग ने उम्मीदों से बढ़कर अपने लक्ष्य का 110% हासिल किया, जिसमें 4.200 लाख मीटर के लक्ष्य के मुकाबले 4.638 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि दर्ज की गई। विभागीय ड्रिलिंग ने लगभग **635 मीटर/ड्रिल/माह** की औसत परिचालन ड्रिल उत्पादकता दर्ज की।

आउटसोर्स एक्सप्लोरेशन ने 5.477 लाख मीटर ड्रिलिंग हासिल की, जो पिछले साल की 4.308 लाख मीटर की उपलब्धि से 27% की मजबूत वृद्धि दर्शाती है। उल्लेखनीय है: राज्य सरकारों ने अपने लक्ष्य का 194% हासिल किया। एमईसीएल ने पिछले वर्ष की तुलना में 27% की वृद्धि के साथ 106% हासिल करते हुए मजबूत प्रदर्शन किया। टेंडर-आधारित संचालन ने 77%

हासिल किया, जो साल-दर-साल 28% की वृद्धि दर्शाता है।

2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण घटक ने भी अपने लक्ष्य को पार कर लिया, तथा 437.95 लाइन किमी की उपलब्धि हासिल की, जो लक्ष्य का 109% है तथा पिछले वर्ष की तुलना में 87% की वृद्धि है।

• सीआईएल ब्लॉकों में ड्रिलिंग

2024-25 के दौरान, सीआईएल ब्लॉकों में कुल 2.82 लाख मीटर की विस्तृत ड्रिलिंग की गई, जिसमें विभिन्न गैर-एनईआर कोयला-असर वाले राज्यों के 45 ब्लॉक शामिल थे। प्रमुख योगदान सोहागपुर (0.75 लाख मीटर), कोरबा (0.55 लाख मीटर), रानीगंज (0.54 लाख मीटर) और उत्तरी करनपुरा (0.24 लाख मीटर) जैसे प्रमुख कोयला क्षेत्रों से आया, जो उच्च संसाधन क्षमता वाले क्षेत्रों पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है।

कुल ड्रिलिंग में से 2.42 लाख मीटर की ड्रिलिंग विभागीय तौर पर सीएमपीडीआई द्वारा 33 ब्लॉकों में की गई। एमईसीएल ने 10 ब्लॉकों में 0.33 लाख मीटर की ड्रिलिंग की, जबकि मेसर्स एपीसी और मेसर्स एमटीसीएस जैसी निजी एजेंसियों ने साउथ करनपुरा और कैम्पटी कोयला क्षेत्रों के 2 ब्लॉकों में 0.07 लाख मीटर की ड्रिलिंग की।

• गैर-सीआईएल ब्लॉकों में ड्रिलिंग :

2024-25 के दौरान, केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत गैर-सीआईएल ब्लॉकों में कुल 4.46 लाख मीटर विस्तृत ड्रिलिंग की गई, जिसमें 45 ब्लॉक शामिल हैं - 5 उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में और 40 गैर-एनईआर कोयला और लिग्नाइट युक्त राज्यों में। एनईआर में, निजी एजेंसी मेसर्स एमएमपीएल द्वारा निष्पादित झांगशी देसाई, मकुम और मिकिर हिल्स में पांच कोयला ब्लॉकों में 0.18 लाख मीटर ड्रिलिंग पूरी की गई।

गैर-एनईआर क्षेत्रों में 4.28 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई, जिसमें 3.98 लाख मीटर ड्रिलिंग शामिल है। बीकानेर में 38 कोयला ब्लॉकों में 0.30 लाख मीटर और 2 लिग्नाइट ब्लॉकों में 0.30 लाख मीटर कोयला खनन हुआ। इसमें मुख्य योगदान मांड-रायगढ़, सिंगरौली, सोनहत, उत्तरी करणपुरा और सोहागपुर जैसे कोयला क्षेत्रों से आया।

ड्रिलिंग का कार्य सीएमपीडीआईएल (1.81 लाख मीटर), एमईसीएल (1.86 लाख मीटर) और विभिन्न निजी एजेंसियों (0.79 लाख मीटर) द्वारा किया गया, जिनमें मेसर्स एसडब्ल्यूपीई, मेसर्स एमएपीएल, मेसर्स एमटीसीएस, मेसर्स एमएमपीएल और मेसर्स केईएमएसपीएल शामिल हैं।

● प्रमोशनल ब्लॉक में ड्रिलिंग

वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रों में सीएमपीडीआईएल, एमईसीएल, निजी एजेंसियों और राज्य सरकारों सहित विभिन्न निष्पादन एजेंसियों द्वारा कुल 2.57 लाख मीटर प्रमोशनल (क्षेत्रीय) ड्रिलिंग की गई। प्रमोशनल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम ने देश भर के 33 ब्लॉकों को कवर किया, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में 8 ब्लॉक और गैर-एनईआर कोयला और लिग्नाइट युक्त राज्यों में 25 ब्लॉक शामिल हैं। सीएमपीडीआईएल ने न केवल 0.31 लाख मीटर विभागीय ड्रिलिंग को अंजाम देकर बल्कि एमईसीएल, डीजीएम असम, डीजीएम नागालैंड और निजी एजेंसियों द्वारा की गई अन्वेषण गतिविधियों की निगरानी करके भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में, 8 ब्लॉकों में कुल 0.20 लाख मीटर की ड्रिलिंग की गई। इस क्षेत्र के प्रमुख

अन्वेषण क्षेत्रों में 0.16 लाख मीटर के साथ मकुम (तीन ब्लॉक), 0.02 लाख मीटर के साथ मेलक-तुसांग (दो ब्लॉक), 0.014 लाख मीटर के साथ मिकिर हिल्स (दो ब्लॉक) और 0.005 लाख मीटर के साथ मिजोरम (एक ब्लॉक) शामिल हैं।

गैर-एनईआर क्षेत्रों में, 25 ब्लॉकों में कुल 2.37 लाख मीटर की ड्रिलिंग की गई, जिसमें 23 कोयला ब्लॉक और 2 लिग्नाइट ब्लॉक शामिल हैं। सोनहाट में 0.35 लाख मीटर, मांड-रायगढ़ में 0.32 लाख मीटर, वर्धा घाटी में 0.33 लाख मीटर और राजमहल-बीरभूम में 0.22 लाख मीटर की ड्रिलिंग में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। अन्य उल्लेखनीय योगदान पेंच कन्नन तवा घाटी (0.19 लाख मीटर), तातापानी-रामकोला (0.22 लाख मीटर), इब घाटी, रानीगंज, सोहागपुर, औरंगा और गोदावरी घाटी से आया। लिग्नाइट क्षेत्र में, नागौर और रामनाद में कुल 0.038 लाख मीटर की ड्रिलिंग की गई।

ड्रिलिंग ऑपरेशन कई एजेंसियों द्वारा किए गए। एमईसीएल ने 1.29 लाख मीटर का काम किया, जबकि निजी एजेंसियों ने सामूहिक रूप से 0.76 लाख मीटर का योगदान दिया। सीएमपीडीआईएल ने 0.31 लाख मीटर का काम किया, और डीजीएम असम और डीजीएम नागालैंड सहित राज्य विभागों ने 0.02 लाख मीटर का योगदान दिया। मेसर्स केईएमएसपीएल, मेसर्स एमएमपीएल, मेसर्स एपीसी, मेसर्स जियोटेक, मेसर्स एमएपीपी और मेसर्स भूशिल्प जैसी अन्य भागीदार एजेंसियों ने भी कार्यक्रम का समर्थन किया। सहयोगात्मक प्रयासों ने देश के विभिन्न कोयला और लिग्नाइट-युक्त क्षेत्रों में प्रमोशनल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया।

2024-25 में प्रमोशनल एक्सप्लोरेशन में सीएमपीडीआईएल का समग्र प्रदर्शन नीचे दिया गया है::

एजेंसी	वित्त वर्ष 2024-25 में प्रमोशनल ड्रिलिंग प्रदर्शन			पिछले वर्ष की उपलब्धि: वित्त वर्ष 2023-24	वृद्धि %
	लक्ष्य (एमओयू)	उपलब्धि	उपलब्धि (%)		
I. कोयला क्षेत्र					
क. सीएमपीडीआईएल (विभागीय)	0.320	0.314	98%	0.222	41%
ख. राज्य सरकारें					
i) डीजीएम-नागालैंड	0.010	0.020	201%	0.019	5%
ii) डीजीएम-असम	0.002	0.003	158%	0.003	21%
iii) डीएमआर-मेघालय	0.002	0.000	0%	0.003	-100%
योग राज्य सरकार	0.012	0.023	194%	0.022	7%
ग. एमईसीएल- समझौता ज्ञापन	0.895	1.256	140%	1.196	5%
घ. निविदा	0.883	0.936	106%	0.115	712%
ई. योग (आउटसोर्सिंग) (ख+ग+घ)	1.790	2.215	124%	1.333	66%
कुल कोयला (क+ई)	2.110	2.529	120%	1.555	63%
II. लिग्नाइट क्षेत्र					
क. एमईसीएल- समझौता ज्ञापन	0.090	0.038	43%	0.188	-80%
कुल लिग्नाइट (क)	0.090	0.038	43%	0.188	-80%
कुल प्रमोशनल	2.200	2.567	117%	1.743	47%

● कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों में ड्रिलिंग :

2024-25 के दौरान, कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों में कुल 0.19 लाख मीटर की विस्तृत ड्रिलिंग की गई। ड्रिलिंग में औरंगा, उत्तरी करनपुरा, कैम्पटी, राजमहल-बीरभूम, सिंगरौली, वर्धा घाटी और पश्चिम बोकारो जैसे प्रमुख कोयला क्षेत्रों के 8 ब्लॉक शामिल थे। औरंगा में 0.07 लाख मीटर और उत्तरी करनपुरा में 0.08 लाख मीटर के साथ उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई।

यह कार्य विभागीय और संविदात्मक दोनों एजेंसियों द्वारा किया गया। सीएमपीडीआई ने विभागीय ड्रिलिंग के माध्यम से 3 ब्लॉकों में 0.10 लाख मीटर की खुदाई पूरी की, जबकि एमईसीएल ने 5 ब्लॉकों में 0.10 लाख मीटर की खुदाई की। गवेषण ने भूवैज्ञानिक आश्वासन सुनिश्चित करके और भविष्य के संचालन के लिए खदान नियोजन का समर्थन करके कैप्टिव ब्लॉकों के विकास को आगे बढ़ाने में योगदान दिया।

● एनएमईटी वित्त पोषित ब्लॉकों में ड्रिलिंग :

2024-25 में, सीएमपीडीआईएल और इसकी आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा एनएमईटी फंडिंग के तहत 5 ब्लॉकों में कुल 0.075 लाख मीटर की विस्तृत ड्रिलिंग की गई, जो सभी गैर-एनईआर कोयला वाले राज्यों में स्थित हैं। इनमें से 4 कोयला ब्लॉकों में 0.072 लाख मीटर की ड्रिलिंग की गई, जबकि शेष 0.003 लाख मीटर की ड्रिलिंग 1 गैर-कोयला ब्लॉक में पूरी की गई।

कोयला ब्लॉकों में, वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र (0.065 लाख मीटर) और पेंच-कन्नन-तवा घाटी (0.007 लाख मीटर) में महत्वपूर्ण ड्रिलिंग की सूचना मिली। झारखंड राज्य में बॉक्साइट में गैर-कोयला ड्रिलिंग (0.003 लाख मीटर) की गई।

1.2 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट

- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, विस्तृत गवेषण गतिविधियों के माध्यम से अनुमानित 7.5 बिलियन टन कोयला संसाधनों को मापी गई (प्रमाणित) श्रेणी में जोड़ा गया है। यह वृद्धि लगभग 270 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किए गए कार्य पर आधारित थी, जिसे 21 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से प्रलेखित किया गया था।
- इसके अलावा, क्षेत्रीय (प्रचार) गवेषण के हिस्से के रूप में संकेतित और अनुमानित श्रेणियों के तहत लगभग 7.4 बिलियन टन कोयला संसाधनों का अनुमान लगाया गया है। ये अनुमान 9 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के माध्यम से रिपोर्ट किए गए लगभग 208 वर्ग किलोमीटर के गवेषण पर आधारित हैं।
- इसके अलावा, 1 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के माध्यम से संकेतित श्रेणी में लगभग 75 मिलियन टन लिग्नाइट संसाधन प्रमाणित किए गए हैं, जो लगभग 166 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करते हैं।
- झारखंड राज्य में 1 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के माध्यम से विभिन्न ग्रेड के 65 मिलियन टन शुद्ध इन-सीटू बॉक्साइट संसाधनों के साथ-साथ 19 मिलियन टन शुद्ध इन-सीटू एल्युमिनस लेटराइट संसाधनों की भी स्थापना की है। उल्लेखनीय रूप से, उसी ब्लॉक में टीआई₂ (टाइटेनियम डाइऑक्साइड) और वी₂ओ₅ (वैनेडियम पेंटोक्साइड) की उपस्थिति की भी रिपोर्ट की गई है।

1.3 हाइड्रोज्योलोजी

- एनओसी के लिए कुल 88 व्यापक जल विज्ञान रिपोर्ट और 90 भूजल मॉडलिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह खनन क्षेत्र के लिए सीडजीब्ल्यूए की राजपत्र अधिसूचना द्वारा सितंबर 2020 से प्रभावी वैधानिक रिपोर्ट है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ईआईए/ईएमपी तैयार करने के लिए 26 खनन परियोजनाओं की हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
- 2024-25 के दौरान पीजोमीटर / क्षति आकलन रिपोर्ट / भूवैज्ञानिक रिपोर्ट / परियोजना रिपोर्ट

/ ढलान स्थिरता रिपोर्ट / जलापूर्ति योजनाओं के लिए कुल 26 अन्य जल विज्ञान अध्ययन / अध्याय तैयार किए गए।

- एमओईएफ एंड सीसी, नई दिल्ली द्वारा सीआईएल (ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल और एनसीएल) की मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं के अनुपालन के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ क्षेत्रीय भूजल स्तर और गुणवत्ता निगरानी कार्य भी कर रहा है।
- **अन्य विशिष्ट कार्य/ बाहरी परामर्श कार्य / नए प्रकार के अध्ययन –**
 - एनसीएल कमांड क्षेत्र के वहन क्षमता अध्ययन के लिए हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान तैयार किया गया एक नया प्रकार का अध्ययन है।
 - गवेषण विभाग के हाइड्रोज्योलॉजी अनुभाग ने 2024-26 से भूजल मॉडलिंग रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसओपी सीजीडब्ल्यूए, नई दिल्ली के अनुसार मान्यता प्राप्त/ सूचीबद्ध विशेषज्ञों के साथ 03 समझौता ज्ञापन निष्पादित किए। प्रस्तुत कुल 90 जीडब्ल्यूएम रिपोर्टों में से, 44 जीडब्ल्यूएम रिपोर्ट विभागीय रूप से तैयार की गई हैं और शेष 46 जीडब्ल्यूएम रिपोर्ट वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान समझौता ज्ञापन सलाहकारों द्वारा तैयार की गई हैं।
 - हाइड्रोज्योलॉजी अनुभाग ने यूसीआईएल, झारखंड (यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड) की 03 खदानों के लिए रिपोर्ट तैयार की है और बाहरी परामर्श परियोजनाओं के रूप में सीजीडब्ल्यूए से सफलतापूर्वक एनओसी प्राप्त की है।
 - 22 मार्च 2025 को सीएमपीडीआईएल के गवेषण विभाग के हाइड्रोज्योलॉजी अनुभाग और आईएनसी-आईएच (भारतीय अध्याय-अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोज्योलॉजी एसोसिएशन) द्वारा संयुक्त रूप से एक

राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया जाएगा जिसमें 100 से अधिक प्रतिभागी और टेक्सास विश्वविद्यालय, अमेरिका और इसरो, भारत के प्रख्यात वक्ता शामिल होंगे।

1.4 भूभौतिकीय सर्वेक्षण

- **डाउनहोल भूभौतिकीय लॉगिंग:** गवेषण उद्देश्यों के लिए ड्रिल किए गए बोरहोल्स को भी जियोफिजिकल रूप से लॉग किया गया ताकि बोरहोल्स में पाए जाने वाले विभिन्न स्तरों की इन-सीटू जानकारी प्राप्त की जा सके। वर्ष 2024-25 के दौरान, इस उद्देश्य के लिए सीआईएल, गैर-सीआईएल, प्रमोशनल, एनएमईटी और कंसल्टेंसी परियोजनाओं में मल्टी-पैरामीट्रिक जियोफिजिकल लॉगिंग उपकरणों के साथ कुल 5.515 लाख मीटर जियोफिजिकल लॉगिंग की गई है। इसमें से लगभग 2.116 लाख मीटर जियोफिजिकल लॉगिंग 6 जियोफिजिकल लॉगिंग इकाइयों के माध्यम से विभागीय रूप से की गई और 3.399 लाख मीटर जियोफिजिकल लॉगिंग संविदा एजेंसियों द्वारा की गई।
- **सतही भूभौतिकीय सर्वेक्षण:** विभागीय और आउटसोर्सिंग संसाधनों के माध्यम से कुल 437.95 लाइन किमी 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण किया गया है। 437.95 लाइन किमी में से, 7 ब्लॉकों में विभागीय संसाधनों के माध्यम से लगभग 300.02 लाइन किमी 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण किया गया है। वर्धा घाटी कोलफील्ड में कोलार पिंपरी ब्लॉक का डिप साइड, वर्धा घाटी कोलफील्ड में उकनी, पिंपलगांव, निलजय ब्लॉक का डिप साइड, कोरबा कोलफील्ड में नूनबीरा ब्लॉक, कोरबा कोलफील्ड में करतली-1 के उत्तर, रतिजा और सैला ब्लॉक, और आईबी वैली कोलफील्ड में चटाबार ब्लॉक का डिप साइड। इसके अलावा, आउटसोर्स संसाधनों के माध्यम से लगभग 137.93 एलकेएम 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण भी किया गया है।

इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल ने कोयला सीमों की इन-क्रॉप के चित्रण, डाइक के चित्रण के लिए सीआईएल और गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विद्वत प्रतिरोधकता और चुंबकीय सर्वेक्षण भी किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 224 स्टेशनों में कुल लगभग 65.85 लाइन किमी विद्वत इमेजिंग, गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण और लगभग 86.79 लाइन किमी चुंबकीय सर्वेक्षण किया गया है।

- **रिपोर्ट:** 2024-25 के दौरान कुल 23 भूभौतिकीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गईं। इनमें से 15 अनुसूचित रिपोर्ट थीं और 8 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के अध्यायों के लिए थीं। इन 15 अनुसूचित रिपोर्टों में से तीन रिपोर्ट भूकंपीय सर्वेक्षण की थीं, छह रिपोर्ट प्रतिरोधकता इमेजिंग सर्वेक्षण की थीं, तीन रिपोर्ट एकीकृत भूभौतिकीय सर्वेक्षण की थीं, दो रिपोर्ट चुंबकीय सर्वेक्षण की थीं और एक लॉगिंग रिपोर्ट थी।

1.5 महत्वपूर्ण खनिज और आरईई अध्ययन

भारत सरकार के सतत खनिज संसाधन विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप, सीएमपीडीआईएल ने सीएसएस और सीआईएल-वित्त पोषित कोयला अन्वेषण परियोजनाओं के अंतर्गत कोयले के अलावा अन्य खनिज वस्तुओं के लिए आधारभूत डेटा सृजन शुरू किया है। एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की स्थापना जनवरी, 2024 में की गई थी।

मार्च 2025 तक, 15 ब्लॉकों में 15 बोरहोल से 4,172 कोयला नमूनों का विश्लेषण किया गया है। पांच ब्लॉकों- तामरा, धीरौली उत्तर, करीछापर, धमनीपहाड़ और रायडीह का विश्लेषण पूरा हो गया है। चार ब्लॉकों के लिए रिपोर्ट कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है, जबकि एक बोरहोल के परिणामों की जांच की जा रही है। शेष दस ब्लॉकों का अभी भी विश्लेषण किया जा रहा है।

मार्च 2025 तक दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई) विश्लेषण की विस्तृत स्थिति नीचे दी गई है।

क्र. सं.	ब्लॉक	कोलफील्ड	विश्लेषित बोरहोल की संख्या	विश्लेषित नमूनों की संख्या	टिप्पणी
1	तामरा	रानीगंज	1	411	विश्लेषण परिणाम प्राप्त और कोयला मंत्रालय एवं खनिज मंत्रालय को परिणाम सुपुर्द।
2	धीरौली उत्तर	सिंगरौली	1	432	विश्लेषण परिणाम प्राप्त और कोयला मंत्रालय एवं खनिज मंत्रालय को परिणाम सुपुर्द।
3	करिछपार	मंद-रायगढ़	1	391	विश्लेषण परिणाम प्राप्त और कोयला मंत्रालय एवं खनिज मंत्रालय को परिणाम सुपुर्द।
4	नागधरन	मंद-रायगढ़	1	117	विश्लेषण प्रक्रियाधीन है।
5	महाई	सोनहाट	1	249	विश्लेषण प्रक्रियाधीन है।
6	रायडीह	राजमहल	1	249	विश्लेषण परिणाम प्राप्त और रिपोर्ट जांच के बाद और कोयला मंत्रालय एवं खनिज मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।
7	धम्रिपहाड़	राजमहल	1	246	विश्लेषण परिणाम प्राप्त और कोयला मंत्रालय एवं खनिज मंत्रालय को परिणाम सुपुर्द।
8	कर्तली के उत्तर	कोरबा	1	93	विश्लेषण प्रक्रियाधीन है।
9	तंगरडीह पूर्व	आईबी घाटी	1	162	विश्लेषण प्रक्रियाधीन है।
10	धुमदांड	मंद-रायगढ़	1	335	विश्लेषण प्रक्रियाधीन है।
11	मेरखी पश्चिम	सोहागपुर	1	134	विश्लेषण प्रक्रियाधीन है।
12	जदुनाथपुर	आईबी घाटी	1	181	विश्लेषण प्रक्रियाधीन है।
13	मौसिंघ	उत्तर करणपुरा	1	726	विश्लेषण प्रक्रियाधीन है।
14	बेलपहाड़ का डिप विस्तार	आईबी घाटी	1	229	विश्लेषण प्रक्रियाधीन है।
15	महाई पश्चिम	सोनहाट	1	217	विश्लेषण प्रक्रियाधीन है।

1.6 भू-प्रणाली

• कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए खान सारांश तैयारी:

वित्तीय वर्ष 2024-25 में शुरू की गई कुल 3 किस्तों के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए कोयला खान सारांश तैयारी सफलतापूर्वक तैयार की गई:

- किस्त 10 (जून 2024) - प्रस्तावित ब्लॉक 67, नीलाम किए गए ब्लॉक 10
- किस्त 11 (दिसंबर 2024) – प्रस्तावित ब्लॉक 27, नीलाम किए गए ब्लॉक 16
- किस्त 12 (24 मार्च 2025) – प्रस्तावित ब्लॉक 28

• भूवैज्ञानिक ब्लॉक सीमा प्रमाणीकरण:

कोयला मंत्रालय के 2024 अधिदेश के अनुसार 5 कोयला ब्लॉक सीमाओं के लिए प्रमाणीकरण पूरा हो गया है और पूर्वोक्त लाइसेंस के लिए 2 कोयला ब्लॉक सीमाओं का प्रमाणीकरण पूरा हो गया है।

- **वेब में ओसीबीआईएस एप्लीकेशन को अद्यतन करना:**

51 कोयला क्षेत्रों के साथ ओसीबीआईएस पोर्टल को अद्यतन किया गया, जिसमें 1090 कोयला ब्लॉक की नवीनतम सीमाएं शामिल हैं।

- **राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी (एनजीडीआर) :**

65 कोयला ब्लॉकों के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी (एनजीडीआर) हेतु डेटा साझा करने का कार्य पूरा हो गया है और एनजीडीआर पोर्टल पर एनएमईटी के लिए लगभग 15 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट अपलोड की गई हैं।

- **कौशल विकास :**

आर्कजीआईएस और क्यूजीआईएस जैसे सॉफ्टवेयरों, वल्कन, माइनेक्स और सुरपैक का उपयोग करके 3डी मॉडलिंग सॉफ्टवेयरों का उपयोग करके कोयला अन्वेषण में जीआईएस अनुप्रयोग पर विभागों/विषयों और उद्योगों के अधिकारियों के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण।

2.0 कोल बेड मीथेन (सीबीएम)

2.1 सीआईएल और ओएनजीसी के संघ द्वारा झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में सीबीएम का सहयोगात्मक वाणिज्यिक विकास

- भारत सरकार ने 2002 में सीबीएम के वाणिज्यिक विकास के लिए नामांकन के आधार पर ओएनजीसी-सीआईएल के संघ को दो सीबीएम ब्लॉक 1. झरिया सीबीएम ब्लॉक 2. रानीगंज उत्तर सीबीएम ब्लॉक आवंटित किए। इन दो ब्लॉकों के विकास के लिए सीएमपीडीआईएल सीआईएल का तकनीकी सलाहकार है। झरिया सीबीएम ब्लॉक विकास चरण में है और मार्च, 24 तक 11 विकास कुओं की खुदाई की जा चुकी है। पाइपलाइन बिछाने के काम सहित सतही सुविधा का निर्माण प्रगति पर है। रानीगंज उत्तर सीबीएम ब्लॉक के लिए संशोधित क्षेत्र विकास योजना (चरण-1) को ओएनजीसी और सीआईएल दोनों

ने मंजूरी दे दी है। ब्लॉक विकास चरण में है। वित्त वर्ष 2024-25 में दो मूल्यांकन कुओं की खुदाई की गई है।

2.2 सीआईएल लीजहोल्ड क्षेत्र में सीबीएम विकास

- भारत सरकार ने 8 मई, 2018 को सीबीएम नीति, 1997 में आंशिक संशोधन करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों को कोयला खनन पट्टे के तहत अपने क्षेत्रों से सीबीएम की खोज और दोहन की अनुमति दी। सीएमपीडीआई सीआईएल पट्टा क्षेत्रों यानी बीसीसीएल, ईसीएल और एसईसीएल में सीबीएम के विकास के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) है। तीन (03) सीबीएम ब्लॉक वर्तमान में सीआईएल पट्टा क्षेत्रों में विचाराधीन हैं: 1.) झरिया सीबीएम ब्लॉक- I (बीसीसीएल), 2.) रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (ईसीएल), 3.) झरिया सीबीएम ब्लॉक- II (बीसीसीएल)। झरिया सीबीएम ब्लॉक- I (बीसीसीएल पट्टा क्षेत्र) को राजस्व साझेदारी के आधार पर सीबीएम के निष्कर्षण के लिए मेसर्स प्रभा एनर्जी लिमिटेड (पीईएल) को दिया गया है। झरिया सीबीएम ब्लॉक-II के लिए परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट को अक्टूबर, 2024 में बीसीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। रानीगंज सीबीएम ब्लॉक और झरिया सीबीएम ब्लॉक-II के लिए सीबीएम डेवलपर के चयन के लिए एक मॉडल निविदा दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2.3 सीबीएम लैब

- **सीबीएम लैब द्वारा 2024-2025 के दौरान संवर्धनात्मक गवेषण / क्षेत्रीय / विस्तृत गवेषण के अंतर्गत सीबीएम और शेल गैस से संबंधित अध्ययन**

सीएमपीडीआईएल प्रचारात्मक/क्षेत्रीय/विस्तृत गवेषण के दौरान ड्रिल किए गए बोरहोल के माध्यम से "भारतीय कोयला क्षेत्रों/लिग्राइट क्षेत्रों के कोलबेड मीथेन गैस-इन-प्लेस संसाधन

के आकलन" से संबंधित अध्ययन कर रहा है। प्रचारात्मक गवेषण कार्यक्रम के तहत सीबीएम लेब ने वित्त वर्ष 2024-25 तक सीबीएम के लिए 16 बोरहोल और शेल गैस के लिए 5 बोरहोल में फील्ड डिसोर्प्शन अध्ययन पूरा कर लिया है। 93 कोयला नमूनों और 26 शेल नमूनों में गैस पारगम्यता और हीलियम पोरोसिटी परीक्षण पूरे किए गए, शेल गैस के लिए 11 बोरहोल में कुल कार्बनिक सामग्री (टीओसी) विश्लेषण और रॉक इवल पायरोलिसिस अध्ययन पूरा किया गया है। यह अध्ययन सीबीएम और शेल गैस क्षमता के आकलन के लिए डेटा बेस बनाता है और सीबीएम और शेल गैस विकास के लिए और अधिक ब्लॉकों के चित्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सीआईएल की सहायक कंपनियों और बाहरी ग्राहकों के लिए सीबीएम विशिष्ट विश्लेषण किया गया है।

2.4 भूमिगत कोयला गैसीकरण

भारतीय भू-खनन स्थितियों में भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए एक अनुसंधान एवं विकास पायलट परियोजना सीएमपीडीआईएल, ईसीएल और एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजी इंक. (ईईटीआई), कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना में 02 चरण शामिल हैं। वर्तमान में चरण-1 प्रगति पर है।

3.0 परियोजना योजना और डिजाइन

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा प्राथमिकता के अनुसार, अतिरिक्त कोयला उत्पादन क्षमता के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान नई/विस्तार/पुनर्गठन खदानों के लिए परियोजना रिपोर्ट (पीआर) की तैयारी की गई। 33 परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई हैं, जिसमें गेवरा ओसी की विस्तार पीआर भी शामिल है, जिसकी प्रति वर्ष 85 मीट्रिक टन कोयले की योजनाबद्ध क्षमता है। नई पीआर के साथ-साथ परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट/लागत अनुमानों का संशोधन भी किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्य भी किए :

- वाशरी / डीशेलिंग संयंत्र के लिए संकल्पनात्मक/

व्यवहार्यता रिपोर्ट, निविदा/बोली दस्तावेज, बोलियों का मूल्यांकन आदि तैयार करना

- पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)
- ओसी और यूजी खदानों की खनन योजनाएं और खदान बंद करने की योजनाएं
- सीआईएल की खुली और भूमिगत खदानों की खान क्षमता का मूल्यांकन।
- खुली एवं भूमिगत खदानों के संचालन से संबंधित विभिन्न तकनीकी अध्ययन।
- सीआईएल की ओसी खानों में कार्यरत एचईएमएम का प्रदर्शन विश्लेषण।
- भूमिगत खदानों, खुली खदानों, बंद खदानों के लिए एमडीओ दस्तावेज
- जोखिम मूल्यांकन अध्ययन
- हाईवॉल खनन परियोजनाओं के लिए योजना
- मृदा अपरदन अध्ययन
- सिविल कार्य, ईटीपी/एसटीपी, सौर ऊर्जा संयंत्र आदि के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं।
- व्यापक जलविज्ञान रिपोर्ट
- कोयला निकासी मास्टर प्लान/कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान
- सीआईएल की खुली खदानों में डीजल, विस्फोटक और विद्युत शक्ति के लिए विशिष्ट खपत
- विस्तृत डिजाइन और चित्र, एनआईटी, निविदा जांच, आदि।

वर्ष 2024-25 के दौरान, पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी, रिमोट सेंसिंग अध्ययन, भूमि उपयोग/भूमि आवरण और वनस्पति आवरण मानचित्रण, ऊर्जा लेखा परीक्षा (डीजल और विद्युत) और ओपनकास्ट खदानों की बेंचमार्किंग, रोशनी सर्वेक्षण, चट्टान और कोयले के नमूनों पर भौतिक -यांत्रिक परीक्षण, अवतलन अध्ययन, स्ट्रेटा नियंत्रण, गैर-विनाशकारी परीक्षण (एनडीटी), नियंत्रित ब्लास्टिंग और कंपन अध्ययन और विस्फोटक उपयोग , खनन इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयले के नमूनों पर पेट्रोग्राफी अध्ययन, कोल कोर प्रसंस्करण और विश्लेषण, वाशबिलिटी परीक्षण, ओबीआर सर्वेक्षण, कोयला

खनन क्षेत्रों/नदी पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता, ढलान स्थिरता अध्ययन, अपशिष्ट/सीवरेज उपचार संयंत्र, खदान बंद करने की ऑडिटिंग आदि के क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को विशेषज्ञ परामर्श सेवाएं भी प्रदान की गईं।

वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 313 रिपोर्ट तैयार की गई हैं। तैयार की गई रिपोर्टों का विवरण नीचे दिया गया है:

रिपोर्टें	संख्या
भूवैज्ञानिक रिपोर्ट	31
परियोजना रिपोर्ट	33
ड्राफ्ट ईएमपी/फॉर्म-I/IV/VI	48
अन्य अध्ययन	201
कुल	313

2024-25 की अवधि के दौरान तैयार की गई रिपोर्टों का विवरण नीचे दिया गया है:

2024-25 के दौरान पूरी की गई रिपोर्टों की सूची

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय	रिपोर्ट का नाम
भूवैज्ञानिक रिपोर्ट :	
आरआई-I	1. लखीमाता कापासारा मंदामन संशोधित
	2. झांझरा
आरआई-III	1. ट्यूबेड के पश्चिम (एनएमईटी)
	2. चान्हो के पश्चिम में रिक्बा (एनएमईटी)
आरआई-IV	1. साओनेर के उत्तर में (एनएमईटी)
	2. मकरी-बरका पूर्व - इंगुरी - एक संयुक्त ब्लॉक
	3. राजतहरी के उत्तर में (एनएमईटी)
	4. मुगली नाकोडा एक्सटेंशन (संयुक्त संशोधित जी.आर.)
	5. येन्सा ब्लॉक (गैर-सीआईएल)
आरआई-V	1. भिलाई
आरआई-VI	1. झिंगुरदा डीप
आरआई-VII	1. बेलपहाड़ और डिपसाइड
मुख्यालय	1. उरटन उत्तर के उत्तर (एनएमईटी)
संविदात्मक	1. चिरा दक्षिण पूर्व
	2. नवगांव पूर्व (गैर-सीआईएल)
	3. नवगांव पश्चिम (गैर-सीआईएल)
	4. कोटमेर दक्षिण (गैर-सीआईएल)
	5. विजयनगर-गिद्दी साउथ (नॉन-सीआईएल)
	6. कोटमेर उत्तर (गैर-सीआईएल)

	7. विजयनगर-गिद्दी उत्तर (गैर-सीआईएल)
	8. नामचिक पूर्व (गैर-सीआईएल)
	9. नामचिक पश्चिम (गैर-सीआईएल)
	10. चैनपुर (गैर-सीआईएल)
	11। जिलगा-बरपाली (गैर-सीआईएल)
	12. पुरैल
	13. खेडुली - लिग्राइट (प्रचारात्मक)
	14. घुघरा के उत्तर में (प्रचारात्मक)
	15. मोगचेन दुबिया (प्रचारात्मक)
	16. राजगांव (प्रचारात्मक)
	17. तातापानी -I
	18. जगराहिपारा (प्रचारात्मक)
परियोजना रिपोर्ट:	
आरआई-I	1. रंगमती - ए यूजी
	2. भनोरा वेस्ट रीकास्ट यूजी+ओसी+एचडब्ल्यूएम
आरआई-II	1. ब्लॉक-डी पुनर्गठन ओसी
	2. कल्याणेश्वरी ओसी - पुनर्चना
आरआई-III	1. रोहने कोल ब्लॉक (गैर-सीआईएल)
	2. उत्तरी धाड़ (पश्चिमी भाग) (गैर-सीआईएल)
	3. टैपिन साउथ ओसी - रीकास्ट
	4. भैरवी ओ.सी.पी.
	5. अशोक करकट्टा पश्चिम ओसी (द्वितीय चरण) (उत्तरी भाग)
आरआई-IV	1. अनंत यूजी (जगन्नाथ+तालचेर डब्ल्यू)
	2. शिवानी ओसी - रीकास्ट
	3. चिंचला पिसगांव ओसी - पुनर्चना
	4. छिंदा विस्तार ओसी
	5. नीलजय डीप एक्सपेंशन । ओसी (डिपसाइड विस्तार .)
	6. साओनेर -III यूजी माइन एक्सपं.
	7. टाकली जेना पश्चिम ओ.सी.
आरआई-V	1. मालाचुआ यूजी एमडीओ - रीकास्ट
	2. अमृतधारा यूजी एमडीओ - पुनर्चना
	3. मदननगर ओसी एमडीओ विकल्प - पुनर्चना
	4. रेहार विस्तार यूजी रीकास्ट
	5. बदौली यूजी एमडीओ पुनर्चना
	6. रामपुर बटुरा ओसी - आरपीआर
	7. बागदेवा विस्तार यूजी - रीकास्ट
	8. राजेंद्र एक्सपेंशन (करकटी यूजी) - रीकास्ट
	9. गेवरा विस्तार ओसी
आरआई-VI	1. जयंत डिपसाइड विस्तार ओसी
आरआई-VII	1. लाजपुरा डिपसाइड ओसी एक्सपेंशन - रीकास्ट
	2. बैतरनी ईस्ट ओ.सी.
मुख्यालय	1. चिनाकुरी यूजी - राजस्व साक्षाकरण एमडीओ

	2. नया गोधुर कुसुंडा यूजी
	3. मकरी बोर्का यूजी - रीकास्ट
	4. भौरा संयुक्त यूजी, बीसीसीएल
	5. कयादा चौधर गरियापानी ओसी
पर्यावरण प्रबंधन योजना:	
फॉर्म-I (फॉर्म III, IV और VI सहित)	
आरआई-I	1. क्लस्टर संख्या 4 (2 खदानों का समूह) (क्षेत्र में परिवर्तन)
	2. क्लस्टर संख्या 12 (ईसीएल की 14 खदानों का समूह) (ई.सी. में संशोधन)
आरआई-II	1. क्लस्टर VII (ई.सी. में संशोधन)
	2. क्लस्टर III (ई.सी. में संशोधन)
आरआई-III	1. आम्रपाली ओसीपी (क्षमता में विस्तार)
	2. स्वांग वाशरी
	3. आम्रपाली ओ.सी.पी. (ई.सी. में संशोधन)
	4. (टीओआर में संशोधन)
आरआई-IV	1. मुंगोली-निरगुडा एक्सटेंशन डीप ओसी (ईसी में संशोधन)
	2. समामेलित येकोना । और II ओसी (क्षमता में विस्तार)
	3. समामेलित गौरी पौनी ओसी (क्षमता में विस्तार)
	4. मकरधोकरा - I ओसी (ईसी में संशोधन)
	5. कोलगांव ओसी (टीओआर में संशोधन)
	6. पेंगांगा ओसी (ईसी में संशोधन)
	7. गौरी पौनी ओसी (ईसी में संशोधन)
	8. कोलगांव ओसी (ईसी में संशोधन)
आरआई-V	1. झिरिया यूजी (पुनर्वैधीकरण के लिए फॉर्म VI)
	2. खैराहा यूजी (क्षमता में विस्तार)
	3. आमदंड ओसी (ईसी में संशोधन के लिए फॉर्म-IV)
	4. राजेंद्र यूजी (पुनर्वैधीकरण के लिए फॉर्म-IV)
आरआई-VI	1. बीना ओ.सी.पी. (ई.सी. में संशोधन हेतु फॉर्म IV)
	2. खड़िया ओ.सी.पी. (टीओआर में संशोधन के लिए फॉर्म III)
	3. ब्लॉक-बी ओसीपी (टीओआर में संशोधन के लिए फॉर्म III)
	4. निगाही ओसीपी (ईसी में संशोधन के लिए फॉर्म IV)
	5. खड़िया ओ.सी.पी. (ई.सी. में संशोधन हेतु प्रपत्र IV)
आरआई-VII	1. एकीकृत लखनपुर-बेलपहाड़-लिलारी ओ.सी.पी. (फॉर्म IV: ई.सी. में संशोधन)
	2. कुल्दा ओ.सी.पी. (ई.सी. में संशोधन हेतु फॉर्म IV)
	3. एकीकृत लखनपुर, बेलपहाड़ और लिलारी ओसीपी (ईसी में संशोधन के लिए फॉर्म IV)
मुख्यालय	1. क्लस्टर- VII, बीसीसीएल (फॉर्म-IV: ईसी में संशोधन)
ड्राफ्ट ईएमपी	
आरआई-I	1. क्लस्टर संख्या 12 (ईसीएल की 14 खदानों का समूह) (क्षेत्रफल एवं क्षमता में विस्तार)
	2. क्लस्टर क्रमांक 3 (ईसीएल की 3 खदानों का समूह) (क्षेत्र में विस्तार)
आरआई-II	1. क्लस्टर-एक्स, बीसीसीएल

आरआई-III	1. न्यू ढोरी कोकिंग कोल वाशरी
	2. आम्रपाली ओ.सी.पी. (ई.सी. में संशोधन)
आरआई-IV	1. समामेलित येकोना । और II ओसी (परिशिष्ट ईआईए)
	2. धुप्ताला विस्तार ओसी
आरआई-V	1. कुसमुंडा ओसीपी (द्वितीय चरण) (क्षमता में विस्तार)
	2. जगन्नाथपुर ओ.सी. (क्षमता में विस्तार)
	3. दामिनी यूजी (पुनर्वैधीकरण के लिए ईआईए)
	4. रजगामार यूजी (पुनर्वैधीकरण के लिए ईआईए)
आरआई-VI	1. ब्लॉक-बी ओसीपी
आरआई-VII	1. भुवनेश्वर ओसीपी जिसमें 20.383 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है (क्षेत्र में विस्तार)
	2. रजगामार यूजी, एसईसीएल (ईसी का पुनर्वैधीकरण)
	3. अनंत ओसी विस्तार (7(ii) के अंतर्गत क्षमता में वृद्धि)
	4. हिंगुला ओ.सी.पी. (7(ii) के अंतर्गत क्षमता में वृद्धि)
मुख्यालय	1. अमलो ओसीपी, सीसीएल (क्षमता में विस्तार)
	2. स्वांग वाशरी
	3. घोन्सा विस्तार (डीप) ओसी, डब्ल्यूसीएल

4.0 कोयला एवं खनिज तैयारी

कोयला एवं खनिज तैयारी प्रभाग, ग्रीनफील्ड कोयला वाशरी, खनिज परिष्करण संयंत्र और मौजूदा संयंत्रों के संशोधन/आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में विस्तृत प्रयोगशाला अध्ययन, पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर), वैचारिक रिपोर्ट (सीआर), बोली प्रक्रिया प्रबंधन, अनुबंध दस्तावेज़ तैयार करना और परियोजना निष्पादन के दौरान चित्रों की जांच के बाद कार्यों को प्रदान करने में सहायता शामिल है। यह अनुसंधान एवं विकास सेवाओं और कॉर्पोरेट सहायता की विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करता है। सीएमपी लैब को अगस्त 2024 में परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से पुनः मान्यता प्राप्त हुई है। इस तरह के पुनर्गठित निकाय को परीक्षण परिणामों की पारस्परिक स्वीकृति की सुविधा के लिए पहला आवश्यक कदम माना जाता है।

यह प्रभाग प्रयोगशाला स्तर पर अध्ययन करने के लिए नवीनतम और परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित आईएसओ प्रमाणित आधुनिक प्रयोगशाला से सुसज्जित है।

वर्ष 2024-2025 के दौरान इस प्रभाग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कार्य पूरे किए गए हैं।

4.1. संकल्पनात्मक रिपोर्ट

- तालाबीरा ओसीपी, एनएलसीआईएल में नॉन-कोकिंग कोल वाशरी (8.0 एमटीवाई) की स्थापना के लिए मसौदा संकल्पनात्मक रिपोर्ट।
- एमसीएल में नॉन-कोकिंग कोल वाशरी के निर्माण की संभावनाओं पर अवधारणा नोट

4.2. व्यवहार्यता / पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट

- एमसीएल में बलराम खदान के लिए डीशेलिंग प्लांट/ वाशरी की स्थापना के लिए मसौदा व्यवहार्यता रिपोर्ट।
- केदला वाशरी (2.6 मीट्रिक टन), सीसीएल की क्षमता वृद्धि के लिए विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट
- बीसीसीएल की मौजूदा कोकिंग कोल वाशरियों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट
- नई सवांग वाशरी (1.5 मीट्रिक टन), सीसीएल की स्थापना के लिए पीएफआर का अद्यतन लागत अनुमान,
- ठोरी वाशरी (3.0 मीट्रिक टन), सीसीएल की स्थापना के लिए पीएफआर का अद्यतन लागत अनुमान

4.3. निविदा दस्तावेज़

- सीआईएल में बिल्ड-ऑपरेट-मेंटेन (बीओएम) अवधारणा पर वाशरियों की स्थापना और संचालन के लिए ऑपरेटरों का चयन करने के लिए मॉडल बोली दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों को संशोधित करना।
- बीओओ कॉन्सेप्ट पर ठोरी वाशरी (3.0 एमटीवाई) के संशोधित बोली दस्तावेज़ की तैयारी
- अमरकोंडा के लिए जीईएम संगत एमडीओ दस्तावेज़ की तैयारी/अनुकूलन ईसीएल का मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक।
- डब्ल्यूबीपीडीसीएल को आवंटित देवचा-पचामी-दीवानगंज-हरिसिंधा कोयला ब्लॉक के लिए

एमडीओ के चयन के लिए ईओआई

4.4. निविदा दस्तावेज़ के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन

- बीओओ आधार पर बसंतपुर तापिन कोकिंग कोल वाशरी और न्यू सवांग कोकिंग कोल वाशरी के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन।
- एमसीएल के लखनपुर में आईबी वैली वाशरी के संबंध में नमूना लेने के लिए स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति के कार्य के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन
- मेसर्स तेनुघाट विद्वत निगम, रांची लिमिटेड के लिए राजबार ई एंड डी कोयला खदान के लिए एमडीओ के चयन हेतु परामर्श सेवाएं.

4.5. निर्माण चित्रों की जांच

- बीसीसीएल की पुरानी मूनीडीह वाशरी, पाथरडीह- II वाशरी।
- बसुंधरा ओसीपी के लिए ईटीपी के डिजाइन ड्राइंग की जांच

4.6. अध्यायों की तैयारी

- झिंगुरदा ओसीपी, एनसीएल के ईटीपी के लिए एनआईटी का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल चैप्टर
- निगाही, एनसीएल के लिए ईटीपी योजना के लिए यूसीई
- टिकक ओसीपी, 1000 केएलडी के लिए ईटीपी योजना की लागत का अनुमान
- नीलजई विस्तार, ओसीएम, डब्ल्यूसीएल के लिए वाशरी पर अध्याय।

4.7. अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ

- कार्बन मूल्यों की वसूली के लिए कोकिंग कोल वाशरी के मिडिलिंग और फाइन्स का प्रभावी उपयोग"-परियोजना पूर्णता रिपोर्ट नवंबर 2024 में स्वीकार की गई
- "भौतिक और रासायनिक लाभकारीकरण के माध्यम से उच्च राख वाले भारतीय कोयले का उन्नयन" - जनवरी 2025 में मसौदा पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी

- वाशरी के प्रदर्शन में सुधार पर अध्ययन"-परियोजना पूर्णता रिपोर्ट नवंबर 2024 में स्वीकार की गई।

4.8. कॉर्पोरेट समर्थन

- नई वाशरियों की निविदाएं जारी करने के लिए सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा अपनाई गई विभिन्न बोली अवधारणाओं की जांच करने के लिए सीएमपीडीआई के निदेशक (टी/ईएस) की अध्यक्षता में सीआईएल द्वारा गठित समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई।
- वाशरियों की निष्क्रिय क्षमता के उपयोग के लिए अध्ययन करने और सुझाव देने हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा सीआईएल के निदेशक (तकनीकी) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी।
- सीसीएल के संभावित कोकिंग कोयला खदानों की पहचान करने के लिए मसौदा रिपोर्ट डी (टी/ईएस) सीएमपीडीआईएल द्वारा गठित वाशरी की स्थापना के लिए।

5.0 परियोजना समीक्षा

- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, परियोजना मूल्यांकन विभाग (पीएडी) कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों को व्यापक जांच, मूल्यांकन और निगरानी सहायता प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।
- कुल 33 परियोजना रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की गई हैं। परियोजना रिपोर्टें क्षेत्रीय संस्थानों और सीएमपीडीआई के मुख्यालय में तैयार की गई और पीएडी प्रभाग के समन्वय और सहयोग के द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सीएमपीडीआई मुख्यालय में इन रिपोर्टों पर चर्चा और जांच की गई।
- इसके अतिरिक्त, कोयला मंत्रालय (एमओसी) की आवश्यकता के अनुसार "कोयला खनन परियोजनाओं के पूरा होने के मानदंडों की समीक्षा" का कार्य पूरा कर लिया गया है।

6.0 खुली खदान खनन

6.1 पूर्ण किये गये प्रमुख बाहरी परामर्श कार्य:

- रबोडीह कोयला ब्लॉक के लिए खनन योजना , मेसर्स 21 वीं सेंचुरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड।
- सुलियारी कोयला खदान की परिचालन योजना , मेसर्स एपीएमडीसी
- ताडीचेरला ओसी, मेसर्स टीएसजीईएनसीओ के लिए वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए वार्षिक उत्पादन कार्यक्रम की जांच

6.2 पूर्ण किये गये प्रमुख सीआईएल कार्य:

- जीवनधारा ओसीपी (2.50 एमटीपीए), सीसीएल के लिए यूसीई
- खदान पट्टे के आवेदन के लिए टिकक विस्तार हेतु खनन योजना, एनईसी
- तिराप के लिए खनन पट्टे के आवेदन हेतु खनन योजना, एनईसी
- क्यादा-चौधर-गरियापानी ओसीपी (4 एमटीवाई), ईसीएल के लिए पीआर
- बीना परियोजना, एनसीएल की ढलान स्थिरता के लिए वैज्ञानिक अध्ययन
- निगाही ओसीपी, एनसीएल की ढलान स्थिरता के लिए वैज्ञानिक अध्ययन
- कृष्णशिला ओसीपी, एनसीएल की ढलान स्थिरता के लिए वैज्ञानिक अध्ययन
- काकरी ओसीपी, एनसीएल की ढलान स्थिरता के लिए वैज्ञानिक अध्ययन
- बोकारो कोलियरी ओसीपी, सीसीएल की ढलान स्थिरता के लिए वैज्ञानिक अध्ययन
- एमटीपीए की खनन योजना के आधार पर मौजूदा और प्रस्तावित अंतिम ओबी डंप के लिए वैज्ञानिक अध्ययन (ढलान स्थिरता) ब्लॉक बी ओसीपी के 10 एमटीपीए के लिए ईआईए-ईएमपी की तैयारी के एक भाग के रूप में
- टापिन साउथ ओसीपी, सीसीएल की ढलान स्थिरता के लिए वैज्ञानिक अध्ययन

- मगध ओसीपी, सीसीएल के लिए मृदा अपरदन अध्ययन
- सीआईएल की खुली खदानों की क्षमता का आकलन - 01.04.2025 तक का अनुमान।
- 2023-24 के दौरान सीआईएल की खुली खदानों की क्षमता और क्षमता उपयोग का आकलन।
- सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के लिए 2023-24 के दौरान एचईएमएम का प्रदर्शन विश्लेषण।
- 2023-24 के दौरान डम्पर्स और एक्सकेवेटर का प्रदर्शन विश्लेषण और सीआईएल का सारांश।
- 2023-24 के दौरान सीआईएल की खुली खदानों में विस्फोटक, डीजल और विद्युत-शक्ति के लिए विशिष्ट खपत का विश्लेषण।
- परियोजना रिपोर्टों का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन।

6.3 2024-25 में ओपनकास्ट डिवीजन की उपलब्धि

- एनसीएल की खदानों के लिए ढलान स्थिरता हेतु वैज्ञानिक अध्ययन पूरा हो गया।
- नए प्रकार का कार्य - मृदा अपरदन अध्ययन से संबंधित कार्य, जो अब एफसी अनुमोदन के लिए एक अनुपालन आवश्यकता है, एक बहुक्रियाशील टीम के माध्यम से शुरू किया गया और सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

7.0. भूमिगत खनन

7.1 सीआईएल के कार्य (पूर्ण रिपोर्ट/कार्य)

- अमरकोंडा का जीईएम संगत एमडीओ दस्तावेज़ ईसीएल का मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक
- सुदामडीह कोल वाशरी के नीचे यूजी खनन क्षमता का आकलन।
- एसईसीएल के भटगांव क्षेत्र के शिवानी यूजी खदान में 3डी अवतलन भविष्यवाणी अध्ययन।
- गोधुर के लिए परियोजना रिपोर्ट कुसुंडा यूजी

- खनन उपकरण के लिए मानक मूल्य सूची, 2024.
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यूजी खदान क्षमता मूल्यांकन और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यूजी खदान उपयोग।
- चूरी की खनन योजना बेंटी यूजी.
- परियोजना रिपोर्ट भौरा उत्तर, बीसीसीएल
- बलरामपुर यूजी, बिश्रामपुर क्षेत्र, एसईसीएल का 3डी धंसाव पूर्वानुमान अध्ययन।

7.2 सीआईएल के कार्य (सुपुर्द किए गए ड्राफ्ट रिपोर्ट)

- सीआईएल के लिए सतत माइनर हेतु जीईएम संगत मॉडल एनआईटी की तैयारी
- एएपी 2024-25 के अनुसार एनसीएल की मकरी बोरका यूजी परियोजना के लिए संक्षिप्त पीआर, एमसीए और आरएफबीलाबजी की परियोजना रिपोर्ट पुसला यूजी, एसईसीएल
- एसईसीएल के लब्जी पुसला यूजी की परियोजना रिपोर्ट
- ब्राह्मणी नॉर्थ कोल ब्लॉक के आरएफबी और एमसीए की तैयारी।

7.3 बाहरी परामर्श कार्य (पूर्ण रिपोर्ट/कार्य):

- मेसर्स तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, रांची के लिए राजबार ई एंड डी कोयला खदान के लिए एमडीओ के चयन हेतु परामर्श सेवाएं।
- राजस्व साझेदारी के आधार पर चिनाकुरी यूजी खदान के पुनः खोलने, बचाव, पुनर्वास, विकास और संचालन के कार्य की खनन योजना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।

7.4 बाहरी परामर्श नौकरियां (ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत)

- डब्ल्यूबीपीडीसीएल के डीपीडीएच ब्लॉक के लिए खनन ऑपरेटर के चयन हेतु वैश्विक ईओआई हेतु दस्तावेज़ तैयार करना।

7.5 कोयला मंत्रालय के कार्य

- वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी के 10वें, 11 वें और 12 वें दौर का खदान डोजियर कोयला मंत्रालय को सौंप दिया गया है।
- कोयला ब्लॉक से संबंधित मुद्दों के संबंध में कोयला मंत्रालय द्वारा अपेक्षित होने पर बोली-पूर्व प्रश्नों का उत्तर देना तथा अन्य तकनीकी सहायता प्रदान करना।

8.0 सिविल अभियंत्रण सेवायें

8.1 परियोजना प्रबंध कंसल्टेंसी के कार्य

- आईआईसीएम, रांची के छात्रावास इमारत का निर्माण
- महाप्रबंधक कार्यालय, हजारीबाग क्षेत्र में इनडोर स्टेडियम और बरकासयाल, रामगढ़ क्षेत्र, सीसीएल, झारखंड में इनडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम और ईटीपी के निर्माण के लिए वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
- एमसीएल के लखनपुर क्षेत्र में विकसित की जाने वाली अतिरिक्त अवसंरचनाओं के साथ आवासीय और सेवा भवनों सहित कॉलोनियों के कार्याकल्प के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
- एमसीएल के हिंगुला क्षेत्र में विकसित की जाने वाली अतिरिक्त अवसंरचनाओं के साथ आवासीय और सेवा भवनों सहित कॉलोनियों के कार्याकल्प के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
- एमसीएल के लिंगराज क्षेत्र में विकसित की जाने वाली अतिरिक्त अवसंरचनाओं के साथ आवासीय और सेवा भवनों सहित कॉलोनियों के कार्याकल्प के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
- एमसीएल के जगन्नाथ क्षेत्र में विकसित की

जाने वाली अतिरिक्त अवसंरचनाओं के साथ आवासीय और सेवा भवनों सहित कॉलोनियों के कार्याकल्प के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।

- एमसीएल के भरतपुर क्षेत्र में विकसित की जाने वाली अतिरिक्त अवसंरचनाओं के साथ आवासीय और सेवा भवनों सहित कॉलोनियों के कार्याकल्प के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
- एमसीएल के तालचर क्षेत्र में विकसित की जाने वाली अतिरिक्त अवसंरचनाओं के साथ आवासीय और सेवा भवनों सहित कॉलोनियों के कार्याकल्प के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
- एमसीएल के आईबी वैली क्षेत्र में विकसित की जाने वाली अतिरिक्त अवसंरचनाओं के साथ आवासीय और सेवा भवनों सहित कॉलोनियों के कार्याकल्प के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
- एमसीएल मुख्यालय, संबलपुर में विकसित की जाने वाली अतिरिक्त अवसंरचनाओं के साथ आवासीय और सेवा भवनों सहित कॉलोनियों के कार्याकल्प के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
- केंद्रीय अस्पताल, गांधीनगर, सीसीएल रांची, से उत्पन्न तरल अपशिष्ट के लिए इसमें 25 केएलडी क्षमता के अपशिष्ट उपचार संयंत्र की योजना, जांच, डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, स्थापना, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, ट्रायल रन और कमीशनिंग। इसमें सभी सिविल, संरचनात्मक, विद्युतीय और यांत्रिक कार्य तथा अन्य सभी सहायक उपकरण और सुविधाएं शामिल हैं जो इसे टर्नकी आधार पर सभी तरह

- से पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक हैं, जिसमें छह वर्षों का संचालन और 01 वर्ष की वारंटी अवधि के बाद पांच वर्षों के लिए संयंत्र का व्यापक रखरखाव शामिल है।
- कोनार ओसीपी, बी एंड के क्षेत्र, सीसीएल, बोकारो, जिला, झारखंड के लिए सभी बुनियादी ढांचे के साथ आवासीय और सेवा भवनों का निर्माण शामिल है।
 - नईसराय, रामगढ़ सीसीएल में 80 केएलडी (प्री-ट्रीटमेंट के लिए 25 केएलडी के ईटीपी सहित) के एसटीपी की योजना, जांच, डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, निर्माण, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, ट्रायल रन और कमीशनिंग।
 - सीसीएल, रांची के जीएम यूनिट के तहत बीटीटीआई, भुरकुंडा में बरका-सयाल क्षेत्र के जीएम कार्यालय के लिए सामुदायिक भवनों सहित जीएम कार्यालय और नई टाउनशिप का निर्माण के लिए वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
 - जारंगडीह ओसीपी, कथारा क्षेत्र, सीसीएल में विभिन्न सामुदायिक भवनों के विध्वंस और पुनर्निर्माण के लिए वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं "
 - दीपका क्षेत्र में पार्किंग के लिए भूतल (स्टिल्ट) और रहने योग्य मंजिलों के साथ मोनोलिथिक/पारंपरिक आरसीसी निर्माण के साथ बहुमंजिला आवासीय प्रकार के क्वार्टरों के निर्माण और संबद्ध बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
 - गेवरा क्षेत्र, एसईसीएल में पार्किंग के लिए भूतल (स्टिल्ट) और रहने योग्य मंजिलों के साथ मोनोलिथिक/पारंपरिक आरसीसी निर्माण के साथ बहुमंजिला आवासीय प्रकार के क्वार्टरों के निर्माण और संबद्ध बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
 - कुसमुंडा क्षेत्र में पार्किंग के लिए भूतल (स्टिल्ट) और रहने योग्य मंजिलों के साथ मोनोलिथिक/पारंपरिक आरसीसी निर्माण के साथ बहुमंजिला आवासीय प्रकार के क्वार्टरों के निर्माण और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
 - घरघोड़ा, रायगढ़ क्षेत्र, एसईसीएल में पार्किंग के लिए भूतल (स्टिल्ट) और रहने योग्य मंजिलों के साथ मोनोलिथिक/पारंपरिक आरसीसी निर्माण के साथ बहुमंजिला आवासीय प्रकार के क्वार्टरों के निर्माण और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
 - "सीसीएल के बरका-सयाल क्षेत्र के अस्पताल कॉलोनी, लपंगा कॉलोनी और पटेल नगर कॉलोनी के लिए अनुक्रमिक बैच रिएक्टर (एसबीआर) तकनीक पर आधारित 200 केएलडी क्षमता के 03 एसटीपी की योजना, डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, निर्माण, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, ट्रायल रन और कमीशनिंग, जिसमें सभी सिविल, संरचनात्मक, विद्युत और यांत्रिक कार्य और अन्य सभी सहायक उपकरण और सुविधाएं शामिल हैं, जिसमें पूर्ण सीवेज नेटवर्क का निर्माण शामिल है, ताकि इसे टर्नकी आधार पर सभी तरह से पूर्ण बनाया जा सके, जिसमें छह साल के लिए संचालन और 01 वर्ष की वारंटी अवधि के बाद पांच साल के लिए संयंत्र और अन्य बुनियादी ढांचे का व्यापक रखरखाव शामिल है।"
 - उरीमारी परियोजना, बरका सयाल क्षेत्र, सीसीएल में ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं.
 - नईसराय कॉलोनी, सीसीएल रांची में अस्पताल भवन सहित विभिन्न आरसीसी फ्रेमवर्क संरचनाओं और चिनाई संरचनाओं के संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक सदस्यों

के सुदृढीकरण, रेट्रोफिटिंग , पुनर्वास के लिए वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।

- एमसीएल के महालक्ष्मी क्षेत्र में जीएम कार्यालय महालक्ष्मी क्षेत्र सह सियारमल ओसीपी के परियोजना कार्यालय के निर्माण के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं ।
- एमसीएल के जगन्नाथ क्षेत्र में समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (जीवीटीसी) के निर्माण के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं
- एमसीएल के विभिन्न स्थानों पर 3 इको पार्क के विकास के लिए एसक्यूसी (पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ वास्तुकला और संबद्ध कार्य।
 - हिंगुला क्षेत्र के अंतर्गत बलराम ओसीपी के गांधीसागर में श्रमिक गौरव वाटर पार्क
 - लखनपुर क्षेत्र के अंतर्गत लिलारी ओसीपी में इको पार्क (द्वितीय चरण)।
 - ओरिएंट क्षेत्र के अंतर्गत ओरिएंट कोलियरी खदान संख्या 04 में इको पार्क (द्वितीय चरण)
- "आईआईसीएम में खेल परिसर के साथ-साथ संबद्ध अवसंरचनाओं के निर्माण" के लिए वास्तुकला और संबद्ध परामर्श सेवाएं।
- धनबाद, बीसीसीएल में नए ओपीडी भवन का निर्माण" के लिए वास्तुकला और संबद्ध कार्य ।
- सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की पीएमसी सेवा के लिए योजना, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, गठन, परिनिर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।
- डब्ल्यूसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की पीएमसी सेवा के लिए योजना, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, गठन, परिनिर्माण आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।

8.2 डिज़ाइन/ चित्रकला जांच का एफएमसी एवं अन्य परियोजनाएं

- पाथरडीह वाशरी, बीसीसीएल के लिए डिजाइन/ ड्राइंग की जांच।
- जंझरा सीएचपी, ईसीएल के लिए डिजाइन/ ड्राइंग की जांच।
- कनिहा सीएचपी, एमसीएल के लिए डिजाइन/ ड्राइंग की जांच।
- हुरा-सी सीएचपी, ईसीएल के लिए डिजाइन/ ड्राइंग की जांच।
- अमलोहरी ओसीपी, एनसीएल में 190 टी डम्पर मरम्मत कार्यशाला की ड्राइंग जांच।
- ब्लॉक बी ओसीपी कार्यशाला, एनसीएल की ड्राइंग जांच।
- जयंत ओसीपी, एनसीएल में 190 टी डम्पर मरम्मत कार्यशाला की ड्राइंग जांच।
- सीडब्ल्यूएस जयंत (उन्नयन), एनसीएल की ड्राइंग जांच।
- लखनपुर वाशरी, एमसीएल के लिए डिजाइन/ ड्राइंग की जांच।
- दीपका मैकेनाइज्ड साइडिंग, एसईसीएल के लिए डिजाइन/ड्राइंग की जांच।
- कुसमुंडा सेंट्रल इनपिट, एसईसीएल के लिए डिजाइन/ड्राइंग की जांच।
- चाल सीएचपी और सबस्टेशन, एसईसीएल के लिए डिजाइन/ड्राइंग की जांच।
- मानिकपुर सीएचपी और साइलो, एसईसीएल के लिए डिजाइन/ड्राइंग की जांच।
- बीना-ककरी अमलगमेशन ओसीपी वर्कशॉप, एनसीएल के ड्राइंग की जांच।
- खड़िया ओसीपी सीएचपी के ड्राइंग की जांच
- आम्रपाली सीएचपी, सीसीएल के ड्राइंग की जांच

8.3 परियोजना नियोजन कार्य:

- निम्नलिखित के सिविल भाग के लिए पीआर तैयारी/लागत अद्यतनीकरण
 - केसीजी (4.0 एमटीवाई), ईसीएल
 - रबोडीह कोयला ब्लॉक (2.5 एमटीवाई)
- वर्ष भर में पीएडी द्वारा तकनीकी जांच के लिए इस विभाग को भेजी गई 15 रिपोर्टों के लिए पीआर/आरपीआर की तकनीकी जांच।

8.4 सिविल और वास्तुकला विस्तृत डिजाइन और ड्राइंग जॉब्स/ईटीपी/एसटीपी:

- सीसीएल के अरगडा क्षेत्र में रेलिगारा परियोजना के अंतर्गत मंगेरधा नाले पर पुल का निर्माण।
- डब्ल्यूसीएल के माजरी क्षेत्र के अंतर्गत कुचना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में 20 बी-टाइप क्वार्टर और 16 सी टाइप क्वार्टर के निर्माण और संबद्ध कार्यों के लिए योजना डिजाइन और ड्राइंग सहित डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए डब्ल्यूसीएल वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
- 4.0 एमटीपीए के लिए झिंगुरदा ओसीपी की संशोधित खदान योजना के अनुसार ईटीपी को स्थानांतरित करना।
- पूर्वोत्तर कोलफील्ड्स, कोल इंडिया लिमिटेड, मार्गेरिटा, असम के जयपोरे डिल्ली कोलियरी (यूजी खदान), बारगोलाई कोलियरी (यूजी खदान) और लेडो कोलियरी के लिए अंतिम खदान बंद करने की योजना की तैयारी
- डीपीएस निगाही में अतिरिक्त कक्षा और सभागार के निर्माण के लिए प्रस्तावित संरचनात्मक रेखाचित्रों की जाँच।

8.5 जल विज्ञान अध्ययन के कार्य :

- पुंडी ओसीपी नाला डायवर्सन, सीसीएल
- बंगारू झोर धारा की डायवर्सन योजना और अध्ययन क्षेत्र के 10 किमी बफर जोन में पहले से क्षतिग्रस्त जल निकायों की उचित बहाली

कार्य योजना के साथ एक विस्तृत जल विज्ञान अध्ययन" भरतपुर ओसीपी (20 मीट्रिक टन; क्षेत्र विस्तार-927.42 हेक्टेयर से 1556.94 हेक्टेयर) के संबंध में 28.06.2022 को एमओईएफ एंड सीसी द्वारा दिए गए टीओआर के अनुसार।

- पतरातू एबीसी, यूजीपी, संचमित्रा ओसीपी, चंद्रगुप्त ओसीपी, पुंडी ओसीपी, अशोक एक्सप्लोरेशन और अरगडा ओसीपी में 06 नालों के डायवर्सन का अध्ययन।
- राजहरा ओसीपी, सीसीएल के लिए सदाबाह नदी के दोनों किनारों पर मौजूदा तटबंध का वैज्ञानिक अध्ययन।

8.6 बाहरी कार्य:

- ईपीसी मोड पर आरजीओसी 3 6 सीएचपी, आरजी 2 क्षेत्र में कोयला हैंडलिंग संयंत्र की स्थापना के लिए परामर्श सेवा अनुबंध।

8.7 निविदा दस्तावेज़/अनुमान/योजना की प्रस्तुति:

- मोहनपुर ओसीपी (चरण-II), सलानपुर क्षेत्र, ईसीएल के कोयला हैंडलिंग प्लांट (2.5 एमटीवाई) के लिए एनआईटी, अनुमान (खंड II और III) की तैयारी।
- बोनजेमेहरी ओसीपी, सलानपुर क्षेत्र, ईसीएल में 2X2MVA, 11kV/3.3kV सबस्टेशन के निर्माण के लिए एनआईटी।
- कांके रोड, सीसीएल में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए एप्रोच पीक्यूसी रोड और बाउंड्री वॉल का निर्माण।
- निगाही ओसीपी, एनसीएल में रेलवे साइडिंग, सीएचपी और ओबी डंप एरिया की ओर जाने वाली हॉल रोड के साथ-साथ फिक्स्ड वाटर स्प्रींकलर सिस्टम (फॉग-मिस्ट) प्रकार की स्थापना की योजना।
- अरगडा क्षेत्र, सीसीएल में रेलिगारा परियोजना के तहत मंगेरधा नाला पर पुल का निर्माण।
- मौजूदा जयंत सीएचपी, एनसीएल में सेकेंडरी साइजर (-100 मिमी) की स्थापना के लिए

एनआईटी (तकनीकी और वाणिज्यिक) की तैयारी।

- कुसुंडा क्षेत्र में कन्वेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम (विशेष रूप से उपयुक्तता के अनुसार पाइप कन्वेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम) की स्थापना के लिए विस्तृत तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट की तैयारी और डीपीआर की तैयारी।
- खड़िया परियोजना में कार्यशाला / रनिंग रिपेयर डम्पर शेड के लिए योजना, डिजाइन, आकलन और एनआईटी की तैयारी।
- सीसीएल की 2 खदानों में ग्री-वेट ट्रक लोडिंग हॉपर की स्थापना के लिए योजना, आकलन और एनआईटी की तैयारी।
- राजमहल क्षेत्र में मौजूदा 10.5 एमटीवाई सीएचपी के पूर्ण नवीनीकरण की व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट।
- टिकक कोलियरी में स्थापित किए जाने वाले 1000 केएलडी की क्षमता के लिए ईटीपी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी।
- डब्ल्यूसीएल के बल्लारपुर क्षेत्र में सस्ती सेंट्रल इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन (2 x 45/50 एमवीए, 220 केवी / 33 केवी) के लिए एनआईटी की तैयारी।

8.8 संरचनात्मक पर्याप्तता अध्ययन:

- एएपी 2024-25 के अनुसार एनसीएल के बीना सीएचपी का संरचनात्मक स्थिरता अध्ययन



चित्र 2: सीसीएल में प्रस्तावित जवाहरनगर क्लब



चित्र 3: आईआईसीएम में प्रस्तावित खेल परिसर।



चित्र 4: आम्रपाली, सीसीएल में प्रस्तावित जीएम कार्यालय पर



चित्र 1: प्रस्तावित ओपीडी भवन का निर्माण सीएचडी धनबाद, बीसीसीएल



चित्र 5(ए) :



चित्र 5 (बी):

चित्र 5 (ए) और 5 (बी): वानी क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल में प्रस्तावित पर्यावरण पार्क

- एएपी 2024-25 के अनुसार एनसीएल के काकरी सीएचपी का संरचनात्मक स्थिरता अध्ययन
- एनसीएल के एपी के अनुसार जयंत ओसीपी में सीएचपी संरचना के लिए संरचनात्मक स्थिरता अध्ययन।

9.0 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेवाएं

9.1 खान योजना (बुनियादी ढांचा)

• परियोजना रिपोर्ट की तैयारी

➤ मुख्यालय

- बरोरा क्षेत्र के मुराईडीह भूमिगत खदान के लिए फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।
- कुसुंडा क्षेत्र, बीसीसीएल में उपयुक्तता के अनुसार पाइप कन्वेयर परिवहन प्रणाली के लिए तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना

➤ क्षेत्रीय संस्थान I

- रंगमती के लिए पीआर - एक यूजी (3.48 एमटीवाई)
- भनोरा वेस्ट यूजी के लिए पीआर (ओसी-0.5 एमटीवाई, एचडब्ल्यू-0.5 एमटीवाई और यूजी - 0.36 एमटीवाई)
- ब्लॉक सी ओसी के लिए पीआर (6.0 एमटीवाई)

➤ क्षेत्रीय संस्थान II

- ब्लॉक डी की परियोजना रिपोर्ट.

- कल्याणेश्वरी रामनागोर ओसीपी की परियोजना रिपोर्ट

➤ क्षेत्रीय संस्थान III

- अशोक करकट्टा ओसीपी (10.0 एमटीवाई)
- भैरवी ओसीपी (8.0 मीट्रिक टन)
- रोहने ओसीपी (8.0 एमटीवाई), एनएमडीसी
- उत्तर धाधु ओसीपी (4.5 मीट्रिक टन)

➤ क्षेत्रीय संस्थान IV

- नीलजई डीप ओसीएम, डब्ल्यूसीएल (7.0 एमटीवाई)
- सावनेर-III यूजी विस्तार, डब्ल्यूसीएल (1.02 एमटीवाई)
- छिंदा विस्तार ओसीएम, डब्ल्यूसीएल (2.00 एमटीवाई)
- टाकली-जेना बेलोरा ओसीएम, डब्ल्यूसीएल (1.25 एमटीवाई)
- गौरी सेंट्रल ओसीएम, डब्ल्यूसीएल (7.00 एमटीवाई)
- नीलगांव ओसीएम, डब्ल्यूसीएल (2.00 मीट्रिक टन)
- गोंडेगांव ओसीएम, डब्ल्यूसीएल (4.00 मीट्रिक टन)
- चिंचला पिसगांव ओसी (3.0 एमटीवाई)

➤ क्षेत्रीय संस्थान V

- गेवरा ओसीपी विस्तार (70-85 एमटीवाई)
- बागदेवा यूजी (0.96 मीट्रिक टन)
- मालाचुआ यूजी (1.44 मीट्रिक टन)
- रेहर यूजी (1.56 मीट्रिक टन)
- अमृतधारा यूजी (0.96 मीट्रिक टन)
- बदौली यूजी (1.44 मीट्रिक टन)
- नंदीरा यूजी (0.78 मीट्रिक टन)
- राजेंद्र (करकट्टी) यूजी, (0.96 एमटीवाई)

➤ क्षेत्रीय संस्थान VI

- जयंत ओसीपी की ईपीआर (38 एमटीपीए)
- निगाही आर.सी.ई.

- बाहरी परामर्श के लिए स्वतंत्र इंजीनियर (अमेलिया ओसीपी)
 - **क्षेत्रीय संस्थान VII**
 - परियोजना रिपोर्ट तैयार करना
 - बैतरणी पूर्व 20 मीट्रिक टन, एमसीएल
 - लाजकुरा ओसीपी, 8 एमटीवाई, एमसीएल।
 - गोगरपाली के लिए खदान योजना, 20 मीट्रिक टन।
 - **परियोजना रिपोर्ट/लागत अनुमान का अद्यतनीकरण**
 - **क्षेत्रीय संस्थान IV**
 - विष्णुपुरी यूजी से ओसी
 - गड़ेगांव ओसीएम, डब्ल्यूसीएल (2.50 मीट्रिक टन)
 - **क्षेत्रीय संस्थान V**
 - दुर्गापुर ओसीपी (8 मीट्रिक टन)
 - रामपुर बटुरा ओसीपी (4 मीट्रिक टन)
 - सिंघली यूजी के लिए खनन योजना (0.4 मिलियन टन)
- 9.2 कोयला हैंडलिंग प्लांट: ई-टेंडर दस्तावेजों की तैयारी:**
- **मुख्यालय**
 - निगाही ओसीपी में मौजूदा सीएचपी की संरचनात्मक मरम्मत, जीर्णोद्धार, रेट्रोफिटिंग, पुनर्वास, सुदृढ़ीकरण और नया रूप देना।
 - पुराने सीएचपी जयंत (10 एमटीपीए) के नवीनीकरण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण की योजना।
 - सीसीएल की दो खदानों में ग्री-वेट ट्रक लोडिंग हॉपर की स्थापना हेतु योजना की तैयारी।
 - **क्षेत्रीय संस्थान I**
 - सोनपुर बाजारी (12 एमटीवाई) सीएचपी के संचालन और रखरखाव के लिए लागत अनुमान के साथ एनआईटी।
 - **क्षेत्रीय संस्थान III**
 - अशोका सीएचपी के लिए एनआईटी (20.0 मीट्रिक टन)
 - **क्षेत्रीय संस्थान IV**
 - गौरी-पौनी-सस्ती ओसी परियोजना, बल्लारपुर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल (10 एमटीवाई)
 - समामेलित धनकसा-जमुनिया, पेंच क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल (2.0 एमटीवाई)
 - शारदा यूजी, कन्हान क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल (0.51 एमटीवाई)
 - **क्षेत्रीय संस्थान V**
 - अमाडांड ओसीपी का सीएचपी
 - पोर्डा सिमटापानी ओसीपी के लिए सीएचपी
 - कटकोना यूजी बंकर और सीएचपी के लिए एनआईटी
 - **क्षेत्रीय संस्थान VI**
 - जयंत एसटीपी के लिए एनआईटी
 - **क्षेत्रीय संस्थान VII**
 - बारपाली बल्ब, बसुंधरा क्षेत्र में कुल्दा-गर्जनबहाल ओसीपी के लिए 43 एमटीवाई कोयला निकासी प्रणाली और 3 एसआईएलओ और 4 टीएलएस के माध्यम से प्रेषण के लिए ई-टेंडर दस्तावेज और लागत अनुमान तैयार करना।
 - कोयला निकासी प्रणाली (17.5 एमटीवाई) के कार्य के लिए लागत अनुमान के साथ योजना और ई-निविदा दस्तावेज, साथ ही स्क्रीनिंग सह क्रशिंग व्यवस्था और 5 एमटीवाई एटीएलएस, स्वतंत्र टीआरएच और पाइप कन्वेयर का प्रावधान कुल्दा गर्जनबहाल ओसीपी से सरडेगा सीएचपी (यू/सी) तक।
 - लखनपुर क्षेत्र (चरण-II), 20 मीट्रिक टन में सीएचपी/एसआईएलओ के कार्य के लिए निविदा दस्तावेज और लागत अनुमान तैयार करना।
 - एमसीएल के हिंगुला क्षेत्र में हिंगुला ओसीपी (7.5 एमटीवाई) और बलराम ओसीपी (7.5 एमटीवाई) से पाइप कन्वेयर के साथ सीएचपी/

एसआईएलओ के कार्य के लिए एनआईटी और
लागत अनुमान के साथ योजना की तैयारी।

एमवीए, 33/6.6 केवी सबस्टेशन की
एनआईटी तैयारी।

9.3 कार्यशाला एवं स्टोर: ई-निविदा दस्तावेजों की तैयारी

➤ क्षेत्रीय संस्थान VII

- लखनपुर - बेलपहाड़ - लिलारी एकीकृत परियोजना की अनुमोदित परियोजना के अंतर्गत स्टोर के साथ-साथ एचईएमएम और ईएंडएम कार्यशाला परिसर का निर्माण।

9.4 सबस्टेशन: ई-टेंडर दस्तावेजों की तैयारी

➤ मुख्यालय

- डब्ल्यूसीएल, बल्लारपुर क्षेत्र के सस्ती ओसी में 220 केवी/33 केवी सबस्टेशन के निर्माण के लिए एनआईटी और लागत अनुमान तैयार करना।

➤ क्षेत्रीय संस्थान I

- श्यामसुंदरपुर सबस्टेशन 2x7.5 एमवीए-33 केवी / 3.3 केवी के लिए एनआईटी तैयारी।
- नकरकोंडा कुमारडीह बी सबस्टेशन 2x4 एमवीए, 33 केवी/6.6 केवी के लिए एनआईटी तैयारी।

➤ क्षेत्रीय संस्थान III

- अशोका सबस्टेशन के लिए योजना और निविदा दस्तावेज
- अशोक ओएचटीएल के लिए योजना और निविदा दस्तावेज

➤ क्षेत्रीय संस्थान IV

- सावनेर यूजी सबस्टेशन - 2x5 एमवीए, 33/3.3 केवी
- धनकासा यूजी सबस्टेशन - 2x6.3 एमवीए, 33/6.6 केवी
- निलजाई ओसी सबस्टेशन - 2x7.5 एमवीए, 33/6.6 केवी
- सिंघोरी ओसी सबस्टेशन - 2x5 एमवीए, 33/6.6 केवी

➤ क्षेत्रीय संस्थान V

- पोरडा चिमटापानी ओसीपी में 2X10

➤ क्षेत्रीय संस्थान VII

- जगन्नाथ खदान में 2x7.5 एमवीए, 33/3.3 केवी सबस्टेशन और 33 केवी ओएचटीएल के लिए लागत अनुमान के साथ संशोधित ई-एनआईटी तैयार करना।
- 120 एमवीए, 132/33 केवी नंदीरा सेंट्रल सबस्टेशन पर 132/33 केवी के स्वचालन और 33 केवी आउटडोर स्विचयार्ड के संवर्धन के लिए लागत अनुमान के साथ संशोधित ई-एनआईटी तैयार करना।
- बलराम ओसीपी में 132/33 केवी नंदीरा सेंट्रल सबस्टेशन से 2x10 एमवीए, 33/6.6 केवी प्रोजेक्ट सबस्टेशन और 33 केवी डबल सर्किट ओएचटीएल की कमीशनिंग के लिए ई-एनआईटी और लागत अनुमान तैयार करना।
- लखनपुर-बेलफर-लिलारी ओसीपी की एकीकृत पीआर के अनुसार दक्षिण खदान में 3x10 एमवीए, 33/6.6/3.3 केवी सबस्टेशन और 132/33 केवी जोराबगा सबस्टेशन से दक्षिण खदान लखनपुर क्षेत्र, एमसीएल में चरण-II सबस्टेशन तक अलग 33 केवी फीडर (टॉवर लाइन) के काम के लिए ई-एनआईटी और लागत अनुमान तैयार करना।

9.5 सीएचपी/वर्कशॉप/सबस्टेशन के चित्रों की जांच/अनुमोदन

➤ मुख्यालय

- आम्रपाली सीएचपी (25 एमटीवाई) की ड्राइंग जांच
- कनिहा सीएचपी (10 एमटीपीए) की ड्राइंग जांच
- आरजी ओसी सीएचपी की ड्राइंग जांच
- दुधिचुआ कार्यशाला की ड्राइंग जांच
- बीना काकरी अमलगमेशन कार्यशाला की ड्राइंग स्कूटनी।

➤ **क्षेत्रीय संस्थान I**

- सीएचपी - कुमारडीही बी, बंकोला क्षेत्र की ड्राइंग संवीक्षा।
- झांझरा परियोजना में 2X10 एमवीए सब-स्टेशन की ड्राइंग जांच
- सोनपुर बाजारी क्षेत्र के बटमोरा में 2X10 एमवीए सब-स्टेशन की ड्राइंग जांच।

➤ **क्षेत्रीय संस्थान III**

- कोनार सीएचपी (5.0 मीट्रिक टन) की ड्राइंग संवीक्षा।
- केडीएच-पुरनाडीह सीएचपी (7.5 एमटीवाई), मास्टर एसएस और ओएचटीएल की ड्राइंग स्कूटनी।
- कारो सीएचपी (7.0 मीट्रिक टन) की ड्राइंग जांच
- कोनार ओसीपी सबस्टेशन की ड्राइंग जांच
- रजरप्पा ओसीपी सबस्टेशन की ड्राइंग जांच
- मगध सीएचपी अल्टरनेटिव की ड्राइंग स्कूटनी

➤ **क्षेत्रीय संस्थान IV**

- सीएचपी की जांच का आरेखण
- मुंगोली-निर्गुडा ओसीएम सीएचपी (10 एमटीवाई), वाणी क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल
- दिनेश ओसीएम सीएचपी (8 एमटीवाई)। उमरेर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल
- मकरधोकरा-I ओसी विस्तार परियोजना सीएचपी (4 एमटीवाई), उमरेर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल
- मुंगोली निर्गुडा ओसी सबस्टेशन - 2 x 6.3 एमवीए, 33/6.6 केवी
- दिनेश ओसी सबस्टेशन-2x7.5 एमवीए, 33/6.6 केवी और 2x6.3 एमवीए, 33/11 केवी
- सावनेर यूजी सबस्टेशन - 2 x 5 एमवीए, 33/3.3 केवी
- एमालगमेटेड इंदर-कैम्पटी (डीप) ओसी सबस्टेशन - 2x5 एमवीए, 33/6.6 केवी
- धनकसा सबस्टेशन- 2x6.3 एमवीए, 33/6.6 केवी

➤ **क्षेत्रीय संस्थान V**

- सीएचपी की जांच:

- गोवरा सीएचपी चरण-II

- मानिकपुर सीएचपी

- सबस्टेशन की ड्राइंग जांच:

- मानिकपुर ओसीपी, कोबरा क्षेत्र, एसईसीएल में 33 केवी सबस्टेशन।

- रामपुर बटुरा ओसीपी सोहागपुर क्षेत्र, एसईसीएल में 33 केवी सबस्टेशन।

- दीपका ओसीपी, एसईसीएल में 33 केवी सबस्टेशन

- 33 केवी सबस्टेशन, बरौद ओसीपी, रायगढ़ क्षेत्र, एसईसीएल

- 132/33 केवी सबस्टेशन, बरौद ओसीपी, रायगढ़ क्षेत्र, एसईसीएल

- एनएसएन कॉलोनी, एसईसीएल (मुख्यालय), बिलासपुर में 33 केवी सबस्टेशन

- शिवानी यूजी, भटगांव क्षेत्र, एसईसीएल में 33 केवी सबस्टेशन

➤ **क्षेत्रीय संस्थान VI**

- एनसीएल के निगाही सीएचपी (10 एमटीपीए) की ड्राइंग स्कूटनी।

- एनसीएल के बीना सीएचपी (9.5 एमटीपीए) की ड्राइंग स्कूटनी।

- एनसीएल परियोजनाओं के बीना स्विचिंग उप-स्टेशन की ड्राइंग जांच।

- एनसीएल परियोजनाओं के निगाही उप-स्टेशन की ड्राइंग जांच।

- एनसीएल के खड़िया सीएचपी (04 एमटीपीए) की ड्राइंग स्कूटनी।

➤ **क्षेत्रीय संस्थान VII**

- रिपोर्ट, चित्र, योजना, परीक्षण रिपोर्ट और बीओक्यू की जांच तथा पुराने भरतपुर सीएचपी, एमसीएल के नवीनीकरण की योजना और डिजाइन।

- हिंगुला क्षेत्र के हिंगुला ओसीपी में टीएच-2 पर पाइप कन्वेयर के शीर्ष छोर से साइलो (निर्माणाधीन) तक कोयला परिवहन (10 एमटीवाई) के लिए सीएचपी के निर्माण के

लिए ड्राइंग जांच।

- अनंत ओसीपी में सर्जबिन के साथ टीआरएच से आरएलएस तक बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से कोयला परिवहन (20 एमटीवाई) के लिए सीएचपी के निर्माण के लिए ड्राइंग की जांच।
- गर्जनबहाल ओसीपी पर 33/6.6 केवी परियोजना सबस्टेशन और 33 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए ड्राइंग की जांच।
- 220/33 केवी गर्जनबहाल केंद्रीय सबस्टेशन से सियारमल ओसीपी, महालक्ष्मी क्षेत्र, एमसीएल तक 33 केवी डबल सर्किट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की ड्राइंग जांच।
- उत्तरी खदान, एलबीएल ओसीपी, लखनपुर क्षेत्र, एमसीएल में 3 x 12.5 एमवीए, 33/6.6 केवी सबस्टेशन और 33 केवी ओएचटीएल की ड्राइंग जांच।
- एमसीएल के बसुंधरा टाउनशिप, बसुंधरा क्षेत्र में नए 928 (जी+8) क्वार्टरों को बिजली की आपूर्ति के लिए 2 x 5 एमवीए, 33/6.6 केवी सबस्टेशन की ड्राइंग की जांच।

9.6 ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंचमार्किंग

- मुख्यालय, रांची द्वारा निम्नलिखित सहायक कंपनियों के लिए पचासी (85) खुली खदानों के लिए वार्षिक डीजल बेंचमार्किंग

➤ मुख्यालय

- बीसीसीएल के 11 ओसीपी
- कुल मिलाकर 28 ओ.सी.पी.+सी.सी.एल.
- ईसीएल के 07 ओसीपी
- एमसीएल के 11 ओसीपी
- एनसीएल के 10 ओसीपी
- एसईसीएल के 03 ओसीपी
- डब्ल्यूसीएल के 15 ओसीपी

➤ क्षेत्रीय संस्थान III

- चंद्रगुप्त ओसीपी, सीसीएल

• विस्तृत डीजल बेंचमार्किंग

• विद्युत ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंचमार्किंग

➤ मुख्यालय

- गोपालीचक कोलियरी, पीबी एरिया, बीसीसीएल
- खोट्टाडीह उग खदान पांडेश्वर क्षेत्र, ईसीएल
- बिरसा, बरकासयाल क्षेत्र, सीसीएल
- झारखंड, हजारीबाग क्षेत्र, सीसीएल
- ढोरी खास उग खदान, ढोरी क्षेत्र, सीसीएल
- खास महल, बी एंड के एरिया, सीसीएल
- स्वांग/गोविंदपुर पीएच II, कथारा क्षेत्र, सीसीएल
- गोकुल, उमरेर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल
- उमरेर ओसीएम जिसमें उमरेर सीएचपी, उमरेर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल शामिल है

➤ क्षेत्रीय संस्थान I

- पांडेश्वर क्षेत्र ईसीएल की खोट्टाडीह कोलियरी।

➤ क्षेत्रीय संस्थान III

- उत्तर उरीमारी ओसीपी, सीसीएल

➤ क्षेत्रीय संस्थान IV

- विस्तृत डीजल बेंचमार्किंग
 - इंदर-कामटी ओसीएम डीजल ऑडिट
 - मुंगोली ओसीएम डीजल ऑडिट
 - संबलेश्वरी ओसीएम, एमसीएल प्रति घंटा एचएसडी खपत अध्ययन
 - अनंत ओसीएम, एमसीएल प्रति घंटा एचएसडी खपत अध्ययन
 - हिंगुला ओसीएम, एमसीएल प्रति घंटा एचएसडी खपत अध्ययन
 - लिंगराज ओसीएम, एमसीएल प्रति घंटा एचएसडी खपत अध्ययन

■ विद्युत ऊर्जा लेखा परीक्षा और
बैंचमार्किंग

- गोंडेगांव ओसीएम
- अदासा ओसीएम
- साओनेर-॥ यूजी
- समामेलित इंदर-कैम्पटी डीप ओसीएम
- पौनी-॥ ओसीएम
- सस्ती ओसीएम
- निलजई ओसीएम
- मुंगोली ओसीएम
- पेंगांगा ओसीएम
- भटाडी ओसीएम
- एचएल ओसीएम
- येकोना ओसीएम
- एनएमओसीएम

➤ क्षेत्रीय संस्थान VI

- ब्लॉक-बी ओसीपी का डीजल ऑडिट

● रोशनी सर्वेक्षण

➤ मुख्यालय

● राजमहल, ओसीपी का रोशनी सर्वेक्षण

➤ क्षेत्रीय संस्थान II

- एबीओसीपी खान बीसीसीएल

➤ क्षेत्रीय संस्थान VI

- अमलोहरी ओ.सी.पी.
 - झिंगुरदह ओसीपी
 - निगाही ओ.सी.पी.

9.7 विद्युत आपूर्ति और वितरण एवं नियंत्रण प्रणाली

➤ मुख्यालय

- जयंत सीएचपी, एनसीएल में विशिष्ट विद्युत खपत के पुनर्मूल्यांकन के लिए एनआईटी की तैयारी।
- ई-हाउस के सामान्य विनिर्देशन के लिए एनआईटी की तैयारी

9.8 सौर पहल

➤ मुख्यालय

- व्यवहार्यता/योजना के अंतर्गत
 - 50 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड, बीसीसीएल
 - 17.5 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड, ईसीएल
 - 34.5 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड, एनसीएल
 - 63 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड, एमसीएल
 - 34 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड, डब्ल्यूसीएल
 - 0.2 मेगावाट-आरटीएस, आईआईसीएम

■ निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत

- 1.3 मेगावाट-आरटीएस, एनसीएल

■ अनुबंध समझौता के तहत

- 13 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड एसपीपी, एनके एरिया, सीसीएल
- 10 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड, एमसीएल
- 98 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड एसपीपी, डब्ल्यूसीएल

■ कमीशन

- सीसीएल के गिरिडीह क्षेत्र में मेगावाट एसपीपी।

➤ क्षेत्रीय संस्थान II

- बालाकुद्रा पुराने डंप पर मेगावाट एसपीपी का पीएमसी

➤ क्षेत्रीय संस्थान V

- विवेकनगर साइट, सोहागपुर क्षेत्र एसईसीएल में 5 मेगावाट (एसी) / 6.75 मेगावाट पी (डीसी) ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए डीपीआर तैयारी
- शारदा ओसीपी, एसईसीएल में 1.5 मेगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए एनआईटी की तैयारी
- विवेकनगर साइट, सोहागपुर क्षेत्र एसईसीएल में 5 मेगावाट (एसी) / 6.75 मेगावाट पी (डीसी) ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए एनआईटी तैयारी
- एसईसीएल के बरौद ओसीपी के ट्रेंच में फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है

- विवेकनगर साइट, सोहागपुर क्षेत्र एसईसीएल में 5 मेगावाट (एसी) / 6.75 मेगावाट पी (डीसी) ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए ड्राइंग स्कूटनी

➤ क्षेत्रीय संस्थान VII

- एमसीएल के लखनपुर क्षेत्र के किरारामा गांव में 10 मेगावाट (एसी) / 14 मेगावाट पी (डीसी) ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी पावर प्लांट के डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति और स्थापना के साथ परीक्षण, कमीशनिंग आदि के लिए पीएमसी सेवा।
- एमसीएल के ओरिएंट क्षेत्र और इब-वैली क्षेत्र में कैप्टिव उपयोग के लिए 25 मेगावाट (एसी) ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी प्लांट के डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति और स्थापना के साथ परीक्षण, कमीशनिंग आदि के लिए पीएमसी सेवा।
- पीएमसी सर्विस, गांधीसागर, बलराम ओसीपी और माइन सम्प, एमसीएल के भरतपुर ओसीपी में जलाशय पर 8 मेगावाट (एसी) / 11.2 मेगावाट (डीसी) फ्लोटिंग सोलर पीवी पावर प्लांट के डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति और स्थापना के साथ परीक्षण, कमीशनिंग आदि के लिए।
- पीएमसी सर्विस, बसुंधरा ईस्ट ओसीपी, एमसीएल में जलाशय पर 5 मेगावाट (एसी)/7 मेगावाट (डीसी) क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति और स्थापना के साथ परीक्षण, कमीशनिंग आदि के लिए।
- एमसीएल के नटराज यूजी माइन, तालचेर क्षेत्र और एचबीआई यूजी माइन, ओरिएंट क्षेत्र में 4 मेगावाट (एसी) / 5.6 मेगावाट पी (डीसी) क्षमता के ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र के डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति और स्थापना के साथ परीक्षण, कमीशनिंग आदि के लिए पीएमसी सेवा।
- परमानपुर, संबलपुर जिला, एमसीएल में 75 (एसी)/105 एमडब्ल्यूपी (डीसी) मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र के

डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति और स्थापना के साथ परीक्षण, कमीशनिंग आदि के लिए पीएमसी सेवा।

- ओडिशा के रायगढ़ जिले के कुत्रुमाली में एमसीएल द्वारा 99 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र के विकास के लिए परीक्षण, कमीशनिंग और डब्ल्यूआरए अध्ययन सहित डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति और स्थापना के लिए पीएमसी सेवा, एमसीएल।
- सीएमपीडीआई आरआई-VII कॉलोनी में 40 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया।
- भुवनेश्वर स्थित नेत्रहीन संस्थान में सीएसआर के तहत 10 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया।

9.9 अन्य रिपोर्ट/निविदा दस्तावेज/योजना

➤ मुख्यालय

- मुनीडीह सबस्टेशन का सुरक्षा अध्ययन
- राबोडीह कोल ब्लॉक, वेस्ट बोकारो, टीएफसीएमपीएल के लिए खदान बंद करने की योजना की तैयारी।

➤ क्षेत्रीय संस्थान I

- डाबर ओसीपी (0.25 एमटीवाई) के लिए योजना
- खोट्टाडीह कोलियरी (बढ़ती क्षमता 0.51 एमटीवाई) पांडेश्वर क्षेत्र ईसीएल में आर-III/II सीम में स्वदेशी सीएम की शुरुआत के लिए योजना।
- निम्नलिखित कोयला खदानों के लिए बंकोला क्षेत्र में ट्रक लोडिंग स्टेशन (टीएलएस) और बेल्ट कन्वेयर के साथ 80 टी बंकर की स्थापना के लिए लागत अनुमान के साथ योजना ईसीएल को प्रस्तुत की गई है।
 - बंकोला कोलियरी
 - बंकोला कोलियरी - इनक्लाइन नं 2
 - खंडरा कोलियरी - एनके यूनिट
 - खंडरा कोलियरी - वीके यूनिट
 - कुमारडीह ए कोलियरी - पिट नं. 3
 - कुमारडीह ए कोलियरी - पिट नं. 4

➤ **क्षेत्रीय संस्थान III**

- कथारा सीएचपी - व्यवहार्यता रिपोर्ट

➤ **क्षेत्रीय संस्थान V**

- 'चित्रा ओसीपी, ईसीएल के जोखिम मूल्यांकन अध्ययन' के लिए रिपोर्ट तैयार करना
- एफएमसी परियोजना की गुणवत्ता लेखापरीक्षा रिपोर्ट – मानिकपुर ओसीपी
- एफएमसी परियोजना की गुणवत्ता लेखापरीक्षा रिपोर्ट-कुसमुंडा सीएचपी फेज-3

9.10 निरीक्षण सेवाएँ

- निर्माता के कारखाने में सभी सीआईएल सहायक कंपनियों द्वारा खरीदे गए संयंत्र और मशीनरी के लिए प्रेषण-पूर्व निरीक्षण सेवाएँ
- वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय संस्थानों सहित सीएमपीडीआई द्वारा सेवाओं से अर्जित राजस्व लगभग 5.00 करोड़ रुपये है।

9.11 एनडीटी (गैर-विनाशकारी परीक्षण) नौकरियाँ

➤ **मुख्यालय**

- शिवानी और नवापारा यूजी खदान, भटगांव क्षेत्र, एसईसीएल में मैन राइडिंग सिस्टम का एनडीटी
- महाकाली और डीआरसी यूजी खदान, चंद्रपुर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल में मैन राइडिंग सिस्टम का एनडीटी
- राजमहल क्षेत्र, ईसीएल में सीएचपी का एनडीटी
- सीसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में एचईएमएम का एनडीटी
- एनसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में एचईएमएम का एनडीटी
- एनसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में सीएचपी का एनडीटी
- घुगुस ओसीएम, वाणी क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल में सीएचपी का एनडीटी
- गोंडेगांव ओसीएम, नागपुर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल में सीएचपी (02 संख्या) का एनडीटी
- एआईकेडी ओसीएम, नागपुर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल में सीएचपी का एनडीटी
- एचएलसी-1 खदान, चंद्रपुर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल में हेड गियर संरचनाओं का एनडीटी

- आरडी-100 डेरिक का एनडीटी आरआई-III के मैक्लुस्कीगंज कैप में तैनात किया गया

➤ **क्षेत्रीय संस्थान VI**

- काकरी ओसीपी (सीएचपी) पर एनडीटी
- दुधिचुआ ओसीपी (एचईएमएम) में एनडीटी
- बीना ओसीपी (सीएचपी) पर एनडीटी

9.12 आईएसओ परामर्श:

➤ **मुख्यालय**

- एनसीएल के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2013-सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन कार्य हेतु प्रमाणन पश्चात परामर्श कार्य
- सीएमपीडीआई (मुख्यालय) और इसके सभी सात आरआई के लिए आईएसओ 9001:2015-क्यूएमएस के लिए प्रमाणन पश्चात परामर्श कार्य।
- सीसीएल की 05 इकाइयों के लिए आईएसओ 50001:2018 के कार्यान्वयन और प्रमाणन कार्य के लिए परामर्श।
- सहायक कंपनी द्वारा आवश्यकतानुसार ईसीएल, सीसीएल, एनसीएल, एमसीएल और डब्ल्यूसीएल के लिए आईएमएस प्रमाणन पश्चात सहायता कार्य।
- सीएमपीडीआई मुख्यालय के लिए आईएसओ 37001:2016-एंटी ब्रीबरी मैनेजमेंट सिस्टम (एबीएमएस) पुनः प्रमाणन कार्य पूरा हो गया।

9.13 गुणवत्ता लेखापरीक्षा के कार्य:

➤ **मुख्यालय**

- राजमहल सीएचपी, ईसीएल का तृतीय पक्ष गुणवत्ता ऑडिट
- झांझरा सीएचपी, ईसीएल का तृतीय पक्ष गुणवत्ता ऑडिट
- हुर्रा-सी सीएचपी, ईसीएल का तृतीय पक्ष गुणवत्ता ऑडिट
- कनिहा सीएचपी, एमसीएल का तृतीय पक्ष गुणवत्ता ऑडिट
- आरजीओसी 3 सीएचपी (5 एमटीवाई), एससीसीएल का तृतीय पक्ष गुणवत्ता ऑडिट।

➤ **क्षेत्रीय संस्थान III**

- निर्माणाधीन एफएमसी परियोजनाओं (केडीएच पूर्णाडीह सीएचपी) की गुणवत्ता लेखापरीक्षा।

➤ **क्षेत्रीय संस्थान VII**

- भुवनेश्वर ओसीपी, एमसीएल में 15 मीट्रिक टन सीएचपी और साइलो लोडिंग व्यवस्था के लिए तीसरे पक्ष द्वारा गुणवत्ता लेखा परीक्षा।
- सारडेगा साइडिंग, बसुंधरा क्षेत्र, एमसीएल में सर्जबिन लोडिंग व्यवस्था के साथ 20 एमटीवाई सीएचपी और आरएलएस के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता ऑडिट।
- अनंत ओसीपी, एमसीएल में सर्जबिन लोडिंग व्यवस्था के साथ 20 मीट्रिक टन सीएचपी और आरएलएस के लिए तीसरे पक्ष द्वारा गुणवत्ता लेखा परीक्षा।
- सरडेगा साइडिंग, बसुंधरा क्षेत्र, एमसीएल में सर्जबिन लोडिंग व्यवस्था के साथ 20 एमटीवाई सीएचपी और आरएलएस के लिए पीजी परीक्षण और ट्रायल रन।
- लाजकुरा ओसीपी, आईबी-वैली क्षेत्र, एमसीएल में सर्जबिन लोडिंग व्यवस्था के साथ 15 एमटीवाई सीएचपी और आरएलएस के लिए पीजी परीक्षण और ट्रायल रन।

9.14 अन्य प्रमुख कार्य

➤ **क्षेत्रीय संस्थान V**

- कोयला निकासी मास्टर प्लान की तैयारी/अद्यतन, एसईसीएल
- बरौद ओसीपी, पोरदा चिमटापानी ओसीपी, मदननगर ओसीपी और रामपुर बटुरा ओसीपी की रेलवे साइडिंग योजना के लिए डीपीआर की जांच

9.15 बाहरी परामर्श के कार्य

➤ **क्षेत्रीय संस्थान VII**

- एससीसीएल के अंतर्गत ईपीसी मोड पर केजीएम क्षेत्र में वीके 7 सीएचपी के लिए ई-निविदा दस्तावेज और अनुमानित लागत की तैयारी।

- ओडिशा के नैनी ओसी में 10 एमटीपीए कोयला हैंडलिंग प्लांट के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के लिए एससीसीएल को परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
- एससीसीएल के अंतर्गत ईपीसी मोड पर एमएनजी क्षेत्र में पीकेओसी सीएचपी में 10 एमटीपीए कन्वेयर स्ट्रीम के लिए ड्राइंग की जांच।

9.16 नई पहल:

➤ **क्षेत्रीय संस्थान V**

- राजनगर ओसीपी, हसदेव क्षेत्र, एसईसीएल के खदान रिक्त स्थान पर 'पंप स्टोरेज प्लांट' पर पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट

10. नगर अभियंत्रण सेवायें:

नगर इंजीनियरिंग विभाग की मुख्य जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

- इमारतों का रखरखाव, जैसे कार्यालय भवन और आवासीय स्टाफ क्वार्टर। आवश्यक बागवानी कार्यों के साथ साफ-सफाई, स्वच्छ और हरित वातावरण का रखरखाव।
- कार्यालय से संबंधित सभी विद्त, इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक उपकरणों का रखरखाव तथा उनकी सूची बनाए रखना।
- सभी कार्यालय फर्नीचर का रखरखाव।
- आवश्यक कदम उठाकर जल आपूर्ति प्रबंधन।
- बिजली संरक्षण एवं बचत के लिए आवश्यक कदम उठाकर विद्युत प्रबंधन।
- बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी बिल और अन्य वैधानिक भुगतान आदि के भुगतान के लिए प्रस्तावों की प्राप्ति, जांच और प्रस्तुति सुनिश्चित करना।
- नगर निगम और जेबीवीएनएल जैसी स्थानीय वैधानिक संस्थाओं के साथ लाइजनिंग का काम। सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) के टीई और सीएम डिवीजन में 2024-25 में पूंजीगत कार्यों, चालू मरम्मत कार्यों और विशेष मरम्मत कार्यों के तहत कुल व्यय निम्नानुसार है:
- राजस्व प्रकृति के कार्य (सिविल और इलेक्ट्रिकल): रु. 1300.15 लाख
- पूंजीगत प्रकृति के कार्य (सिविल और इलेक्ट्रिकल): रु. 228.12 लाख

11. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

11.1 कोयला मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएं

- कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) गतिविधियों को एक स्थायी निकाय अर्थात् स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसके अध्यक्ष सचिव (कोयला) होते हैं। इस शीर्ष निकाय के अन्य सदस्यों में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अध्यक्ष, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) और नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) के सीएमडी, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के महानिदेशक (डीजी), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के महानिदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि, ऊर्जा सलाहकार, नीति आयोग, निदेशक, सीआईएमएफआर, धनबाद, निदेशक, टेरी और एसएसआरसी की तकनीकी उप-समिति के अध्यक्ष शामिल हैं।
- एसएसआरसी को वार्षिक रोटेशन के आधार पर आईआईटी-केजीपी/आईआईटी-आईएसएम/आईआईटी-बीएचयू के विभागाध्यक्ष (खनन) की अध्यक्षता में एक तकनीकी उप-समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उप-समिति भूमिगत खनन और ओपन कास्ट खनन से उत्पादन और उत्पादकता में सुधार, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण में सुधार, अपशिष्ट से धन, कोयले और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के वैकल्पिक उपयोग, कोयला लाभकारीकरण और उपयोग, अन्वेषण, नवाचार और स्वदेशीकरण (मेक-इन-इंडिया अवधारणा के तहत) आदि के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी/पद्धति से संबंधित नए शोध प्रस्तावों पर विचार करती है।
- सीएमपीडीआईएल कोयला क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें अनुसंधान गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान, उन एजेंसियों की पहचान करना जो पहचाने गए क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य कर सकती हैं, सरकारी अनुमोदन के लिए प्रस्तावों की जांच और प्रसंस्करण, अनुसंधान गतिविधियों के लिए बजट अनुमान तैयार करना, परियोजना की प्रगति के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का संवितरण और परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी आदि शामिल हैं।
 - शुरू की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2025 तक) - 425
 - पूर्ण की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2025 तक) - 346

• वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन

➤ भौतिक प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोयला एसएंडटी परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है (विवरण अनुलग्नक-क में है):

01.04.2024 तक जारी परियोजनाएं	-	22
एसएसआरसी द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं	-	06
पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं	-	08
परियोजनाएं समाप्त/बंद	-	शून्य
31.03.2025 तक जारी परियोजनाएं	-	20

➤ वित्तीय प्रदर्शन:

बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय नीचे दर्शाए गए हैं:

(रुपए करोड़ में)

2023-24			2024-25 (31.3.2025 तक)		
आरई	कोयला मंत्रालय से प्राप्त धनराशि	वास्तविक	आरई	कोयला मंत्रालय से प्राप्त धनराशि	वास्तविक
18.00	18.00	18.00	20.00	20.00	20.00

अनुलग्नक-क

2024-25 के दौरान कोयला मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित अनुमोदित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के नाम

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसियां	स्वीकृत लागत (रुपयें लाख में)
1.	ऑपरेटर के केबिन में प्रदर्शित लोडिंग उपकरण (हाइड्रोलिक उत्खननकर्ता) की पेलोड निगरानी	गेनवेल कॉमोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड (जीसीपीएल), कोलकाता, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंटोरिया	266.34
2.	संरचनाओं में दरारों के प्रसार पर विस्फोट के प्रभाव का पता लगाने की तकनीक	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय), वाराणसी, टेक्नो वेव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (टीडब्ल्यूएसपीएल), रांची, एनसीएल, सिंगरौली	116.79
3.	ऊर्जा संचयन और गैस पहचान-आधारित सेंसर अनुप्रयोगों के लिए कोयला व्युत्पन्न मूल्य-वर्धित कार्बनयुक्त नैनोमटेरियल	केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद	189.54
4.	कोयला खदानों में यूएवी का उपयोग करके धूल कणों और खतरनाक गैसों की निगरानी और दमन के लिए एआई-एमएल क्लाउड-आधारित रियल टाइम व्यापक स्वायत्त प्रणाली	जेपी इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (जेआईआईटी), नोएडा, गरुड़यूएवी सॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (जीएसएसपीएल), नोएडा, एमसीएल, संबलपुर	146.90
5.	कोयला खदानों के लिए 3डी असिमेट्रिक विशाल मैग्नेटोइम्पेडेंस सेंसर का उपयोग करके एक नए एनडीटी उपकरण का विकास	इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन केंद्र (सीएसईएसटी), भौतिकी विद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान (जीआईटीएम), विशाखापत्तनम, एससीसीएल, कोठागुडेम और मेसर्स अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	91.77
6.	बड़े पैमाने पर भू-तकनीकी भरण अनुप्रयोगों के लिए कोल टेलिंग एक्सट्रैक्ट्स (सीटीई) की पुनः प्रयोज्यता का मूल्यांकन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ बीसीसीएल, धनबाद	27.74

कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा वित्त पोषित 2024-25 के दौरान पूरी की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के नाम

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसियां	स्वीकृत लागत (रुपये लाख में)
1.	ऊर्जा भंडारण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेफीन और कार्बन नैनो -कणों के उत्पादन के लिए निम्न श्रेणी के कोयले का उपयोग	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची	86.61
2.	कोयले के विगंधकीकरण के लिए अल्ट्रासोनिक धुलाई	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी (आईआईटीजी), गुवाहाटी, अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन (एआईएचएसईडबल्यू), कोयंबटूर, तमिलनाडु, कुवेम्पु विश्वविद्यालय, ज्ञानसह्याद्री, शंकरगढ़ा, तुमकुर विश्वविद्यालय, वेंकटेश राव कॉलोनी, तुमकुरु और एनईसी, मार्गेरिता	197.35
3.	समयपूर्व विफलताओं की रोकथाम और बकेट व्हील उत्खनन में प्रयुक्त बॉटम रोलर्स के जीवन को बढ़ाना।	अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र, एनएलसीआईएल, नेवेली, एनआईटी, त्रिची और आईआईएससी, बेंगलुरु	188.27
4.	भारत में कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए इष्टतम रणनीति पर अध्ययन	स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (एसआईएस), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली	79.17
5.	सीओ ₂ को पकड़ने के लिए छिद्रयुक्त अधिशोषक विकसित करने हेतु कोयला गैंग का उपयोग	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर और बीसीसीएल, धनबाद	84.73
6.	कोयले का बायोमेथेनाइजेशन	विज्ञान संस्थान, बीएचयू, वाराणसी	69.94
7.	कोल बेड मीथेन रिकवरी और कार्बन पृथक्करण की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कोयला भंडार का जलाशय लक्षण वर्णन और संख्यात्मक मॉडलिंग	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे और सीएमपीडीआई, रांची	193.77
8.	कोयला उद्योग के लिए सीएमपीडीआई में 5जी उपयोग केस परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल), नई दिल्ली, सीएमपीडीआई, रांची, और आईआईआईटी, रांची	454.15

11.2 कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजना

- सीआईएल के आंतरिक अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए, सीआईएल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक अनुसंधान एवं विकास बोर्ड है। अनुसंधान एवं विकास बोर्ड को निदेशक (तकनीकी), सीआईएल की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सीएमपीडीआई अनुसंधान गतिविधियों के लिए बजट अनुमान तैयार करने, नई परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन, परियोजना की प्रगति के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का वितरण, परियोजनाओं के पूरा होने तक उनकी प्रगति की निगरानी और अनुसंधान निष्कर्षों के प्रसार आदि के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

- सीआईएल के कमांड क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास आधार को बढ़ाने के लिए, सीआईएल बोर्ड ने 24 मार्च 2008 को आयोजित अपनी बैठक में सीआईएल के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड और अनुसंधान एवं विकास बोर्ड की शीर्ष समिति को पर्याप्त अधिकार सौंपे हैं। शीर्ष समिति को सभी परियोजनाओं पर विचार करते हुए प्रति वर्ष 25.0 करोड़ रुपये की सीमा के साथ 5.0 करोड़ रुपये तक की व्यक्तिगत अनुसंधान एवं विकास परियोजना को मंजूरी देने का अधिकार है और सीआईएल अनुसंधान एवं विकास बोर्ड को प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये आवंटित करने और 50.0 करोड़ रुपये तक की व्यक्तिगत अनुसंधान एवं विकास परियोजना को मंजूरी देने का अधिकार है।
 - आरएंडडी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2025 तक) – 124।
 - पूर्ण की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2025 तक) – 88।

● 2024-25 के दौरान भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन

➤ भौतिक प्रदर्शन:

2024-25 के दौरान सीआईएल अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है (विवरण अनुलग्नक-ख में है):

क्रम सं.	पैरामीटर	संख्या
1	01.04.2024 तक जारी परियोजनाएं	22
2	2024-25 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं	06
3	2024-25 के दौरान पूरी की जाने वाली परियोजनाएं	10
4	2024-25 के दौरान समाप्त/बंद परियोजनाएं	00
5	31.03.2025 तक जारी परियोजनाएं	18

➤ वित्तीय प्रदर्शन:

इस अवधि के दौरान बजट प्रावधान के मुकाबले वास्तविक निधि संवितरण नीचे दिया गया है:
(रुपए करोड़ में)

2023-24		2024-25 (31.3.2025 तक)	
आरई	वास्तविक	बीई	वास्तविक
70.00	43.21	40.00	31.13

अनुलग्नक- ख

2024-25 के दौरान मंजूरी दी गई सीआईएल द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसियां	स्वीकृत लागत (लाख रुपए में)
1.	ऊर्जा कुशल एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन (ईईईडी) चेंबर लिफ्ट मैन राइडिंग सिस्टम का विकास	आईआईटी-आईएसएम, धनबाद, बीसीसीएल, धनबाद और डीजीएमएस, धनबाद	53.95

2.	सतत खनन मशीन का उपयोग करके उच्च गहराई पर कोयला सीम के निष्कर्षण के लिए भू-तकनीकी संरचनाओं का डिजाइन।	खनन अभियांत्रिकी विभाग, एनआईटी, राउरकेला; उप-कार्यान्वयन एजेंसी: भूमिगत खनन प्रभाग, आरआई-V, सीएमपीडीआई, बिलासपुर ; एससीसीएल और एसईसीएल	303.38
3.	मृदा सूक्ष्मजीव समुदाय का उपयोग करके कोयला खनन क्षेत्र में खनन के बाद त्वरित सुधार पर अध्ययन	सीआईएमएफआर, धनबाद और बीसीसीएल, धनबाद	51.23
4.	मानसिक स्थिति की जांच और मनोभ्रंश सहित मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए अनुसंधान सुविधाओं का निर्माण	आईआईटी, मंडी; सीसीएल और सीएमपीडीआई	333.56
5.	कोकिंग कोयले में मौजूद सक्रिय घटकों के संबंध में कोकिंग कोयले की गुणवत्ता का आकलन	एनएमएल, जमशेदपुर , सीएमपीडीआई	195.64
6.	खदान सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव: सक्रिय और परित्यक्त भूमिगत कोयला खदानों के लिए एआई-सक्षम अग्नि संसूचन प्रणाली	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला; मिलियू ग्लोबल आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद और सीसीएल	421.03

2024-25 के दौरान सीआईएल द्वारा वित्तपोषित पूर्ण की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसियां	स्वीकृत लागत (रुपये लाख में)
1.	भूमिगत कोयला खदानों में प्रयुक्त पिट बॉटम बफर के लिए ड्रॉप टेस्ट सुविधा का डिजाइन और विकास।	आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और ईसीएल, सैंक्टोरिया	248.61
2.	भूमिगत कोयला खदानों में विद्युत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में वेंटिलेशन फैन पवन ऊर्जा पुनर्प्राप्ति प्रणाली का डिजाइन और परिनियोजन।	आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और ईसीएल, सैंक्टोरिया	66.7
3.	मॉडलिंग और सिमुलेशन विश्लेषण के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड के तहत कोकिंग कोल वाशरी के प्रदर्शन में सुधार पर अध्ययन।	एनएमएल जमशेदपुर और सीएमपीडीआई रांची	264.04
4.	कार्बन मूल्यों की वसूली के लिए कोकिंग कोल वाशरी के मिडिलिंग्स और फाइनस का प्रभावी उपयोग।	एनएमएल जमशेदपुर, सीएमपीडीआई रांची और बीसीसीएल धनबाद	141.02
5.	खनिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए घुटने और रीढ़ की हड्डी के स्मार्ट सुरक्षात्मक उपकरणों का डिजाइन और विकास।	आईआईटी-आईएसएम धनबाद और बीसीसीएल धनबाद	72.06
6.	सिंगरौली कोयला खदानों में सीएएलपीयूएफ और ईआरएमओडी के साथ तुलना।	बीआईटी मेसरा और सीएमपीडीआई रांची	85.25

7.	जैव-स्कंदनक का उपयोग करके कोयला वाशरी अपशिष्टों से सूक्ष्म कणों को पृथक करना और पुनः प्राप्त करना।	आईआईटी-आईएसएम धनबाद	54.87
8.	कोयला खदानों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर (वीआरएमएस) का विकास।	आईटी-आईएसएम, धनबाद और सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची।	1410.4
9.	हाईवॉल खनन व्यवहार्यता मूल्यांकन और लेआउट डिजाइन।	भूमिगत खनन प्रभाग (यूएमडी), सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची; राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (सीआईएसआरओ), ऑस्ट्रेलिया और सीआईएल (मुख्यालय), कोलकाता	493.53
10.	विस्तृत प्रकृति की आधार मिट्टी को स्थिर करने तथा इष्टतम ओवरबर्डन डंप ऊंचाई को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए उपयुक्त भूमि सुधार प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए भू-तकनीकी पहलुओं से संबंधित फोरेंसिक जांच	सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग, सीएमपीडीआई (मुख्यालय) रांची और आरआई-IV, सीएमपीडीआई, नागपुर; वीएनआईटी, नागपुर और डब्ल्यूसीएल, नागपुर	492.26

12. विस्फोटन

सीएमपीडीआई ने नियंत्रित विस्फोट और कंपनी अध्ययन, विस्फोटकों और सहायक उपकरणों के परीक्षण, विखंडन मूल्यांकन और एचईएमएम के लाभकारी उपयोग के लिए सुधार अध्ययन के क्षेत्र में मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और क्षमताएं विकसित की हैं। सीएमपीडीआई का ब्लास्टिंग डिवीजन अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, जैसे हाई स्पीड कैमरा, डेटा ट्रेप-II, माइक्रो ट्रेप-II, इन-द-होल वीओडी माप के लिए हांडी ट्रेप-II, विपफ्रेग सॉफ्टवेयर द्वारा विखंडन मूल्यांकन और माप, जेके सिमब्लास्ट द्वारा ब्लास्ट सिमुलेशन और अनकंपाइन्ड स्थिति में विस्फोटक के वीओडी माप के लिए डिजिटल वीओडी मीटर।

2024-25 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों और बाहरी एजेंसियों को प्रदान की गई तकनीकी सेवाएं:

12.1 सीआईएल की सहायक कंपनियों में कार्य

- वर्ष भर विस्फोटकों (थोक विस्फोटक, गैर-अनुमत बड़े व्यास (एनपीएलडी) और अनुमत छोटे व्यास विस्फोटक (पीएसडी) और **सहायक उपकरण** (नोनेल, डेटोनेटिंग फ्यूज, एमएस कनेक्टर, कॉर्ड रिले, पीईटीएन कास्ट बूस्टर, इमल्शन कास्ट बूस्टर, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और सीडीडी/सीईडी डेटोनेटर) का **यादृच्छिक नमूनाकरण और परीक्षण** :
 - बीसीसीएल, सीसीएल, और एनईसी - सीएमपीडीआई (मुख्यालय) के ब्लास्टिंग डिवीजन द्वारा परीक्षण किया गया - मासिक रिपोर्ट
 - ईसीएल - सीएमपीडीआई (मुख्यालय) और आरआई-I, सीएमपीडीआई के ब्लास्टिंग सेल द्वारा परीक्षण किया गया। - मासिक रिपोर्ट
 - डब्ल्यूसीएल - आरआई-IV, सीएमपीडीआई के ब्लास्टिंग सेल द्वारा परीक्षण - मासिक रिपोर्ट
 - एसईसीएल - आरआई-V, सीएमपीडीआई के ब्लास्टिंग सेल द्वारा परीक्षण - मासिक रिपोर्ट

- एनसीएल - आरआई-VI, सीएमपीडीआई के ब्लास्टिंग सेल द्वारा परीक्षण - मासिक रिपोर्ट
- एमसीएल - आरआई-VII, सीएमपीडीआई के ब्लास्टिंग सेल द्वारा परीक्षण - मासिक रिपोर्ट
- **बेंच मार्क पाउडर फैक्टर (बीएमपीएफ) का निर्धारण**
 - सीएमपीडीआई (मुख्यालय) का ब्लास्टिंग प्रभाग: - 6 रिपोर्ट
 - आरआई-I, सीएमपीडीआई का ब्लास्टिंग सेल: - 1 रिपोर्ट
 - आरआई-IV, सीएमपीडीआई का ब्लास्टिंग सेल: - 2 रिपोर्ट
 - आरआई-V, सीएमपीडीआई की ब्लास्टिंग सेल: - 3 रिपोर्ट
 - आरआई-VI, सीएमपीडीआई का ब्लास्टिंग सेल: - शून्य
 - आरआई-VII, सीएमपीडीआई का ब्लास्टिंग सेल: - 4 रिपोर्ट
- **नियंत्रित विस्फोटन एवं कंपनी अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन**
 - सीएमपीडीआई (मुख्यालय) का ब्लास्टिंग प्रभाग: - 7 रिपोर्ट
 - आरआई-I, सीएमपीडीआई का ब्लास्टिंग सेल: - शून्य
 - आरआई-IV, सीएमपीडीआई का ब्लास्टिंग सेल: - शून्य
 - आरआई-V, सीएमपीडीआई की ब्लास्टिंग सेल: - 1 रिपोर्ट
 - आरआई-VI, सीएमपीडीआई का ब्लास्टिंग सेल: - 1 रिपोर्ट
 - आरआई-VII, सीएमपीडीआई का ब्लास्टिंग सेल: - 6 रिपोर्ट
- **एसडीओसीएम, ठोरी क्षेत्र, सीसीएल में ब्लास्टिंग ऑपरेशन के दौरान बोल्टर को कम करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन**
- **कंपनी अध्ययन की नियमित निगरानी**
 - सीएमपीडीआई (मुख्यालय) का ब्लास्टिंग प्रभाग: - 2 माईस

12.2 सीएमपीडीआई (मुख्यालय) के ब्लास्टिंग डिवीजन द्वारा किया गया बाहरी परामर्श कार्य

- एनएलसी इंडिया लिमिटेड की खदानों को विभिन्न निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किए गए विस्फोटकों और सहायक उपकरणों का त्रैमासिक प्रदर्शन मूल्यांकन - 4 रिपोर्ट
- एनएलसी इंडिया लिमिटेड की तालाबीरा II और III खदानों में विभिन्न निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किए गए विस्फोटकों और सहायक उपकरणों का त्रैमासिक प्रदर्शन मूल्यांकन - 4 रिपोर्ट
- 2 वर्ष की अवधि के लिए एससीसीएल की भूमिगत और खुली खदान परियोजनाओं में कोयले में विस्फोट के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमत विस्फोटकों (पी1 और पी5) और डेटोनेटर और एलडीसी विस्फोटकों और सहायक उपकरणों का त्रैमासिक आवधिक यादृच्छिक परीक्षण। - 4 रिपोर्ट
- नए विस्फोटकों और सहायक उपकरणों का प्रदर्शन मूल्यांकन: - 3 रिपोर्ट

12.3 आरआई-VII, सीएमपीडीआई के ब्लास्टिंग सेल द्वारा किया गया आउट-साइड परामर्श कार्य

- नियंत्रित विस्फोट एवं कंपनी अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन: - 2 रिपोर्ट

12.4 सीएमपीडीआई (मुख्यालय) के ब्लास्टिंग प्रभाग द्वारा किए गए विशेष कार्य

- कोल इंडिया लिमिटेड की खदानों में उन्नत कार्यप्रणाली के आधार पर बेंचमार्क पाउडर फैक्टर के निर्धारण के लिए वैज्ञानिक कार्यप्रणाली का विकास करना।

- एसडीओसीएम, ठोरी क्षेत्र, सीसीएल में ब्लास्टिंग ऑपरेशन के दौरान बोल्टर को कम करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन
- सीआईएल द्वारा अनुमोदित विस्फोटकों और सहायक उपकरणों की उत्पाद सूची में विस्फोटक निर्माताओं को सूचीबद्ध करने के संबंध में एसओपी को अद्यतन करना।
- आरआई/सीआईएल के लिए तकनीकी सहायता/रिपोर्टों की जांच।

13. प्रयोगशाला सेवाएँ

13.1 रासायनिक प्रयोगशाला

रासायनिक प्रयोगशाला कोयला/कोक/लिग्नाइट के समीपस्थ विश्लेषण के लिए थर्मोग्रैविमेट्रिक विश्लेषक, कोयला और लिग्नाइट के सकल कैलोरी मान के निर्धारण के लिए स्वचालित बम कैलोरीमीटर, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर के निर्धारण के लिए सीएचएनएस उपकरण, कोयले के राख संलयन तापमान सीमा (आईडीटी, एसटी, एचटी और एफटी) के लिए एएफटीआर उपकरण, कोयले की प्लास्टिसिटी के निर्धारण के लिए स्वेलिंग इंडेक्स, एलटीजीके, प्लास्टोमीटर और कोयले के कोकिंग गुणों के निर्धारण के लिए अन्य पारंपरिक और परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित है।

इसके अलावा, प्रयोगशाला को हाल ही में कोयला और गैर-कोयला नमूनों में खनिज चरणों की पहचान करने के लिए एक एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर (एक्सआरडी) प्रणाली और कोयला राख में ऑक्साइड के रूप में तत्वों का निर्धारण करने के लिए एक एक्स-रे फ्लोरोसेंस (एक्सआरएफ) उपकरण से सुसज्जित किया गया है। प्रयोगशाला दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (आरईई) और ट्रेस धातुओं के गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण के लिए एक आईसीपी-एमएस (इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा - मास स्पेक्ट्रोमेट्री) सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया में भी है।

13.2 कोयला पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला

पेट्रोग्राफी लैब पेट्रोग्राफिक विश्लेषण जैसे कि मैकरल संरचना, यादृच्छिक परावर्तन (आरओआर%) और औसत अधिकतम परावर्तन% (एमएमआर%) का निर्धारण करती है। यह अध्ययन नमूनों के कोयला-प्रकार और कोयला रैंक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह अध्ययन हाइड्रोकार्बन, तेल शेल, कोल बेड मीथेन और शेल गैस मूल्यांकन के लिए स्रोत रॉक मूल्यांकन के लिए भी उपयोगी है।

पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला पेट्रोग्राफिक अध्ययन करने के लिए उन्नत पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप से सुसज्जित है जिसमें कोयले के नमूनों की मैकरल सामग्री (कोयला प्रकार) और परावर्तन प्रतिशत (रैंक/परिपक्वता) निर्धारित की जाती है। कोक बनाने में मिश्रण के रूप में दिए गए कोयले की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए पेट्रोग्राफिक अध्ययन अनिवार्य है। पेट्रोग्राफिक अध्ययन और क्लीट अध्ययन के लिए कोयला छरों की तैयारी के लिए अपघर्षक कटिंग मशीन और हॉट माउंटिंग प्रेस भी उपलब्ध हैं।

13.3 कोल प्रेपरेशन प्रयोगशाला

सीएमपी प्रयोगशाला आवश्यकता के अनुसार विभिन्न कोयला क्षेत्रों के कोकिंग और नॉन-कोकिंग कोयले के नमूनों के लिए वाशेबिलिटी विश्लेषण (समीपस्थ विश्लेषण, जीसीवी, एचजीआई, केकिंग गुण आदि सहित) में कार्यरत है। ये विश्लेषण बोर कोर कोयला नमूनों और आरओएम कोयले के लिए किए जाते हैं। 2024-2025 के दौरान जिन कोयला नमूनों का विश्लेषण किया गया है, उनकी संख्या नीचे दी गई है:

- बोर कोर कोयला नमूने – 19 नमूने
- आरओएम कोयला नमूने – 06 नमूने
- कोयला नमूनों के गुणवत्ता मापदंड – 08 नमूने

13.4 एमवी और एमटी लैब

एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को चट्टान और कोयला कोर नमूनों का भौतिक-यांत्रिक परीक्षण करना है, जिसमें असीमित संपीड़न शक्ति, त्रिअक्षीय संपीड़न शक्ति (संलग्नता और आंतरिक घर्षण कोण), तन्य शक्ति, कतरनी शक्ति, प्रत्यास्थ स्थिरांक (यंग मापांक, पॉइसन अनुपात), थोक घनत्व, प्रोटोड्याकोनोव शक्ति सूचकांक (पीएसआई), प्वाइंट लोड सूचकांक और स्लेक स्थायित्व सूचकांक शामिल हैं।

उत्पन्न आंकड़ों और तैयार रिपोर्टों का उपयोग भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के भाग के रूप में किया जाता है तथा भूमिगत और खुली खदानों दोनों के लिए भू-तकनीकी अध्ययनों के इनपुट के रूप में भी किया जाता है।

रॉक-मास रेटिंग और सपोर्ट डिज़ाइन भी इस इकाई द्वारा तैयार किए गए स्ट्रेटा नियंत्रण और निगरानी योजना का एक हिस्सा हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एमवी और एमटी प्रयोगशाला द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ/कार्य किए गए हैं।

- **चट्टान और कोयला कोर नमूनों के लिए भौतिक-यांत्रिक गुण (पीएमपी) का पूरा किया गया परीक्षण - 5044 मीटर लंबाई कोर:**
 - कोटमेर ब्लॉक, मांड-रायगढ़ कोयला क्षेत्र के बीएच संख्या एमकेटीडी - 60 का भौतिक - यांत्रिक गुण परीक्षण (अप्रैल 2024)
 - सीसीएल कमांड क्षेत्र के अंतर्गत, बलकुदरा ब्लॉक, बीएच संख्या सीएमपीडी- 01, 02 और 03 का भौतिक-यांत्रिक गुण परीक्षण। (अप्रैल 2024)
 - कोटमेर ब्लॉक, मांड-रायगढ़ कोलफील्ड के बीएच संख्या एमकेटीडी - 129 का भौतिक - यांत्रिक गुण परीक्षण। (मई 2024)
 - पतरातू साउथ ब्लॉक, साउथ करनपुरा कोलफील्ड के बीएच संख्या एपीपीएस - 27 (पी - 44) का भौतिक - यांत्रिक गुण परीक्षण। (जून '2024)
 - नामचिक-पश्चिम ब्लॉक, नामचिक-नामफुक कोलफील्ड के बीएच संख्या एनएनडब्ल्यू - 08 (पीबीएच -06) का भौतिक - यांत्रिक गुण परीक्षण। (अगस्त 2024)
 - कोटमेर ब्लॉक, मांड रायगढ़ कोलफील्ड के बीएच संख्या एमकेटीडी - 147 का भौतिक - यांत्रिक गुण परीक्षण। (सितंबर 2024)
 - मांड-रायगढ़ कोलफील्ड के जिल्ला बरपाली ब्लॉक के बीएच संख्या एमएमजेबी - 175 का भौतिक - यांत्रिक गुण परीक्षण। (नवंबर 2024)
 - कोसला ईस्ट ब्लॉक, तालचेर कोलफील्ड के बीएच संख्या सीटीकेई -58 का भौतिक - यांत्रिक गुण परीक्षण। (दिसंबर 2024)
 - देवनाड-1 ब्लॉक, एनके कोलफील्ड के बीएच संख्या सीडीएनए-18 का भौतिक-यांत्रिक गुण परीक्षण। (जनवरी 2025)
 - बीएच संख्या सी.एम.टी.बी.बी. - 179, बलभद्र पश्चिम एक्सटेंशन ब्लॉक, तालचेर कोयला क्षेत्र का भौतिक-यांत्रिक गुण परीक्षण। (फरवरी 2025)
 - बीएच संख्या सी.एम.टी.बी.बी. - 180, बलभद्र उत्तर विस्तार ब्लॉक, तालचेर कोयला क्षेत्र का भौतिक-यांत्रिक गुण परीक्षण (फरवरी 2025)
 - सरधापुर उत्तर, तालचेर कोलफील्ड के बीएच संख्या सीटीएसएन-74 का भौतिक-यांत्रिक गुण परीक्षण। (मार्च 2025)।

प्रस्तुत रिपोर्टों की कुल संख्या - 12

- **स्तंभ स्थिरता अध्ययन / एस.सी.ए.एम.पी. / आर.एम.आर. / कैवेबिलिटी अध्ययन:**

- स्तंभ स्थिरता अध्ययन / एस.सी.ए.एम.पी. / आर.एम.आर. / कैवेबिलिटी अध्ययन की पूर्ण रिपोर्ट:
- विकास को अंतिम मानते हुए दीर्घकालिक स्थिरता के लिए भानोरा पश्चिम यूजी परियोजना, ईसीएल के पिलर आकार और गैलरी की चौड़ाई का निर्धारण। (अप्रैल 2024)।
- स्ट्रेटा नियंत्रण एवं निगरानी योजना (एससीएएमपी) तैयार करने के लिए आरएमआर का निर्धारण तथा विंध्य यूजी खदान, जोहिला क्षेत्र, एसईसीएल के प्रस्तावित सीएम-4 एवं सीएम-5 पैनल में सतत माइनर के साथ कार्य करने की उपयुक्तता। (फरवरी 2025)

प्रस्तुत रिपोर्टों की कुल संख्या - 2

- **अनिर्धारित कार्यों के लिए पीएमपी टेस्ट (पूर्ण):**

- एचबीएम, एमसीएल की यूजी खदान के कोर नमूनों के पीएमपी पर परीक्षण के परिणाम।
- निगाही परियोजना, एनसीएल के कोर नमूनों के पीएमपी पर परीक्षण के परिणाम।
- कृष्णशिला परियोजना, एनसीएल के कोर नमूनों के पीएमपी पर परीक्षण के परिणाम।
- काकरी परियोजना, एनसीएल के कोर नमूनों के पीएमपी पर परीक्षण के परिणाम।
- बोकारो, सीसीएल के कोर नमूनों के पीएमपी पर परीक्षण के परिणाम।
- टीएलसीएमपी, एनटीपीसी के पश्चिमी पिट, दक्षिणी पिट, पूर्वी पिट के कोर नमूनों के थोक घनत्व पर परीक्षण के परिणाम।
- एएडीसीओएम, ढोरी क्षेत्र, सीसीएल के कोर नमूनों के पीएमपी पर परीक्षण के परिणाम।
- लखनपुर ओसीपी, एमसीएल के कोर नमूनों के पीएमपी पर परीक्षण के परिणाम।
- कुल्दा ओसीपी, एमसीएल के कोर नमूनों के पीएमपी पर परीक्षण के परिणाम।

पूर्ण की गई रिपोर्टों की कुल संख्या - 9

- **प्रस्तुत कुल चट्टान प्रकार परीक्षण रिपोर्ट:**

मार्च 2025 तक पूरी की गई रिपोर्टों की कुल संख्या - 23

14. पर्यावरण सेवा

14.1 सीआईएल परियोजनाओं के लिए ईआईए/ईएमपी

वर्ष 2024-25 के दौरान, पर्यावरण विभाग ने कुल 29 फॉर्म-1 (फॉर्म III, IV और VI सहित) और 19 ड्राफ्ट ईएमपी/परिशिष्ट ईएमपी तैयार किए। कुल 48 रिपोर्ट तैयार की गईं।

14.2 बाहरी परियोजनाएँ

वर्ष 2024-25 के दौरान पर्यावरण विभाग ने तैयार की:

- मेसर्स एम चावला के लिए कनवारा-2 खदान, बांदा, यूपी के लिए अंतिम रेत पुनःपूर्ति अध्ययन रिपोर्ट
- मेसर्स एम चावला के लिए भोजपुर सोन-35 घाट, यूपी के लिए अंतिम रेत पुनःपूर्ति अध्ययन रिपोर्ट
- पछवाड़ा सेंट्रल ब्लॉक ओसीपी, मेसर्स पीएसपीसीएल के लिए खदान बंद करने का ऑडिट
- परसा ईस्ट और कांता बेसिन ओसीपी के लिए खदान बंद करने का ऑडिट, मेसर्स अदानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड

14.3 वायु, जल और ध्वनि की पर्यावरणीय निगरानी

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) खनन परियोजनाओं को इस शर्त पर पर्यावरण मंजूरी (ईसी) देता है कि नियमित पर्यावरण निगरानी (आरईएम) की जाए। परियोजना स्थलों पर लागू प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता को सत्यापित करने और खदानों के परिचालन चरण के दौरान निर्धारित ईसी शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह निगरानी आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सीआईएल (ईसीएल-16, बीसीसीएल-17, सीसीएल-74, डब्ल्यूसीएल-75, एसईसीएल-78, एनसीएल-13 और एमसीएल-30) की 303 परियोजनाओं/क्लस्टरों/प्रतिष्ठानों की पर्यावरण निगरानी आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, हसदेव, जयंत और रांची में स्थित आठ पर्यावरण प्रयोगशालाओं के माध्यम से की गई।

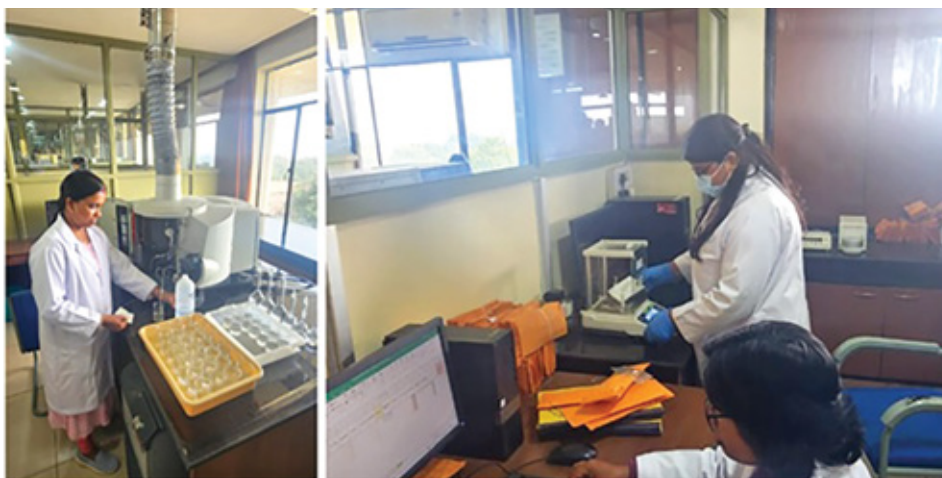
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एकत्रित एवं विश्लेषित कुल नमूने:

वायु : 1,60,689,

शोर: 26,042 + 312 (दिन और रात + केवल दिन) और

जल : 23,716

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पर्यावरण सेवाओं से अर्जित कुल राजस्व जीएसटी को छोड़कर 359.69 करोड़ रुपये है।



नमूना विश्लेषण: पर्यावरण प्रयोगशाला, सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय), रांची का एक दृश्य

14.4 सीएमपीडीआईएल को ईआईए परामर्श संगठन के रूप में मान्यता

सीएमपीडीआईएल को भारतीय गुणवत्ता परिषद (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की नामित एजेंसी) द्वारा ओपनकास्ट/भूमिगत खनन क्षेत्र, थर्मल पावर और कोल वॉशरीज क्षेत्र, अपतटीय और तटवर्ती तेल एवं गैस अन्वेषण, कोल बेड मीथेन के ईआईए के लिए विकास और उत्पादन सहित खनिजों के खनन क्षेत्रों के लिए ईआईए मान्यता प्राप्त सलाहकार संगठन (एसीओ) के रूप में मान्यता प्राप्त है। सीएमपीडीआईएल ईआईए और ईएमपी की तैयारी के लिए भारत में सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त सलाहकार संगठन (एसीओ) है और इसके पास 80 से अधिक अनुमोदित विशेषज्ञ हैं।

14.5 सीएमपीडीआईएल पर्यावरण प्रयोगशाला का मान्यता

सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची स्थित पर्यावरण प्रयोगशाला को 170 मापदंडों के लिए आईएसओ/आईसीसी 17025:2017 मानकों के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा पुनः मान्यता दी गई। यह मान्यता 24 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। प्रयोगशाला को व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) आईएस/आईएसओ 45001:2018 के अनुसार भी मान्यता प्राप्त है।

इसी प्रकार, आरआई-I, आसनसोल, आरआई-II, धनबाद, आरआई-IV, नागपुर, आरआई-V, बिलासपुर और आरआई-VII, भुवनेश्वर की पर्यावरण प्रयोगशालाओं को भी आईएसओ/आईसीसी 17025:2017 मानकों के तहत एनएबीएल मान्यता प्राप्त है।

14.6 कोयला परियोजनाओं के लिए ईटीपी/आईडब्ल्यूएसएस योजना

वित्तीय वर्ष के दौरान, निम्नलिखित एकीकृत जल आपूर्ति प्रणाली (आईडब्ल्यूएसएस) / अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) से संबंधित कार्य किए गए:-

- 2.5 एमएलडी आईडब्ल्यूएसएस, पश्चिम-जेकेडी, हसदेव क्षेत्र, एसईसीएल के उन्नयन की योजना।
- 1.4 एमएलडी एमडी-ईटीपी और मौजूदा 300 केएलडी वर्कशॉप ईटीपी, बलराम ओसीपी, एमसीएल के संशोधन की योजना।
- साथ ही, 1(एक) परियोजनाओं के लिए निविदा दस्तावेज (तकनीकी भाग) यानी, 7.2 एमएलडी ईटीपी, झिंगुरदह ओसीपी, एनसीएल का स्थानांतरण भी तैयार किया गया और प्रस्तुत किया गया।
- इसके अलावा, 2 (दो) परियोजनाओं अर्थात 75 केएलडी सीएचपी ईटीपी, दिनेश ओसीपी, डब्ल्यूसीएल और 7.2 एमएलडी ईटीपी, झिंगुरदाह ओसीपी, एनसीएल के सफल बोलीदाताओं की डिजाइन और ड्राइंग की जांच की गई।

14.7 कोयला खनन परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन

वर्ष 2014 में पर्यावरण प्रभाग द्वारा कोयला खनन परियोजनाओं के लिए 19 परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन किया गया।

14.8 सतत विकास प्रकोष्ठ, कोयला मंत्रालय की सहायता के लिए

एमओसी के निर्देशानुसार एसडीसी कार्यों के अंतर्गत सीएमपीडीआईएल ने निम्नलिखित रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है:

- कोयला क्षेत्र में ओवर बर्डन (ओबी) के लाभकारी उपयोग पर एचपीईसी रिपोर्ट।
- सीआईएल द्वारा विकसित इको-पार्कों की प्रभावशीलता की मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रारूप)।
- कोयला रहित भूमि के पुनः उपयोग के लिए एसओपी का विकास।

14.9 विशेष अध्ययन

- एकीकृत लखनपुर-बेलफर लिलारी ओसीपी, एमसीएल की मृदा नमी संरक्षण योजना प्रस्तुत की गई।
- 2 परियोजनाओं अर्थात केदला ओसी और मगध ओसी, सीसीएल के लिए शीर्ष मृदा प्रबंधन और मृदा अपरदन योजना प्रस्तुत की गई।
- 5 परियोजनाओं अर्थात सीसीएल के अमलो विस्तार ओसीपी, एसईसीएल के जगरनाथपुर ओसीपी और कुसमुंडा ओसीपी, एनसीएल के ब्लॉक बी ओसीपी और निगाही ओसी के लिए ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
- ढोरी कोकिंग कोल वाशरी, सीसीएल की कार्बन सीकेस्ट्रेशन अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
- भटाडी ओसीपी, डब्ल्यूसीएल के लिए नदी पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
- बीसीसीएल के सात क्लस्टरों का प्रदूषण न्यूनीकरण अध्ययन (वित्त वर्ष 2023-24) प्रस्तुत किया गया।
- 3 परियोजनाओं अर्थात लेडो यूजी कोलियरी, बारगोलाई यूजी कोलियरी और जयपुर डेली यूजी कोलियरी, एनईसी की अंतिम खान बंद करने की योजना प्रस्तुत की गई।

14.10 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/अनुसंधान एवं विकास अध्ययन

वर्ष के दौरान निम्नलिखित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएं पूरी की गईं:

- सिंगरौली कोयला खदानों में एएनएन, पीएनएन और कार्ट मॉडल के माध्यम से पार्टिकुलेट मैटर और गैसीय प्रदूषक सांद्रता का पूर्वानुमान और कैलपफ और ईआरएमओडी के साथ तुलना।

14.11 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण

पर्यावरण प्रभाग, सीएमपीडीआईएल ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का आयोजन किया था :-

- सीएमपीडीआईएल मुख्यालय में सीआईएल विभिन्न सहायक कंपनियों और आरआई के 50 प्रतिभागियों के लिए "माइन क्लोजर पोर्टल" पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- 19 से 21 जून, 2024 के बीच क्यूसीआई-एनएबीईटी के सहयोग से सीएमपीडीआईएल मुख्यालय में पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) सलाहकार संगठनों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्यालय और आरआई दोनों से 52 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

14.12 पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम

• विश्व पर्यावरण दिवस का उत्सव

विश्व पर्यावरण दिवस 2024 को 5 जून 2024 को सीएमपीडीआईएल के मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय संस्थानों (RI) में "भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता" की वैश्विक थीम के साथ मनाया गया।

इस वैश्विक आयोजन से पहले, सीएमपीडीआईएल ने मुख्यालय और सभी RI में वृक्षारोपण पहल, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता, क्विज़, सेमिनार और निबंध प्रतियोगिताओं जैसे विविध अभियानों और प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों की मेजबानी की। इन पहलों का उद्देश्य स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देना और भूमि प्रबंधन प्रथाओं में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना था।



• वृक्षारोपण अभियान'2024

सीएमपीडीआईएल ने अपने रांची मुख्यालय और छह राज्यों में स्थित सात क्षेत्रीय संस्थानों में वृक्षारोपण अभियान के साथ इस अवसर को मनाया। वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत इसके सम्मानित निदेशकों, क्षेत्रीय निदेशकों, विभागाध्यक्षों, अन्य गणमान्य व्यक्तियों और इसके कर्मचारियों की भागीदारी के साथ हुई।

सीएमपीडीआईएल के मुख्यालय और क्षेत्रीय संस्थानों में फलदार और औषधीय प्रजातियों के कुल 1400 पौधे लगाए गए। खास बात यह है कि इनमें से 1200 पौधे स्थानीय समुदायों, स्कूली बच्चों, सुरक्षाकर्मियों और अन्य लोगों को वितरित किए गए।



• एक पेड़ माँ के नाम अभियान

स्वच्छता ही सेवा पहल के तहत चलाए गए "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान में सीएमपीडीआई के मुख्यालय और क्षेत्रीय संस्थानों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। उल्लेखनीय है कि माननीय केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने अपने दौरे के दौरान अभियान के समर्थन में सीएमपीडीआई, रांची में एक पौधा लगाया।

इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल ने राज्य वन विभाग, रांची के सहयोग से अभियान के तहत नगर वन, बरियातू, रांची में 1000 पौधे लगाए। कार्यक्रम में श्री एस.आर. नटेश, आईएफएस, सीसीएफ वन्यजीव, श्री श्रीकांत वर्मा, आईएफएस, सदस्य सचिव, राज्य ईएसी, डीएफओ रांची और सीएमपीडीआई और राज्य वन विभाग, रांची के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।



15. सूचना एवं संचार तकनीक।

इन-हाउस सहायता प्रदान करने के अलावा, सीएमपीडीआईएल का आईसीटी प्रभाग एमओसी, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों को परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए प्रमुख कार्यों की रूपरेखा नीचे दी गई है:

15.1 एमओसी और संपूर्ण सीआईएल के लिए आईसीटी प्रभाग, सीएमपीडीआईएल द्वारा विकसित और अनुरक्षित केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर :

- अनुबंध श्रम सूचना पोर्टल (सीएलआईपी) के लिए पोर्टल।
- अधिकारी सूचना प्रणाली (ईआईएस)।
- प्राइड/पार सहित ऑन-लाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस)।
- सतर्कता मंजूरी प्रणाली/सतर्कता निगरानी प्रणाली।
- अधिकारियों के लिए वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) और संपत्ति सूचना एवं संपत्ति स्वीकृति (पीआईपीएस) पोर्टल।

- बैंक कार्ड दर प्रणाली - कंपनियों की एफडी के लिए बैंकों से ब्याज दर उद्धरण आमंत्रित करती है।
- भूमिगत एवं खुली खदान क्षमता मूल्यांकन।
- ऑनलाइन कोयला ब्लॉक सूचना प्रणाली।
- कोयला मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा रही परियोजनाओं के लिए खान डेटा प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (एमडीएमएस)। इसमें 1 बीटी योजना, पर्यावरण मंजूरी (ईसी), वन मंजूरी (एफसी), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) और सतत विकास सेल (एसडीसी) योजनाओं का निर्माण शामिल है।
- फार्म 1,2,3,4,5 और ईआईए/ईएमपी के संबंध में ईसी/एफसी जांच पर परिवेश पोर्टल का क्लोन, जिसका सत्यापन समकक्षों (सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थान), सीआईएल और परियोजनाओं की संबंधित सहायक कंपनियों द्वारा किया जाएगा।
- कोयला मंत्रालय के लिए एक डैशबोर्ड, राष्ट्रीय कोयला पोर्टल।
- सीआईएल की सीएसआर गतिविधियों के एक भाग के रूप में निर्माण (राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए शानदार पहल) पोर्टल
- सीएमपीडीआई एल संपूर्ण कोल इंडिया लिमिटेड के लिए ई-ऑफिस एप्लिकेशन हेतु सहायता प्रदान कर रहा है।

15.2 सीएमपीडीआईएल के लिए विकसित किए गए वेब पोर्टल

- सीएमपीडीआईएल मुख्यालय और आरआई से चालान अपलोड करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है जो हमारे ग्राहक सीआईएल सहायक कंपनियों को चालान डाउनलोड करने और उन्हें जल्दी से संसाधित करने की सुविधा देता है। इससे सीएमपीडीआईएल को चालान के भुगतान में होने वाली देरी कम हो जाएगी।
- कार्यो/कार्य बिंदुओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए, सीएमपीडीआईएल डैशबोर्ड विकसित किया गया है।
- सीएमपीडीआईएल के लिए कॉलोनी शिकायत प्रबंधन प्रणाली - सीएमपीडीआईएल कॉलोनियों में क्वार्टरों के रखरखाव से संबंधित शिकायतों की एंड-टू-एंड ट्रेकिंग और प्रबंधन के लिए ऑनलाइन सुविधा।
- सीएमपीडीआईएल के लिए ऑनलाइन क्वार्टर आवंटन प्रणाली
- RASTEAL - सहायक कंपनियों में पत्रिकाओं में विस्फोटक स्टॉक की निगरानी करना
- हैकाथॉन - सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रकाशित समस्या विवरण के लिए समाधान आमंत्रित करने हेतु विकसित एक पोर्टल
- ओएलपीएस - सीएमपीडीआईएल के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली
- कार्य - सीएमपीडीआईएल कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन ईडी बुकिंग की प्रणाली
- सीएमपीडीआईएल की सार्वजनिक वेबसाइट और इंटरनेट वेबसाइट का अद्यतन और रखरखाव

15.3 सीएमपीडीआईएल के लिए अन्य आईटी पहल

- ईआरपी अपने 6 मॉड्यूलों एचसीएम, एफआईसीओ, पीएम, पीएस, एमएम और एसडी के साथ सीएमपीडीआईएल में लागू किया गया है। मुख्यालय, डीसी और डीआर में 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ और आरआई में 40 एमबीपीएस बैंडविड्थ के साथ प्राथमिक एमपीएलएस कनेक्टिविटी रेलटेल कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित की गई है। मुख्यालय में 500 एमबीपीएस बैंडविड्थ और आरआई में 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ के साथ माध्यमिक एमपीएलएस कनेक्टिविटी बीएसएनएल द्वारा स्थापित की गई है।

- फाइबर ऑप्टिक बैकबोन के साथ लोकल एरिया नेटवर्क का रखरखाव कर रहा है। सभी आरआई को एमपीएलएस वीपीएन सर्किट के माध्यम से सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) से जोड़ा गया है। सीएमपीडीआईएल के पास बीएसएनएल के माध्यम से 1 जीबीपीएस समर्पित इंटरनेट लीज्ड लाइन और रेलटेल के माध्यम से 1 जीबीपीएस सेकेंडरी आईएलएल है।
- एनआईटी तैयारी, तकनीकी जांच और नई प्रौद्योगिकी सेवाएं
- मुख्यालय एवं क्षेत्रीय संस्थानों के लिए आईटी अवसंरचना प्रबंधन
- ईआरपी, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए समर्थन
- डीसी (रांची) और डीआर (नागपुर) में सर्वरों का रखरखाव
- कोल इंडिया मेल के लिए सीआईएल के साथ समन्वय
- सीएमपीडीआईएल के लिए ई-ऑफिस गतिविधियों का समन्वय
- नेटवर्क और साइबर सुरक्षा अनुपालन
- एसएमएस सेवाओं का प्रबंधन

16. सूचना प्रबंधन प्रणाली

वर्ष 2024-25 के दौरान की जाने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियाँ/कार्य इस प्रकार हैं:

- त्रैमासिक पत्रिकाएँ "माइनटेक" और "गोंडवाना भारती" का प्रकाशन
- इन-हाउस वितरण के अलावा, वर्ष 2024-25 के दौरान दोनों पत्रिकाओं की लगभग 10000 प्रतियाँ कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया और इसकी विभिन्न सहायक कंपनियों (मुख्यालय, क्षेत्र और कोयला इकाई), विभिन्न संस्थानों और अन्य ज्ञात संगठनों को भेजी गईं।
- वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है:
 - सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के अवसर पर प्रकाशित सीवीसी/सीआईएल/एमओसी/डीओपीटी/सीएमपीडीआई परिपत्रों और दिशानिर्देशों के संग्रह की ई-बुक।
 - अन्वेषण प्रभाग सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची के सहयोग से "कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण पर रणनीति" की डिजाइनिंग और रचना और उसका प्रकाशन।
- सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों और बाहरी पार्टियों में तकनीकी पुस्तकों और हमारे इन-हाउस जर्नल 'माइनटेक' की बिक्री उनकी आवश्यकता के अनुसार की जाती है।
- विशेष उपलब्धियाँ
 - पर सीएमपीडीआई तकनीकी जर्नल माइनटेक के विशेष अंक प्रकाशित किए गए हैं।
 - प्रकाशित पुस्तक "कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण पर रणनीति" का अनावरण माननीय कोयला मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी के साथ-साथ भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के सचिव श्री विक्रम देव दत्त, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव सुश्री रूपिंदर बरार, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव सुश्री विस्मिता तेज, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, सीआईएल के अध्यक्ष श्री पी.एम. प्रसाद और सीएमपीडीआई के सीएमडी श्री मनोज कुमार ने 3 नवंबर 2024 को कोलकाता में 50वें कोल इंडिया स्थापना दिवस समारोह के दौरान किया।

17. सतर्कता

17.1 प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या और उन पर की गई कार्रवाई:

शिकायतों	वर्ष 2024-25
1 अप्रैल 2024 को लंबित शिकायतें	03
1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	32
दर्ज की गई शिकायतों की संख्या, जो गुमनाम/छद्मनाम/होने के कारण आरोप सत्यापन योग्य नहीं हैं।	13
1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान जांच/सत्यापन के लिए ली गई शिकायतों की संख्या।	10
आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विभागाध्यक्षों/महाप्रबंधकों को भेजी गई शिकायतों की संख्या।	12

17.2 नियमित जांच के तहत मामले (आरआई मामले):

जांच मामले	वर्ष 2024-25
1 अप्रैल 2024 को लंबित मामले	02
1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान जांच के लिए उठाए गए मामले	00
1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान पूरी की गई जांचों की संख्या	02
31 मार्च 2025 तक लंबित मामले	00

17.3 अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उठाए गए मामलों की संख्या (आरडीए मामले):

अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उठाए गए मामलों की संख्या (आरडीए मामले)	मामलों	वर्ष 2024-25	
		व्यक्तियों की संख्या	
		प्रमुख पी.पी.	माइनर पी.पी.
प्रमुख	-	-	-
गौण	-	-	-

17.4 विभागीय जांच:

पूर्ण की गई विभागीय जांचों की संख्या	वर्ष 2024-25	
	मामलों	व्यक्तियों की संख्या
पूर्ण	01	03
आंशिक कार्रवाई	-	-

17.5 जुर्माना लगाए जाने वाले मामलों की संख्या:

जुर्माना लगाए जाने वाले मामलों की संख्या	वर्ष 2024-25	
	मामलों	व्यक्तियों की संख्या
प्रमुख		
पूर्ण	01	01
आंशिक कार्रवाई	-	-
गौण		
पूर्ण	-	-
आंशिक कार्रवाई	-	-

प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में एग्रीड सूची/ओडीआई सूची तैयार की जाती है।

17.6 निवारक सतर्कता

प्रकार	वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक)
आकस्मिक जाँच	22
फ़ाइल जांच	12
गहन जांच (आईटीई मामले)	03
अधिकारियों के संपत्ति रिटर्न की जांच	170
ऑडिट रिपोर्ट की जांच	19
प्रशिक्षण	36

17.7 प्रणाली सुधार उपाय (एसआईएम)/ सलाह/ सतर्कता चेतावनी

शिकायतों की जांच के दौरान तथा सतर्कता विभाग द्वारा आकस्मिक जांच के दौरान, प्रचलित प्रणाली में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर, प्रणाली सुधार के लिए निवारक उपायों की सिफारिश की जाती है।

भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए कुछ प्रणाली सुधार उपाय (एसआईएम)/सलाह/सतर्कता चेतावनी निम्नलिखित हैं:

- दिनांक 02.04.2024 का परामर्श, तिमाही आवंटन और गैर-कार्यकारी के लिए अर्जित अवकाश से संबंधित है।
- शक्तियों के प्रत्यायोजन के उल्लंघन पर दिनांक 24.07.2024 का परामर्श।
- बिना किसी अपवाद के सभी मैनुअल, दिशा-निर्देश, अनिवार्य नियमों आदि का सख्ती से पालन करने के संबंध में दिनांक 26.09.2024 को जारी परामर्श।
- नकदी बीमा और श्रम कानूनों के अनुपालन पर दिनांक 10.01.2025 को सतर्कता चेतावनी।
- सभी क्षेत्रीय संस्थानों और सीएमपीडीआईएल मुख्यालय में सीएमपीडीआई इंटरनेट पोर्टल पर उपलब्ध मास्टर एक्टिविटी पोर्टल के माध्यम से डाक प्रणाली के कार्यान्वयन पर एसआईएम।

17.8 सहभागी सतर्कता

• सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2024 का आयोजन

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में, **16.08.2024 से 15.11.2024** तक सीएमपीडीआईएल के मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय संस्थानों में “**राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति**” विषय पर **सतर्कता जागरूकता अभियान - 2024** मनाया गया। तीन महीने के जागरूकता अभियान के दौरान बैनर प्रदर्शन, नुक्कड़

नाटक, जागरूकता ग्राम सभा, स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। खरीद, अनुबंध और निवारक सतर्कता आदि जैसे विभिन्न विषयों पर क्षमता निर्माण के लिए कार्यशाला आयोजित करने पर एक प्रमुख जोर दिया गया था। तीन महीने के सतर्कता जागरूकता अभियान के दौरान सभी आरआई और सीएमपीडीआईएल के मुख्यालय में निवारक सतर्कता / खरीद / अनुबंध के विषय पर कुल 25 प्रशिक्षण आयोजित किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 616 कर्मचारियों ने भाग लिया।

17.9 संगठन के भीतर आयोजित गतिविधियाँ/ कार्यक्रम

• सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का आयोजन सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय), रांची के साथ-साथ सीएमपीडीआईएल के सभी क्षेत्रीय संस्थानों में सभी कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ लेने के साथ शुरू हुआ। सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) में, सीएमपीडीआईएल के सीएमडी द्वारा 28.10.2024 को शपथ दिलाई गई।

वास्तव में, सभी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को भ्रष्टाचार की रोकथाम और उसके खिलाफ लड़ाई में सामूहिक रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 से काफी पहले ही सत्यनिष्ठा शपथ दिलाने का उपाय शुरू कर दिया गया था।

• ई-शपथ

कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राहकों, ठेकेदारों, नागरिकों आदि को ई-शपथ लेने के लिए प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए गए। इस उद्देश्य के लिए, सीएमपीडीआईएल वेबसाइट पर "ईमानदारी-शपथ" के लिए www.cvc.nic.in का एक हाइपरलिंक सक्रिय किया गया था और ई-शपथ लेने के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों, नागरिकों (विक्रेताओं, ठेकेदारों, संविदा श्रमिकों, आदि) की सुविधा के लिए 28.10.2024 से सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) में दो "ई-शपथ बूथ" भी स्थापित

किए गए थे। अधिकांश कर्मचारियों ने पिछले वीड्यू के दौरान पहले ही ई-शपथ ले ली थी, हालांकि, इस वर्ष भी अधिकारियों, गैर-कार्यकारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, नागरिकों आदि सहित 100 से अधिक लोगों को ई-शपथ दिलाई गई।

• प्रतियोगिताओं का आयोजन

सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय और सीएमपीडीआईएल के सभी आरआई में भाषण प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, एक्सटेम्पोर प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

• वॉकथॉन

भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 29.10.2024 को सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय), रांची में वॉकथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के कुल 100 छात्रों ने भाग लिया। सभी छात्रों को ईमानदारी की शपथ भी दिलाई गई।

• कार्यशालाएं

सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय और सीएमपीडीआईएल के सभी क्षेत्रीय संस्थानों में विभिन्न कार्यशालाएं/संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सीएमपीडीआईएल मुख्यालय, रांची: 15 कार्यशाला/संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्षेत्रीय संस्थान-I, आसनसोल: 06 कार्यशाला/संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्षेत्रीय संस्थान -II, धनबाद: 02 कार्यशाला/संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्षेत्रीय संस्थान -III, रांची: 06 कार्यशाला/संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्षेत्रीय संस्थान -IV, नागपुर: 05 कार्यशाला/संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्षेत्रीय संस्थान -V, बिलासपुर: दिनांक 02.11.2024 को री-5 बिलासपुर में सतर्कता

जागरूकता पर 01 कार्यशाला आयोजित की गई।

क्षेत्रीय संस्थान -VI, सिंगरौली: 01 कार्यशाला/ संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्षेत्रीय संस्थान -VII, भुवनेश्वर: 12 नंबर। कार्यशाला/ संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

17.10 संगठन के बाहर आयोजित गतिविधियाँ/ कार्यक्रम

• प्रतियोगिताओं का आयोजन

रांची, धनबाद, आसनसोल, बिलासपुर, बुरहानपुर, सिंगरौली और नागपुर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

• जागरूकता ग्राम सभा

सीएमपीडीआईएल के विभिन्न कमांड क्षेत्रों में कुल 05 जागरूकता ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। सभाओं में मुखिया, सरपंच, ग्रामीण, छात्र आदि शामिल हुए। जागरूकता सभाओं के दौरान ग्रामीणों को सामूहिक शपथ दिलाई गई और भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया।

• सोशल मीडिया का उपयोग

28.10.2024 से 03.11.2024 तक एफएम रेडियो के माध्यम से सतर्कता जागरूकता संदेश। गतिविधियों को सीएमपीडीआई के आधिकारिक फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपलोड किया गया तथा व्हाट्सएप पर भी साझा किया गया।

• मोबाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदेश के माध्यम से जागरूकता

सीएमपीडीआईएल सतर्कता ने सप्ताह के दौरान जागरूकता पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सीएमपीडीआईएल के अधिकारियों को और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए कुछ नवीन तरीके अपनाए।

➤ सभी गतिविधियों को तस्वीरों सहित सीएमपीडीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपलोड किया गया।

➤ तीन महीने के सतर्कता जागरूकता अभियान के दौरान प्रतिदिन एक खंड के आधार पर सीडीए नियम अधिकारियों के मोबाइल नंबरों पर भेजे गए।

➤ वीएडब्ल्यू-2024 के दौरान 28.10.2024 से 03.11.2024 तक एफएम चैनलों पर प्रेरणादायक संदेश भी प्रसारित किए गए।

18. जियोमैटिक्स

जियोमैटिक्स प्रभाग रिमोट सेंसिंग और सर्वेक्षण के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है। इसके प्रमुख कार्यों में भूमि पुनर्ग्रहण निगरानी, ओबी माप, वनस्पति आवरण मानचित्रण, भूमि उपयोग / आवरण मानचित्रण, निपटान मानचित्रण, कोयला खदान अग्नि मानचित्रण, डीजीपीएस सर्वेक्षण, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूमिगत सहसंबंध सर्वेक्षण, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन आधारित सर्वेक्षण आदि शामिल हैं।

18.1 रिमोट सेंसिंग सेल

• भूमि पुनर्ग्रहण निगरानी

सीएमपीडीआई एल उच्च रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा के आधार पर नियमित आधार पर सीआईएल खदानों की भूमि सुधार निगरानी कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में, सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों के तहत 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) श्रेणी से अधिक उत्पादन करने वाली 75 ओपनकास्ट परियोजनाओं और 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) श्रेणी से कम उत्पादन करने वाली 39 खदानों/ क्लस्टरों सहित कुल 114 परियोजनाओं की भूमि सुधार निगरानी पूरी हो चुकी है।

• वनस्पति आवरण मानचित्रण

कोयला क्षेत्र में भूमि उपयोग/वनस्पति आवरण पर खनन के प्रभाव के आकलन के लिए उच्च रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा के आधार पर

सीआईएल कोलफील्ड्स के वनस्पति आवरण का मानचित्रण नियमित रूप से किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, छह कोयला क्षेत्रों के वनस्पति आवरण का मानचित्रण किया जाएगा। सिंगरौली (एनसीएल), ईस्ट बोकारो और वेस्ट बोकारो (सीसीएल), कोरबा (एसईसीएल), करणपुरा (सीसीएल) और बांडेर कोलफील्ड (डब्ल्यूसीएल) का काम पूरा हो चुका है।

• ईएमपीएस के लिए कोर और बफर जोन का भूमि उपयोग/कवर मानचित्रण

उपग्रह डेटा के आधार पर सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों के तहत 21 परियोजनाओं के कोर और बफर जोन के भूमि उपयोग/कवर मानचित्रण का कार्य 2024-25 के दौरान पूरा कर लिया गया है।

• डीएसएस विश्लेषण

डीएसएस विश्लेषण कार्य जो कोयला ब्लॉक नीलामी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है, कोयला ब्लॉकों के लिए भी आवश्यकतानुसार किया जा रहा है। डीएसएस विश्लेषण के माध्यम से, वन्यजीव गलियारों, अभयारण्यों, पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों आदि से उनकी निकटता के संबंध में ब्लॉकों की पर्यावरणीय स्थिति का आकलन किया जाता है।

• पीएम गति शक्ति परियोजना (राष्ट्रीय मास्टर प्लान)

सीएमपीडीआईएल कोयला मंत्रालय के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान, गांधीनगर (बीआईएसएजी-एन) के साथ पीएम गति शक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर एमओसी पेज के विकास में समन्वय और सुविधा प्रदान कर रहा है।

सीएमपीडीआईएल, बीआईएसएजी-एन के साथ समन्वय में, पीएमजीएस-एनएमपी पोर्टल पर विभिन्न उपकरणों के विकास में भी शामिल है, जिनका उपयोग खदान योजना सहित विभिन्न विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

सीएमपीडीआईएल आगामी और विस्तार परियोजनाओं के विश्लेषण और विभिन्न सहायक कंपनियों 22 परियोजनाओं (ब्लॉक डी ओसीपी, निलजाई ओसीएम का डिप साइड विस्तार, साओनेर -III यूजी विस्तार खदान, टाकली जेना ओसीएम, येन्सा ब्लॉक, ताकुआ ब्लॉक, अमलगमेटेड गोंडेगांव घाटोहन ओसीएम, अनंता, लाजकुरा और डिप्सिस विस्तार, बैतराणी ईस्ट ओसीपी, झुनकुंदर ओसीपी, बदौली, रेहर यूजी माइन, केसीजी, शिवानी ओसीएम, चिउंचाला पिसगांव ओसी, उत्तरी ढाधू पूर्वी भाग, समामेलित चिंदा विष्णुपुरी ओसीएम, भगवानपुर पूर्वोत्तर ब्लॉक, मकरी बरका पूर्व एवं इंगुरी संयुक्त, हिंगला ब्लॉक के दक्षिण और कल्याणेश्वरी) के लिए परियोजनावार रिपोर्ट के लिए पीएमजीएस-एनएमपी पोर्टल का उपयोग कर रहा है।

इसके लिए एक व्यापक मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार की गई जिसमें परत संबंधी विवरण, विशेषताएं, जिम्मेदारियां और उपयोगकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश शामिल थे।

• कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली

सीएमपीडीआईएल कोयला खदान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली के सुचारू संचालन को सुनिश्चित कर रहा है तथा संबंधित मोबाइल ऐप के साथ साइट को चालू रख रहा है। प्रहरी को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान, गांधीनगर (बीआईएसएजी-एन) के सहयोग से अद्यतन किया गया है। सिस्टम द्वारा स्वतः उत्पन्न मासिक रिपोर्ट संबंधितों को भेजी जा रही है।

• ड्रोन/यूएवी आधारित सर्वेक्षण

कोयला मंत्रालय द्वारा नीलामी के अंतर्गत ब्लॉकों के लिए ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया गया।

- **चिरिमिरी ओसीएम, एसईसीएल और अंजन हिल माइन, एएमपीएल में अग्नि मानचित्रण**

सीएमपीडीआईएल को 5 वर्षों तक वार्षिक आधार पर थर्मल इमेजरी के माध्यम से चिरिमिरी ओसीएम में आग के स्थानों का पता लगाने और उनकी पहचान करने का काम सौंपा गया है। नवंबर 2024 की थर्मल इंफ्रारेड इमेजरी पर आधारित रिपोर्ट पहले ही तैयार करके प्रस्तुत की जा चुकी है।

अंजन हिल माइन, अंजन माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए वर्ष 2024-25 के लिए इसी तरह का अध्ययन भी किया गया।

- **संपूर्ण सीआईएल के लिए वन छत्र घनत्व (एफसीडी) का अध्ययन**

सेंटिनल 2ए उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए, सभी सहायक कंपनियों के लिए एफसीडी मूल्यांकन और एसीए भूमि की अन्य स्थितियों के संबंध में एक अध्ययन आयोजित किया गया है।

- **एसीए भूमि बैंक के लिए समग्र रूप से सम्पूर्ण सीआईएल का वृक्षारोपण मूल्यांकन**

सीआईएल के एसीए भूमि बैंक की पहचान करने और एनडीवीआई तकनीक का उपयोग करके बागानों की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए कंपनी-वार अध्ययन किया गया।

- **कुसमुंडा ओसीपी, एनसीएल के लिए समग्र रूप से वहन क्षमता का आकलन (रिमोट सेंसिंग परिप्रेक्ष्य)**

वित्तीय वर्ष में, विभिन्न समय-सीमाओं के लिए एनडीवीआई (वनस्पति सूचकांक), एनडीडब्ल्यूआई (जल सूचकांक), एलएसटी (भूमि सतह तापमान) सहित एल्यूएलसी मानचित्र तैयार किया गया और विभिन्न विशेषताओं और उपग्रह डेटा के आधार पर ग्राहक को भेजा गया और प्रस्तुत किया गया।

का ओबीआर मापन और 1 एमटीवाई से कम उत्पादन करने वाली ओसी खानों (केवल किराये पर लिए गए पैच) का वार्षिक मापन पूरा हो चुका है और रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है।

- **ड्रोन अनुप्रयोग**

सीएमपीडीआईएल में स्थलाकृतिक मानचित्रण, कोयला खदान अग्नि मानचित्रण, वनस्पति आवरण मानचित्रण, बस्तियों का मानचित्रण, वृक्षारोपण ऊंचाई आकलन और खनन से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए पूर्णतः प्रचालनात्मक ड्रोन आधारित क्षमता है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली कुछ प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

- गर्जनबहाल ओसीपी, कुल्दा ओसीपी, सियार्मल ओसीपी और आई-एलबीएल ओसीपी के सभी कोयला ढेरों/स्टॉक का ड्रोन आधारित फोटोग्रामेट्री द्वारा वॉल्यूमेट्रिक माप
- राजस्थान राज्य में मानसून पूर्व और मानसून पश्चात अवधि में रेत पुनःपूर्ति अध्ययन।
- बिहार राज्य में मानसून पूर्व और मानसून पश्चात अवधि में रेत पुनःपूर्ति अध्ययन।
- आम्रपाली ओसीपी (सीसीएल) की टीओआर स्थिति के अनुपालन के लिए वीडियो और ऑर्थोफोटोमोजेक प्राप्त करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण [क्षमता: 28 एमटीवाई, क्षेत्र: 1298.98 हेक्टेयर]
- गिरिडीह क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के संबंध में ड्रोन सर्वेक्षण।
- ढोरी कोकिंग कोल वाशरी के ईआईए ईएमपी के लिए वृक्ष गणना और हरित पट्टी के सीमांकन हेतु ड्रोन सर्वेक्षण

- **डीजीपीएस सर्वेक्षण के कार्य:**

- अशोक विस्तार ओसीपी की 928.03 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्सन आवेदन के संबंध में 1856.06 हेक्टेयर सीए भूमि की डीजीपीएस और केएमएल योजना तैयार करना
- मगध ओसीपी (लातेहार भाग) की वन

18.2 सर्वेक्षण विभाग

- **ओबीआर/ ओबी+कोयला माप**

1 एमटीवाई से अधिक उत्पादन करने वाली सभी आउटसोर्स और विभागीय ओसी खानों

- भूमि (450 हेक्टेयर) की डीजीपीएस, भूमि उपयोग और केएमएल फाइलों की तैयारी
- गिद्दी ए, अरगडा क्षेत्र, सीसीएल के 232.42 हेक्टेयर स्टेज। एफसी आवेदन के संबंध में आवंटित 465 हेक्टेयर सीए भूमि के संबंध में केएमएल आकार फ़ाइल, भू-संदर्भ मानचित्र, टोपोशीट मानचित्र तैयार करना
- धाधु (पूर्व) कोयला ब्लॉक का डीजीपीएस सर्वेक्षण
- कठौतिया ओपनकास्ट कोयला खदान की ब्लॉक सीमा के भीतर कैडस्ट्रल मानचित्रों का जियोरेफरेंसिंग और कठौतिया ओपनकास्ट कोयला खदान का सीमा सीमांकन
- दिल्ली-जयपुर यूजी खदान, एनईसी का भू-संदर्भ
- संघमित्रा ओसीपी, मगध-संघमित्रा क्षेत्र, सीसीएल की खदान सीमा की डीजीपीएस योजना
- सीसीएल के बरका-सयाल क्षेत्र के उरीमारी ओसीपी के संबंध में वन विभाग को सौंपने के लिए 49.97 हेक्टेयर वन भूमि के चरण-II एफसी के नवीकरण के लिए आवश्यक 1.41 हेक्टेयर गैर-वन भूमि और रजरप्पा ओसीपी में उपलब्ध पहले से ही परिवर्तित वन भूमि से 49.97 हेक्टेयर विधिवत पुनः प्राप्त क्षेत्र के डीजीपीएस और केएमएल की तैयारी।
- प्रस्तावित नई स्वांग कोकिंग कोल वाशरी (6.32 हेक्टेयर+1.50 हेक्टेयर) के लिए डीजीपीएस तकनीक के माध्यम से डीजीपीएस और केएमएल फाइलों की तैयारी
- मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला के सिंगरौली कोलफील्ड में स्थित मेसर्स बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मर्की बड़का कोल ब्लॉक का डीजीपीएस सर्वेक्षण।
- ब्लॉक सीमा निर्देशांक को अंतिम रूप देने और अंतिम ब्लॉक सीमा योजना की तैयारी के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण:
 - मारा II माहन कोल ब्लॉक
 - लालगढ़ साउथ कोल ब्लॉक
 - दमुदा कोल ब्लॉक के दक्षिण में
 - शहडोल के पश्चिम (दक्षिण) कोल ब्लॉक
 - दुनी सेंट्रल कोल ब्लॉक
 - बाबूपारा ईस्ट कोल ब्लॉक
 - बिनोदपुर भबानीगंज कोल ब्लॉक
 - बैसी कोल ब्लॉक लामाटोला कोल ब्लॉक
 - मेसर्स एस एम स्टील्स एंड पॉवर लिमिटेड का डुमरी कोयला ब्लॉक।
 - मार्की ज़ारी जमानी मेसर्स नीलकंठ इंफ्रा माइनिंग लिमिटेड का अडकोली कोल ब्लॉक
 - मेसर्स एनएलसी इंडिया लिमिटेड का अछकटा (संशोधित) कोयला ब्लॉक
 - मेसर्स तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सखीगोपाल -बी काकुरही कोल ब्लॉक
 - मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कुडनाली-लुबरी कोल ब्लॉक
 - महान कोल ब्लॉक
 - मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मीनाक्षी कोल ब्लॉक
 - मेसर्स झार मिनरल रिसोर्सज प्राइवेट लिमिटेड के रम्पिया कोल ब्लॉक का रम्पिया और डिप साइड
 - मेसर्स एस एम स्टील्स एंड पॉवर लिमिटेड का बुंड़ कोल ब्लॉक
 - मेसर्स श्रीजी का गवा (पूर्व) कोल ब्लॉक नूरवी कोल माइनिंग एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
 - उलिया मेसर्स एस एम स्टील्स एंड पॉवर लिमिटेड का गम्हारडीह कोल ब्लॉक
 - मेसर्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड का बार्ताप (संशोधित) कोयला ब्लॉक
 - मेसर्स एनएलसी इंडिया लिमिटेड का

नया पत्रापाड़ा साउथ कोल ब्लॉक

- मेसर्स एसीसी लिमिटेड का सराय ईस्ट (दक्षिण) कोल ब्लॉक
- मेसर्स उड़ीसा अलॉय स्टील प्राइवेट लिमिटेड का केरेन्दरी -बीसी उत्तर कोल ब्लॉक
- मेसर्स सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड का गारे पाल्मा IV/5 कोयला ब्लॉक।
- मेसर्स माइनवेयर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड का मरवाटोला साउथ कोल ब्लॉक
- न्यू पत्रापाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक
- हिंगला कोल ब्लॉक के दक्षिण में
- नबासन कोल ब्लॉक
- दहेगांव सप्तधारा कोल ब्लॉक
- महुआगढ़ी कोल ब्लॉक
- ट्यूबेड कोल ब्लॉक के पश्चिम में
- थानाटोला उत्तर कोयला ब्लॉक
- थानाटोला ईस्ट कोल ब्लॉक
- ताम्बिया साउथ कोल ब्लॉक
- दहेगांव झुनकी कोल ब्लॉक
- पाताल पूर्व (पश्चिमी भाग) कोयला ब्लॉक
- राजगामार डिपसाइड (देवनारा) कोयला ब्लॉक
- राजगामार डिपसाइड (फुलकडीह के दक्षिण में) नाला) कोयला ब्लॉक
- चितरपुर (संशोधित) कोयला ब्लॉक
- चोलापत्थर कोयला ब्लॉक
- थानाटोला पश्चिम कोल ब्लॉक
- मंदाकिनी -बी कोल ब्लॉक कोल ब्लॉक
- दुनी सेंट्रल कोल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी कैडस्ट्रल/राजस्व योजनाओं का जियोरेफरेंसिंग और डिजिटलीकरण।
- बिजहान कोल ब्लॉक की ब्लॉक सीमा सीमांकन

के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण

- पश्चिम बंगाल जिले की सीमा का सीमांकन अजय नदी के किनारे बर्द्धमान और बीरभूम जिले और बिनोदपुर की ब्लॉक सीमा मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड का भबानीगंज कोयला ब्लॉक।
- मेसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के परबतपुर सेंट्रल कोल ब्लॉक के भीतर जीआर योजना और एफ5-एफ5 फॉल्ट लाइन के ग्राउंड प्रोजेक्शन का जियो-रेफरेंसिंग और पीएमगति शक्ति पोर्टल पर उसे अपलोड करना।
- मेसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड के बृन्दा और सिसई कोल ब्लॉकों की ब्लॉक सीमा सीमांकन के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण।
- गारे-पाल्मा-IV/2 और गारे-पाल्मा-IV/3 कोयला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कैडस्ट्रल/राजस्व योजनाओं के जियो-रेफरेंसिंग के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण
- गढ़वा जिले में चिन्हित सीए भूमि (डीडीएफएल) की डीजीपीएस योजना और केएमएल फाइल की तैयारी, एफसी प्रस्ताव मगध ओसीपी (पश्चिम), सीसीएल बनाने के लिए
- मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के उत्कल बी1 और उत्कल बी2 कोयला ब्लॉकों की संयुक्त सीमा का डीजीपीएस सर्वेक्षण
- बीसीसीएल की तीन वाशरियों (दुग्दा, महुदा और मधुबन) का डीजीपीएस सर्वेक्षण

19. खनन इलेक्ट्रॉनिक्स

सीएमपीडीआई का खनन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग संचार नेटवर्क स्थापित करने, यू/जी और ओ/सी खदानों के लिए पर्यावरण मापदंडों की टेलीमॉनीटरिंग, संग्रहालय और स्मार्ट क्लासरूम के लिए ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए संचार नेटवर्क स्थापित करने, ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओआईटीडीएस) और निविदा दस्तावेजों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट, तकनीकी विनिर्देश, बीओक्यू और बजटीय लागत और पात्रता मानदंड तैयार करने में सेवाएं प्रदान करता

है। यह शॉवेल, डंपर और ड्रैगलाइन आदि के लिए आयातित/स्वदेशी एचईएमएम इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण कार्ड की मरम्मत, खदानों में 5जी नेटवर्क/5जी उपयोग मामलों के कार्यान्वयन में सहायक कंपनी को बहुमूल्य सेवाएं भी प्रदान करता है। विभाग ने खदानों की उत्पादकता और सुरक्षा से संबंधित ओपन कास्ट और भूमिगत खदानों के लिए विभिन्न आरएंडडी/एसएंडडी परियोजनाएं भी शुरू की हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे/परिचालन में थे।

19.1 अनुसंधान एवं विकास/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएं

- मुद्रण द्वारा मोनोलिथिक पेरोवस्काइट मॉड्यूल विनिर्माण का स्वदेशी विकास। - **मॉड्यूल और उपकरणों के लिए त्वरित परीक्षण स्थितियों (नम-गर्मी) के तहत T80 ~ 624 घंटे हासिल किया गया, थर्मल साइकलिंग परीक्षण प्रोटोकॉल पारित किया गया।**
- खदान के ढलान स्वास्थ्य निगरानी के लिए वास्तविक समय ऊर्जा कुशल साइबर-भौतिक इंटेलेजेंट प्रणाली। - **आईआईटी (आईएसएम) धनबाद द्वारा प्रस्तुत मसौदा पूर्णता रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है।**
- कोयला उद्योग के लिए सीएमपीडीआई में 5जी यूज केस टेस्ट लैब की स्थापना का कार्य टीसीआईएल, सीएमपीडीआई और आईआईआईटी, रांची द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। - **कोयला उद्योग के लिए सीएमपीडीआई में 5जी यूज केस टेस्ट लैब की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है और इसके लिए प्रशिक्षण जारी है।**
- सीआईएल आरएंडडी अनुदान के तहत एनसीएल की अमलोहरी ओसी खदानों में ओपनकास्ट कोल माइंस में एकीकृत वॉयस, वीडियो और डेटा संचार के लिए 5जी कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) को सीएमपीडीआई और सीडैक, तिरुवनंतपुरम द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया है। - **सभी टावरों पर 5जी एंटेना और बैकहॉल यूबीआर की स्थापना पूरी हो**

चुकी है, दो टावरों पर 5जी रेडियो लगाए गए हैं और 5जी कोर नेटवर्क के साथ संचार परीक्षण प्रगति पर है। 5जी उपयोग मामलों का विकास चल रहा है, और परियोजना के अक्टूबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

19.2 पी एंड डी/एनआईटी/अन्य कार्य

- सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों और बाहरी एजेंसियों की परियोजना रिपोर्टों में शामिल करने के लिए **10 यूजी और ओसी खानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार पर अध्याय तैयार किए गए हैं।**
- सीएमपीडीआई पृथ्वी विज्ञान संग्रहालय के लिए ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया सिस्टम। - **कार्य पूरा हो गया। संग्रहालय चालू है।**
- एसएपी सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली। - **फेस कम पाम बायोमेट्रिक प्रणाली सफलतापूर्वक स्थापित और चालू।**
- अंगार संग्रहालय के लिए ऑडियो विजुअल सिस्टम और आईआईसीएम, रांची में मल्टीमीडिया स्मार्ट क्लासरूम के लिए **निविदा 04/03/2025 को खोली गई। इसकी तकनीकी जांच प्रक्रियाधीन है।**
- आरआई-॥ धनबाद के लिए सीसीटीवी प्रणाली हेतु तकनीकी विनिर्देश - **प्रस्तुत।**
- बरकाखाना के लिए सीसीटीवी प्रणाली हेतु तकनीकी विनिर्देश - **प्रस्तुत।**

20. कोयला कैरेक्टराईजेशन एवं प्रयोगशाला

कोयला अभिलक्षण प्रयोगशाला में रासायनिक और पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला शामिल है। रासायनिक और पेट्रोग्राफी प्रयोगशालाएं भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए नियमित आधार पर गवेषण चरण में कोयले के व्यवस्थित और विस्तृत लक्षण वर्णन करने में लगी हुई हैं। स्वच्छ कोयले के गुणों का पता लगाने के लिए कच्चे और स्वच्छ कोयले के नमूनों (वाशरी उत्पादों) का व्यवस्थित अभिलक्षण और सीबीएम मूल्यांकन के लिए कोयले के नमूनों का अभिलक्षण किया जा रहा है।

रासायनिक प्रयोगशाला में समीपस्थ विश्लेषण, अंतिम विश्लेषण और सकल कैलोरी मान निर्धारण जैसे परीक्षण किए जाते हैं। कोकिंग कोयले के लिए विशेष परीक्षण जैसे कि मुक्त सूजन सूचकांक, एलटीजीके कोक प्रकार और प्लास्टोमेट्रिक परीक्षण किए जाते हैं। राख संलयन तापमान सीमा निर्धारण, गैर-कोकिंग कोयले के लिए एचजीआई परीक्षण भी किए जाते हैं।

20.1 प्रयोगशालाओं का उन्नयन और कोयला अभिलक्षणीकरण प्रयोगशाला की प्रगति

रासायनिक प्रयोगशाला वर्तमान में नमूना तैयारी इकाई में स्वचालन शुरू करके कोयला कोर विश्लेषण की क्षमता के संवर्द्धन पर अपनी योजना को लागू कर रही है जो बड़ी संख्या में विश्लेषण को संभालने की सुविधा प्रदान करेगी। रासायनिक प्रयोगशाला पारंपरिक और परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित है जैसे कोयला/कोक/लिग्नाइट के निकटतम विश्लेषण के लिए थर्मोग्रैविमेट्रिक विश्लेषक, कोयला और लिग्नाइट के सकल कैलोरीफिक मूल्य के निर्धारण के लिए स्वचालित बम कैलोरीमीटर, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर का निर्धारण, कोयले के राख संलयन तापमान सीमा (आईडीटी, एसटी, एचटी और एफटी) के लिए एएफटीआर उपकरण, कोयले की प्लास्टिसिटी के निर्धारण के लिए सूजन सूचकांक, एलटीजीके, प्लास्टोमीटर जैसे उपकरण और कोयले के कोकिंग गुणों का निर्धारण करने के लिए अन्य उपकरण उपलब्ध हैं। प्रयोगशाला ने हाल ही में कोयला और गैर-कोयला नमूनों में खनिज चरणों की पहचान के विश्लेषण के लिए एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर सिस्टम (एक्सआरडी) और कोयले की राख में ऑक्साइड के रूप में तत्वों के निर्धारण के लिए एक्स-रे फ्लोरोसेंस (एक्सआरएफ) से खुद को सुसज्जित किया है।

पेट्रोग्राफी लैब पेट्रोग्राफिक विश्लेषण जैसे कि मैकरल संरचना, यादृच्छिक परावर्तन (आरओआर%) और औसत अधिकतम परावर्तन% (एमएमआर%) का निर्धारण करती है। यह अध्ययन नमूनों के कोयला-प्रकार और कोयला रैंक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह अध्ययन हाइड्रोकार्बन, तेल शेल, कोल बेड मीथेन और शेल गैस मूल्यांकन के लिए स्रोत रॉक मूल्यांकन के लिए भी उपयोगी है।

पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला पेट्रोग्राफिक अध्ययन करने के लिए उन्नत पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप से सुसज्जित है जिसमें कोयले के नमूनों की मैकरल सामग्री (कोयला प्रकार) और परावर्तन प्रतिशत (रैंक/परिपक्वता) निर्धारित की जाती है। कोक बनाने में मिश्रण के रूप में दिए गए कोयले की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए पेट्रोग्राफिक अध्ययन अनिवार्य है। पेट्रोग्राफिक अध्ययन और क्लीट अध्ययन के लिए कोयला छरों की तैयारी के लिए अपघर्षक कटिंग मशीन और हॉट माउंटिंग प्रेस भी उपलब्ध हैं।

भू-रासायनिक प्रयोगशाला को 12 विभिन्न क्षेत्रों में "परीक्षण" के क्षेत्र में अपनी सुविधाओं के लिए मानक आईएसओ/आईसी 17025:2017 के अनुसार एनएबीएल प्रमाणन से मान्यता प्राप्त है। पेट्रोग्राफी लैब में पेट्रोग्राफर्स को कोयला और कार्बनिक पेट्रोलॉजी (आईसीसीपी) की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रमाणित किया गया है।

20.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोयला अभिलक्षणीकरण प्रयोगशाला की प्रगति:

इकाई	विवरण	वार्षिक लक्ष्य	वित्त वर्ष 2024-25 की उपलब्धि	वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां	%विकास
रासायनिक प्रयोगशाला प्रभाग	1. नमूना विश्लेषण (संख्या)	58000	60069	56599	(+)6.13
	2. कोयला कोर (मीटर)	17000	21072.62	17549.60	(+)20.07
पेट्रोग्राफी प्रभाग	1. पेट्रोग्राफी अध्ययन (संख्या)	960	969	960	(+)0.94

20.3 प्रयोगशाला का प्रदर्शन:

- **भौतिक उपलब्धि** कोयला अभिलक्षण प्रयोगशाला ने पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
 - रासायनिक प्रयोगशाला प्रभाग ने 60,069 नमूनों का विश्लेषण किया, जो 58,000 नमूनों के लक्ष्य से अधिक था (लक्ष्य का 103.57% प्राप्त करना)। इसके अतिरिक्त, नमूना तैयार करने के लिए 21,072.62 मीटर कोयला कोर संसाधित किए गए, जो 17,000 मीटर के लक्ष्य से अधिक था (लक्ष्य का 123.96% प्राप्त करना)। पिछले वर्ष की तुलना में, नमूना विश्लेषण में 6.13% की वृद्धि हुई और कोयला कोर प्रसंस्करण में 20.07% की वृद्धि हुई।
 - पेट्रोग्राफिक अध्ययन के लिए कुल 969 नमूनों का विश्लेषण किया गया, जो अन्वेषण ब्लॉकों, एनएमईटी, वाशरी और सीईडी के लिए निर्धारित 960 नमूनों के लक्ष्य से अधिक था।
 - विभिन्न निजी उद्यमों से प्राप्त कोयले के नमूनों का परीक्षण किया गया और परिणाम समय पर सूचित किये गये।
 - प्रयोगशाला सीएमपीडीआई मुख्यालय के सीईडी, सीएमपी प्रभागों और ईसीएल, सीसीएल और बीसीसीएल की चालू खदानों से विभिन्न नमूनों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में है।
- **दृष्टिकोण और तैयारी**
 - **रासायनिक प्रयोगशाला** वर्तमान में नमूना तैयारी इकाई में स्वचालन शुरू करके कोयला कोर विश्लेषण की क्षमता के संवर्धन पर अपनी योजना को क्रियान्वित कर रही है, जो बड़ी संख्या में विश्लेषण को संभालने में मदद करेगी।
 - प्रयोगशाला ने गैर कोयला नमूना (आधार धातु) तैयार करने की इकाई स्थापित की है, जिसमें वांछित नमूना आकार की आवश्यकताओं के अनुसार नमूना तैयार करने के लिए कंपन कप मिल्स और स्वचालित जबड़े क्रशर शामिल हैं, जो सीएमपीडीआई में अपनी तरह की पहली इकाई है।
 - कोयला और गैर-कोयला में खनिज पहचान की प्रक्रिया के तहत, प्रयोगशाला ने पूरी तरह कार्यात्मक एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर (एक्सआरडी) और एक्स-रे फ्लोरोसेंस (एक्सआरएफ) सुविधा स्थापित की है। एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर अज्ञात नमूनों में खनिज की उपस्थिति का विश्लेषण करने और खदान की धूल के नमूनों में मुक्त सिलिका का पता लगाने में सक्षम बनाता है। एक्स-रे फ्लोरोसेंस सिस्टम (एक्सआरएफ) का उपयोग राख विश्लेषण करने और अन्य धातु ऑक्साइड का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।
 - प्रयोगशाला दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) और ट्रेस धातुओं की गुणात्मक और मात्रात्मक पहचान के लिए आईसीपी-एमएस (इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा - मास स्पेक्ट्रोस्कोपी) सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इस उपकरण के लिए आपूर्ति आदेश पहले ही दिया जा चुका है।
 - गैर-कोयला नमूनों के लिए खनिज पहचान सुविधा विकसित करने की अपनी पहल में, प्रयोगशाला एक परावर्तित प्रकाश ध्रुवीकरण अनुसंधान माइक्रोस्कोप के साथ-साथ एक चट्टान काटने और चमकाने की इकाई खरीद रही है।

21. सामग्री प्रबंधन

21.1 खरीद मूल्य:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
1	कुल खरीद मूल्य	160.89	374.65
2	एमएसई से प्राप्त कुल मूल्य	130.25	255.54
3	केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई द्वारा खरीदे गए माल का कुल मूल्य	0.48	1.04
4	केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई द्वारा खरीदे गए माल का कुल मूल्य	1.49	19.61
5	एमएसई से खरीद का प्रतिशत	80.95%	68.20%
6	कुल खरीद में से केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का प्रतिशत	0.29%	0.28%
7	कुल खरीद में से केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का प्रतिशत	0.92%	5.23%

नोट: एमएसई से खरीद का प्रतिशत भारत सरकार के निर्धारित लक्ष्य 25% से काफी अधिक है।

21.2 जीईएम के माध्यम से खरीद :

(₹ करोड़ में)

जीईएम के माध्यम से लक्षित खरीद		जीईएम के माध्यम से वास्तविक खरीद	
वस्तुएं	सेवाएं	वस्तुएं	सेवाएं
50.00	60.00	68.42	299.68

नोट: सेवाओं के लिए लक्षित खरीद पिछले तीन वर्षों के वास्तविक खरीद आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई थी। वित्त वर्ष 2024-25 में ही कुछ जरूरी गवेषण और सुरक्षा श्रेणी की निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने के कारण सेवा श्रेणी के तहत उपलब्धि लक्ष्य से काफी अधिक रही।

21.3 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वस्तुएं	सेवाएं	कुल
1	कुल लक्षित खरीद (जीईएम + जीईएम के बाहर)	60.00	75.00	135.00
2	एमएसई से लक्षित खरीद (कुल खरीद का लगभग 40%, सीएमपीडीआईएल द्वारा जारी निविदाओं में एमएसई की भागीदारी के अधीन)	24.00	30.00	54.00

22. मानव संसाधन विकास

प्रशिक्षण एवं विकास कर्मचारी के विकास का अभिन्न अंग है। इसलिए सीएमपीडीआईएल में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि उनका समग्र विकास वर्षों तक जारी रहे। संगठन में मानव पूंजी की क्षमता को अनलॉक करने के लिए "सीआईएल कार्यकारी शिक्षण एवं विकास नीति" का पालन किया जा रहा है, जो कॉर्पोरेट योजनाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संगठनात्मक क्षमताओं के निर्माण में मदद करेगी।

नीति के अनुसार, किसी संगठन में प्रत्येक कार्यकारी के लिए प्रशिक्षण चक्र 2023-24 से शुरू होकर 4 वर्ष का होगा। सभी कार्यकारी को एक प्रशिक्षण चक्र में 90 प्रशिक्षण घंटों का अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा।

तदनुसार, सीएमपीडीआईएल के अधिकारियों को वित्त वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक 4 वर्ष की ब्लॉक अवधि में प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन किया गया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित कुल ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण/सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला का सारांश नीचे दिया गया है:-

22.1 कुल कार्यक्रमों का सीएमपीडीआईएल संचालित

कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण दिन	संख्या प्रतिभागियों	प्रशिक्षण मानव -दिन
201	874	1367	4575

उपरोक्त प्रशिक्षणों में से, शिक्षण एवं विकास नीति के अंतर्गत अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार है:

22.2 अधिकारियों के लिए आयोजित एल एंड डी कार्यक्रमों का विवरण

प्रशिक्षण का प्रकार	कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण दिवस	प्रतिभागियों की संख्या	प्रशिक्षण मानव - दिन
एसटीसी	32	68	580	1159
एक्सटी	65	355	231	1256
आईआईसीएम	59	317	165	1324
कुल	156	740	976	3739

22.3 स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण (एसटीसी)

विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी विषयों पर 829 कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आंतरिक प्रशिक्षण आयोजित किये गये पाठ्यक्रम। हमारे कर्मचारियों को दिए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-

- एमएस एक्सेल पर प्रशिक्षण।
- लीका डीजीपीएस और सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण।
- कार्लसन सॉफ्टवेयर का भौतिक/ऑनसाइट प्रशिक्षण
- भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- वल्कन सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण।
- नए आपूर्ति किए गए यूएए और सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण

- एमएसएमई के लिए प्रावधान, एससी/एसटी और महिलाओं के लिए प्रावधान, बोलियों के मूल्यांकन और विचार के संबंध में माल/उपकरण की खरीद पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- एससी, एसटी और ओबीसी रोस्टर पर प्रशिक्षण।
- वित्त अधिकारियों के लिए परियोजना लागत रिपोर्ट तैयार करने पर प्रशिक्षण।
- सिविल रखरखाव अनुबंधों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- माल, संयंत्र मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- पर्यावरण और बेस लाइन कार्य में लगे हुए नमूना सहायक के लिए शोर सर्वेक्षण पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- सीएसआर पर कार्यशाला
- सिविल इंजीनियरों के लिए कार्यशाला।
- नाबेट-क्यूसीआई द्वारा सीएमपीडीआईएल के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) पर कार्यशाला।
- आईएसओ 9001:2015 और सीएमपीडीआईएल की प्रलेखित व्यवस्था
- एबीएम, आईएसओ 37001 और 2016
- गैर-अधिकारियों के लिए कार्यालय संस्कृति, व्यवहार और संचार कौशल।
- प्रबंधन प्रणाली में आंतरिक लेखा परीक्षा कौशल पर जागरूकता कार्यक्रम- आईएसओ 9001:2015 (क्यूएमएस) साइबर स्वच्छता और सुरक्षा।

22.4 आईआईसीएम में प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आईआईसीएम के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, बड़ी संख्या में जूनियर, सीनियर और मध्यम स्तर के अधिकारियों को आईआईसीएम में प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया है। नामांकन प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन और एचआरआईएस प्लेटफॉर्म के आधार पर किए जा रहे हैं। वर्ष **2024-25 के दौरान कुल 183 अधिकारियों ने** आईआईसीएम में ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण लिया है।

22.5 उत्कृष्टता केंद्र में प्रशिक्षण

पूरे वर्ष भर अधिकारियों को तकनीकी/प्रबंधकीय कौशल उन्नयन से संबंधित प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशाला, कॉन्क्लेव और संगोष्ठी आदि में भाग लेने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों/संस्थानों में भेजा जाता रहा है, ताकि उन्हें नवीनतम तकनीकी विकास के साथ तालमेल बिठाने में सहायता मिल सके। इस वर्ष भारत के विभिन्न स्थानों में 355 अधिकारियों और कर्मचारियों ने ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रमों में भाग लिया है। कुछ संस्थानों के नाम जहाँ हमारे कर्मचारियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया, वे इस प्रकार हैं:-

- आईआईटी आईएसएम धनबाद
- आईआईएम लखनऊ
- सीबीआरआई रुड़की
- एससीआई हैदराबाद।
- आईआईटी बॉम्बे
- आईआईएम विशाखापत्तनम
- आईआईएम रांची
- आईआईआरएस देहरादून
- एनआईटीएस, नोएडा

22.6 सीएमपीडीआईएल में इंटरशिप प्रशिक्षण

सीएमपीडीआईएल मुख्यालय और विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में मानव संसाधन विकास प्रभाग द्वारा विभिन्न संस्थानों के छात्रों को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन इंटरशिप / औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 2024-25 के दौरान सीएमपीडीआईएल में कुल **237** छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया है। छात्रों ने अपने-अपने क्षेत्रों में 4-6 सप्ताह तक प्रशिक्षण/परियोजना कार्य किया है।

22.7 प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण: प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार, सीएमपीडीआईएल को ठेकेदार श्रमिकों सहित सीएमपीडीआईएल की औसत जनशक्ति का न्यूनतम 2.5% लक्ष्य प्राप्त करना है। सीएमपीडीआईएल ने 161 प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया है जो 4.04% है। इसमें विभिन्न विषयों जैसे मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में 113 डिप्लोमा धारक और 48 डिग्री धारक शामिल हैं और उन्हें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीएमपीडीआईएल के विभिन्न आरआई और मुख्यालय में रखा गया है।

22.8 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म- आई-गौट

आई-गौट कर्मयोगी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे सभी सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए डिजिटल इंडिया स्टैक के एक अभिन्न अंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के तहत एक एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को उनके करियर के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए 'कभी भी-कहीं भी-किसी भी डिवाइस' पर सीखने की सुविधा प्रदान करेगा।

उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ, कर्मचारियों को आई-गौट प्लेटफॉर्म के कार्यक्रमों को देखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

सीएमपीडीआईएल एमडीओ के संबंध में आई-गौट का सारांशित डेटा इस प्रकार है: -

31.03.2025 तक अधिकारियों द्वारा पूर्ण किए गए पाठ्यक्रमों की कुल संख्या: 8358

31.03.2025 तक कर्मचारियों द्वारा पूर्ण किए गए पाठ्यक्रमों की कुल संख्या: 2532

23. श्रमशक्ति और कल्याण गतिविधियाँ

• श्रमशक्ति की स्थिति :

विवरण		31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक
अधिकारी		788	791
कर्मचारी	मासिक रेटेड	963	940
	दैनिक रेटेड	1015	969
	पीस रेटेड	1	1
	कुल योग	2767	2701

• कल्याणकारी गतिविधियाँ

क्रम संख्या	कार्यक्रम	तारीख
1.	अम्बेडकर जयंती	14.04.2024
2.	आतंकवाद विरोधी दिवस का पालन	21.05.2024
3.	सीएमपीडीआईएल मुख्यालय और आरआई-III के कर्मचारियों के बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर	31.05.2024 से 08.06.2024 तक
4.	स्वच्छता पखवाड़ा	16.06.2024 से 30.06.2024 तक
5.	स्वतंत्रता दिवस समारोह	15.08.2024
6.	स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत गतिविधियाँ	15.09.2024 से 02.10.2024 तक
7.	महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती का उत्सव	02.10.2024
8.	सफाई मित्रों का अभिनंदन	04.10.2024
9.	विशेष अभियान 4.0	02 से 31.10.2024 तक
10.	सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म समारोह पर एकता दौड़	31.10.2024
11.	सीआईएल स्थापना दिवस के अवसर पर 10 वीं और 12 वीं के विद्यार्थियों को पुरस्कार	01.11.2024
12.	सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह	19 से 25.11.2024
13.	ध्वज दिवस	25.11.2024
14.	संविधान दिवस	26.11.2024
15.	गोंडवाना प्राथमिक विद्यालय में आत्मरक्षा पर कार्यशाला एवं प्रेरणा सत्र	18.01.2025
16.	गणतंत्र दिवस परेड	26.01.2025
17.	अंतर सीआईएल कैरम टूर्नामेंट	03 से 05.02.2025

• आरटीआई वार्षिक रिपोर्ट सीएमपीडीआई मुख्यालय 2024-25

31 मार्च 2024 को प्रारंभिक शेष राशि	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	निपटाए गए आवेदनों की कुल संख्या	शेष आवेदन
33	273	285	21

• आरटीआई 2024-25 के तहत पहली अपील

31 मार्च 2024 को प्रारंभिक शेष राशि	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	निपटाए गए आवेदनों की कुल संख्या	शेष आवेदन
0	07	07	0

• आरटीआई 2024-25 के तहत सीआईसी द्वितीय अपील

31 मार्च 2024 को प्रारंभिक शेष राशि	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	निपटाए गए आवेदनों की कुल संख्या	शेष आवेदन
01	0	01	0

• वार्षिक रिपोर्ट सीएमपीएफ और सीएमपीएस

वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त पीएफ के कुल मामले	निपटाए गए मामले	सीएमपीएफओ में प्रक्रियाधीन	सीएमपीडीआई में प्रक्रियाधीन
124	106	12	06

वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त पेंशन के कुल मामले	निपटाए गए मामले	सीएमपीएफओ में प्रक्रियाधीन	सीएमपीडीआई में प्रक्रियाधीन
124	93	23	08

• वर्ष 2024-25 हेतु अधिकारी स्थापना से संबंधित प्रमुख जानकारी

क्रम सं.	वार्षिक कार्य योजना	की गई कार्रवाई
1	टर्मिनल लाभ (ग्रेजुटी) का निपटान	40
2	जीवन बीमा भुगतान योजना	1
3	सेवानिवृत्ति पर प्राप्त अवकाश नकदीकरण	41
4	सेटल्ल्ड	39
5	लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण रोक दिया गया	2
6	प्रक्रियाधीन	2

• वर्ष 2024-25 के दौरान सीपीजीआरएएम से संबंधित जानकारी

क्र.सं.	शिकायत स्रोत	कुल प्राप्त शिकायतें	अवधि के दौरान निपटाई गई शिकायतें	शेष/प्रक्रियाधीन
1	स्थानीय/इंटरनेट	45	45	0
2	पेंशन	0	0	0
3	पीएमओ	9	9	0

• वर्ष 2024-25 के दौरान वीआईपी संदर्भ से संबंधित जानकारी

क्र.सं.	शिकायत स्रोत	कुल प्राप्त आवेदन	अवधि के दौरान निपटाए गए आवेदन	शेष/प्रक्रियाधीन
1	स्थानीय/इंटरनेट	6	6	0

• वर्ष 2024-25 के दौरान कर्मचारियों से संबंधित जानकारी

क्रम सं.	वार्षिक कार्य योजना	की गई कार्रवाई
1	टर्मिनल लाभ (ग्रेच्युटी) का निपटान	73
2	जीवन बीमा योजना का भुगतान	2
3	सीपीआरएमएसएनई के तहत मेडिकल कार्ड जारी करना	72
4	सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण प्राप्त हुआ	75
5	सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण निपटाया गया	53
6	कंपनी क्वार्टर खाली न होने के कारण सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण रोका गया	4
7	सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण प्रक्रियाधीन	16
8	किसी विवाद के कारण सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण रोका गया	1

• राजभाषा

आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों के वैधानिक प्रावधानों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा), कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निर्देशों का क्रियान्वयन जारी रखा तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए।

आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान क्षेत्र 'ग' में हिंदी पत्राचार का लक्ष्य हासिल कर लिया है तथा क्षेत्र 'क' एवं 'ख' में हिंदी पत्राचार का लक्ष्य हासिल करने के बहुत करीब है, जो गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किया गया था।

इसके अलावा, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत दस्तावेज, सीएमडी/निदेशक स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्त, आपकी कंपनी की मासिक एवं वार्षिक रिपोर्ट भी द्विभाषी रूप में तैयार की जाती रहीं। आपकी कम्पनी की प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय स्तर की गृह पत्रिका "गोंडवाना भारती" ने भी हिन्दी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देना जारी रखा, जिसकी देशभर में प्रशंसा हुई।

सितम्बर 2024 के महीने में, कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार "राजभाषा पखवाड़ा" का आयोजन किया गया। कंपनी के कर्मचारियों के बीच हिंदी को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए, इस दौरान कई हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। माह के दौरान आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 5000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 4000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 3000 रुपये और सांत्वना पुरस्कार 800 रुपये दिए गए। सभी पुरस्कार विजेताओं को उनकी संबंधित श्रेणी में प्रमाण पत्र भी दिए गए। इसके अलावा, शेष प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश एवं वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार मुख्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं विभिन्न विभागों का निरीक्षण भी किया गया।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश एवं वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार आपकी कंपनी के विभिन्न विभागों में राजभाषा की त्रैमासिक प्रगति की समीक्षा के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें भी आयोजित की गईं।

आपकी कंपनी ने क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में राजभाषा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पीएसयू), रांची (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की दो अर्धवार्षिक बैठकें भी आयोजित की हैं।

24.0 महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अंतर्गत प्रकटीकरण और जानकारी:

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण और सूचना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान सीएमपीडीआईएल में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों या शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:

1. एक वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न शिकायतों की संख्या – शून्य
2. एक वर्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या – शून्य
3. 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या – शून्य
4. एक वर्ष में यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों या कार्यशालाओं की संख्या -01 (ऑनलाइन)
5. मामले के संबंध में नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति – लागू नहीं

24.1 कंपनी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करती है।

25.0 सीएमपीडीआईएल और सीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन 2024-25 के गैर वित्तीय मापदंडों के विरुद्ध उपलब्धि

25.1 ड्रिलिंग (केवल विभागीय ड्रिलिंग) :

सीएमपीडीआईएल के समझौता ज्ञापन 2024-25 के अनुसार, 'ड्रिलिंग (केवल ड्रिलिंग विभाग) (लाख मीटर), क्रम संख्या 2.0' शीर्षक के अंतर्गत, 4.2 लाख मीटर ड्रिलिंग के लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 4.64 लाख मीटर ड्रिलिंग की रही।

25.2 ड्रिलिंग (कुल):

सीएमपीडीआईएल के एमओयू 2024-25 के अनुसार, शीर्षक 'ड्रिलिंग (कुल) (लाख मीटर), क्रम संख्या 2.1' के अंतर्गत, लक्ष्य 10 लाख मीटर ड्रिलिंग के मुकाबले उपलब्धि 10.12 लाख मीटर ड्रिलिंग की रही।

25.3 अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार जीईएम से खरीद:

सीएमपीडीआईएल के एमओयू 2024-25 के अनुसार, शीर्षक 'अनुमोदित खरीद योजना (%) के अनुसार जेम से खरीद क्रमांक 7.0' के अनुसार, 'अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार जेम 100% खरीद' के लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 334.64% रही।

25.4 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुत करना:

सीएमपीडीआईएल के समझौता ज्ञापन 2024-25 के अनुसार, 'भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (संख्या) की तैयारी और प्रस्तुत करना' शीर्षक के अंतर्गत, क्रम संख्या 8.0' के अनुसार, '32 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (संख्या) की तैयारी और प्रस्तुत करना' के लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 31 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (संख्या) की तैयारी और प्रस्तुत करना थी।

25.5 यूजी खदानों के लिए परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुत करना:

सीएमपीडीआईएल के समझौता ज्ञापन 2024-25 के अनुसार, शीर्षक 'यूजी खदानों (संख्या) के लिए परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुतिकरण, क्रम संख्या 9.1' के अंतर्गत, यूजी खदानों के लिए 14 परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के लक्ष्य के मुकाबले यूजी खदानों के लिए 14 परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुतिकरण की उपलब्धि प्राप्त हुई।

25.6 ओसी खदानों के लिए परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुतीकरण:

सीएमपीडीआईएल के समझौता ज्ञापन 2024-25 के अनुसार, 'ओसी खदानों (संख्या) के लिए परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुतीकरण' शीर्षक के अंतर्गत, क्रम संख्या 9.2, 'ओसी खदानों के लिए 18 परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुतीकरण' लक्ष्य के मुकाबले ओसी खदानों के लिए 19 परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुतीकरण की उपलब्धि रही।

25.7 निर्दिष्ट समय के भीतर टीआरडीएस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के चालान की स्वीकृति/अस्वीकृति:

सीएमपीडीआईएल के समझौता ज्ञापन 2024-25 के अनुसार, 'निर्दिष्ट समय (%) के भीतर टीआरडीएस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के चालान की स्वीकृति/अस्वीकृति, क्रम संख्या 10.0' शीर्षक के अंतर्गत, 100% लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 100% रही।

25.8 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा का अधिग्रहण:

सीएमपीडीआई के एमओयू 2024-25 के अनुसार, '2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण (विभाग) (लाइन किमी) के माध्यम से डेटा का अधिग्रहण, क्रम संख्या 12.0' शीर्षक के अंतर्गत, '2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण (विभाग) के माध्यम से 400 लाइन किमी डेटा का अधिग्रहण' के लक्ष्य के मुकाबले 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण (विभाग) के माध्यम से 437.95 लाइन किमी डेटा का अधिग्रहण किया गया।

26.0 सीएमपीडीआईएल में कोल इंडिया स्थापना दिवस मनाया गया।

मिनी रत्न कंपनी सीएमपीडीआई ने 21 नवंबर, 2024 को रवींद्र भवन, सीएमपीडीआई, रांची में पूरे उत्साह के साथ 50वां कोल इंडिया स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि, पूर्व आईएफएस अधिकारी और धर्मल पावर और कोयला खनन परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष डॉ. शरद सिंह नेगी ने अपने संबोधन में राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सीएमपीडीआई की भूमिका की प्रशंसा की और कहा कि सीएमपीडीआई को पर्यावरण के मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए, खदान की योजना और डिजाइनिंग रिपोर्ट तैयार करते समय पर्यावरण के दृष्टिकोण और पर्यावरण विभाग के कर्मचारियों को शामिल करना चाहिए।

मुख्य अतिथि के रूप में सीआईएल के चेयरमैन श्री पी.एम. प्रसाद ने सीएमपीडीआई की सराहना की तथा विभिन्न क्षेत्रों में कोल इंडिया लिमिटेड और सीएमपीडीआई की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएमपीडीआई को अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बढ़ाना चाहिए, महत्वपूर्ण खनिजों, सौर क्षेत्र, भूमिगत कोयला गैसीकरण और सतही कोयला गैसीकरण के क्षेत्रों में खोज करनी चाहिए। श्री प्रसाद ने आगे कहा कि सीएमपीडीआई कोल इंडिया लिमिटेड की रीढ़ है और निजी क्षेत्र भी इसकी विशेषज्ञता के कारण सीएमपीडीआई की ओर देख रहा है।

सीएमपीडीआई के सीएमडी श्री मनोज कुमार ने अपने संबोधन में पिछले एक वर्ष में सीएमपीडीआई की प्रमुख उपलब्धियों और विशेष रूप से सीएमपीडीआई में राष्ट्रीय कोयला और ऊर्जा अनुसंधान केंद्र (एनएसीसीआईआर) (चरण-I) की स्थापना; इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में 5जी उपयोग मामलों का प्रदर्शन आदि पर प्रकाश डाला।

सीएमपीडीआई के कर्मचारियों को उनके संबंधित परिचालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर ड्रिल उत्पादकता (हाइड्रोस्टिक) के आधार पर सिंगरौली कैंप, रीजनल इंस्टीच्यूट-V। सिंगरौली को प्रथम पुरस्कार तथा राजनगर कैंप, रीजनल इंस्टीच्यूट-V, रांची को द्वितीय पुरस्कार मिला। मैकेनिकल श्रेणी में गोपालपुर कैंप, रीजनल इंस्टीच्यूट-VII को प्रथम पुरस्कार तथा बरकाकाना कैंप, रीजनल इंस्टीच्यूट-III को द्वितीय पुरस्कार मिला।

रिपोर्ट तैयार करने में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए, ओपनकास्ट प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स के लिए श्री जीवाईपी रेड्डी, महाप्रबंधक (खनन), सीएमपीडीआई, आरआई-IV, नागपुर और भूमिगत प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के लिए श्री एस जयकुमार, मुख्य प्रबंधक (खनन), सीएमपीडीआई, आरआई-IV, नागपुर को पुरस्कार दिए गए; ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने के लिए आरआई-III, रांची के श्री लक्ष्मीदीप जी, प्रबंधक (पर्यावरण) और श्री अमूल पटवाल, उप प्रबंधक (पर्यावरण) की टीम को पुरस्कार दिए गए। श्री सुशोभन कुंडू, महाप्रबंधक (सिविल); श्री सुजीब चटर्जी, महाप्रबंधक (सिविल) श्री फराह नवाज, प्रबंधक (सिविल); श्री नवीन कुमार, उप प्रबंधक (सिविल) श्री डी उदय कुमार, सीएमपीडीआई (मुख्यालय) के सहायक प्रबंधक (सिविल) की टीम ने अवसंरचना नियोजन के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। श्री त्रिशित घोष, वरिष्ठ प्रबंधक, श्री अपूर्व दास, प्रबंधक, श्री सुभद्रत बेरा, उप प्रबंधक, सौरव गांगुली, उप प्रबंधक, नोनीहाल पी घाटोवर, उप प्रबंधक की टीम ने जीआर तैयारी के लिए पुरस्कार प्राप्त किया।

उत्कृष्ट प्रदर्शन श्रेणी में, पर्यावरण प्रयोगशाला, आरआई-IV, नागपुर को पर्यावरण प्रयोगशाला सेवाओं के लिए; पर्यावरण विभाग, आरआई-VII, भुवनेश्वर (ईआईए/ईएमपी और प्रयोगशाला सेवाओं के अलावा) और आरआई-VI, सिंगरौली को जियोमैटिक्स सेवाओं के लिए; वित्तीय सेवाओं के लिए श्री पीके सोमानी, आरआई-V, बिलासपुर; श्री मोहम्मद नूर उद्दीन, वरिष्ठ प्रबंधक, श्री दिलीप कुमार किस्कू, उप प्रबंधक, श्री नीतीश कुमार, उप प्रबंधक ड्रिलिंग और जीआर के अलावा भू-भौतिकी और जल विज्ञान सहित अन्वेषण सेवाओं के पुरस्कृत किया गया। ओसी डिवीजन, मुख्यालय और जियोमैटिक्स डिवीजन, मुख्यालय को 2023-24 में बाहरी परामर्श कार्यों के लिए चुना गया है।

5जी प्रौद्योगिकी रोलआउट के 'नवाचार' के लिए डॉ. तारिक सज्जाद, जीएम (एमई), श्री धीरज कुमार, जीएम (खनन) /टीएस, सीएमपीडीआई मुख्यालय; श्री जे. तिवारी, सीएम (ईएंडटी), टीई मुख्यालय, रांची; और सॉफ्टवेयर विकास के लिए डॉ. थिनेश कुमार को पुरस्कार दिया गया।

सीएसआर के अंतर्गत, सीएमपीडीआई (मुख्यालय) को 2023-24 में सीएसआर बजट के अधिकतम उपयोग के लिए पुरस्कार मिला और क्षेत्रीय संस्थान-VII, भुवनेश्वर को वित्त वर्ष 2023-24 में सभी आरआई के बीच व्यय में वृद्धि के लिए पुरस्कार मिला।

सिविल इंजीनियरिंग के लिए पीएमसी सेवाओं के लिए सिविल विभाग मुख्यालय; और डॉ. तारिक सज्जाद, जीएम (एमई), माइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम; श्री कुणाल दास, जीएम (माइनिंग) यूएमडी; श्री आर.के. सिंह, जीएम (एक्सप्लोरेशन); श्री एम.के. माजी, मुख्य प्रबंधक (उत्खनन), ई-पी एंड सीएम; श्री जे. तिवारी, मुख्य प्रबंधक (ईएंडटी) एमई; श्री सुनील कुमार, मुख्य प्रबंधक (वित्त) वित्त और श्री राहुल कुमार, उप प्रबंधक (ईएंडटी), एमई सीएमपीडीआई अर्थ साइंस म्यूजियम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए; श्री तारिक सज्जाद, जीएम (एमई); श्री जे. तिवारी, मुख्य प्रबंधक (ईएंडटी); श्री दीपक कुमार, जीएम (एमएम); श्रीमती सुमन रस्तोगी, मुख्य प्रबंधक (पी); श्री एसबी तिवारी, मुख्य प्रबंधक (वित्त); श्री विक्रान्त त्रिवेदी, प्रबंधक (पी); श्री राहुल कुमार, उप प्रबंधक (ईएंडटी); श्री अम्बरीश चौबे, उप प्रबंधक (एमएम) स्पर्श रहित फेस कम पाम बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीनों की स्थापना के लिए; श्री मोहित रस्तोगी, महाप्रबंधक (जियोमैटिक्स); श्री राकेश रंजन, महाप्रबंधक (उत्खनन)/जियोमैटिक्स; श्री रोहित सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (जियो)/जियोमैटिक्स की टीम कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) वेब पोर्टल और ऐप के लिए; राकेश कुमार प्रधान, प्रबंधक (खनन), यूएमडी डिवीजन, सीएमपीडीआई की टीम; अभिषेक कुमार, प्रबंधक (ई एंड एम), सीएमपी डिवीजन, सीएमपीडीआई; राज कुमार मीना, उप प्रबंधक (भूविज्ञान), ओसी डिवीजन, सीएमपीडीआई; श्री कितली नवीन, प्रबंधक (वित्त), सीएमपीडीआई श्री आलोक कुमार झा, वरिष्ठ प्रबंधक (उत्खनन), सीएमपीडीआई, आरआई-वी, बिलासपुर; श्री विकास रजक, प्रबंधक (भूविज्ञान), सीसी लैब, मुख्यालय, रांची को विशेष उपलब्धि पुरस्कार मिला।

इसके अतिरिक्त, श्रीमती. पौलोमी बक्सी; श्री अवनीश कुमार, श्री सुनील कुमार भावरिया; श्री सचिन मालपा ने 'युवा अधिकारी' पुरस्कार जीता।

इसके अलावा, श्री अनंत चंद, लेखा लिपिक - आरआई-I; श्री मनोज कुमार मंडल, - आरआई-II; पन्ना लाल कश्यप - आरआई-V; श्री शुभ्रजीत तलपात्रा, - आरआई-VI; श्री पी सिम्हाचलम - आरआई-VII; श्री अनीश थॉमस - आईसीटी

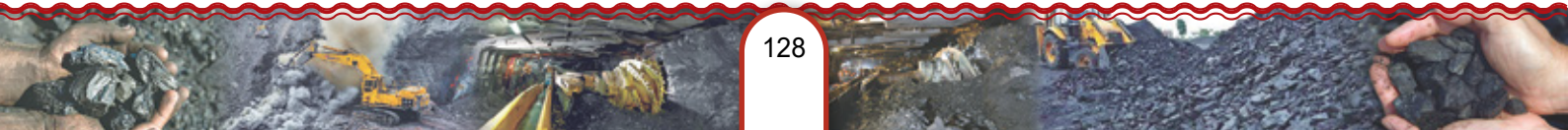
प्रभाग, (मुख्यालय) को कर्मचारी श्रेणी में सेवाओं के संबंधित क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हुए।

श्री अटल बिहारी, जीएम (उत्खनन), आरडी, आरआई-VI, सिंगरौली; श्री केए पांडियन, जीएम/एचओडी (सिविल), सीएमपीडीआई-मुख्यालय; श्री अमर कांत मिश्रा, जीएम (एस एंड टी), सीएमपीडीआई-मुख्यालय; श्री संजीव कुमार, महाप्रबंधक (ईएंडएम), सीएमपीडीआई मुख्यालय; डॉ. तारिक सज्जाद, जीएम (एमई), सीएमपीडीआई-मुख्यालय; श्री आरसी दत्ता, महाप्रबंधक (उत्खनन/ओसी), सीएमपीडीआई मुख्यालय; श्री राकेश रंजन, जीएम (उत्खनन/जियोमैटिक्स), सीएमपीडीआई-मुख्यालय; श्री टीके दास, जीएम/एचओडी (सिविल), सीएमपीडीआई, आरआई-VII; डॉ. विनीता अरोड़ा, जीएम/एचओडी (पर्यावरण), सीएमपीडीआई, आरआई-VII-भुवनेश्वर; श्री भबानी प्रसाद मिश्रा, महाप्रबंधक (सिविल/टीई), सीएमपीडीआई-मुख्यालय; श्री देबाशीष कुमार. रॉय, महाप्रबंधक (उत्खनन), सीएमपीडीआई, आरआई-VII; श्री सुजीब चटर्जी, महाप्रबंधक (सिविल), सीएमपीडीआई-मुख्यालय; श्री सुशोभन कुंडू, महाप्रबंधक (सिविल), सीएमपीडीआई-मुख्यालय; श्री आरके अमर, महाप्रबंधक (बीडीडी), मुख्यालय, रांची; श्री कुमार शशि भूषण, महाप्रबंधक (उत्खनन/पीआरओ), सीएमपीडीआई-मुख्यालय को "लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड" प्राप्त हुआ।

खेल श्रेणी में श्री सतीश कुमार, प्रबंधक (ईएंडएम); श्री दीपांकर कोंवर (सीएटी-I), पीआर विभाग और सोनू पांडे को पुरस्कार मिला।

इस अवसर पर सीसीएल के सीएमडी श्री निलेन्द कुमार सिंह, मुख्य अभियंता (टीपीपीडी)-सह-सदस्य सचिव, केंद्रीय विद्वत प्राधिकरण श्री महिपाल सिंह, निदेशक (टी/सीआरडी) श्री शंकर नागाचारी, निदेशक (पी एंड डी) श्री अजय कुमार, निदेशक (टी/ईएस) श्री सतीश झा, निदेशक (टी/आरडी एंड टी) श्री अच्युत घटक, सीएमपीडीआई के सीवीओ श्री सुमित कुमार सिन्हा, सीएमपीडीआई के पूर्व सीएमडी, पूर्व निदेशक, सीएमपीडीआई, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के पूर्व जीएम, सभी क्षेत्रीय निदेशक, जीएम/एचओडी, सीएमओआई के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड का कॉर्पोरेट गीत गाया गया।







27.0 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के फोरम (डब्ल्यूआईपीएस) सीएमपीडीआईएल की गतिविधियाँ।

कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए डब्ल्यूआईपीएस के पदाधिकारी और कार्यकारी समिति इस प्रकार हैं:

1. सुश्री शिल्पी स्वरूप, उप सीएमओ	: समन्वयक
2. सुश्री आभा प्रसाद, महाप्रबंधक (सीपी)	: महासचिव
3. सुश्री स्वप्नाली बसु, सीएम (वित्त)	: कोषाध्यक्ष
4. सुश्री प्रियंका भट्टा, प्रबंधक (भू-विज्ञान)	: वैकल्पिक समन्वयक
5. सुश्री चारु ओबेरॉय, सहायक प्रबंधक (सीपी)	: संयुक्त कोषाध्यक्ष

01.01.2025 से डब्ल्यूआईपीएस की कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया गया है और यह इस प्रकार है:

1. सुश्री पूनम सिंह, मुख्य सचिव (पर्यावरण) : समन्वयक
2. सुश्री गार्गी पांडे, उप प्रबंधक (पर्यावरण) : अपर समन्वयक
3. सुश्री चारु ओबेरॉय, सहायक प्रबंधक (सीपी) : सचिव
4. सुश्री दीप्ति मोहन पिल्लई, सहायक प्रबंधक (पर्यावरण) : कोषाध्यक्ष

वित्त वर्ष 24-25 (01.04.2024 से 31.03.2025 तक) के दौरान गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:

- **सीएमपीडीआईएल के संविदा कर्मियों को डिस्पोजेबल डायपर का वितरण**

डब्ल्यूआईपीएस, सीएमपीडीआईएल चैप्टर, रांची ने 3 अक्टूबर, 2024 को स्वच्छता ही सेवा मिशन के एक भाग के रूप में सीएमपीडीआईएल के संविदा श्रमिकों को डिस्पोजेबल डायपर वितरित किए।

कोयला इंडिया
Coal India

cmpdi
A Bharat Ratna Company

कोयला मंत्रालय
Ministry of Coal
भारत सरकार

ITUWTSA
NEW DELHI 2024

WIPS, CMPDI distributed Disposable diapers to contractual workers of CMPDI on 03.10.24

Women in Public
CMPDI

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी).

- **"उमंग" का आयोजन : डब्ल्यूआईपीएस और कस्तूरी महिला सभा द्वारा सीएमपीडीआईएल मुख्यालय रांची में उत्सव-सह-प्रदर्शनी**

21 मार्च 2025 से 23 मार्च 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाएं (डब्ल्यूआईपीएस) और कस्तूरी महिला सभा (केएमएस) द्वारा तीन दिवसीय कार्यक्रम "उमंग" उत्सव-सह-प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

मनोज कुमार, सीएमडी, सीएमपीडीआईएल और श्रीमती रूपाली गुप्ता, अध्यक्ष, कस्तूरी महिला सभा (केएमएस) ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मेले का उद्देश्य ग्रामीण और स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाना और छोटे उद्यमियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना था और साथ ही मिट्टी, जूट, लकड़ी के उत्पाद और बांस आदि जैसी प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल चीजों के उपयोग को बढ़ावा देना था। इस मेले में फैशनेबल परिधान/साड़ी, उत्तम आभूषण, घरेलू सामान, कला और सजावट, सजावटी पौधे और स्वादिष्ट भोजन से संबंधित लगभग 50 स्टॉल लगाए गए थे।



• सीएमपीडीआईएल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का उत्सव

मुख्य अतिथि बिलासपुर के अपोलो अस्पताल की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शांभवी कल्याणी श्रीवास्तव ने स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण टिप्स और तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए व्यावहारिक सलाह दी।

कार्यक्रम में क्षेत्रीय निदेशक श्री मनोज कुमार, श्यामली महिला सभा की अध्यक्ष, आरआई-5 की सभी महिला कर्मचारी/अधिकारी, महिला ठेका श्रमिक, अधिकारी और कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारी मौजूद थे।

कार्यक्रम के दौरान महिला कर्मचारियों ने रैंप वॉक, स्किट, नृत्य प्रदर्शन, गीत, भाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को उत्साह और जीवंतता से भर दिया।

इस अवसर पर, आरआई-5 प्रबंधन ने कार्यस्थल में महिलाओं की मजबूत भागीदारी को बढ़ावा देने और उनके अमूल्य योगदान को मान्यता देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।



- **सीएमपीडीआईएल आरआई-IV, नागपुर द्वारा गर्भाशय ग्रीवा कैंसर पर जागरूकता सत्र का आयोजन**
सामुदायिक स्वास्थ्य की दिशा में एक सक्रिय कदम उठाते हुए, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), क्षेत्रीय संस्थान-IV, नागपुर ने सर्वाधिक कैंसर जागरूकता सत्र का आयोजन किया। इस पहल में कई कर्मचारियों ने भाग लिया, जो समुदाय की मजबूत भागीदारी और निवारक स्वास्थ्य सेवा के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।



- **सीएमपीडीआईएल क्षेत्रीय संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का उत्सव**
इन कार्यक्रमों में क्षेत्रीय निदेशक, सभी महिला कर्मचारी, महिला संविदा श्रमिक, अधिकारी और कंपनी के वरिष्ठ कार्मिक उपस्थित थे।

28. ई-नीलामी

इससे पहले, कोयले की ई-नीलामी केवल बाहरी एजेंसियों जैसे एमएसटीसी और एमजंक्शन द्वारा की जा रही थी। सीआईएल के निदेशक मंडल ने सीआईएल को कोयले की ई-नीलामी आयोजित करने के लिए इन-हाउस क्षमता विकसित करने का निर्देश दिया। सीएमपीडीआईएल ने सिंगल विंडो मोड एग्रीस्टिक स्कीम 2022 के अनुसार कोयले की नीलामी के लिए कोयला ई-नीलामी मंच विकसित किया है। पोर्टल का विकास और इसके संशोधन एनआईसी, एमआईआईटीवाई, भारत सरकार द्वारा किए गए हैं, जो इस परियोजना के लिए हमारे प्रौद्योगिकी भागीदार हैं। सीएमपीडीआईएल ने 2023 से कोयले के लिए ई-नीलामी आयोजित करना शुरू कर दिया है। सीएमपीडीआईएल ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 130 मिलियन टन मात्रा के लिए सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के लिए 237 नीलामी सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई है। दिसंबर 2024 में, एसडब्ल्यूएमए योजना 2022 में परिवर्तन किए गए हैं। नीलामी योजना में किए गए परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए पोर्टल का विकास किया जा रहा है और संशोधित योजना के अनुसार नीलामी आयोजित करने के लिए बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। नए विकसित प्लेटफॉर्म में, सिस्टम में अधिक पारदर्शिता की चिंता व्यक्त की गई है। बोलीदाता अपनी बोलियों को टाइम पंच के साथ देख और संदर्भित कर सकेंगे क्योंकि लाइव पोर्टल में की गई प्रत्येक गतिविधि के लिए इसे बोलीदाता के डैशबोर्ड में संग्रहीत किया जाएगा। नए विकसित प्रणाली उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल होगी और लाइव नीलामी के दौरान बोलीदाता द्वारा गलती करने की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी। नए विकसित प्लेटफॉर्म में, नीलामी के सफल समापन तक नीलामी प्रक्रिया में कोई भी बदलाव करने के लिए सीएमपीडीआईएल या एनआईसी द्वारा प्रशासक की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

एसडब्ल्यूएमए के माध्यम से कोयले की नीलामी से सीआईएल के समग्र लाभ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पन्न होता है।

29. निदेशक का उत्तरदायित्व विवरण:

- 29.1 वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था तथा भौतिक विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था।
- 29.2 निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया था तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
- 29.3 निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी।
- 29.4 निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए थे।
- 29.5 निदेशकों ने पुष्टि की कि उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

लेखा परीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर मेसर्स केसी टाक एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रांची को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

पावती:

आपके निदेशक भारत सरकार, विशेष रूप से कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड, तथा उसकी सहायक कम्पनियों, राज्य सरकारों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रति आभारी हैं, जिनके साथ आपकी कम्पनी को निकट संपर्क में काम करना पड़ता है, तथा कम्पनी के कार्यों को पूरा करने में उनके सहयोग तथा प्रोत्साहन के लिए हम आभारी हैं। हम अपने सम्मानित ग्राहकों के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने हम पर विश्वास जताया तथा हमें तथा कम्पनी के समर्पित कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान किया।

परिशिष्ट :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अंतर्गत निदेशकों की रिपोर्ट में दी जाने वाली अपेक्षित सूचना जैसे ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय, अनुसंधान और विकास, सीईओ और सीएफओ प्रमाणीकरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न का सार, कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और प्रबंधन के उत्तर, सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और प्रबंधन के उत्तर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ, एमओयू 2024-25 पर रिपोर्ट और प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक आदि के विवरण की सूचना भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल की ओर से



(मनोज कुमार)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : रांची

तारीख : 12.08.2025

परिशिष्ट - I

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अंतर्गत निदेशकों की रिपोर्ट में दी जाने वाली अपेक्षित सूचना, बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के साथ, नियम-8, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय के संबंध में।

क. कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए ऊर्जा संरक्षण पहल

सीएमपीडीआई ने 2024-25 में ऊर्जा संरक्षण अध्ययन किया है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) से मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में स्थित विभिन्न खुली और भूमिगत खदानों में डीजल ऑडिट और विशिष्ट डीजल खपत की बेंचमार्किंग के साथ-साथ विद्युत ऊर्जा ऑडिट और विशिष्ट विद्युत ऊर्जा खपत की बेंचमार्किंग का संचालन किया है।

डीजल बेंचमार्किंग अध्ययन में सीआईएल के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित मुख्य मद अपनाए गए हैं: डीजल संरक्षण:

- रिसाव की पहचान एवं न्यूनीकरण तथा तैनात एचईएमएम के लिए निवारक रखरखाव उपायों को अपनाना
- ढोने वाली सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एचईएमएम का गति अनुकूलन
- निष्क्रिय घंटों को कम करने और एचईएमएम की अनावश्यक आवाजाही को रोकने के लिए समय अध्ययन
- सीएमपीडीआई योजना एवं डिजाइन मानदंडों के साथ तुलना, ट्रैक माउंटेड के लिए 0.1 लीटर/बीएचपी-घंटा, व्हील माउंटेड के लिए 0.06 लीटर/बीएचपी-घंटा और इलेक्ट्रिक व्हील माउंटेड एचईएमएम के लिए 0.054 लीटर/बीएचपी-घंटा

सीआईएल के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में किए गए विद्युत ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंचमार्किंग अध्ययनों में, पिछले तीन (3) वर्षों के ऐतिहासिक आंकड़ों और भूमिगत और खुली खदानों के क्षेत्र दौरे के दौरान किए गए विद्युत मापों के आधार पर प्रवृत्ति विश्लेषण में, निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण विधियों को अपनाया गया है:

- मांग पक्ष प्रबंधन
- संचरण एवं वितरण घाटे में कमी
- पावर फैक्टर सुधार
- कुशल रोशनी प्रणाली
- ट्रांसफार्मरों के पुनर्गठन द्वारा परिवर्तन ट्रांसफार्मर में कमी
- ऊर्जा निगरानी के लिए ऊर्जा मीटरों की स्थापना
- पम्पिंग प्रणाली में ऊर्जा संरक्षण के उपाय

बीईई मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए ऊर्जा लेखा परीक्षा और ऊर्जा बेंचमार्किंग अध्ययनों के लिए, कृपया नीचे दी गई तालिका देखें:

(A1) वर्ष 2024-25 के लिए सीएमपीडीआई द्वारा शुरू की गई ऊर्जा संरक्षण पहल

क्र	डीजल ऑडिट और बेंचमार्किंग	डीजल खपत (किलोलीटर)	प्रस्तावित बचत क्षमता
1.	ईसीएल द्वारा पहचाने गए 7 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग	26572	1146 किलो लीटर/वर्ष
2.	बीसीसीएल द्वारा चिन्हित 11 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग	29606	1296 किलो लीटर/वर्ष
3.	सीसीएल द्वारा चिन्हित 28 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग	49866	2102 किलो लीटर/वर्ष
4.	डब्ल्यूसीएल द्वारा चिन्हित 15 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग	59007	2566 किलो लीटर/वर्ष
5.	एसईसीएल द्वारा चिन्हित 3 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग	90569	4004 किलो लीटर/वर्ष
6.	एनसीएल द्वारा चिन्हित 10 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग	142437	6325 किलो लीटर/वर्ष
7.	एमसीएल द्वारा चिन्हित 11 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग	43592	1935 किलो लीटर/वर्ष
ख	2024-25 के दौरान किए गए विद्युत ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंचमार्किंग के अध्ययन		
1.	एमपी कोलियरी और दामोदा कोलियरी, बीसीसीएल के लिए विदूत ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंचमार्किंग रिपोर्ट।		
2.	एमकेडी-I और एमकेडी-III, उमरेर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल के लिए विदूत ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंचमार्किंग रिपोर्ट		
3.	सीसीएल की निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए विदूत ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंचमार्किंग रिपोर्ट। • बिरसा, बरकासयाल क्षेत्र • झारखंड, हजारीबाग क्षेत्र • धोरी खास उग खदान, ढोरी क्षेत्र • खास महल, बी एंड के क्षेत्र • स्वांग/गोविंदपुर पीएच II, कथारा क्षेत्र		

(A2) वर्ष 2024-25 के लिए सीएमपीडीआई द्वारा की गई खान रोशनी सर्वेक्षण रिपोर्ट

क्र. सं.	कार्य विवरण
1.	राजमहल ओसीपी, ईसीएल का रोशनी सर्वेक्षण

ख. सौर ऊर्जा संयंत्र पहल

- सीसीएल के गिरिडीह क्षेत्र में 4 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र (एसपीपी) पीएमसी सेवाओं के अंतर्गत चालू किया गया।
- सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में 2.05 मेगावाट एसपीपी (आरटीएस) की स्थापना की जा रही है।
- सीसीएल के बरकासयाल क्षेत्र में 5 मेगावाट एसपीपी की स्थापना की जा रही है।
- सीसीएल के बीएंडके और एनके क्षेत्र में 23.5 मेगावाट एसपीपी के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया गया।
- डब्ल्यूसीएल के चंद्रपुर क्षेत्र में 5 मेगावाट, ग्राउंड माउंटेड एसपीपी के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया गया।
- डब्ल्यूसीएल के माजरी क्षेत्र में 23 मेगावाट, ग्राउंड माउंटेड एसपीपी के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया गया।
- डब्ल्यूसीएल के कन्हान क्षेत्र में 70 मेगावाट, ग्राउंड माउंटेड एसपीपी के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया गया।
- एनसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में 1.3 मेगावाट एसपीपी (आरटीएस) के लिए निविदा जारी की गई।
- एमसीएल के लखनपुर क्षेत्र में 10 एसपीपी के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया गया।
- एमसीएल के ओरिएंट क्षेत्र और आईबी वैली क्षेत्र में 25 मेगावाट एसपीपी की एनआईटी।
- एमसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में 15 मेगावाट एसपीपी की डीपीआर/पीएफआर।

- ईसीएल के सालनपुर क्षेत्र में 5 मेगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र (एफएसपीवी) की एनआईटी।
- ईसीएल के सोनेपुर बाजारी क्षेत्र में 5 मेगावाट एसपीपी की डीपीआर।
- एसईसीएल के शारदा ओसीपी में 1.5 मेगावाट ऊर्जा सरोवर फ्लोटिंग सौर संयंत्र की एनआईटी।
- एसईसीएल के विवेक नगर में 5 मेगावाट एसपीपी की एनआईटी।
- सीएमपीडीआईएल, आरआई-VII, भुवनेश्वर में 40 किलोवाट एसपीपी चालू।
- सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) में 25 किलोवाट क्षमता के सौर वृक्ष सहित 115 किलोवाट क्षमता के सौर वृक्ष का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।
- इलेक्ट्रिक वाहन: सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, रांची में 23 इलेक्ट्रिक वाहनों को किराए पर लिया गया है।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

क्र.सं.	विवरण	2024-25
1.	कमाई	3.57
2.	विदेशी मुद्रा पर व्यय	0.01

घ. ऊर्जा संरक्षण

- एस एंड टी परियोजना जिसका शीर्षक है "क्लोड लूप बाइनरी ऑर्गेनिक रैंकिन साइकिल प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित एससीसीएल कमांड क्षेत्र के मनुगुरु क्षेत्र में भू-तापीय ऊर्जा (20 किलोवाट कैप) बिजली उत्पादन पायलट परियोजना की स्थापना" - **सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोठागुडेम और शीरम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली**, को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया है:
 - तेलंगाना के मनुगुरु में भूतापीय द्रव को ऊष्मा स्रोत के रूप में उपयोग करके स्वच्छ, विश्वसनीय और कुशल बिजली का उत्पादन करने के लिए बंद लूप बाइनरी ऑर्गेनिक रैंकिन साइकिल (ओआरसी) प्रक्रिया प्रौद्योगिकी पर आधारित भारत में स्वदेशी 20 किलोवाट पायलट प्रदर्शन इकाई स्थापित करना।
 - भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन लागत को मानकीकृत और अनुकूलित करना निर्बाध विद्वत् आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र रूप से या संयोजन में स्रोत के लिए व्यावसायिक व्यवहार्यता।
- अनुसंधान एवं विकास परियोजना जिसका शीर्षक है "भारतीय भू-खनन परिस्थितियों में प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) पर एक पायलट परियोजना (चरण-I)" - **सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची, ईसीएल, सैंक्टोरिया और मेसर्स एगो एक्सर्जी टेक्नोलॉजीज इंक (ईईटीआई), कनाडा**
 - इस अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य भारतीय कठोर कोयला उत्पादन की विशिष्ट परिस्थितियों में सिंथेटिक गैस के उत्पादन के लिए यूसीजी पायलट प्लांट विकसित करना है।
 - चरण-I में कोयला ब्लॉक के भीतर पायलट प्लांट स्थल का चयन, कास्ता वेस्ट कोयला ब्लॉक के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन और गवेषण कुओं की ड्रिलिंग, कोर नमूनों का संग्रह और अन्य क्षेत्र परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण, डेटा प्रसंस्करण और विश्लेषण सहित साइट लक्षण वर्णन, पायलट प्लांट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी और अन्य वैधानिक अनुमोदन शामिल होंगे।
- अनुसंधान एवं विकास परियोजना जिसका शीर्षक है "द्वि-चेहरे वाला पेरोव्स्काइट मॉड्यूल - 4-टी पेरोव्स्काइट-एसआई टैंडम संरचना की ओर अग्रसर"- **आईआईटी बॉम्बे**।
 - इस परियोजना का लक्ष्य मॉड्यूल स्तर पर लगभग 20% और सेल स्तर पर लगभग 24% दक्षता प्राप्त करना है,

- साथ ही लगभग 10 वर्षों तक स्थिरता बनाए रखना है। उपकरणों की विश्वसनीयता ISOS प्रोटोकॉल के अनुसार मापी जाएगी। विकसित मॉड्यूल का एक प्रोटोटाइप TRL4/5 में वितरित करने की योजना है।
- इसका लक्ष्य 4T टैंडम उपकरणों को साकार करना है। इससे मॉड्यूल स्तर पर >25% और सेल स्तर पर >30% की अनुमानित दक्षता वाली 4T Si-पेरोव्स्काइट टैंडम संरचना विकसित करने की उम्मीद है। विकसित मॉड्यूल का एक प्रोटोटाइप TRL3/4 पर वितरित करने की योजना है।
 - अनुसंधान एवं विकास परियोजना जिसका शीर्षक है "प्रिंटिंग द्वारा मोनोलिथिक पेरोव्स्काइट मॉड्यूल निर्माण का स्वदेशी विकास।" - आईआईटी बॉम्बे
 - 100 सेमी² उपकरणों में 12-14% की लक्षित दक्षता और 10 वर्ष से अधिक के उपकरण जीवनकाल के साथ बड़े क्षेत्र के मुद्रण योग्य पेरोव्स्काइट मॉड्यूल के लिए पायलट संयंत्र का विकास।
 - शून्य आयात निर्भरता के साथ 100% मेक-इन-इंडिया दृष्टिकोण को सक्षम करने के लिए उपकरण के अलग-अलग घटकों का अनुसंधान और विकास।
 - प्रस्तावित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक पहलू को मान्य करने के लिए भारतीय संदर्भ के संबंध में तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण किया जाएगा।
 - लगभग 100 मॉड्यूलों का क्षेत्र परीक्षण प्रस्तावित है। एक स्टैंड-अलोन स्ट्रीट लाइट के रूप में, एक उत्पाद को क्षेत्र परीक्षण के लिए सीआईएल/सीएमपीडीआई को सौंपे जाने की उम्मीद है।

ड. प्रौद्योगिकी अवशोषण

कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का उद्देश्य मुख्य रूप से खान सुरक्षा, कोयला लाभकारीकरण/उपयोग, खान पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा तथा स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के विकास सहित खनन कार्यों में दक्षता मापदंडों में सुधार करना है।

सीएमपीडीआईएल एक नोडल एजेंसी और अनुसंधान संगठन होने के नाते, अपनी कुल परिचालन गतिविधियों में विभिन्न क्षेत्रों में कई तकनीकी पहल की है।

• तकनीकी अवशोषण की दिशा में प्रयास

सीआईएल ने अपनी कुल परिचालन गतिविधियों में विभिन्न क्षेत्रों में कई तकनीकी पहल की हैं।

- भूमिगत खनन में, कई खदानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक लागू की गई है। सीआईएल की अब तक 24 खदानों में सतत खनन तकनीक (32) और बोल्टर खनन तकनीक (3) लागू की जा चुकी हैं, जो अभी भी चालू हैं। बीसीसीएल की मूनीडीह भूमिगत खदान और ईसीएल की झांझरा भूमिगत खदान में लॉन्ग वाल खनन तकनीक लागू है।
- एसईसीएल, ईसीएल और बीसीसीएल की परियोजनाओं में हाईवॉल माइनर्स के छह सेट प्रचालन में हैं, जिनकी कुल क्षमता 2.8 मिलियन टन प्रति वर्ष है। सीसीएल में लगभग 0.5 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली एक अन्य हाईवॉल माइनर परियोजना प्रदान की गई है।
- सीआईएल की 41 भूमिगत खदानों में कुल 48 मैन राइडिंग सिस्टम (एमआरएस) कार्यरत हैं। 48 मैन राइडिंग सिस्टम में से 39 चेयर लिफ्ट प्रकार के, 5 रेल कार प्रकार के, 3 फ्री-स्टीयर वाहन प्रकार के और 1 सस्पेंडेड मोनो रेल प्रकार के मैन राइडिंग सिस्टम हैं।
- बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक वाली कुछ प्रस्तावित भूमिगत खदानों के लिए, श्रमिकों और सामग्री के लिए ट्रैकलेस परिवहन प्रणाली प्रस्तावित की गई है। तदनुसार, ईसीएल की झांझरा और खोटाडीह भूमिगत खदानों में वर्तमान में दो फ्री-स्टीयर वाहन और छह बहु-उपयोगी वाहन कार्यरत हैं, और सीसीएल की चुरी भूमिगत खदान में एक फ्री-स्टीयर वाहन कार्यरत है।

- अब तक किए गए सभी चार चरणों में, कुल 27 बंद पड़ी भूमिगत खदानें राजस्व साझाकरण मोड के माध्यम से एमडीओ को आवंटित की गई हैं। इससे प्रस्तावित क्षमता में लगभग 40.0 मिलियन टन की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- खदान नियोजन के लिए उद्योग-मानक सॉफ्टवेयर जैसे जियोविया माइनएक्स, डेटा माइन, वल्कन, कार्लसन सॉफ्टवेयर पेश किए गए हैं। ये गड्ढे के डिज़ाइन, गड्ढे के अनुकूलन, संसाधनों और डंपों के निर्धारण आदि के माध्यम से सर्वोत्तम संसाधन नियोजन प्रदान करते हैं। साथ ही, चट्टान और मिट्टी के ढलानों की स्थिरता का विश्लेषण करने के लिए रॉकसाइंस इंक. से भू-तकनीकी सॉफ्टवेयर/उपकरण भी खरीदे गए हैं।
- अनुसंधान एवं विकास परियोजना (आईआईटी दिल्ली के सहयोग से डिज़ाइन की गई) के माध्यम से 2500 केएन सामान्य शियर भार क्षमता वाली बड़ी डायरेक्ट शियर मशीन (भारत में सबसे बड़ी) का कमीशनिंग और एक भू-तकनीकी प्रयोगशाला की स्थापना। कमीशनिंग के बाद से, एनसीएल, एसईसीएल, सीसीएल, एमसीएल, बीसीसीएल और एनटीपीसी की 29 खदानों से प्राप्त नमूनों का परीक्षण किया गया है और ढलान स्थिरता के लिए वैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्टों में उनका उपयोग किया गया है।
- ड्रिलिंग और विस्फोटन को समाप्त करने तथा चयनात्मक खनन को सुविधाजनक बनाने के लिए सीआईएल की कई खुली खदानों में 47 विभागीय सर्फ़ेस माइनर्स कार्यरत हैं।
- हाल ही में खुली खदानों में वाइब्रो रिपर के उपयोग पर एक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से यह पता चला है कि वाइब्रो रिपर उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहाँ पर्यावरण, सुरक्षा या अन्य कारणों से ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं है/वांछित है। वर्तमान में इन्हें एमसीएल, एसईसीएल और बीसीसीएल की कुछ खदानों में लगाया जा रहा है।
- कोयले की चोरी और संधमारी को रोकने के लिए कोयला परिवहन वाहनों में जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली [वीटीएस] शुरू की गई है।
- आरएफआईडी, सीसीटीवी और ब्रूम बैरियर आधारित भार निगरानी एवं नियंत्रण प्रणाली शुरू की गई है। इससे केंद्रीय सर्वर तक कोयले के वजन संबंधी आंकड़ों का वास्तविक समय में प्रसारण सुनिश्चित हुआ है। इससे प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है और परिवहन के दौरान कोयले की चोरी कम करने में भी मदद मिली है।
- ऑपरेटर स्वतंत्रता ट्रक डिस्पैच प्रणाली (ओआईटीडीएस) - वर्तमान में अधिकांश खदानों में वाहनों की ट्रैकिंग के स्थान पर चक्र समय और लागत को कम करने के लिए डम्पर्स का स्वचालित आवंटन, साथ ही वास्तविक समय वाहन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली, वीआईएमएस और ईंधन प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) का उपयोग किया जा रहा है।
- खुली खदानों में धूल नियंत्रण के लिए स्थायी प्रकार की स्वचालित स्पिंकलर प्रणाली - पंप ड्राइव अर्थात् स्टार्ट, स्टॉप, ट्रिप आदि की निरंतर निगरानी अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से शुरू की गई है।
- अन्वेषणात्मक ड्रिलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पीसीडी बिट्स के साथ हाइड्रोस्टैटिक ड्रिलों को पेश किया गया है।
- कोयला अन्वेषण के लिए 2डी और 3डी भूकंपीय सर्वेक्षणों के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के साथ - अत्याधुनिक सीस्मोग्राफ और वाइब्रेटर और विस्फोटक जैसे आधुनिक भूकंपीय स्रोतों का उपयोग करते हुए - आईएसपी, 2022 के दिशानिर्देशों के अनुरूप, ड्रिलिंग कार्य को काफी अनुकूलित किया गया है।
- सीएमपीडीआई ने भूकंपीय आंकड़ों के प्रसंस्करण और व्याख्या के लिए अत्याधुनिक पैराडाइम सॉफ्टवेयर के साथ-साथ घरेलू स्तर पर विकसित सॉफ्टवेयर "एसपीई" भी पेश किया है, जो कल्पनाशील प्रौद्योगिकी द्वारा उप-सतह की बेहतर संरचनात्मक जानकारी उत्पन्न करता है।
- स्ट्रेटा नियंत्रण से संबंधित कार्यों के लिए, एफएलएसी 3डी और 3डीईसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। वेंटिलेशन नेटवर्क विश्लेषण और सिस्टम सुधार से संबंधित कार्यों के लिए वेंटसिम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया

- जा रहा है, और 3डी अवतलन पूर्वानुमान के लिए सर्फर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है।
- सीएमपीडीआई सीआईएल लीजहोल्ड क्षेत्रों अर्थात बीसीसीएल, ईसीएल और एसईसीएल में सीबीएम के विकास के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) है।
 - झरिया सीबीएम ब्लॉक-I (बीसीसीएल लीजहोल्ड क्षेत्र) राजस्व साझेदारी के आधार पर सीबीएम निष्कर्षण हेतु मेसर्स प्रभा एनर्जी लिमिटेड (पीईएल) को प्रदान किया गया है। यह ब्लॉक वर्तमान में अन्वेषण चरण में है। न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) के अंतर्गत 05 अन्वेषणात्मक कोरहोल की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। परीक्षण कुओं के लिए स्थल की तैयारी प्रगति पर है।
 - झरिया सीबीएम ब्लॉक-II के लिए परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट को बीसीसीएल बोर्ड द्वारा अक्टूबर, 2024 में अनुमोदित किया गया है।
 - रानीगंज सीबीएम ब्लॉक और झरिया सीबीएम ब्लॉक-II के लिए सीबीएम डेवलपर के चयन के लिए एक मॉडल निविदा दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
 - स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगशाला ने प्रचारात्मक/क्षेत्रीय/विस्तृत अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत सीबीएम और शेल गैस पर विशिष्ट अध्ययन किए
 - इसके अतिरिक्त, सीआईएल की सहायक कंपनियों के अलावा अन्य ग्राहकों के लिए भी सीबीएम विशिष्ट विश्लेषण किया गया है।
 - सीएमपीडीआई ने आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से "कोल बेड मीथेन रिकवरी में वृद्धि और कार्बन पृथक्करण की संभावनाओं के लिए कोयला भंडार का जलाशय लक्षण वर्णन और संख्यात्मक मॉडलिंग" शीर्षक से एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना लागू की है। परियोजना की गतिविधियाँ जनवरी, 2025 में पूरी हो चुकी हैं और मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

• तकनीकी अवशोषण की दिशा में प्रयास

खुली खदान परियोजनाओं के लिए विश्व प्रौद्योगिकी के अनुरूप, सर्वाधिक उपयुक्त आकार के एचईएमएम का प्रावधान किया जा रहा है। बड़ी खुली खदानों से उच्च उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, पिछले वर्षों में 42 घन मीटर क्षमता वाले इलेक्ट्रिक रोप (ईआर) शॉवेल और 240 टन क्षमता वाले डंप ट्रकों का उपयोग किया गया, जो भारत में अब तक प्रस्तावित आकारों में सबसे अधिक हैं। सतही खनन मशीनों के उपयोग से खुली खदान परियोजनाओं में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और इस प्रकार, ब्लास्टिंग कंपन के उन्मूलन के कारण आबादी वाले क्षेत्रों के बहुत निकट काम करने की समस्या का समाधान हो गया है। इसके अलावा, संभावित चयनात्मक खनन के कारण, उत्पादित कोयले के बाहरी पदार्थों से संदूषण की संभावना भी कम हो गई है।

• आयातित प्रौद्योगिकी पर प्रयासों का विवरण:

कोल इंडिया ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए विदेशी सहयोग की परिकल्पना की है:

- यूजी और ओसी खानों, कोयला तैयारी, कोयला अन्वेषण और अन्य गतिविधियों से अधिकतम संसाधनों का दोहन करने के लिए सिद्ध और उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन कौशल को अपनाना।
- कोयला बिस्तर, परित्यक्त खदान, शेल गैस, कोयला गैसीकरण आदि से मीथेन की खोज और दोहन।
- भारतीय भू-खनन परिस्थितियों में भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) तकनीक स्थापित करने हेतु एक अनुसंधान एवं विकास पायलट परियोजना सीएमपीडीआईएल, ईसीएल और एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजी इंक. (ईईटीआई), कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में दो चरण शामिल हैं। वर्तमान में चरण-I प्रगति पर है।

- कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (सीआईएसआरओ), ऑस्ट्रेलिया द्वारा सीएमपीडीआईएल और सीआईएल के साथ मिलकर हाईवॉल माइनिंग व्यवहार्यता आकलन और लेआउट डिज़ाइन के लिए एक अनुसंधान एवं विकास पायलट परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत हाईवॉल माइनिंग इंडेक्स का उपयोग करते हुए 21 स्थलों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया है। इस परियोजना के तहत एक स्थल पर हाईवॉल खनन के लिए संभावित स्थलों का व्यवहार्यता अध्ययन सफलतापूर्वक किया गया।
- प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नवीनतम और उच्च उत्पादकता वाली भूमिगत खनन/ओपनकास्ट खनन प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण, कठिन भूवैज्ञानिक परिस्थितियों में भूमिगत कार्य में सुधार शामिल थे।
- पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा प्रबंधन और डिजिटलीकरण, कार्बन उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा, एआई और आईओटी का उपयोग, अपशिष्ट से धन सृजन, अन्वेषण में नई तकनीकों की तैनाती आदि के क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू करके अनुसंधान एवं विकास पहलों के विविधीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है।

च. 2024-25 के दौरान पूरी की गई प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं के संक्षिप्त परिणाम:

- **ऊर्जा भंडारण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफीन और कार्बन नैनो-कणों के उत्पादन हेतु निम्न श्रेणी के कोयले का उपयोग**

यह परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी, भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची द्वारा क्रियान्वित की गई।

इस परियोजना के अंतर्गत, निम्न-श्रेणी के कोयले से उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफीन, हेटेरोएटम डोपड ग्राफीन, कार्बन नैनोस्ट्रक्चर और जल-घुलनशील कार्बन नैनोस्ट्रक्चर का संश्लेषण किया गया है। संश्लेषित ग्राफीन और विकसित कार्बन नैनोस्ट्रक्चर की संरचना और संयोजन व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ग्राफीन और कार्बन नैनोस्ट्रक्चर के लगभग समान हैं। ग्राफीन के त्वरित और सरल संश्लेषण के लिए यह संश्लेषण प्रक्रिया अत्यंत उपयोगी और कम लागत वाली पाई गई है।

- **कोयले के विगंधकीकरण के लिए अल्ट्रासोनिक धुलाई**

इस परियोजना को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी (आईआईटीजी), गुवाहाटी, अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन (एआईएचएसएचईडब्ल्यू), कोयंबटूर, तमिलनाडु, कुवेम्पु विश्वविद्यालय, ज्ञानसहाद्री, शंकरगढ़ा, तुमकुर विश्वविद्यालय, वेंकटेश राव कॉलोनी, तुमकुरु और एनईसी, मार्गेरिता द्वारा क्रियान्वित किया गया था।

इस परियोजना के अंतर्गत, पूर्वोत्तर कोयले का अल्ट्रासाउंड विलायक धुलाई आधारित विगंधीकरण प्रायोगिक और अनुकरण अध्ययनों द्वारा किया गया है। कोयले से 65% सल्फर हटाने के लिए बैच रिएक्टर का उपयोग करके प्रक्रिया मापदंडों (अल्ट्रासाउंड आवृत्ति, कण आकार, विलायक, निवास समय) को अनुकूलित किया गया। 55% सल्फर हटाने के लिए जलकुंभी बायोमास से एक कम लागत वाला विलायक निकाला गया। इसके अलावा, अल्ट्रासाउंडीकरण रिएक्टर से प्राप्त सल्फर युक्त अपशिष्ट विलायक को उपयुक्त अधिशोषकों (सक्रिय कार्बन, ग्राफीन ऑक्साइड) से उपचारित किया गया और सल्फर अधिशोषित सक्रिय कार्बन का सुपर कैपेसिटर अनुप्रयोगों के लिए परीक्षण किया गया। अंत में, प्रक्रियाओं की आर्थिक व्यवहार्यता की जाँच के लिए एक तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया गया।

- **समयपूर्व विफलताओं की रोकथाम और बकेट व्हील उत्खनन में प्रयुक्त बॉटम रोलर्स के जीवन को बढ़ाना।**

यह परियोजना अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र, एनएलसीआईएल, नेवेली, एनआईटी, त्रिची और आईआईएससी, बेंगलुरु द्वारा क्रियान्वित की गई।

इस परियोजना के अंतर्गत, उन्नत सामग्री विकास और सतह इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं, विशेष रूप से नाइट्रोकार्बराइजिंग, के संयोजन ने बकेट व्हील एक्स्केवेटर में बॉटम रोलर्स के परिचालन जीवनकाल को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की क्षमता प्रदर्शित की है। नए मिश्रधातुओं के विकास, नाइट्राइडिंग और नाइट्रोकार्बराइजिंग उपचारों के साथ, कठोर परिचालन स्थितियों में घिसाव और संक्षारण प्रतिरोध, सतह की कठोरता और समग्र प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नाइट्रोकार्बराइजिंग, बॉटम रोलर्स के स्थायित्व और दक्षता को बढ़ाने के लिए सबसे संतुलित समाधान के रूप में उभर कर सामने आता है, जिससे यह उच्च-मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए पसंदीदा उपचार बन गया है।

• भारत में कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने की इष्टतम रणनीति पर अध्ययन

यह परियोजना स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (एसआईएस), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली द्वारा क्रियान्वित की गई थी।

इस परियोजना के अंतर्गत, सभी पाँच मांग क्षेत्रों, अर्थात् कृषि, वाणिज्यिक, उद्योग, आवासीय और परिवहन, के लिए टाइम्स-वेड में ऊर्जा आपूर्ति और परिवर्तन (विद्युत, रिफाइनरी आदि) का मॉडलिंग और विश्लेषण किया गया है। इसके बाद, कोयला खनन क्षेत्रों में आजीविका, जोखिम और लचीलेपन के आकलन हेतु सर्वेक्षण के साथ-साथ प्रत्येक क्षेत्र के लिए वैकल्पिक परिदृश्य विकसित किए गए हैं। निष्कर्षों के आधार पर, कोयले से दूर जाने के सापेक्ष जोखिमों और लाभों का आकलन किया गया है ताकि कोयले को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए एक व्यावहारिक और व्यवहार्य नीति विकल्प तैयार किया जा सके, साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोयला क्षेत्र के सभी प्रभावित हितधारकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

• सीओ₂ अवशोषण के लिए छिद्रयुक्त अधिशोषक विकसित करने हेतु कोयला गैस का उपयोग

यह परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर और बीसीसीएल, धनबाद द्वारा क्रियान्वित की गई।

इस परियोजना के अंतर्गत, अध्ययन के लिए कोयले के अपशिष्ट से कम लागत वाले जिओलाइट-आधारित अधिशोषक को संश्लेषित किया गया है। थर्मोग्राविमेट्रिक विश्लेषण (टीजीए) और पैकड-बेड रिएक्टर, दोनों का उपयोग करके सीओ₂ और एन₂ युक्त सिम्पुलेटेड गैस के माध्यम से सीओ₂ अवशोषण दक्षता का परीक्षण किया गया। शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि तापमान का सीओ₂ अवशोषण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि गैस के इनलेट में सीओ₂ की उच्च सांद्रता सीओ₂ अवशोषण को सुगम बनाती है।

• कोयले का बायोमेथेनाइजेशन

विज्ञान संस्थान, बीएचयू, वाराणसी द्वारा क्रियान्वित की गई।

इस परियोजना के अंतर्गत, कोयले के बायोमीथेनाइजेशन के लिए उत्तरदायी सबसे उपयुक्त सूक्ष्मजीवों का पता लगाने हेतु विभिन्न प्रकार/ग्रेड/श्रेणी के कोयले के नमूनों का बायोमीथेनाइजेशन किया गया है। शोध में पाया गया है कि मीथेन उत्पादन का कोयले के ग्रेड, प्रकार या कोयले की श्रेणी से कोई सीधा संबंध नहीं है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि जीवाणु संवर्धन सभी प्रकार के कोयले के साथ अभिक्रिया करता है, चाहे उसकी श्रेणी (निम्न या मध्यम श्रेणी), श्रेणी (राख उत्पादन में निम्न या उच्च), या कोई भी मैकेरल समूह (कोयला प्रकार) हावी हो।

• कोयला-तल मीथेन की उन्नत प्राप्ति और कार्बन पृथक्करण की संभावनाओं के लिए कोयला भंडार का भण्डार लक्षण-वर्णन और संख्यात्मक मॉडलिंग

यह परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे और सीएमपीडीआई, रांची द्वारा क्रियान्वित की गई।

इस परियोजना के अंतर्गत, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की चार कोयला खदानों में स्थित कोयला परतों में सीओ₂ भंडारण क्षमता को समझने के लिए एक व्यापक प्रयोगात्मक और संख्यात्मक विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के आधार पर, 10 वर्षों के अंतःक्षेपण के बाद इन क्षेत्रों में से प्रत्येक में सीओ₂ भंडारण क्षमता को समझने के

लिए एक प्रारंभिक सिमुलेशन तैयार किया गया। परियोजना के निष्कर्ष नमूनों की खनिज संरचना, कार्बनिक पदार्थ, संरचनात्मक गुणों, छिद्र संरचना विशेषताओं और गैस अवशोषण क्षमता के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं, जो गैस अवशोषण, गैस प्रवाह गतिकी, गैस भंडारण, उत्पादन, और ईसीबीएम पुनर्प्राप्ति की दक्षता और प्रभावशीलता को सीधे प्रभावित करते हैं और सीओ₂ अंतःक्षेपण के लिए संभावित ब्लॉकों की पहचान करते हैं।

• **कोयला उद्योग के लिए सीएमपीडीआई में 5जी उपयोग केस परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना**

इस परियोजना का क्रियान्वयन टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल), नई दिल्ली, सीएमपीडीआई, रांची और आईआईआईटी, रांची द्वारा किया गया।

इस परियोजना के अंतर्गत, कोयला उद्योग के लिए सीएमपीडीआई में एक 5जी उपयोग मामला परीक्षण प्रयोगशाला विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में कार्यान्वयन से पहले प्रयोगशाला स्तर पर 5जी नेटवर्क पर उपयोग मामलों और अनुप्रयोगों का परीक्षण करना है। सीएमपीडीआई के अधिकारियों को उपयोग मामला प्रयोगशाला में 5G नेटवर्क पर उपयोग मामलों और अनुप्रयोगों के विकास, परीक्षण और सत्यापन के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया है।

• **भूमिगत कोयला खदानों में प्रयुक्त पिट बॉटम बफर के लिए ड्रॉप टेस्ट सुविधा का डिजाइन और विकास।**

यह परियोजना आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और ईसीएल, सैंक्टोरिया द्वारा क्रियान्वित की गई।

इस परियोजना के अंतर्गत अत्याधुनिक ड्रॉप परीक्षण सुविधा विकसित की गई है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- मजबूत नींव: 3 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले 10 टन के भार के बार-बार होने वाले प्रभाव को सहन करने के लिए उच्च आघात प्रतिरोध।
- गाइड रेल प्रणाली: एक मजबूत गाइड रेल प्रणाली को डिजाइन, विश्लेषण और विकसित किया गया, ताकि 3 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले 10 टन के भार की गति को नियंत्रित किया जा सके, तथा बार-बार परीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण गति, कंपन और झटके को सहन किया जा सके।
- डेडवेट स्लैब: 1-टन (1.25 मी.*1.15 मी.*0.088 मी.) और 1.5-टन (1.25 मी.*1.15 मी.*0.135 मी.) स्लैब को 0.5-टन अंतराल में 1 से 10 टन तक के भार के लिए गड्ढे के तल बफर्स का परीक्षण करने के लिए स्टैकिंग तंत्र के साथ डिजाइन और निर्मित किया गया था।
- लेज़र-आधारित पंचिंग प्रणाली: एक सटीक लेज़र मार्किंग मशीन का उपयोग परीक्षण किए गए बफर्स पर विशेष कोड उकेरने के लिए किया जाता है, जिससे प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है और दोहराव से बचा जा सकता है। यह मशीन 20 µm तक की टेक्स्ट मोटाई बनाए रखती है और इसमें बारकोड प्रिंटिंग की सुविधा भी शामिल है।
- सुरक्षा तंत्र: उन्नत सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि परीक्षण के दौरान किसी को भी बैरिकेड क्षेत्र के अंदर जाने की अनुमति न हो। परीक्षण कक्ष को IS: 9457-1980 के अनुसार सुरक्षा रंग कोडों से चिह्नित किया गया है।
- जिग और फिक्सचर: गड्ढे के तल बफर को स्थिर रखने और 10 टन के गिरते हुए डेडवेट के प्रभाव को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है।
- डेटा अधिग्रहण प्रणाली: शोर भरे वातावरण में 40ms के लिए 2.5g मापते समय शोर और गलत डेटा को फ़िल्टर करने के लिए एक पोर्टेबल, सटीक और मजबूत प्रणाली।
- बौद्धिक संपदा अधिकार: एक डिजाइन पंजीकरण/कॉपीराइट।

• **भूमिगत कोयला खदानों में विद्युत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में वेंटिलेशन फैन पवन ऊर्जा पुनर्प्राप्ति प्रणाली का डिजाइन और परिणियोजन।**

यह परियोजना आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और ईसीएल, सैंक्टोरिया द्वारा क्रियान्वित की गई।

यह शोध परियोजना अपरंपरागत पवन ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य सीओ₂ उत्सर्जन को कम करना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है, जो किसी भी भारतीय खदान में अपनी तरह का पहला प्रयास है। यह अध्ययन खदान के वेंटिलेशन पंखों से निकलने वाली हवा को एकत्रित करके, हाइब्रिड डेरियस-सेवोनियस वीएडब्ल्यूटी प्रणाली का उपयोग करके, स्थायी ऊर्जा उत्पादन की व्यवहार्यता का पता लगाता है। सिमुलेशन और प्रायोगिक दोनों अध्ययनों से न केवल निकास अपशिष्ट हवा से विद्युत शक्ति का उत्पादन, बल्कि जुड़े हुए विद्युत पंखा ड्राइव के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं में कमी भी सामने आई है।

• मॉडलिंग और सिमुलेशन विश्लेषण के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड के तहत कोकिंग कोल वाशरी के प्रदर्शन में सुधार पर अध्ययन।

यह परियोजना एनएमएल जमशेदपुर और सीएमपीडीआई रांची द्वारा क्रियान्वित की गई।

इस परियोजना के अंतर्गत, इसकी दक्षता में सुधार लाने, विशेष रूप से 17% स्वच्छ कोयला राख पर उत्पादन को अधिकतम करने के उद्देश्य से मॉडलिंग और सिमुलेशन अध्ययन किए गए। इसका उद्देश्य विभिन्न इनपुट परिदृश्यों का आकलन करने के लिए वास्तविक संयंत्र आँकड़ों का उपयोग करके एक स्थिर-अवस्था मॉडल विकसित करना था। आँकड़ों के संग्रह के लिए एक नमूनाकरण अभियान चलाया गया, जिसके बाद वर्तमान परिपथ के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए द्रव्यमान संतुलन (मास बैलेंसिंग) किया गया। द्रव्यमान संतुलन पर अवलोकन, सिमुलेशन अध्ययनों के परिणाम और सुझाव नीचे सूचीबद्ध हैं।

- कोल्ह उत्पाद में -1 मिमी अंश को डीवाटरिंग स्क्रीन का उपयोग करके सीधे उत्पाद के रूप में लिया जा सकता है।
- 28-32% राख वाले कोयले के लिए, स्वच्छ कोयले में 17% राख प्राप्त करने के लिए 1.58-1.62 की सीमा में एक परिचालन कट घनत्व आवश्यक है। तदनुसार, मीडिया घनत्व लगभग 1.45 तैयार किया जा सकता है। इससे मीडिया की खपत भी कम होगी। इस उच्च राख-सामग्री वाले कोयले के लिए अनुमानित उपज 50% है।
- 26-28% राख की मात्रा वाले कोयले के लिए, स्वच्छ कोयले में 17% राख प्राप्त करने के लिए 1.68-1.72 की सीमा में एक परिचालन कट घनत्व आवश्यक है। तदनुसार, लगभग 1.5 का माध्यम घनत्व तैयार किया जा सकता है। इस कम राख की मात्रा वाले कोयले के लिए अनुमानित उपज 69.65% है।
- स्क्रीन के बड़े आकार में -0.5 मिमी अंश के गलत स्थानन को कम करने के लिए डीस्लिमिंग स्क्रीन को 40% ठोस से नीचे संचालित किया जाना चाहिए।

• कार्बन मूल्यों की वसूली के लिए कोकिंग कोल वाशरी के मिडिलिंग्स और फाइनस का प्रभावी उपयोग।

इस परियोजना का क्रियान्वयन एनएमएल जमशेदपुर, सीएमपीडीआई रांची और बीसीसीएल धनबाद द्वारा किया गया।

इस परियोजना के अंतर्गत, 5 एमटीपीए पाथेरीडीह वाशरी और 1.6 एमटीपीए धाहिबारी वाशरी से दो मिडिलिंग नमूने परियोजना कार्य हेतु एकत्र किए गए। मिडिलिंग नमूनों के विस्तृत लक्षण-चित्रण, धुलाई क्षमता और गुरुत्व एवं प्लवन तकनीकों का उपयोग करके आर्द्र लाभकारीकरण का उपयोग मिडिलिंग नमूनों से कार्बन मानों की पुनर्प्राप्ति हेतु एक प्रक्रिया प्रवाह पत्रक के विकास हेतु किया गया।

5एमटीपीए पाथेरीडीह वाशरी से मिडिलिंग नमूने के निकटतम विश्लेषण से पता चलता है कि राख की मात्रा 42.8% है, जिसमें 14.9% वाष्पशील पदार्थ, 0.93% नमी और 41.37% स्थिर कार्बन है। मिडिलिंग नमूने की कोयला पेट्रोग्राफी से, यह पाया गया है कि इसमें मुख्य रूप से विट्रीनाइट मैकेरल और इनरटिनाइट मैकेरल का अनुपात है जो तुलनात्मक रूप से विट्रीनाइट्स से कम है। अधिकांश प्रकार के कोयले में इनरटिनाइट एक सामान्य मैकेरल है। मुख्य इनरटिनाइट सबमैकेरल फ्यूसिनाइट, सेमीफ्यूसिनाइट, माइक्रोनाइट, मैक्रिनाइट और फंगीनाइट हैं। इनरटिनाइट

मेकेरल का सबसे सामान्य प्रकार सेमीफ्यूसिनाइट है। सेमीफ्यूसिनाइट के प्रकाशिक गुण विट्रीनाइट के समान ही हैं। पाथरडीह वाशरी के प्राप्त मध्यम आकार के नमूनों के -6 मिमी, -3 मिमी और -1 मिमी तक कुचले जाने के लिए धुलाई योग्यता अध्ययन किए गए। अध्ययनों से यह देखा गया कि 18.5% राख स्तर पर उत्पाद की उपज, 6 मिमी और -3 मिमी कुचले गए नमूनों के शीर्ष आकार की तुलना में -1 मिमी के मामले में अधिक थी। इसलिए, लाभकारी अध्ययनों के लिए फ्रीड सामग्री के -1 मिमी शीर्ष आकार का उपयोग किया गया।

- **खनिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए घुटने और रीढ़ की हड्डी के स्मार्ट सुरक्षात्मक उपकरणों का डिजाइन और विकास।**

यह परियोजना आईआईटी-आईएसएम धनबाद और बीसीसीएल धनबाद द्वारा क्रियान्वित की गई।

इस परियोजना के अंतर्गत, भूमिगत खदानों और खुली खदानों में काम करने के दौरान मानव रीढ़ की हड्डी के घुटने के जोड़ वाले हिस्से और कशेरुकाओं को सहारा देने के लिए स्मार्ट सुरक्षात्मक उपकरण बनाए गए हैं। यह घुटने और रीढ़ की हड्डी का स्मार्ट सुरक्षात्मक उपकरण ग्लास फाइबर सामग्री से बना है, जो रीढ़ की हड्डी के हिस्से में घुटने की चोटों और पीठ दर्द, इंटरवर्टेब्रल डिस्क की समस्याओं, हर्नियेटेड डिस्क की समस्याओं (स्लिप्ड डिस्क या डिस्क का फटना) पर उच्च स्तर का नियंत्रण देने के लिए बहुत उपयोगी है, और यह समस्या आमतौर पर रीढ़ की हड्डी के किसी भी हिस्से में हो सकती है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक पटेला कैप, फीमर, टिबिया हड्डी, घुटने के संयुक्त लिगामेंट और पीठ के निचले हिस्से (काठ का वक्रता या काठ कशेरुका, L1-L5) हैं, और यह तब होता है जब न्यूक्लियस एनलस के हिस्से में फट जाता है। इस स्थिति में मानव शरीर को हाथ, पैर या साइटिका में दर्द, रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी की नली में दर्द का सामना करना पड़ता है। घुटने और रीढ़ की हड्डी के स्मार्ट सुरक्षात्मक उपकरणों का स्थायित्व बाजार में उपलब्ध मौजूदा उत्पादों की तुलना में बहुत अधिक है और यह भूमिगत खदानों और खुली खदानों के क्षेत्र में भारी वजन उठाने के कारण होने वाली साइटिका की समस्याओं को भी रोकता है।

घुटने और रीढ़ की हड्डी के लिए एक स्मार्ट सुरक्षात्मक उपकरण बनाने के लिए, ग्लास फाइबर सामग्री का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के गुण होते हैं। हमें घुटने और रीढ़ की हड्डी के समर्थन के लिए एक मिश्रित नमूना या उपकरण बनाने की आवश्यकता होती है, और उत्पाद की कीमत अन्य सामग्रियों की तुलना में किफायती होती है। यह आविष्कार के प्रयास में एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, घटक के उत्पादन के लिए न्यूनतम संसाधनों का उपयोग और अन्य फाइबर सामग्रियों की तुलना में न्यूनतम समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना।

- **आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क [एएनएन], प्रोबेबिलिस्टिक न्यूरल नेटवर्क [पीएनएन] और क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेसन ट्री [सीएआरटी] मॉडल के माध्यम से कणिकीय पदार्थ और गैसीय प्रदूषकों की सांद्रता की भविष्यवाणी और सिंगरौली कोयला खदानों में सीएएलपीयूएफ और आईआरएमओडी के साथ तुलना।**

यह परियोजना बीआईटी मेसरा और सीएमपीडीआई रांची द्वारा क्रियान्वित की गई थी

इस परियोजना के अंतर्गत, फैलाव मॉडलों में, एयरमोड पसंदीदा मॉडल के रूप में उभरा है, जो कालपफ की तुलना में कम मॉडल पूर्वाग्रह और त्रुटि तथा उच्च पूर्वानुमान सटीकता प्रदर्शित करता है। हालाँकि, एयरमोड में अति-आकलन की प्रवृत्ति होती है, जबकि कालपफ उत्सर्जन को कम करके आंकता है। दोनों मॉडलों के बीच फैलाव पैटर्न अलग-अलग हैं, एयरमोड प्रदूषकों को स्रोत खदानों से दूर तक फैलाता है, जबकि कालपफ उन्हें अपेक्षाकृत कम दूरी तक सीमित रखता है।

- एयरमोड की सटीकता अलग-अलग खदानों के लिए 21% से 89% और साल भर के अलग-अलग मौसमों में 25% से 86% तक होती है। वहीं, कालपफ की सटीकता अलग-अलग खदानों के लिए 30% से 93% और अलग-अलग मौसमों में 29% से 86% तक होती है। पूरे खनन परिसर के लिए एयरमोड की सटीकता 36% से 64% तक होती है, जबकि कालपफ की सटीकता 34% से 64% तक होती है।
- मशीन लर्निंग मॉडलों में, संपूर्ण खदान परिसर के वार्षिक डेटा का उपयोग करके तैयार किया गया कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क (एएनएन) मॉडल सबसे अच्छी भविष्यवाणी सटीकता प्रदान करता है, जिसमें उत्सर्जन दर को इनपुट चर के रूप में मानते हुए आर मान 0.89 से 1.00 तक होता है।
- उत्सर्जन दरों पर विचार किए बिना 0.76 से 0.89 तक।
- संभाव्य तंत्रिका नेटवर्क (पीएनएन) प्रदूषकों के वर्गीकरण में उत्कृष्ट है और उच्च वर्गीकरण सटीकता (89.80% से 99.97%) प्राप्त करता है। हालाँकि, यह प्रदूषकों की पूर्ण सांद्रता का अनुमान लगाने में विफल रहता है।
- एएनएन मॉडल इनपुट चरों की एक विस्तृत श्रृंखला को संसाधित करता है और चरों के बीच जटिल अरैखिक संबंधों को पकड़ता है, जो इसे पर्यावरण निगरानी और प्रबंधन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाता है। अध्ययन औद्योगिक क्षेत्रों में एकीकृत वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के एक भाग के रूप में एएनएन मॉडल के कार्यान्वयन की अनुशंसा करता है। आगे के शोध में पूर्वानुमान सटीकता बढ़ाने के लिए मॉडल में वास्तविक समय डेटा फ्रीड को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

• जैव-स्कंदक का उपयोग करके कोयला वाशरी अपशिष्टों से सूक्ष्म कणों का पृथक्करण और पुनर्प्राप्ति।

यह परियोजना आईआईटी-आईएसएम धनबाद द्वारा क्रियान्वित की गई।

परियोजना कार्य ने कोयला चूर्ण की गन्दगी को दूर करने और कोयला चूर्ण की वसूली के लिए जैव-स्कंदनकों के रूप में ब्रैसिका निग्रा, मोरिंगा ओलीफेरा और लिनम यूसिताटिसिमम के कच्चे अर्क के उपयोग की क्षमता की पुष्टि की है।

- कोयला वाशरी अपशिष्ट और जुमानों के लक्षण वर्णन परिणामों से संकेत मिला कि अपशिष्ट को बायोकोएगुलेंट्स का उपयोग करके सफलतापूर्वक उपचारित किया जा सकता है।
- एक प्राकृतिक परिरक्षक, एजाडिरेक्टा इंडिका पत्तियों का अर्क (एआईएलई), जैव-स्कंदक के शैत्य जीवन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि सकारात्मक परिणामों से संकेत मिलता है कि एआईएलई जैव-स्कंदक में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकता है, जिससे समय के साथ उनकी मैलापन हटाने की क्षमता को बनाए रखने में मदद मिलती है।
- उत्पादित कोयला कीचड़ के निक्षालन विश्लेषण से पता चला कि यह प्रकृति में गैर-खतरनाक है तथा पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित संचालन और प्रबंधन के लिए उपयुक्त है।
- प्रोटोटाइप के परिणामों ने विकसित जैव-स्कंदनकों की क्षेत्र प्रयोज्यता की पुष्टि की।
- लागत की दृष्टि से, एल्यूमीनीय और बीएनसीबी अधिक किफायती पाए गए, तथा इन जैव-स्कंदकों ने आशाजनक मैलापन और टीएसएस निष्कासन दक्षता भी प्रदान की।
- प्रेस्ड केक की उपलब्धता को देखते हुए, ब्रैसिका नाइग्रा (सरसों) के बीज से बना प्रेस्ड केक, लिनम यूसिताटिसिमम (अलसी) के बीज से बने प्रेस्ड केक की तुलना में किसी भी समय बड़ी मात्रा में आसानी से उपलब्ध होता है। इसलिए, क्षेत्रीय परिस्थितियों में कोयला वाशरी के उपचार के लिए, ब्रैसिका नाइग्रा कूड-आधारित जैव-स्कंदक (बीएनसीबी) अधिक उपयुक्त होगा।

- इस अध्ययन में पाया गया कि सभी तैयार बीएनसीबी, एमओसीबी, एलयूसीबी और सीएलयू25एमओ75 कोयला वाशरी अपशिष्टों के उपचार के लिए प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक स्कंदक थे।

- **कोयला खदानों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए वर्चुअल रियलिटी माइन सिम्युलेटर (वीआरएमएस) का विकास।**

यह परियोजना आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची द्वारा क्रियान्वित की गई।

इस परियोजना के अंतर्गत, खनन क्षेत्र के पेशेवरों के प्रदर्शन और प्रशिक्षण हेतु आईआईटी (आईएसएम) धनबाद द्वारा एक स्वदेशी विश्वस्तरीय वर्चुअल रियलिटी सुविधा विकसित की गई है। वर्चुअल रियलिटी वातावरण में सर्वोत्तम खनन पद्धतियों को प्रदर्शित करने के लिए एनसीएल की निगाही ओपनकास्ट परियोजना और ईसीएल की झांझरा भूमिगत परियोजना को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। सर्वोत्तम सुरक्षा पद्धतियों को प्रदर्शित करने के लिए धनसार स्थित माइंस रेस्क्यू स्टेशन को भी शामिल किया गया है। विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से परियोजना की अवधि कई बार बढ़ाई गई, हालाँकि, यह सभी निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करते हुए पूरी हुई है।

सीआईएल अनुसंधान एवं विकास बोर्ड से प्राप्त वित्तीय सहायता से, आईआईटी (आईएसएम) ने मेसर्स लॉन्चट्रेक्स के सहयोग से संचालन और सुरक्षा प्रशिक्षण के तीन अलग-अलग तरीके विकसित किए हैं: 360° बेलनाकार स्क्रीन, हेड माउंटेड डिस्प्ले (एचएमडी) और कियोस्क फुल एचडी टचस्क्रीन। 27-04-2024 को सीआईएल की टीम द्वारा एक समीक्षा भी की गई, जिसमें परियोजना प्रस्ताव के उद्देश्यों में उल्लिखित संचालन और सुरक्षा पहलुओं को शामिल करते हुए ओपनकास्ट और भूमिगत खनन मॉड्यूल प्रदर्शित किए गए। ओपनकास्ट और भूमिगत खदानों के लिए क्रमशः संचालन सिमुलेशन, एसओपी कार्यान्वयन, परिदृश्य निर्माण, उपयोगकर्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण के बाद सीखने के परीक्षण हेतु प्रश्नोत्तरी जैसे विभिन्न संचालन मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

- **हाईवॉल खनन व्यवहार्यता मूल्यांकन और लेआउट डिजाइन।**

यह परियोजना भूमिगत खनन प्रभाग (यूएमडी), सीएमपीडीआई द्वारा क्रियान्वित की गई।

इस परियोजना के अंतर्गत, सीएसआईआरओ के स्पान स्थिरता मूल्यांकन मॉडल और संख्यात्मक मॉडलों का उपयोग करके 22 स्थलों के लिए हाईवॉल प्रवेश छत स्थिरता का आकलन किया गया। यह पाया गया है कि जब तक पैनल प्रविष्टियाँ मानक 3.55 मीटर एचडब्ल्यूएम प्रवेश स्पान के साथ बनी रहती हैं, तब तक स्पान में छत की सभी परतें स्थिर रहती हैं। संख्यात्मक सिमुलेशन से, यह देखा गया है कि ऊपरी और निचले बलकुदरा सीमों के संरेखित स्तंभ, बलकुदरा सीमों के असंरेखित स्तंभों की तुलना में, छत में एक समान प्रतिबल वितरण और सममित विस्थापन पैटर्न प्रदान करते हैं। दोनों ही मामलों में, 3.55 मीटर छत स्पान स्थिर है।

सुविचारित डिजाइन के साथ, सेक्शन एए'-बीबी' के लिए सयाल और दो बलकुदरा सीमों के लिए क्रमशः 58% और 42% रिकवरी प्राप्त होने की उम्मीद है। इसी प्रकार, सेक्शन डीडी' से सयाल और दो बलकुदरा सीमों के लिए क्रमशः 58% और 38% रिकवरी अनुपात अपेक्षित है।

- **भू-तकनीकी पहलुओं से संबंधित फोरेंसिक जांच, ताकि विस्तृत प्रकृति की आधार मिट्टी को स्थिर किया जा सके और इष्टतम ओवरबर्डन डंप ऊंचाई को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए उपयुक्त भूमि सुधार प्रौद्योगिकी को लागू किया जा सके।**

यह परियोजना सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग, सीएमपीडीआई (मुख्यालय) रांची और आरआई-IV, सीएमपीडीआई, नागपुर; वीएनआईटी, नागपुर और डब्ल्यूसीएल, नागपुर द्वारा क्रियान्वित की गई थी।

अध्ययन का निष्कर्ष है कि अवधारण संरचना पार्श्व विस्थापन को रोककर, शुष्क और आर्द्र दोनों स्थितियों में सुरक्षा कारक में सुधार करके, विस्फोट के प्रभावों को कम करके और विफलता की संभावना को कम करके ओबी डंप को प्रभावी ढंग से स्थिर करती है, जिससे डंप की ऊँचाई 54 मीटर से 90 मीटर तक सुरक्षित रूप से बढ़ाना संभव हो पाता है। इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष, दिशानिर्देशों के रूप में, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं, ब्राउनफील्ड परियोजनाओं और सामान्य संदर्भ के लिए रिपोर्ट में उल्लिखित किए गए थे। नए ओवरबर्डन (ओबी) निपटान शुरू करने से पहले डंपिंग ग्राउंड की गहन भू-तकनीकी जाँच आवश्यक है। यदि अंतर्निहित परतें इच्छित भार को सहन करने के लिए अपर्याप्त पाई जाती हैं, तो स्थल स्थानांतरण पर विचार किया जाना चाहिए। जिन मामलों में स्थानांतरण संभव नहीं है, वहाँ डंप सीमा के साथ और स्थानिक परिवर्तनशीलता वाले क्षेत्रों में डंप के नीचे रॉक-फिल खाइयों जैसे उपचारात्मक उपाय लागू किए जाने चाहिए। यदि ऐसे उपाय आर्थिक रूप से अव्यवहारिक साबित होते हैं, तो डंपिंग केवल वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा निर्धारित अनुकूलित ऊँचाई तक ही की जानी चाहिए। स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को स्थल-विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। ऐसे परिदृश्यों में जहाँ कमज़ोर मिट्टी पर डंपिंग अपरिहार्य है, विकसित पद्धति और स्थिरीकरण मॉडल का उपयोग डंप की स्थिरता बढ़ाने और उसकी ऊँचाई सुरक्षित रूप से बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। संक्षेप में, इस परियोजना ने विफल ओबी डंप को स्थिर करने के लिए अवधारण संरचना की उपयोगिता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। निर्माण टिकाऊ खनन सामग्री का उपयोग करके किया गया था, जिससे निर्माण लागत में उल्लेखनीय कमी आई है।

परिशिष्ट - II

प्रति,

निदेशक मंडल

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

हम, मनोज कुमार, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और सुदीप दासगुप्ता, सीएफओ, जो वित्त कार्य के लिए जिम्मेदार हैं, प्रमाणित करते हैं कि:

- क.** 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार:
- इन वक्तव्यों में कोई भी असत्य कथन नहीं है या कोई भी तथ्य छूटा नहीं है या ऐसे वक्तव्य नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
 - ये विवरण मिलकर कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमन के अनुरूप हैं।
 - हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेन-देन धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला नहीं है।
- ख.** हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हो, के बारे में बताया है, जिनके बारे में उन्हें जानकारी है और उन्होंने इन कमियों को दूर करने के लिए जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव दिया है, उनके बारे में बताया है।
- ग.** हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को सूचित कर दिया है,
- 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।
 - 31 मार्च 2025 समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए त्रुटियों को सुधारने और स्पष्टता बढ़ाने के लिए सामग्री लेखांकन नीतियों को अद्यतन किया गया है। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान इन अद्यतनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा।
 - हमें किसी भी ऐसे बड़े धोखाधड़ी के मामले की जानकारी नहीं है जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता हो, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका हो।



(सुदीप दासगुप्ता)
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ



(मनोज कुमार)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

परिशिष्ट - III

Mehta & Mehta COMPANY SECRETARIES

Ground Floor, 36 (179), Sukanta Sarani, Bhadrakali, Hoogly - 712232, West Bengal
Tel.: +91 9867771580, E-mail : raveena@mehta-mehta.com, Visit us : www.mehta-mehta.com
AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

कॉर्पोरेट प्रशासन अनुपालन प्रमाणपत्र

कंपनी का सीआईएन : U14292JH1975GOI001223
नाममात्र पूंजी : रु. 150,00,00,000 (एक सौ पचास करोड़ रुपये मात्र)
चुक्ता पूंजी : रु. 142,80,00,000 (रुपये एक सौ बयालीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)

प्रति,
सदस्य,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
गोंडवाना प्लेस, कांके रोड
रांची - 834008

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड ("कंपनी") के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अनुपालन शर्तों की जांच की है, जैसा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देश 2010 में निर्धारित है।

हमारे परीक्षण का सारांश इस प्रकार है :-

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन (सर्वोत्तम प्रथाओं के मॉड्यूल) और सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश 2010 के तहत संदर्भित कॉर्पोरेट प्रशासन दिशा-निर्देशों के अनुसार है और कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी।

यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है। हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, प्रमाणीकरण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे और हमें ऐसे रिकॉर्ड, दस्तावेज, प्रमाण पत्र आदि प्रदान किए गए हैं जिनकी हमें आवश्यकता थी।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और निदेशकों और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी विभिन्न मॉड्यूल और मानकों के अनुरूप, अच्छे प्रशासन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों और जारी मानकों के अनुपालन की समीक्षा के लिए कदम उठाए हैं।

1. निदेशक मंडल

कंपनी का व्यवसाय निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधित किया जाता है। समय-समय पर अध्यक्ष कंपनी के निदेशकों की संख्या निर्धारित करता है। निदेशकों को कोई योग्यता शेयर रखने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक और गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और नियुक्ति आदेश की शर्तों के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा

Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES

Ground Floor, 36 (179), Sukanta Sarani, Bhadrakali, Hoogly - 712232, West Bengal
Tel.: +91 9867771580, E-mail : raveena@mehta-mehta.com, Visit us : www.mehta-mehta.com
AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

निर्धारित वेतन, भत्ते, बैठने की फीस आदि का भुगतान किया जाता है।

(क) बोर्ड का आकार:

कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद के अनुसार, हमारे बोर्ड में निदेशकों की संख्या 2 से कम और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक/कार्यकारी निदेशक, आधिकारिक अंशकालिक निदेशक या गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक हो सकते हैं।

(ख) निदेशक मंडल की श्रेणीवार संरचना:

31 मार्च, 2025 तक, सीएमपीडीआईएल के निदेशक मंडल में 5 (पाँच) निदेशक हैं, जिनमें से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित तीन पूर्णकालिक निदेशक और दो अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं। बोर्ड के अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष श्री मनोज कुमार हैं।

पूर्व में नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों के पदभार ग्रहण करने के बाद, महिला निदेशक सहित अन्य स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई है। अतः, बोर्ड की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन केवल महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर ही किया जा सकता है।

31 मार्च, 2025 तक निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है:

क्रमांक	निदेशक का नाम	कंपनी में पदनाम
1	श्री मनोज कुमार	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2	श्री शंकर नागाचारी	कार्यकारी निदेशक
3	श्री अजय कुमार	कार्यकारी निदेशक
4	श्री मुकेश अग्रवाल	अंशकालिक सरकारी निदेशक
5.	श्री मारापल्ली वेंकटेश्वरलु	अंशकालिक सरकारी निदेशक



(ग) आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या और तिथियां

निदेशक मंडल कंपनी का सर्वोच्च निकाय है जो कंपनी के समग्र कार्यों की देखरेख करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 11 (ग्यारह) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं।

क्र. सं.	बैठकों की संख्या	तिथि	दिन	बैठक का स्थान
1.	277 वीं	25.04.2024	गुरुवार	रांची
2.	278 वीं	24.05.2024	शुक्रवार	रांची

Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES

Ground Floor, 36 (179), Sukanta Sarani, Bhadrakali, Hoogly - 712232, West Bengal
Tel.: +91 9867771580, E-mail : raveena@mehta-mehta.com, Visit us : www.mehta-mehta.com
AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

क्र. सं.	बैठकों की संख्या	तिथि	दिन	बैठक का स्थान
3.	279 वीं	25.06.2024	मंगलवार	रांची
4.	280 वीं	22.07.2024	सोमवार	रांची
5.	281 वीं	23.08.2024	शुक्रवार	रांची
6.	282 वीं	13.09.2024	शुक्रवार	रांची
7.	283 वीं	01.10.2024	मंगलवार	रांची
8.	284 वीं	20.10.2024	रविवार	रांची
9.	285 वीं	19.01.2025 और 0.01.2025	रविवार और सोमवार	मैसूरु , कर्नाटक
10.	286 वीं	24.02.2025	सोमवार	रांची
11.	287 वीं	25.03.2025	मंगलवार	रांची

2. क. लेखा परीक्षा समिति:

लेखापरीक्षा समिति का प्राथमिक कार्य वित्तीय रिपोर्ट, वित्त, लेखांकन और कंपनी की लेखापरीक्षा, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा करके निदेशक मंडल को अपनी निगरानी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करना है।

लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा करती है, सांविधिक लेखापरीक्षकों से मिलती है और उनके निष्कर्षों, सुझावों और अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा करती है तथा कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रमुख लेखांकन नीतियों की समीक्षा करती है।

ख. संदर्भ की शर्तें:

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ-साथ संगठन के सभी वाणिज्यिक पहलुओं को कवर करेंगे :

- बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरण की समीक्षा।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवधिक समीक्षा।
- सरकारी लेखापरीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा।
- मानक मापदंडों की तुलना में परिचालन प्रदर्शन की समीक्षा।
- परियोजनाओं एवं अन्य पूंजीगत योजना की समीक्षा।



Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES

Ground Floor, 36 (179), Sukanta Sarani, Bhadrakali, Hoogly - 712232, West Bengal
Tel.: +91 9867771580, E-mail : raveena@mehta-mehta.com, Visit us : www.mehta-mehta.com
AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

- vi. आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों/टिप्पणियों की समीक्षा।
- vii. एक समतुल्य एवं प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य का विकास।
- viii. बोर्ड द्वारा संदर्भित मुद्दों सहित किसी भी मामले का विशेष अध्ययन/जांच।

ग. लेखापरीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र:

लेखापरीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र/भूमिका इस प्रकार है :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की देखरेख करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
2. बोर्ड को लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारित करने की सिफारिश करना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
4. बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) और 134(5) के अनुसार निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे।

ख. लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;

ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;

घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

ई. वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं (लागू कानून, विनियमन और कंपनी नीतियों) का अनुपालन;

च. किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन का खुलासा; और

छ. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यताएं।

5. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
6. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है।



Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES

Ground Floor, 36 (179), Sukanta Sarani, Bhadrakali, Hoogly - 712232, West Bengal
Tel.: +91 9867771580, E-mail : raveena@mehta-mehta.com, Visit us : www.mehta-mehta.com
AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

8. आंतरिक लेखा परीक्षक और/या लेखा परीक्षकों के साथ किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।
9. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रकृति की विफलता हो और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना।
10. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में चर्चा, साथ ही लेखापरीक्षा के बाद चर्चा, ताकि चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाया जा सके।
11. व्हिसल ब्लोअर तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।
12. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
13. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का खुला मार्ग उपलब्ध कराना।
14. कंपनी में सभी संबंधित पक्ष लेन-देन की समीक्षा करना और उन्हें मंजूरी देना। इस उद्देश्य के लिए, लेखा परीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 18 में निहित संबंधित पक्ष लेन-देन की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा।
15. स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की समीक्षा करना, ताकि कवरेज की पूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी, तथा सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
16. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के साथ कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता की समीक्षा करना, तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्षों और सिफारिशों के साथ-साथ प्रबंधन की प्रतिक्रियाओं की भी समीक्षा करना।
17. प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर विचार और समीक्षा करना, जिसमें पिछली लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति और लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आने वाली किसी भी कठिनाई, जिसमें गतिविधियों के दायरे या आवश्यक जानकारी तक पहुंच पर कोई प्रतिबंध शामिल है।
18. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना।
19. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
20. लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।

घ. लेखा परीक्षा समिति की शक्तियां:

लेखापरीक्षा समिति को अपनी भूमिका के अनुरूप निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी:

1. अपने संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत किसी भी गतिविधि की जांच करना।



Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES

Ground Floor, 36 (179), Sukanta Sarani, Bhadrakali, Hoogly - 712232, West Bengal
Tel.: +91 9867771580, E-mail : raveena@mehta-mehta.com, Visit us : www.mehta-mehta.com
AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

2. किसी भी कर्मचारी से जानकारी मांगना।
3. बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
4. यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
5. मुखबिरो की सुरक्षा करना।
6. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों को सशक्त बनाकर हितों के टकराव को कम करना।
7. आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना।

ड. लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा:

लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करेगी:

- i. वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;
- ii. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण;
- iii. वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;
- iv. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;
- v. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और हटाने का मामला लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा; और
- vi. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा।

च. संरचना:

बोर्ड ने 24.02.2025 को आयोजित अपनी 286 वीं बोर्ड बैठक में सीएमपीडीआईएल की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया। 31 मार्च, 2024 तक लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं और इसका नेतृत्व सरकारी अंशकालिक निदेशक करते हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	कंपनी में पदनाम
1	श्री मुकेश अग्रवाल	अध्यक्ष	सरकारी अंशकालिक निदेशक
2	श्री मारापल्ली वेंकटेश्वरलु	सदस्य	सरकारी अंशकालिक निदेशक
3	श्री शंकर नागाचारी	सदस्य	कार्यकारी निदेशक
4	श्री अजय कुमार	सदस्य	कार्यकारी निदेशक



Mehta & Mehta COMPANY SECRETARIES

Ground Floor, 36 (179), Sukanta Sarani, Bhadrakali, Hoogly - 712232, West Bengal
Tel.: +91 9867771580, E-mail : raveena@mehta-mehta.com, Visit us : www.mehta-mehta.com
AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

विभागाध्यक्ष (आईएडी) और सांविधिक लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षा समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। सीएफओ स्थायी आमंत्रित व्यक्ति है और कंपनी सचिव समिति का सचिव है। समिति को आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए वरिष्ठ कार्यात्मक अधिकारियों को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग लेखा परीक्षा समिति की बैठक आयोजित करने और संचालन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

छ. वित्त वर्ष 2024-25 में आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान क्रमशः क्रमशः 25.04.2024, 25.06.2024, 22.07.2024, 23.08.2024, 13.09.2024, 01.10.2024, 20.10.2024, 20.01.2025, 24.02.2025, 25.03.2025 को 10 (दस) बैठकें आयोजित की गईं।

3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

बोर्ड ने कॉर्पोरेट प्रशासन के सर्वोत्तम अभ्यास का पालन करने और कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशानिर्देशों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए लिस्टिंग समझौते का अनुपालन करने के लिए 30.12.2015 को आयोजित अपनी 191 वीं बोर्ड बैठक में सीएमपीडीआईएल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया।

सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, कंपनी की पारिश्रमिक समिति निष्क्रिय रही। चूंकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए कंपनी के प्रबंधन ने समय-समय पर मंत्रालय को आवश्यक पत्र भेजे थे, जिनकी प्रतियाँ होलिंग कंपनी को भी भेजी गई थीं, जिनमें स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध किया गया था।

क. वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयोजित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का बैठक का विवरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी



4. सीएसआर समिति

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संधारणीयता एक कंपनी की अपने हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता है कि वह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय तरीके से व्यवसाय संचालित करे जो पारदर्शी और नैतिक हो। हितधारकों में कर्मचारी, निवेशक, शेयरधारक, ग्राहक, व्यापार भागीदार, ग्राहक, नागरिक समाज समूह, सरकारी और गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण और समाज शामिल हैं।

प्रत्येक सीपीएसई को कंपनी के सीएसआर और स्थिरता नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख करने और डीपीई द्वारा 01.04.2013 से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी के इन एजेंडे को वांछित दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करने के लिए अध्यक्ष और/या प्रबंध निदेशक

Mehta & Mehta

COMPANY SECRETARIES

Ground Floor, 36 (179), Sukanta Sarani, Bhadrakali, Hoogly - 712232, West Bengal
Tel.: +91 9867771580, E-mail : raveena@mehta-mehta.com, Visit us : www.mehta-mehta.com

AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

या एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक बोर्ड स्तरीय समिति रखने की आवश्यकता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, सीएसआर और स्थिरता को एमओयू में गैर-वित्तीय मापदंडों के तहत एक अनिवार्य तत्व के रूप में शामिल किया गया है।

दिशानिर्देशों के अनुरूप, बोर्ड ने 24.02.2025 को आयोजित अपनी 286 वीं बैठक में सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया।

क. रचना:

31 मार्च, 2025 तक सीएसआर समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं और इसका नेतृत्व अंशकालिक निदेशक करेंगे:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	कंपनी में पदनाम
1	श्री मारापल्ली वेंकटेश्वरलु	अध्यक्ष	सरकारी अंशकालिक निदेशक
2	श्री शंकर नागाचारी	सदस्य	कार्यकारी निदेशक
3	श्री अजय कुमार	सदस्य	कार्यकारी निदेशक

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा महाप्रबंधक (ईएनवी /सीएसआर) समिति के नोडल अधिकारी होंगे, जो सीएसआर समिति को सभी सेवाएं प्रदान करेंगे।

ख. वित्त वर्ष 2024-25 में आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 7 (सात) बैठकें क्रमशः 25.04.2024, 21.06.2024, 19.08.2024, 12.09.2024, 01.10.2024, 18.12.2024, 24.02.2025 को आयोजित की गईं।

5. जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन सीएमपीडीआईएल निदेशक मंडल द्वारा 02.02.2016 को आयोजित 192 वीं बोर्ड बैठक में किया गया था और बोर्ड द्वारा 29.01.2024 को आयोजित 274वीं बोर्ड बैठक में इसका पुनर्गठन किया गया था।

क. रचना:

जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं और इसका नेतृत्व एक कार्यकारी निदेशक करता है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	कंपनी में पदनाम
1	श्री शंकर नागाचारी	अध्यक्ष	कार्यकारी निदेशक
2	श्री अजय कुमार	सदस्य	कार्यकारी निदेशक
3	श्री अच्युत घटक	सदस्य	कार्यकारी निदेशक



Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES

Ground Floor, 36 (179), Sukanta Sarani, Bhadrakali, Hoogly - 712232, West Bengal
Tel.: +91 9867771580, E-mail : raveena@mehta-mehta.com, Visit us : www.mehta-mehta.com
AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा महाप्रबंधक (एक्ससीवी/ एस एंड टी) समिति के नोडल अधिकारी होंगे, जो समिति को सभी सेवाएं प्रदान करेंगे।

ख. वित्त वर्ष 2024-25 में आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 18.12.2024 को 1 (एक) बैठक आयोजित की गई।

6. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

क. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को निम्नलिखित पर चर्चा करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करना आवश्यक है:

क. गैर-स्वतंत्र निदेशकों और पूरे बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा।

ख. कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा।

ग. कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन करना, जो बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से निभाने के लिए आवश्यक है।

ख. वित्त वर्ष 2024-25 में आयोजित स्वतंत्र निदेशक बैठक का विवरण:

सीएमपीडीआईएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

कृते मेहता और मेहता

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई नं.: P1996MH007500)



रवीना दुगर अग्रवाल

पार्टनर

एसीएस नं.: A51836

सीपी नं.: 26055

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 30.06.2025

Addendum – IV

K C TAK & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्य

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड ("कंपनी") के साथ भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणीयों, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी ("भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी को अपेक्षित तरीके से देते हैं तथा भारतीय लेखा मानक सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के विवरण सहित इसके वित्तीय निष्पादन का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं।

अभिमत के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

1, Anantpur, Doranda, Ranchi, Jharkhand – 834002,
3rd Floor, Paras complex, Near Akash Institute, Club Road, Ranchi Jharkhand-834004
Mail Id: fca.kctanil@gmail.com Mob. No. +91-9031008947



K C TAK & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS



मामलों पर जोर

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क) अधिकांश मामलों में ऋणों के शेष (टिप्पणी संख्या 4.2), अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी संख्या 4.6), अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी संख्या 6.2), अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी संख्या 6.1), व्यापार देयताएँ (टिप्पणी संख्या 8.3), व्यापार प्राप्य (टिप्पणी संख्या 4.3), अन्य वित्तीय देनदारियाँ (टिप्पणी संख्या 8.4) और अन्य चालू देनदारियाँ (टिप्पणी संख्या 10.2) की पुष्टि नहीं की गई है। इनमें खातों की पुस्तकों में अंतिम समायोजन/स्केयर-अप के लिए लंबित पिछले कई वर्षों से पड़ी पुरानी शेष राशि भी शामिल है। ऐसी शेष राशियों की पुष्टि/समाधान/समायोजन पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में पता लगाने योग्य नहीं है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र.सं.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	ऑडिटर की प्रतिक्रिया
1.	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करें सहित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों और इसके प्रावधानों का आकलन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं : हमारी लेखापरीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों और संबंधित कानून के निर्णयों/व्याख्या का विश्लेषण करने पर केंद्रित थी। - अन्य पक्षों द्वारा दायर प्रत्यक्ष कर/अप्रत्यक्ष कर/विभिन्न दावों सहित आकस्मिक देनदारियों की सूची प्राप्त करना। - परीक्षण जांच के आधार पर जांच करना, विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेश और/या संचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।





प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी के मूल्यांकन को मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकार की सलाह द्वारा समर्थित किया जाता है, जहां भी आवश्यक माना जाता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम कंपनी के रिपोर्ट किए गए लाभ और शुद्ध संपत्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। परिणाम से संबंधित संबद्ध अनिश्चितता के लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 16 पैरा 4 (क) देखें।	• मुकदमे/कर आकलन की वर्तमान स्थिति को समझना • विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन उसमें प्रस्तुत आधारों और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सलाह के संदर्भ में करना। • चर्चा, विचाराधीन विषय-वस्तु के विवरण का संग्रह, उन मुद्दों पर संभावित परिणाम और परिणामी संभावित बहिर्वाह के माध्यम से कंपनी के तर्कों की समीक्षा और विश्लेषण। लेखापरीक्षा निष्कर्ष: हमारी प्रक्रियाओं में कोई भौतिक अपवाद नहीं पाया गया।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यवसाय जिम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या ऑडिट में प्राप्त हमारा ज्ञान अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक भौतिक गलत विवरण है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। चूंकि हमें अन्य जानकारी प्रदान नहीं की गई है, इसलिए हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।



K C TAK & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS



जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, जो इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध होने की उम्मीद है, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें एक भौतिक गलत बयान है, तो हमें मामले को शासन के आरोप वाले लोगों को सूचित करना आवश्यक है।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। अन्य व्यापक आय और नकदी प्रवाह और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (Ind_AS) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ें।" इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, चालू चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने, जैसा लागू हो, और लेखांकन के चल रहे चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का इरादा नहीं रखता है या संचालन बंद करने के लिए, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर एक अहम मिथ्याकथन का पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उन्हें इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित उम्मीद की जा सकती है।

ऑडिट पर मानकों के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:





- भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। त्रुटि के कारण हुई गलतबयानी की अपेक्षा धोखाधड़ी से की गई गलतबयानी का पता नहीं चल पाने का जोखिम अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठगांठ, जालसाजी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चूक, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण के उल्लंघन की आशंका रहती है।
- ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के क्रम में जो परिस्थितियों के अनुसार समुचित हों लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चल रहे चिंता के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चिंता के रूप में जारी रखने के लिए बंद हो सकती है।

प्रकटीकरण सहित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व इस तरह से करते हैं जो उचित प्रस्तुति प्राप्त करता है।

भौतिकवादी भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत बयानों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकवादी और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, गवर्नेंस के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण की कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।



K C TAK & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS



हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन से जुड़े मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से यथोचित रूप से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभ की अधिक अपेक्षा की जाएगी।

अन्य मामले

क) यह देखा गया कि देनदारों में सीआईएल सहायक कंपनियों के खिलाफ 72.03 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 65.71 करोड़) की पुरानी बकाया राशि शामिल है, जो 1 वर्ष से अधिक समय से वसूली के लिए लंबित है। सीआईएल द्वारा जारी परिपत्र संख्या CIL/DT/2021/3093 के अनुसार; i) बिल मूल्य की मूल राशि का 70% और 18% जीएसटी (अर्थात, कुल बिल मूल्य का कुल 75%) का भुगतान सहायक कंपनियों द्वारा बिल प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सीएमपीडीआई को किया जाएगा; ii) भविष्य में बिल समाधान एक पोर्टल के माध्यम से होगा और सीएमपीडीआई पोर्टल पर कार्रवाई को सूचित करेगा और सहायक कंपनियों के साथ संवाद करेगा; iii) एक वर्ष से अधिक के बकाया बिलों की समीक्षा सीएमपीडीआई और संबंधित सहायक कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। हालांकि, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि सीआईएल द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार सहायक कंपनियों को जुटाए गए बिलों की वसूली नहीं की जा रही है। ऐसी शेष राशियों की पुष्टि/समाधान/समायोजन पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में पता लगाने योग्य नहीं है।

ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के तहत गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में भारत सरकार/कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास अनुदान/फंड से खरीदी गई गैर-वर्तमान संपत्ति शामिल है। 31/03/2025 तक, इन निधियों से खरीदी गई 327 परिसंपत्तियों (संयंत्र और उपकरण) का अवशिष्ट मूल्य (डब्ल्यूडीवी) 7.33 करोड़ रुपये था। यह देखा गया कि 327 परिसंपत्तियों में से 1.81 करोड़ रुपये मूल्य की 217 परिसंपत्तियों का जीवन 15 वर्ष से अधिक था और इसे 50 वर्ष (1975 से) तक बढ़ाया गया था।

भारतीय लेखांकन मानक-16 के पैरा 16 के अनुसार कहा गया है कि पीपीई की किसी मद की लागत को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी यदि, और केवल यदि: (क) यह संभावना हो कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ यूनिट को प्रवाहित होंगे; तथा (ख) वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा





सके। इसके अलावा, पीपीई की एक वस्तु को निपटान पर या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से गैर-भविष्य के आर्थिक लाभों की उम्मीद की जाती है।

कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संयंत्र और उपकरण परिसंपत्तियों के तहत किसी भी संपत्ति के अधिकतम उपयोगी जीवन को 15 वर्ष के रूप में मानती है, इसलिए, 15 वर्ष या उससे अधिक की संपत्ति का उपयोगी जीवन पहले ही समाप्त हो चुका है और इन परिसंपत्तियों को पूंजी आरक्षित खाते में डी-चार्ज करने की आवश्यकता है जिसमें फंड/अनुदान बनाए रखा जाता है।

हालांकि, सीएमपीडीआईएल प्रबंधन ने बताया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास परिसंपत्तियों का स्वामित्व कोयला और कोल इंडिया लिमिटेड के पास है। सीएमपीडीआईएल एक कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते कोयला मंत्रालय/कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्व अनुमति के बिना अपने दम पर सर्वेक्षण-ऑफ पहले नहीं कर सकता है और उन्होंने इस मामले को कोयला मंत्रालय और कोल इंडियन लिमिटेड को सूचित किया है, जिसमें उनसे परिसंपत्ति निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाने और सीएमपीडीआईएल को एक अपडेट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। सीएमपीडीआईएल प्रबंधन से अनुस्मारक के बावजूद, इन परिसंपत्तियों के निपटान के संबंध में कोयला मंत्रालय और कोल इंडियन लिमिटेड के निर्देश अभी भी लंबित हैं। इस स्थिति को देखते हुए, सीएमपीडीआईएल प्रबंधन कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास द्वारा वित्त पोषित परिसंपत्तियों के निपटान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने के लिए कोयला मंत्रालय और कोल इंडियन लिमिटेड से आगे संचार की प्रतीक्षा कर रहा है।

उपरोक्त के मद्देनजर, पुरानी परिसंपत्तियों की गैर-मान्यता जिनकी 15 वर्ष या उससे अधिक की संपत्ति का उपयोगी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान। 1.81 करोड़ रुपये के लिए गैर-वर्तमान संपत्ति और पूंजी भंडार में समायोजन नहीं किया गया है।

- ग) हमने देखा कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के साथ कंपनी का चालू खाता वर्ष के अंत में 61.58 करोड़ रुपये के डेबिट शेष को दर्शाता है, जिसमें से 60.58 करोड़ रुपये पूर्व वर्षों से संबंधित हैं और आगे ले जाया गया है। यह शेष राशि कथित तौर पर सीआईएल के साथ बिक्री लेनदेन से संबंधित है। हालांकि, प्रबंधन लेनदेन को प्रमाणित करने या इस शेष राशि की प्राप्ति न होने के कारणों को समझाने के लिए विशिष्ट विवरण या दस्तावेज प्रदान करने में असमर्थ था। बकाया राशि की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए सीआईएल से कोई समाधान विवरण या खाते की पुष्टि प्रस्तुत नहीं की गई है। पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के अभाव में, हम शेष राशि की सटीकता और वसूली को सत्यापित करने में असमर्थ हैं। नतीजतन, हम वित्तीय विवरणों में आवश्यक संभावित समायोजन, यदि कोई हो, और कंपनी की वित्तीय स्थिति पर उनके प्रभाव का पता लगाने में भी असमर्थ हैं।



K C TAK & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS



घ) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, क्षेत्रीय संस्थान-7 में कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस (सीडब्ल्यूआईपी) लेजर, विशेष रूप से एयूसी बिल्डिंग अकाउंट (एसेट कोड: 20101030) की पुष्टि करते हुए, हमने देखा कि गोपालपुर शिविर के लिए लखनपुर में आवासीय भवनों के निर्माण से संबंधित समापन शेष में 0.14 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

सहायक दस्तावेजों के प्रबंधन और समीक्षा के साथ चर्चा के आधार पर, यह नोट किया गया था कि निविदा जारी करने और मृदा परीक्षण, सर्वेक्षण और वन भूमि मंजूरी की ओर प्रारंभिक लागत वहन करने के बाद कंपनी द्वारा परियोजना को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया है।

भारतीय लेखा मानक 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की वहन राशि को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के किसी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है।

कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस (सीडब्ल्यूआईपी) आमतौर पर उन परिसंपत्तियों पर खर्च की गई लागत का प्रतिनिधित्व करता है जो निर्माणाधीन हैं और भविष्य के आर्थिक लाभों के परिणामस्वरूप होने की उम्मीद है। वर्तमान मामले में, चूंकि परियोजना को बंद कर दिया गया है और इसके पुनरुद्धार की कोई संभावना नहीं है, ऐसे व्यय का निरंतर पूंजीकरण भारतीय लेखा मानक 16 के अनुपालन में नहीं है।

जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि यह मामला 01.11.2024 को आयोजित एफडी समिति की 24वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था और मामला टीओसी में लंबित है। इसे अनुमोदन के लिए अगली सीओएफडीएस की बैठक में रखा जाएगा। इस तरह के अनुमोदन के लंबित होने पर, अंतिम परिणाम पर परिणामी प्रभाव वर्तमान में पता लगाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत आवश्यक है, हम "अनुलग्नक क" में लेखापरीक्षा की सुझाई गई कार्यप्रणाली, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के खातों और भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/अतिरिक्त निर्देशों पर एक विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम "अनुलग्नक ख" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में लागू





सीमा तक निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे, जैसा कि ऊपर "मामलों पर जोर" पैराग्राफ के खण्ड (क) में रिपोर्ट किया गया है।
- ख) हमारी राय में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने से संबंधित कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित पुस्तकें कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- ग) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण खातों की पुस्तकों के अनुरूप है।
- घ) हमारी राय में, हमारे पास कोई अवलोकन नहीं है जिसका कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- ङ) हमारी राय में, पूर्वोक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक का पालन करते हैं, जो इसके तहत जारी प्रासंगिक नियम के साथ पढ़े जाते हैं।
- च) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या G.S.R.463(E) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में, निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- छ) हमारे पास खातों के रखरखाव और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक ग" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।
- झ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या G.S.R.463(E) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- ञ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित किया गया है, हमारी राय में और हमारी





सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- I. कंपनी ने भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के अतिरिक्त टिप्पणी 16 के तहत अपने लंबित उकसावे का खुलासा किया है। इन मुकदमे के प्रभाव, यदि कोई हो, को तब और जब भी निर्धारित/ निपटाया जाता है, प्रभावी किया जाएगा।
- II. कंपनी ने लंबी अवधि के अनुबंधों पर यदि कोई हो, तो भौतिक संभावित नुकसान के लिए लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए हैं और कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं था।
- III. प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार, कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- IV. (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को या उसमें कोई धन उन्नत या उधार नहीं दिया गया है या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के प्रकार से) विदेशी इकाई ("मध्यस्थ"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करेगा;
- (ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी को किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें विदेशी इकाई ("फंडिंग पार्टियां") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करेगी;
- (ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं आया है जिसने यह विश्वास किया है कि नियम 11(e) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत कथन शामिल है।
- V. कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।



- VI. हमारी परीक्षा के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा की रिकॉर्डिंग की विशेषता है और यह पूरे वर्ष संचालित होता है। सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का कोई उदाहरण नहीं मिला और रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल सुविधा को संरक्षित किया गया है।

के सी टाक एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म का पंजीकरण संख्या: 000216C

स्थान: राँची
दिनांक: 30/04/2025

सीए अनिल जैन

साझेदार

मोबाइल नं.: 079005

यूडीआईएन: 25079005BMOKCP8577



K C TAK & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ '1' में संदर्भित **अनुलग्नक "क"**, हम रिपोर्ट करते हैं कि;

भाग- I

क्र. सं.	निदेश	लेखा परीक्षक का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ खातों की अखंडता पर आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का निहितार्थ बताया जा सकता है	सभी भौतिक लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है और सभी अंतर्निहित व्यावसायिक लेनदेन की रिकॉर्डिंग इसके एसएपी-ईआरपी सॉफ्टवेयर में की जाती है। तदनुसार, खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूचना/डेटा विभिन्न मॉड्यूलों से बह रहा है और वित्तीय लेखांकन और नियंत्रण (एफआईसीओ), बिक्री और वितरण (एस एंड डी), सामग्री प्रबंधन (एमएम), मानव पूंजी प्रबंधन (एचसीएम), उत्पादन योजना (पीपी), परियोजना प्रणाली (पीएस) और संयंत्र रखरखाव (पीएम) जैसी प्रक्रियाओं के लिए एसएपी के तहत स्वचालन के माध्यम से वित्तीय में कैप्चर किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2022 को स्थिरीकरण चरण के पूरा होने के बाद, सिस्टम एएमसी चरण के तहत है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि, एसएपी के बाहर निम्नलिखित गतिविधियां की जाती हैं: वर्तमान वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में एसएपी में बैलेंस शीट (बीएस) और लाभ और हानि (पी एंड एल) खातों की तैयारी शामिल है। हालांकि, त्रैमासिक/वार्षिक खातों की प्रस्तुति के लिए, एसएपी से प्राप्त प्रत्येक फुटनोट को मैनुअल रूप से एक अलग एक्सेल प्रारूप में संकलित किया जाता है। यह कंपनी अधिनियम की भारतीय लेखा मानक और अनुसूची-III की प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, खातों के लिए पूरक नोटों का निर्माण वर्तमान में एक शब्द दस्तावेज़ में की गई एक मैनुअल प्रक्रिया है। एसएपी के बाहर की गई गतिविधियों के संबंध में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, हमारी राय में कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव नहीं है।



2.	क्या मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं। कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को एक ऋणदाता द्वारा बनाया गया? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामलों के किसी भी पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित किया गया था/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भाग- II के खंड 2 और 3 में उल्लिखित विस्तृत और प्रचार ड्रिलिंग, आर एंड डी और एस एंड टी और एनएमईटी के अलावा कोई भी फंड/अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है/कोई प्राप्य नहीं है - अतिरिक्त निर्देश (अनुलग्नक - 'क')।

भाग-II - अतिरिक्त निर्देश

क्र. सं.	निर्देश	लेखा परीक्षक का उत्तर
1.	क्या कोलनेट पोर्टल से एसएपी तक डेटा की माइग्रेशन प्रक्रिया का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन और प्रमाणन किया गया था।	हां, वर्ष के दौरान कोलनेट पोर्टल से एसएपी सिस्टम तक डेटा माइग्रेशन प्रक्रिया का एक स्वतंत्र मूल्यांकन और प्रमाणन किया गया था। बाहरी सेवा प्रदाता, अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा विभिन्न कार्यात्मक डोमेन को कवर करते हुए एक डेटा माइग्रेशन ऑडिट रिपोर्ट जारी की गई थी। अर्न्स्ट एंड यंग के रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए डेटा माइग्रेशन को मान्य और प्रमाणित किया गया था। मानव पूंजी प्रबंधन (एचसीएम) डोमेन के भीतर, कर्मचारी मास्टर डेटा के लिए 99.63% और कर्मचारी मास्टर मॉड्यूल रिपोर्ट के लिए 85.33% तक समाधान प्राप्त किया गया था। हालांकि, एचसीएम के तहत कुछ मॉड्यूल अर्थात् ऋण मास्टर, एलआईसी मास्टर और वेतन मास्टर को कोलनेट सिस्टम से अपेक्षित स्रोत डेटा की अनुपलब्धता के कारण पूरी तरह से मिलान या मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था। नतीजतन, अर्न्स्ट और यंग इन विशिष्ट मॉड्यूल के लिए डेटा माइग्रेशन की सटीकता और पूर्णता को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने में असमर्थ थे।



K C TAK & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS



2. क्या एमओयू के अनुपालन में कोयला ब्लॉकों की खोज पूरी की गई थी और विस्तृत और प्रचार ड्रिलिंग के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग किया गया था और ठीक से हिसाब लगाया गया था। विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीएमपीडीआई और एमओसी/सीआईएल/एनएमईटी के बीच कोई समझौता ज्ञापन नहीं है। सीएमपीडीआई देश में कोयले और लिग्राइट की खोज से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए नोडल एजेंसी है। सीएमपीडीआई एमओसी/सीआईएल/एनएमईटी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित परियोजना/ब्लॉकों के अनुसार या तो स्वयं या एमईसीएल और निजी पार्टियों के साथ समझौतों के अनुसार विस्तृत और प्रचार ड्रिलिंग की गतिविधियों को करता है। परीक्षण जांच के आधार पर नमूनों की हमारी जांच के आधार पर, यह देखा गया कि एमईसीएल और निजी पक्षों के साथ किए गए समझौतों के अनुपालन में ब्लॉकों की खोज पूरी की गई थी और विस्तृत और प्रचार ड्रिलिंग के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग किया जा रहा है और ठीक से हिसाब लगाया जा रहा है।
3. क्या आरएंडडी और एसएंडटी परियोजनाओं के लिए प्राप्त निधियों को नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा / उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसी/संस्थान द्वारा सीएमपीडीआई को प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर कुछ नियमों और शर्तों के साथ एमओसी/सीआईएल की तकनीकी समिति द्वारा आर एंड डी और एस एंड टी परियोजनाओं को अनुमोदित/स्वीकृत किया जाता है। सीएमपीडीआई सभी चल रही या नई आरएंडडी/एसएंडटी परियोजनाओं के लिए निधि की आवश्यकता का अनुमान लगाता है और एमओसी/सीआईएल से एक समेकित मांग करता है। एक बार निधि प्राप्त होने के बाद, सीएमपीडीआई परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर विभिन्न किशतों में कार्यान्वयन एजेंसी/संस्थान को निधि वितरित करता है। एक बार जब परियोजना पूरी हो जाती है और परियोजना पूर्णता रिपोर्ट तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित हो जाती है, तो कार्यान्वयन एजेंसी/संस्थान सीएमपीडीआई को उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं और ऐसी परियोजनाओं पर प्राप्त निधि की अव्ययित राशि को सीएमपीडीआई को उन निधियों पर अर्जित ब्याज के साथ वापस कर देते हैं।



	परीक्षण-जांच के आधार पर चयनित नमूनों की हमारी जांच के आधार पर, यह देखा गया कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के आर एंड डी फंड और कोयला मंत्रालय (एमओसी) के एस एंड टी फंड के तहत प्राप्त धन सामान्य रूप से, संबंधित परियोजना अनुमोदन में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ठीक से हिसाब और उपयोग किया गया था। हालांकि, 2021 में कोयला मंत्रालय द्वारा जारी "अनुसंधान परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देशों" से कुछ विचलन को नोट किया गया था, जैसा कि नीचे संक्षेप में दिया गया है: • प्रत्येक व्यक्तिगत परियोजना के लिए अलग बैंक खाते बनाए रखना; • परियोजना के पूरा होने पर लागू ब्याज के साथ परियोजना निधियों के किसी भी अप्रयुक्त शेष को वापस करना; • संवितरण की तारीख से परियोजना निधियों पर अर्जित ब्याज की रिपोर्ट करें; और • या तो बाद की फंड किशतों के खिलाफ रिपोर्ट किए गए ब्याज को समायोजित करें या परियोजना के अंत में कोयला मंत्रालय को आगे ऋण के लिए इसे सीएमपीडीआई को भेजें। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देश गैर-ब्याज वाले खातों में परियोजना निधियों की पार्किंग को प्रतिबंधित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी सार्वजनिक धन उत्पादक रूप से रखे जाते हैं और पारदर्शी रूप से प्रबंधित किए जाते हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्ष: लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि प्रबंधन ने विभिन्न बैंक खातों में रखी गई निधियों पर अर्जित ब्याज के संबंध में उचित दस्तावेजीकरण नहीं किया है। यह चूक वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता और सटीकता को कमजोर करती है, विशेष रूप से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधि प्रबंधन के संबंध में। प्रमुख टिप्पणियों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:



	1. वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज के साथ-साथ प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा संचालित सभी बैंक खातों का विवरण देते हुए कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। यह ब्याज आय से वित्तीय प्रवाह की प्रभावी ट्रेकिंग को बाधित करता है। 2. परियोजना निधियों पर अर्जित ब्याज आय की न तो उचित गणना की गई और न ही दस्तावेजी साक्ष्य जैसे बैंक विवरण, ब्याज प्रमाण पत्र या समाधान के साथ पुष्टि की गई। यह रिपोर्ट किए गए ब्याज आंकड़ों की सटीकता के बारे में चिंता पैदा करता है। 3. व्यक्तिगत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अर्जित ब्याज आय की गणना न तो बैंक विवरण, ब्याज प्रमाण पत्र या अन्य वित्तीय रिकॉर्ड जैसे सत्यापन योग्य दस्तावेज के साथ साझा की गई थी और न ही समर्थित थी। यह रिपोर्ट किए गए आंकड़ों को स्वतंत्र रूप से मान्य करने की क्षमता को सीमित करता है। 4. यह दिखाने के लिए कोई स्पष्ट ऑडिट ट्रेल या सहायक रिकॉर्ड नहीं था कि अर्जित ब्याज को आगे फंड संवितरण के खिलाफ कैसे समायोजित किया गया था या परियोजना बंद होने पर फंड में वापस भेज दिया गया था। कई मामलों में, यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि इस तरह के ब्याज का उचित उपयोग किया गया था या वापस कर दिया गया था। 5. यह देखा गया कि कार्यान्वयन एजेंसियां परियोजना अवधि के दौरान परियोजना निधियों पर अर्जित ब्याज की रिपोर्ट नहीं कर रही हैं। नतीजतन, चल रही परियोजनाओं के लिए बाद की किश्तों को जारी करते समय अर्जित ब्याज पर विचार नहीं किया जा रहा है। इसके बजाय, ब्याज की पूरी राशि परियोजना के पूरा होने के समय ही समायोजित की जाती है। इस प्रथा के परिणामस्वरूप अर्जित ब्याज के लिए अंतरिम समायोजन के बिना स्वीकृत परियोजना निधियों का पूर्ण संवितरण होता है, जिससे परियोजना अवधि के दौरान धन की अतिरिक्त रिहाई हो सकती है।



	6. ऐसे मामलों की पहचान की गई जहां पूरी की गई परियोजनाओं के संबंध में अप्रयुक्त परियोजना निधि वापस नहीं की गई थी, और उन मामलों में भी कोई ब्याज रिपोर्ट या प्रेषित नहीं किया गया था, जहां पूरी संवितरित राशि का उपयोग करने का दावा किया गया था, हालांकि प्रबंधन द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी। नीचे दी गई निम्नलिखित तालिका- 1 में गैर-अनुपालन के मामलों का सारांश दिया गया है। 7. तिमाही प्रगति रिपोर्ट और व्यय विवरण प्रस्तुत न करना : दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रधान कार्यान्वयन और उप-कार्यान्वयन एजेंसियों को मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और व्यय विवरण (फॉर्म III, IV और V) प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन्हें जांच के लिए प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद महीने की 15 तारीख तक सीएमपीडीआई को प्रस्तुत किया जाना है। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कार्यान्वयन एजेंसियां प्रबंधन द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, नियमित आधार पर आवश्यक तिमाही प्रगति रिपोर्ट और व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं कर रही हैं। 8. फॉर्म VII जमा करने में देरी: दशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना अवधि के विस्तार के लिए किसी भी अनुरोध को विधिवत हस्ताक्षरित और संस्था के प्रमुख या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, अधिमानतः परियोजना पूरा होने की निर्धारित तिथि से कम से कम दो महीने पहले। हालांकि, इस समयसीमा का पालन नहीं किया जा रहा है। लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि निम्नलिखित मामले में, परियोजना की निर्धारित पूर्णता तिथि के बाद विस्तार के लिए फॉर्म VII प्रस्तुत किया गया था, जो निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने का संकेत देता है।





	नीचे दी गई निम्नलिखित तालिका- 2 में गैर-अनुपालन के मामलों का सारांश दिया गया है। 9. लेखापरीक्षा आवश्यकताओं का गैर-अनुपालन: दिशानिर्देशों के अनुसार, यह प्रधान कार्यान्वयन और उप-कार्यान्वयन एजेंसी (एजेंसी) की जिम्मेदारी है कि वे एसएंडटी अनुदान से संबंधित खातों का नियमित रूप से ऑडिट करें और सीएमपीडीआई को लेखापरीक्षित विवरण की एक प्रति प्रस्तुत करें। हालांकि, यह देखा गया है कि कार्यान्वयन एजेंसियां आवश्यक लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत नहीं कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है। इसके अलावा, दिशानिर्देश यह भी निर्धारित करते हैं कि परियोजना पूर्णता रिपोर्ट के साथ एक लेखापरीक्षित व्यय विवरण या विधिवत प्रमाणित निधि उपयोग प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। यह नोट किया गया कि प्रबंधन द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजना पूर्णता रिपोर्ट के साथ ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।



तालिका 1: अप्रयुक्त निधियों की वापसी और ब्याज रिपोर्टिंग में गैर-अनुपालन का सारांश

क्र. सं.	परियोजना कोड	कार्यान्वयन एजेंसियां	परियोजना पूर्णता तिथि	निधि का नाम	संवितरित निधि (₹ करोड़)	व्यय (₹ करोड़)	अप्रयुक्त (₹ करोड़)	प्राप्त ब्याज
1	CIL/ R&D/02/10/2021	एनएमएल, जमशेदपुर; सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची; बीसीसीएल, धनबाद	31-12-2023	आर &डी	2.8	2.6	0.2	नहीं
2	CIL/ R&D/02/11/2021	सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची; बीसीसीएल, धनबाद	28-02-2024	आर &डी	2.65	2.65	शून्य	नहीं
3	CIL/ R&D/01/76/2021	आईआईटी- आईएसएम, धनबाद; बीसीसीएल, धनबाद	14-11-2023	आर &डी	0.7	0.61	0.09	नहीं
4	CIL/ R&D/01/74/2021	सीएमईआरआई, दुर्गापुर; ईसीएल, सैंक्टोरिया	09-11-2023	आर &डी	4.8	4.6	0.2	नहीं
5	MT – 172	आईआईटी, खड़गपुर; सीएमपीडीआई	01-12-2020	एस&टी	4.71	3.44	1.27	नहीं

तालिका 2: परियोजना विस्तार अनुरोधों को समय पर प्रस्तुत करने में गैर-अनुपालन का सारांश (फॉर्म VII)

क्र. सं.	परियोजना कोड	कार्यान्वयन एजेंसियां	परियोजना पूर्णता तिथि	निधि का नाम	संवितरित निधि (₹ करोड़)	व्यय (₹ करोड़)
1	CIL/R&D/04/18/2022	ईसीएल, सैंक्टोरिया और सीआईएमएफआर, धनबाद	31-03-2025	आर &डी	49.2	0.22

K C TAK & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS



अनुलग्नक - "ख" 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ 2 में संदर्भित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि;

(i) क) (क) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी ने आम तौर पर संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के पूर्ण विवरण दिखाने के उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों के संपूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख रखे हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए रिकॉर्ड बनाए रखा है।

हमें सूचित किया गया है कि प्रबंधन ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार उचित अंतराल पर अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है, और ऐसा सत्यापन विधिवत गठित टीम द्वारा किया गया था। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, इस तरह के सत्यापन के दौरान कोई भौतिक विसंगतियां नोट नहीं की गई थीं।

हालांकि, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने देखा कि विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में परिसंपत्तियों की संख्या, जिनमें से कई को वित्तीय वर्ष 2000 से पहले पूंजीकृत किया गया था और व्यक्तिगत रूप से ₹100.00 से कम के अवशिष्ट/लिखित मूल्य को स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर में दिखाया जाना जारी है। ये परिसंपत्तियां भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में दिखाई नहीं देती हैं और उपलब्ध जानकारी के आधार पर, अब अस्तित्व में या सक्रिय उपयोग में नहीं हो सकती हैं। यह इंगित करता है कि जबकि भौतिक सत्यापन किया गया है, अचल संपत्ति रजिस्टर को भौतिक सत्यापन परिणामों के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाया जा सकता है। हमारे विचार में, यह कुछ परिसंपत्तियों के अस्तित्व और निरंतर मान्यता के बारे में चिंता पैदा करता है, और सुझाव देता है कि कंपनी को भारतीय लेखा मानक 16 की आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसी वस्तुओं की अमान्यता के लिए एक विस्तृत मूल्यांकन करना चाहिए - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, विशेष रूप से जहां भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए जाते हैं) के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं।

हालांकि, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने देखा कि भारत के राजपत्र दिनांक 14 अप्रैल 1979 (चैत्र 24, 1901) के अनुसार, केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान (सीएमपीडीआई) को कुछ अचल संपत्तियों के शीर्षक के साथ निहित किया गया था, जिसमें भूमि, कार्यालय और आवासीय भवन और परिसर शामिल थे जिन्हें लछीपुर और आसनसोल में कोयला बोर्ड कॉलोनी के रूप में जाना जाता है, जिसमें पंप हाउस, रेस्ट हाउस, कोल बोर्ड का कार्यालय और सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान-1 से संबंधित स्टाफ कॉलोनी शामिल है। उपरोक्त संपत्तियों के शीर्षक कर्मों को हमारे सत्यापन के लिए हमारे सामने पेश नहीं किया गया था। तदनुसार, हम इन अचल संपत्तियों के संबंध में शीर्षक की वैधता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।



- घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया है, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दोनों की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।
- ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- (ii) क) कंपनी की नीति के अनुसार, स्टोर और पुर्जों का भौतिक सत्यापन कंपनी द्वारा विधिवत नियुक्त बाहरी एजेंसी द्वारा उचित अंतराल पर किया जाता है और कंपनी द्वारा 31 दिसंबर 2025 को स्टॉक की स्थिति के लिए एक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है; इस तरह के सत्यापन पर इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगतियां नहीं देखी गई।
- ख) कंपनी को वर्ष के दौरान अपनी वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से 5 करोड़ रुपये से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वतंत्र रूप से स्वीकृत नहीं की गई है। हालांकि, कंपनी अपने और अपनी सहायक कंपनियों के लाभ के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के पक्ष में स्वीकृत 140 करोड़ रुपये (निधि-आधारित) और 290 करोड़ रुपये (गैर-निधि आधारित) की एक प्लूड कंसोर्टियम कैश क्रेडिट सुविधा के तहत एक व्यक्तिगत उधारकर्ता है। कंपनी सहित। इस व्यवस्था के हिस्से के रूप में, कंपनी की वर्तमान संपत्ति, अन्य समूह संस्थाओं के साथ, संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखी गई है। वर्ष के दौरान, कुछ नए बैंकों को शामिल करने के साथ कंसोर्टियम का पुनर्गठन किया गया था; हालांकि, 430 करोड़ रुपये (फंड-आधारित और गैर-फंड-आधारित संयुक्त) की समग्र स्वीकृत सीमा अपरिवर्तित रही।
- जैसा कि हमें सूचित किया गया है, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋण देने वाली संस्था के साथ वर्तमान परिसंपत्तियों का कोई त्रैमासिक रिटर्न या विवरण दायर नहीं किया है। ऐसी फाइलिंग, जहां लागू हो, समूह की ओर से होल्डिंग कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाती है।
- (iii) क) वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।
- ख) कंपनी ने बिजली सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सुरक्षा जमा के लिए इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में 0.14 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष: 0.14 करोड़ रुपये) की गारंटी प्रदान की है। यह गारंटी प्रकृति में चालू है और किसी वित्तीय आवास या ऋण से संबंधित नहीं है। हमारी राय में, गारंटी के नियम और शर्तें कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।
- ग) पहले के वर्षों में कर्मचारियों को दिए गए कुछ आवास अग्रिम बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार बकाया रहते हैं। हालांकि, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई नया आवास अग्रिम नहीं दिया है। इस संबंध में संदर्भ इस रिपोर्ट के खंड (xvi) में दिया जा सकता है।



K C TAK & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS



- घ) जबकि कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय ऋण के लिए गारंटी नहीं दी है, इसने कंपनी सहित कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के पक्ष में स्वीकृत 430 करोड़ रुपये की पूलड कंसोर्टियम कैश क्रेडिट सुविधा के तहत अपनी वर्तमान संपत्ति को गिरवी रखकर सुरक्षा प्रदान की है। हमारी राय में, इस प्रकार प्रदान की गई सुरक्षा कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं है।
- ङ) खंड (बी) में निर्दिष्ट परिचालन गारंटी, खंड (सी) में उल्लिखित विरासत कर्मचारी आवास अग्रिम, और खंड (डी) के अनुसार प्रदान की गई सुरक्षा, के अलावा कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, एलएलपी या अन्य पक्षों को ऋण की प्रकृति में कोई नया निवेश नहीं किया है और न ही कोई अतिरिक्त गारंटी, प्रतिभूतियां, ऋण या अग्रिम प्रदान किया है।
- (iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 में परिभाषित ऋण, निवेश, गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है।
- (v) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। हालांकि, कंपनी के व्यवसाय के दौरान या उसके उद्देश्य से ग्राहकों/अन्य से बयाना राशि जमा, सुरक्षा जमा और अग्रिम जमा के रूप में प्राप्त राशि के संबंध में शेष राशि, कंपनी का विचार है कि ये जमा नहीं आते हैं कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम 2014 के दायरे में।
- (vi) हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी द्वारा बनाए गए लागत अभिलेखों की व्यापक रूप से समीक्षा की है और उनकी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए गए हैं और बनाए रखा गया है। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सटीक हैं या पूर्ण।
- (vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, पेंशन निधि, पेशेवर कर और अन्य सामग्री सहित निर्विवाद वैधानिक देय राशि के संबंध में खाते की पुस्तकों में कटौती / अर्जित राशि आम तौर पर कंपनी द्वारा उपयुक्त अधिकारियों के साथ वर्ष के दौरान नियमित रूप से जमा की गई है।
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर पेंशन निधि, पेशेवर कर और अन्य भौतिक वैधानिक देय राशि के संबंध में उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद राशि 31 मार्च 2025 को बकाया नहीं थी।
- (ख) उप-खंड (ए) में संदर्भित वैधानिक बकाया जो **किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है**, शामिल राशि और मंच जहां ऐसा विवाद लंबित है, का उल्लेख **“परिशिष्ट-1”** में किया गया है।
- (viii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण के तहत कर अधिकारियों द्वारा किसी भी लेनदेन की पहचान या रिपोर्ट नहीं की गई है, जिसे वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या प्रकट करने की आवश्यकता है।



- (ix) (क) कंपनी ने किसी भी ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- (ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
- (ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उस उद्देश्य के लिए कोई सावधि ऋण लागू नहीं किया गया था जिसके लिए वर्ष के दौरान ऋण प्राप्त किया गया था।
- (घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर कोई निधि नहीं जुटाई है जिसका उपयोग दीर्घकालिक आधार के रूप में किया गया है।
- (ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों के कारण या पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।
- (च) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनी में रखी गई प्रतिभूतियों की प्रतिज्ञा पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।
- (x) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए पुस्तकों और अभिलेखों के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (x) पैरा (ए) लागू नहीं है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए पुस्तकों और अभिलेखों के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमाम्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (x) पैरा (बी) लागू नहीं है।
- (xi) (क) भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार की गई कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें न तो धोखाधड़ी का कोई उदाहरण मिला है या कंपनी पर, वर्ष के दौरान देखा या रिपोर्ट किया गया, न ही हमें मल्लारपुर शिविर, क्षेत्रीय संस्थान -1 में सड़क कर भुगतान के मामले को छोड़कर, प्रबंधन द्वारा ऐसे मामले के बारे में सूचित किया गया है, यह ध्यान दिया गया था कि 2021 के बाद से 5 वाहनों के लिए सड़क कर भुगतान के लिए अग्रिम तैयार किया गया था, जिसमें एक्सए अग्रिम को समायोजित करने के लिए प्रस्तुत ट्रेजरी रसीदें थीं। **हालांकि, 2021 से परिवार की वेबसाइट पर कर भुगतान की स्थिति को अपडेट नहीं किया गया था। सत्यापन पर, प्रस्तुत ट्रेजरी रसीदों का पता लगाने के लिए गढ़ा हुआ पाया गया और ऑनलाइन पता नहीं लगाया जा सका। मुद्दे को उठाए जाने के बाद, वर्ष 2021 और उसके बाद के भुगतान अंततः जुलाई और अगस्त 2024 में किए गए थे। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि आहरित अग्रिम वास्तविक देय कर से अधिक बढ़ा दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 2024 में 0.02 करोड़ रुपये की वसूली हुई।**
- (ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है। केंद्र सरकार के साथ।
- (ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत नहीं मिली है।



K C TAK & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS



- (xii) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए आदेश का पैरा 3 के खंड 3 (xxi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए आदेश का पैरा 3 के खंड 3 (xxi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए आदेश का पैरा 3 के खंड 3 (xxi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और धारा 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और ऐसे लेनदेन का विवरण लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- (xiv) (क) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है;
- (ख) हां, ऑडिट के तहत अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर हमारे द्वारा विचार किया गया था;
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xv) लागू नहीं है।
- (xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (xvi) लागू नहीं है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकरण की आवश्यकता वाली कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।
- हालांकि, कंपनी ने अपनी कर्मचारी कल्याण पहल के हिस्से के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम के तहत कुछ कर्मचारियों को आवास ऋण दिया है। ये अग्रिम व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में उधार देने की प्रकृति में नहीं हैं और इसलिए गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों के दायरे में नहीं आते हैं।
- (ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है।
- (घ) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है और न ही इसके पास एक से अधिक सीआईसी हैं।
- (xvii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद नुकसान नहीं हुआ है।
- (xviii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं है।



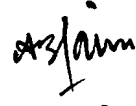
- (xix) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी के आधार पर, ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है;
- (xx) वर्ष के दौरान, कंपनी के पास चल रही और चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य दोनों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार कोई अव्ययित राशि नहीं थी। तदनुसार, धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में, या उक्त अधिनियम की धारा 135(6) के अनुपालन में किसी विशेष खाते में वित्तीय वर्ष के अंत से छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में कोई राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।
- (xxi) यह खंड लागू नहीं है।

के सी टाक एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म का पंजीकरण संख्या: 000216C

स्थान: राँची
दिनांक: 30/04/2025


सीए अनिल जैन
साझेदार
मोबाइल नं.: 079005
यूडीआईएन: 25079005BMOKCP8577



K C TAK & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS



अनुलग्नक - "ग" 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ 3 (एच) में संदर्भित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि;

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च 2025 तक 'सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड' ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संयोजन में है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना शामिल है। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना गया। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, उस जोखिम का आकलन करना जो एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।



हमारा मानना है कि हमने लेखापरीक्षा के जो साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि शर्तों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

अभिमत

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।

हालांकि, इसमें और सुधार की आवश्यकता है i) कंपनी के जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का प्रलेखन, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों का जोखिम विश्लेषण और बीमा कवरेज के संबंध में जोखिम शमन सहित विभागीय स्तरों पर प्रक्रिया प्रवाह को शामिल करना, ii) विविध व्यय के संबंध में नियंत्रणों की निगरानी को मजबूत करना, iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य चालू और गैर-चालू परिसंपत्तियों, व्यापार देय और प्राप्य, अन्य वित्तीय देनदारियों और अन्य वर्तमान और गैर-वर्तमान देनदारियों की पुष्टि/समाधान/समायोजन।



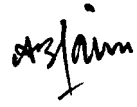
K C TAK & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS



उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

के सी टाक एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म का पंजीकरण संख्या: 000216C

स्थान: राँची
दिनांक: 30/04/2025


सीए अनिल जैन
साझेदार
मोबाइल नं.: 079005
यूडीआईएन: 25079005BMOKCP8577

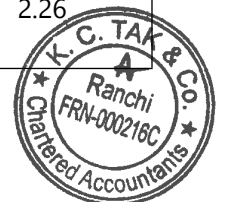




31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ '2' में संदर्भित **अनुलग्नक-"ख"** के खंड **vii** में संदर्भित **परिशिष्ट-"1"**।

31.03.2025 तक विवादित वैधानिक देनदारियों का विवरण

क्रानून की प्रकृति	बकाया राशि की प्रकृति	मंच जहां विवाद लंबित है	लंबित अवधि जिससे राशि संबंधित है	राशि (₹ करोड़ में)	विरोध स्वरूप भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में)
आयकर अधिनियम, 1961	पूर्व अवधि के व्यय की अस्वीकृतियाँ।	सीआईटी(ए)	वित्तीय वर्ष 2010-2011	1.05	0.59
आयकर अधिनियम, 1961	सीएसआर, चिकित्सा व्यय और परिसंपत्ति की बिक्री से लाभ की अस्वीकृतियाँ।	सीआईटी(ए)	वित्तीय वर्ष 2012-2013	0.33	-
आयकर अधिनियम, 1961	सीएसआर, एनसीडब्ल्यू के लिए प्रावधान, चिकित्सा व्यय, अनुदान, कैंटीन, क्रेच और अन्य कर्मचारी लाभ की अस्वीकृतियाँ।	सीआईटी(ए)	वित्तीय वर्ष 2017-2018	31.67	25.12
आयकर अधिनियम, 1961	एनसीडब्ल्यू, अधिकारी वेतन संशोधन, चिकित्सा व्यय, स्कूल और संस्थानों को अनुदान, खेल और मनोरंजन जैसे कर्मचारी लाभ व्यय की अस्वीकृतियाँ।	सीआईटी(ए)	वित्तीय वर्ष 2018-2019	55.02	32.44
आयकर अधिनियम, 1961	क्लब की सदस्यता, फंड और ग्रेच्युटी के प्रावधान के लिए सदस्यता की अस्वीकृतियाँ।	सीआईटी(ए)	वित्तीय वर्ष 2019-2020	0.02	-
आयकर अधिनियम, 1961	आकस्मिकता, निधि और ग्रेच्युटी के प्रावधान की अस्वीकृतियाँ।	सीआईटी(ए)	वित्तीय वर्ष 2020-2021	25.69	19.13
आयकर अधिनियम, 1961	बोनस या कमीशन, छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी, धारा 43बी के तहत पीएफ और मूल्यहास का व्यय की अस्वीकृतियाँ।	सीआईटी(ए)	वित्तीय वर्ष 2021-2022	7.38	5.73
आयकर अधिनियम, 1961	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए ₹8,06,00,000.00 (आठ करोड़ छह लाख रुपये) के प्रावधान को अस्वीकार करना।	सीआईटी(ए)	वित्तीय वर्ष 2022-23	2.03	
आयकर अधिनियम, 1961	सेवा कर ब्याज और दंड के बकाया की मांग।	झारखंड उच्च न्यायालय	वित्तीय वर्ष 1999-2005	5.05	5.05
आयकर अधिनियम, 1961	सेवा कर की मांग।	झारखंड उच्च न्यायालय	वित्तीय वर्ष 1998-1999	3.82	-
आयकर अधिनियम, 1961	सेवा कर और दंड की मांग।	सीईएसटीएटी	वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18	60.16	2.26



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर

मुख्य मामले	प्रबंध का टिप्पणी
क) अधिकांश मामलों में ऋणों के शेष (टिप्पणी संख्या 4.2), अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी संख्या 4.6), अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी संख्या 6.2), अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी संख्या 6.1), व्यापार देयताएँ (टिप्पणी संख्या 8.3), व्यापार प्राप्य (टिप्पणी संख्या 4.3), अन्य वित्तीय देनदारियाँ (टिप्पणी संख्या 8.4) और अन्य चालू देनदारियाँ (टिप्पणी संख्या 10.2) की पुष्टि नहीं की गई है। इनमें पिछले कई वर्षों से लेखा पुस्तकों में अंतिम समायोजन/समायोजन हेतु लंबित पुरानी शेष राशियाँ भी शामिल हैं। ऐसी शेष राशियों की पुष्टि/समाधान/समायोजन पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में ज्ञात नहीं है।	नोट 4.2 के मामले में, यह दो कर्मचारियों (अनामिका सिंह और शशांक शरण) के एचबीए ऋण को दर्शाता है, जिन्हें सीआईएल से अंतर-सहायक कंपनी में स्थानांतरण पर स्थानांतरित किया गया है। नोट 4.3 के मामले में, व्यापार प्राप्य - शेष राशि की पुष्टि के लिए सभी देनदारों को पत्र भेजे गए थे। सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों ने 31.03.2025 तक शेष राशि की पुष्टि कर दी है। नोट 4.6 के मामले में, 179.22 करोड़ रुपये के कुल शेष में से, 61.58 करोड़ रुपये सीआईएल के साथ चालू खाता लेनदेन को दर्शाता है। इस राशि का सीआईएल द्वारा पहले ही मिलान और सहमति हो चुकी है। भारतीय लेखा परीक्षा मानक 115 से 69.90 करोड़ रुपये प्राप्य हैं, जिसके लिए किसी पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, 47.74 करोड़ रुपये की शेष राशि अर्जित ब्याज/भुगतान की गई सुरक्षा जमा/प्राप्ति योग्य दावे आदि को दर्शाती है। ऐसी राशि के लिए पुष्टिकरण प्राप्त करने की कोई प्रथा नहीं रही है। व्यापारिक देनदारियों, अन्य चालू एवं गैर-चालू परिसंपत्तियों के मामले में, शेष राशि की पुष्टि हेतु संबंधित घरेलू विक्रेता/लेनदारों/देनदारों को सामान्य पत्र/मेल पहले ही भेजे जा चुके हैं। कुछ पक्षों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं।
क) यह देखा गया कि देनदारों में सीआईएल की सहायक कंपनियों के विरुद्ध 72.03 करोड़ रुपये (वार्षिक वर्ष 65.71 करोड़ रुपये) के पुराने बकाया शेष शामिल हैं, जो 1 वर्ष से अधिक समय से वसूली के लिए लंबित हैं। सीआईएल द्वारा जारी परिपत्र संख्या सीआईएल/डीटी/2021/3093 के अनुसार; i) बिल मूल्य की मूल राशि का 70% और उस पर 18% जीएसटी (अर्थात्, कुल बिल मूल्य का कुल 75%) का भुगतान सहायक कंपनियों द्वारा बिल प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर सीएमपीडीआई को किया जाना है; ii) भविष्य में बिल समाधान एक पोर्टल के माध्यम से होगा और सीएमपीडीआई पोर्टल पर कार्रवाई की सूचना देगा और सहायक कंपनियों के साथ संवाद करेगा;	सीएमपीडीआईएल द्वारा बिक्री पोर्टल विकसित किया गया है और मुख्यालय के साथ-साथ सभी सहायक कंपनियों के क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा नियमित रूप से उक्त पोर्टल पर बिल अपलोड किए जा रहे हैं। हालाँकि, बीसीसीएल, एनसीएल और एमसीएल द्वारा बिलों को डाउनलोड करने और संसाधित करने के लिए उक्त पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, शेष सहायक कंपनियों के लिए भी संबंधित सहायक कंपनियों के अनुरोध पर बिल भौतिक प्रतियों में या ईमेल या ई-ऑफिस के माध्यम से जमा किए जा रहे हैं। सीएमपीडीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के उच्चतम स्तर पर बकाया राशि की वसूली के लिए नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

मुख्य मामले	प्रबंध का टिप्पणी
iii) एक वर्ष से अधिक समय से बकाया बिलों की समीक्षा सीएमपीडीआई और संबंधित सहायक कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। हालाँकि, हमारे लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि सहायक कंपनियों को दिए गए बिलों की वसूली सीआईएल द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार नहीं की जा रही है। ऐसे शेषों की पुष्टि/समाधान/समायोजन पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में पता लगाने योग्य नहीं है।	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीएमपीडीआईएल ने सभी सहयोगी कम्पनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और निदेशक (तकनीकी), सीआईएल को ई-ऑफिस दिनांक 14.07.2022/25.07.2022 के माध्यम से कुल बिल मूल्य का 75% अग्रिम भुगतान करने के लिए सूचित किया है, जैसा कि सीआईएल द्वारा कार्यालय आदेश संदर्भ संख्या : CIL/DT/2021/3093 के तहत निर्देश दिया गया है। इस प्रकार, सीएमपीडीआईएल द्वारा सभी सहायक कंपनियों से नियमित अंतराल पर परिपत्र के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई का अनुरोध किया जा रहा है और उम्मीद है कि सहायक कंपनियों द्वारा जल्द से जल्द इसका पालन किया जाएगा।
(ख) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) के तहत गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में भारत सरकार/सीआईएल से प्राप्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास अनुदान/निधि से खरीदी गई गैर-वर्तमान संपत्ति शामिल है। दिनांक 31.03.2025 तक, इन निधियों से खरीदी गई 327 परिसंपत्तियों (संयंत्र और उपकरणों) का अवशिष्ट मूल्य (डब्ल्यूडीवी) 7.33 करोड़ रुपये था। यह देखा गया कि 327 परिसंपत्तियों में से 1.81 करोड़ रुपये मूल्य की 217 परिसंपत्तियों का जीवन 15 वर्ष से अधिक था और इसे 50 वर्ष (1975 से) तक बढ़ाया गया था। भारतीय लेखा मानक-16 के पैरा 16 के अनुसार कहा गया है कि पीपीई की किसी वस्तु की लागत को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी यदि, और केवल यदि: (क) यह संभव है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई में प्रवाहित होंगे; और (ख) वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। इसके अलावा, पीपीई की एक वस्तु को निपटान पर या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से गैर-भविष्य के आर्थिक लाभों की उम्मीद की जाती है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संयंत्र और उपकरण परिसंपत्तियों के तहत किसी भी संपत्ति के अधिकतम उपयोगी जीवन को 15 वर्ष के रूप में मानती है, इसलिए, 15 वर्ष या उससे अधिक की संपत्ति का उपयोगी जीवन पहले ही समाप्त हो चुका है और इन परिसंपत्तियों को पूंजी आरक्षित खाते में ले जाने की आवश्यकता है जिसमें निधि/अनुदान बनाए रखा जाता है। हालांकि, सीएमपीडीआईएल प्रबंधन ने बताया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास परिसंपत्तियों का स्वामित्व कोयला और सीआईएल मंत्रालय के पास है। सीएमपीडीआईएल एक कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते कोयला मंत्रालय/सीआईएल की पूर्व	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) और अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) परिसंपत्तियों का स्वामित्व कोयला मंत्रालय (एमओसी) और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के पास है। कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, सीएमपीडीआईएल के पास कोयला मंत्रालय/सीआईएल से पूर्व अनुमोदन के बिना इन परिसंपत्तियों के निपटान (सर्वेक्षण-बंद) को स्वतंत्र रूप से शुरू करने का अधिकार नहीं है। सीएमपीडीआईएल ने इस मामले को औपचारिक रूप से दोनों संस्थाओं (कोयला मंत्रालय/सीआईएल) को सूचित किया है, जिसमें उनसे परिसंपत्ति निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाने और सीएमपीडीआईएल को एक अपडेट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। सीएमपीडीआईएल प्रबंधन से अनुस्मारकों के बावजूद, इन परिसंपत्तियों के निपटान के संबंध में कोयला मंत्रालय और सीआईएल से आधिकारिक निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। नतीजतन, सीएमपीडीआईएल वर्तमान में कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं और सीआईएल द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के तहत प्राप्त परिसंपत्तियों के निपटान के लिए आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा है।

अन्य मामले	प्रबंध का टिप्पणी
अनुमति के बिना अपने दम पर सर्वेक्षण-बंद पहल नहीं कर सकता है और उन्होंने कोयला मंत्रालय और सीआईएल को मामले को सूचित किया है, उनसे परिसंपत्ति निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाने और सीएमपीडीआईएल को एक अपडेट प्रदान करने का अनुरोध किया है। सीएमपीडीआईएल प्रबंधन से अनुस्मारक के बावजूद, अब तक, इन परिसंपत्तियों के निपटान के संबंध में कोयला मंत्रालय और सीआईएल के निर्देश अभी भी लंबित हैं। इस स्थिति को देखते हुए, सीएमपीडीआईएल प्रबंधन एमओसी और सीआईएल द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास द्वारा वित्त पोषित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के तहत खरीदी गई परिसंपत्तियों के निपटान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने के लिए एमओसी और सीआईएल से आगे संचार की प्रतीक्षा कर रहा है। उपरोक्त के मद्देनजर, पुरानी परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना, जिनकी संपत्ति का उपयोगी जीवन 15 वर्ष या उससे अधिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित है और 1.81 करोड़ रुपये के लिए गैर-वर्तमान संपत्ति और पूंजी भंडार में समायोजन, चालू वित्त वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।	कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा वित्त पोषित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के तहत खरीदी गई परिसंपत्तियों के निपटान के मामले के जवाब में, यह उल्लेख करना है कि इस मुद्दे की विस्तार से जांच करने के लिए सीएमपीडीआईएल में एक समिति का विधिवत गठन किया गया है। समिति को ऐसी परिसंपत्तियों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने और कोयला मंत्रालय और सीआईएल से आधिकारिक निर्देश प्राप्त करने के अधीन उनके निपटान के लिए उचित सिफारिशें तैयार करने का काम सौंपा गया है।
(ग) हमने देखा कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के साथ कंपनी का चालू खाता वर्ष के अंत में 61.58 करोड़ रुपये के डेबिट शेष को दर्शाता है, जिसमें से 60.58 करोड़ रुपये पूर्व वर्षों से संबंधित हैं और आगे बढ़ाया गया है। यह शेष राशि कथित तौर पर सीआईएल के साथ बिक्री लेनदेन से संबंधित है। हालांकि, प्रबंधन लेनदेन को प्रमाणित करने या इस शेष राशि की प्राप्ति न होने के कारणों को समझाने के लिए विशिष्ट विवरण या दस्तावेज प्रदान करने में असमर्थ था। बकाया राशि की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए सीआईएल से कोई समाधान विवरण या खाते की पुष्टि प्रस्तुत नहीं की गई है। पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के अभाव में, हम शेष राशि की सटीकता और वसूली को सत्यापित करने में असमर्थ हैं। नतीजतन, हम वित्तीय विवरणों में आवश्यक संभावित समायोजन, यदि कोई हो, और कंपनी की वित्तीय स्थिति पर उनके प्रभाव का पता लगाने में भी असमर्थ हैं।	इस खाते में वृद्धि को जनवरी-2025 से रोक दिया गया है क्योंकि सीआईएल अपना भुगतान सीधे सीएमपीडीआईएल बैंक खाते में जमा कर रहा है। इसके अलावा, सीएमपीडीआईएल प्रबंधन जल्द से जल्द सीसी खाते में दिखाई देने वाली सभी बकाया राशि की वसूली के लिए सीआईएल के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

अन्य मामले	प्रबंध का टिप्पणी
(घ) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, क्षेत्रीय संस्थान-7 में पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) लेजर, विशेष रूप से एयूसी भवन खाता (परिसंपत्ति कोड: 20101030) की पुष्टि करते हुए, हमने देखा कि गोपालपुर शिविर के लिए लखनपुर में आवासीय भवनों के निर्माण से संबंधित समापन शेष में 0.14 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। । सहायक दस्तावेजों के प्रबंधन और समीक्षा के साथ चर्चा के आधार पर, यह नोट किया गया था कि निविदा जारी करने और मिट्टी परीक्षण, सर्वेक्षण और वन भूमि मंजूरी की ओर प्रारंभिक लागत वहन करने के बाद कंपनी द्वारा परियोजना को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया है। भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार – (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की वहन राशि को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के किसी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस (सीडब्ल्यूआईपी) आमतौर पर उन परिसंपत्तियों पर खर्च की गई लागत का प्रतिनिधित्व करता है जो निर्माणाधीन हैं और भविष्य के आर्थिक लाभों के परिणामस्वरूप होने की उम्मीद है। वर्तमान मामले में, चूंकि परियोजना को बंद कर दिया गया है और इसके पुनरुद्धार की कोई संभावना नहीं है, ऐसे व्यय का निरंतर पूंजीकरण भारतीय लेखा मानक 16 के अनुपालन में नहीं है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि 01.11.2024 को आयोजित एफडी समिति की 24वीं बैठक में मामला प्रस्तुत किया गया था और मामला टीओसी में लंबित है। इसे अनुमोदन के लिए अगली सीओएफडीएस बैठक में रखा जाएगा। इस तरह के अनुमोदन के लंबित होने पर, अंतिम परिणाम पर परिणामी प्रभाव वर्तमान में पता लगाने योग्य नहीं है।	लखनपुर शिविर में आवासीय भवन के लिए क्षेत्रीय संस्थान-7 से संबंधित हमारी पुस्तकों में वर्तमान में पूंजी डब्ल्यूआईपी में 0.14 करोड़ रुपये का उपरोक्त व्यय किया गया है, जिसकी अब आवश्यकता नहीं है और हमें अपनी पुस्तकों से बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता है। खारिज करने का प्रस्ताव सीओएफडी में फिर से रखा गया है और सीओएफडी के अनुमोदन के बाद ही इसे खारिज करने के लिए बोर्ड में रखा जा सकता है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक "ए" के लिए प्रबंधन की टिप्पणी।

निदेश	लेखापरीक्षा का उत्तर	प्रबंधन का उत्तर
1) क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ खातों की अखंडता पर आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का निहितार्थ बताया जा सकता है।	सभी भौतिक लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है और सभी अंतर्निहित व्यावसायिक लेनदेन की रिकॉर्डिंग इसके एसएपी-ईआरपी सॉफ्टवेयर में की जाती है। तदनुसार, खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूचना/ डेटा विभिन्न मॉड्यूलों से बह रहा है और वित्तीय लेखांकन और नियंत्रण (एफआईसीओ), बिक्री और वितरण (एस एंड डी), सामग्री प्रबंधन (एमएम), मानव पूंजी प्रबंधन (एचसीएम), उत्पादन योजना (पीपी), परियोजना प्रणाली (पीएस) और संयंत्र रखरखाव (पीएम) जैसी प्रक्रियाओं के लिए एसएपी के तहत स्वचालन के माध्यम से वित्तीय में कैप्चर किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2022 को स्थिरीकरण चरण के पूरा होने के बाद, सिस्टम एएमसी चरण के तहत है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि, एसएपी के बाहर निम्नलिखित गतिविधियां की जाती हैं: वर्तमान वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में एसएपी में बैलेंस शीट (बीएस) और लाभ और हानि (पीएंडएल) खातों की तैयारी शामिल है। हालांकि, त्रैमासिक/वार्षिक खातों की प्रस्तुति के लिए, एसएपी से प्राप्त प्रत्येक फुटनोट को मैनुअल रूप से एक अलग एक्सेल प्रारूप में संकलित किया जाता है। यह भारतीय लेखा मानक और कंपनी अधिनियम की अनुसूची-III की प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, खातों के लिए पूरक नोटों का निर्माण वर्तमान में एक शब्द दस्तावेज़ में की गई एक मैनुअल प्रक्रिया है। एसएपी के बाहर की गई गतिविधियों के संबंध में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, हमारी राय में कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव नहीं है।	वित्तीय विवरणों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

निदेश	लेखापरीक्षा का उत्तर	प्रबंधन का उत्तर
2) क्या मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं। कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को एक ऋणदाता द्वारा बनाया गया? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, मौजूदा ऋण के किसी भी पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामलों का कोई मामला नहीं है। कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को एक ऋणदाता द्वारा बनाया गया।	आगे कोई टिप्पणी नहीं।
3) क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित किया गया था/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भाग-II के खंड 2 और 3 में उल्लिखित विस्तृत और प्रचार ड्रिलिंग, आरएंडडी और एसएंडटी और एनएमईटी के अलावा कोई भी निधि/अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है / प्राप्त नहीं हुआ है - अतिरिक्त निर्देश (अनुलग्नक - 'क')।	आगे कोई टिप्पणी नहीं।

भाग-II नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अतिरिक्त निदेश

निदेश	लेखापरीक्षा का उत्तर	प्रबंधन का उत्तर
1) क्या कोलनेट पोर्टल से एसएपी तक डेटा की माइग्रेशन प्रक्रिया का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन और प्रमाणन किया गया था।	हां, वर्ष के दौरान कोलनेट पोर्टल से एसएपी सिस्टम तक डेटा माइग्रेशन प्रक्रिया का एक स्वतंत्र मूल्यांकन और प्रमाणन किया गया था। बाहरी सेवा प्रदाता, अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) द्वारा विभिन्न कार्यात्मक डोमेन को कवर करते हुए एक डेटा माइग्रेशन ऑडिट रिपोर्ट जारी की गई थी। ईवाई की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए डेटा माइग्रेशन को मान्य और प्रमाणित किया गया था। मानव पूंजी प्रबंधन (एचसीएम) डोमेन के भीतर, कर्मचारी मास्टर डेटा के लिए 99.63% और कर्मचारी मास्टर मॉड्यूल रिपोर्ट के लिए 85.33% तक समाधान प्राप्त किया गया था। हालांकि, एचसीएम के तहत कुछ मॉड्यूल-अर्थात् ऋण मास्टर, एलआईसी मास्टर, और वेतन मास्टर- कोलनेट सिस्टम से अपेक्षित स्रोत डेटा की अनुपलब्धता के कारण पूरी तरह से मिलान या मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। नतीजतन, ईवाई इन विशिष्ट मॉड्यूल के लिए डेटा माइग्रेशन की सटीकता और पूर्णता को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने में असमर्थ था।	आगे कोई टिप्पणी नहीं।

निदेश	लेखापरीक्षा का उत्तर	प्रबंधन का उत्तर
2) क्या एमओयू के अनुपालन में कोयला ब्लॉकों की खोज पूरी की गई थी और विस्तृत और प्रचार ड्रिलिंग के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग किया गया था और ठीक से हिसाब लगाया गया था। विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीएमपीडीआई और एमओसी / सीआईएल/ एनएमईटी के बीच कोई समझौता ज्ञापन नहीं है। सीएमपीडीआई देश में कोयले और लिग्नाइट की खोज से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए नोडल एजेंसी है। सीएमपीडीआई एमओसी / सीआईएल/ एनएमईटी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित परियोजना / ब्लॉकों के अनुसार या तो स्वयं या एमईसीएल और निजी पार्टियों के साथ समझौतों के अनुसार विस्तृत और प्रचार ड्रिलिंग की गतिविधियों को करता है। परीक्षण जांच के आधार पर नमूनों की हमारी जांच के आधार पर, यह देखा गया कि एमईसीएल और निजी पक्षों के साथ किए गए समझौतों के अनुपालन में ब्लॉकों की खोज पूरी की गई थी और विस्तृत और प्रचार ड्रिलिंग के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग किया जा रहा है और ठीक से हिसाब लगाया जा रहा है।	आगे कोई टिप्पणी नहीं।
3) क्या आरएंडडी और एसएंडटी परियोजनाओं के लिए प्राप्त निधियों को नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित किया गया था/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसी / संस्थान द्वारा सीएमपीडीआई को प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर कुछ नियमों और शर्तों के साथ एमओसी / सीआईएल की तकनीकी समिति द्वारा आर एंड डी और एस एंड टी परियोजनाओं को अनुमोदित / स्वीकृत किया जाता है। सीएमपीडीआई सभी चल रही या नई आरएंडडी/एसएंडटी परियोजनाओं के लिए निधि की आवश्यकता का अनुमान लगाता है और एमओसी/सीआईएल से एक समेकित मांग करता है। एक बार निधि प्राप्त होने के बाद, सीएमपीडीआई परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर विभिन्न किशतों में कार्यान्वयन एजेंसी/ संस्थान को निधि वितरित करता है। एक बार जब परियोजना पूरी हो जाती है और परियोजना पूर्णता रिपोर्ट तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित हो जाती है, तो कार्यान्वयन एजेंसी/संस्थान सीएमपीडीआई को उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं और ऐसी परियोजनाओं पर प्राप्त निधि की अव्ययित राशि को सीएमपीडीआई को उन निधियों पर अर्जित ब्याज के साथ वापस कर देते हैं।	एक एमआईएस बनाए रखा जा रहा है जिसमें परियोजना शीर्षक, कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम, शुरुआत की तारीख, पूरा होने की तारीख, परियोजना उद्देश्य, कुल स्वीकृत लागत आदि के बारे में जानकारी भी शामिल है, परियोजना की अवधि का विस्तार आदि परियोजना विशिष्ट फाइलों में बनाए रखा जाता है। एक समर्पित वेबसाइट (https://scienceandtech.cmpdi.co.in) भी विकसित की गई है जिसमें चल रही और पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाओं के बारे में विवरण शामिल है। एमआईएस में लेखापरीक्षित विवरण और ब्याज अर्जित विवरण शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

निदेश	लेखापरीक्षा का उत्तर	प्रबंधन का उत्तर
	परीक्षण-जांच के आधार पर चयनित नमूनों की हमारी जांच के आधार पर, यह देखा गया कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के आर एंड डी फंड और कोयला मंत्रालय (एमओसी) के एस एंड टी फंड के तहत प्राप्त धन सामान्य रूप से, संबंधित परियोजना अनुमोदन में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ठीक से हिसाब और उपयोग किया गया था। हालांकि, 2021 में कोयला मंत्रालय द्वारा जारी "अनुसंधान परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देशों" से कुछ विचलन को नोट किया गया था, जैसा कि नीचे संक्षेप में दिया गया है: • प्रत्येक व्यक्तिगत परियोजना के लिए अलग बैंक खाते बनाए रखें; • परियोजना पूरा होने पर लागू ब्याज के साथ परियोजना निधियों का कोई अप्रयुक्त शेष वापसी; • संवितरण की तारीख से परियोजना निधियों पर अर्जित ब्याज की रिपोर्ट करें; और • या तो बाद की फंड किशतों के खिलाफ रिपोर्ट किए गए ब्याज को समायोजित करें या परियोजना के अंत में कोयला मंत्रालय को आगे ऋण के लिए इसे सीएमपीडीआई को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देश गैर-ब्याज वाले खातों में परियोजना निधियों की पार्किंग को प्रतिबंधित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी सार्वजनिक धन उत्पादक रूप से रखे जाते हैं और पारदर्शी रूप से प्रबंधित किए जाते हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्ष: लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि प्रबंधन ने विभिन्न बैंक खातों में रखी गई निधियों पर अर्जित ब्याज के संबंध में उचित दस्तावेजीकरण नहीं किया है। यह चूक वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता और सटीकता को कमजोर करती है, विशेष रूप से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधि प्रबंधन के संबंध में। प्रमुख टिप्पणियों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:	सूचीबद्ध लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर इस प्रकार है: 1. परियोजना अनुमोदन के बाद, सीएमपीडीआई द्वारा बैंक जनादेश के रूप में बैंक खाते की जानकारी इस शर्त के साथ मांगी जाती है कि यह एक ब्याज कमाने वाला खाता होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के बाद, विक्रेता पंजीकरण सीआईएल के एसएपी प्लेटफॉर्म में किया जाता है। धन केवल उन खातों में स्थानांतरित किया जा रहा है, जो सीएमपीडीआई के वित्त विभाग के माध्यम से सत्यापित हैं। 2. 3. और 5. प्रत्येक संस्थान परियोजना के पूरा होने के बाद अपने नामित वित्त अधिकारी के माध्यम से अपने बैंक खाते में रखी गई परियोजना निधि पर अर्जित ब्याज के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, संस्थानों/संगठनों का सामान्य बचत बैंक खाता विभिन्न स्रोतों से वित्तपोषण/अनुदान सहायता प्राप्त करता है और तार्किक कारणों से संस्थान द्वारा व्यक्तिगत परियोजना के लिए ब्याज दिखाते हुए परियोजनावार बैंक खाता विवरण जारी नहीं किया जाता है। इसलिए, सीएमपीडीआई द्वारा संस्थान द्वारा अर्जित ब्याज के बारे में जानकारी के लिए संस्थान के वित्त अधिकारी के प्रमाणन पर विचार किया जाता है।

निदेश	लेखापरीक्षा का उत्तर	प्रबंधन का उत्तर
	- वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज के साथ-साथ प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा संचालित सभी बैंक खातों का विवरण देते हुए कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। यह ब्याज आय से वित्तीय प्रवाह की प्रभावी ट्रेकिंग को बाधित करता है। - परियोजना निधियों पर अर्जित ब्याज आय की न तो उचित गणना की गई और न ही दस्तावेजी साक्ष्य जैसे बैंक विवरण, ब्याज प्रमाण पत्र या समाधान के साथ पुष्टि की गई। यह रिपोर्ट किए गए ब्याज आंकड़ों की सटीकता के बारे में चिंता पैदा करता है। - व्यक्तिगत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अर्जित ब्याज आय की गणना न तो बैंक विवरण, ब्याज प्रमाण पत्र या अन्य वित्तीय रिकॉर्ड जैसे सत्यापन योग्य दस्तावेज के साथ साझा की गई थी और न ही समर्थित थी। यह रिपोर्ट किए गए आंकड़ों को स्वतंत्र रूप से मान्य करने की क्षमता को सीमित करता है। - यह दिखाने के लिए कोई स्पष्ट ऑडिट ट्रेल या सहायक रिकॉर्ड नहीं था कि अर्जित ब्याज को आगे फंड संवितरण के खिलाफ कैसे समायोजित किया गया था या परियोजना बंद होने पर फंड में वापस भेज दिया गया था। कई मामलों में, यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि इस तरह के ब्याज का उचित उपयोग किया गया था या वापस कर दिया गया था। - यह देखा गया कि कार्यान्वयन एजेंसियां परियोजना अवधि के दौरान परियोजना निधियों पर अर्जित ब्याज की रिपोर्ट नहीं कर रही हैं। नतीजतन, चल रही परियोजनाओं के लिए बाद की किश्तों को जारी करते समय अर्जित ब्याज पर विचार नहीं किया जा रहा है। इसके बजाय, ब्याज की पूरी राशि परियोजना के पूरा होने के समय ही समायोजित की जाती है।	- अर्जित ब्याज के साथ अव्ययित राशि वापस करने के लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को संचार भेजा जाता है। 8. 9. और 10. एसएंडटी और आरएंडडी परियोजनाओं के संबंध में, प्रत्येक संस्थान के नामित वित्त अधिकारी द्वारा प्रमाणित फॉर्म-III, IV और V में क्यूपीआर त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। और सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर निर्धारित प्रपत्रों में आवश्यक विवरण प्रदान करने के लिए संचार भेजा जाता है। प्रत्येक संस्थान अपने खाते का ऑडिट कराता है जिसमें सरकार द्वारा वैधानिक रूप से आवश्यक ब्याज अर्जित विवरण भी शामिल है। संस्थान आम तौर पर एक साथ महत्वपूर्ण संख्या में परियोजनाओं को संभालता है जो विभिन्न मंत्रालयों/ एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित होते हैं और संस्थानों द्वारा खातों की समग्र लेखापरीक्षा की जाती है। इसकी रिपोर्ट संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की गई है जो संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है।

निदेश	लेखापरीक्षा का उत्तर	प्रबंधन का उत्तर
	इस प्रथा के परिणामस्वरूप अर्जित ब्याज के लिए अंतरिम समायोजन के बिना स्वीकृत परियोजना निधियों का पूर्ण संवितरण होता है, जिससे परियोजना अवधि के दौरान धन की अतिरिक्त रिहाई हो सकती है। 6. ऐसे मामलों की पहचान की गई जहां पूरी की गई परियोजनाओं के संबंध में अप्रयुक्त परियोजना निधि वापस नहीं की गई थी, और कोई ब्याज रिपोर्ट या प्रेषित नहीं किया गया था - यहां तक कि उन मामलों में जहां पूरी संवितरित राशि का उपयोग करने का दावा किया गया था, हालांकि प्रबंधन द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी। नीचे दी गई निम्नलिखित तालिका- '1' में पहचान किए गए गैर-अनुपालन के मामलों का सारांश दिया गया है। 7. तिमाही प्रगति रिपोर्ट और व्यय विवरण प्रस्तुत न करना दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रधान कार्यान्वयन और उप-कार्यान्वयन एजेंसियों को मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और व्यय विवरण (फॉर्म III, IV और V) प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन्हें जांच के लिए प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद महीने की 15 तारीख तक सीएमपीडीआई को प्रस्तुत किया जाना है। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कार्यान्वयन एजेंसियां प्रबंधन द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, नियमित आधार पर आवश्यक तिमाही प्रगति रिपोर्ट और व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं कर रही हैं।	4. कार्यान्वयन एजेंसी ने फॉर्म- II (फंड की मांग) में ब्याज राशि का उल्लेख किया। उदाहरण के लिए: - स्वीकृत राशि: ₹200 (किसी विशेष परियोजना के लिए), पहले से ही संवितरित: ₹100 (सीएमपीडीआई द्वारा)। अब, कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) एक अवधि के लिए ₹100 बनाए रखती है। इस समय के दौरान, ₹2 अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज के रूप में अर्जित होता है। ऐसे मामलों में, इस ब्याज राशि (₹2) को अगली किस्त में समायोजित किया जाता है। इसलिए, पूर्ण शेष ₹100 को वितरित करने के बजाय, सीएमपीडीआई कार्यान्वयन एजेंसी को केवल ₹ 98 वितरित करता है।

निर्देश	लेखापरीक्षा का उत्तर	प्रबंधन का उत्तर
	8. फॉर्म VII जमा करने में देरी: दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना अवधि के विस्तार के लिए किसी भी अनुरोध को विधिवत हस्ताक्षरित और संस्था के प्रमुख या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, अधिमानतः परियोजना पूरा होने की निर्धारित तिथि से कम से कम दो महीने पहले। हालांकि, इस समयसीमा का पालन नहीं किया जा रहा है। लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि निम्नलिखित मामले में, परियोजना की निर्धारित पूर्णता तिथि के बाद विस्तार के लिए फॉर्म VII प्रस्तुत किया गया था, जो निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने का संकेत देता है। नीचे दी गई निम्नलिखित तालिका- '2' में पहचान किए गए गैर-अनुपालन के मामलों का सारांश दिया गया है।	
	9. लेखापरीक्षा आवश्यकताओं का गैर-अनुपालन: दिशानिर्देशों के अनुसार, यह प्रधान कार्यान्वयन और उप-कार्यान्वयन एजेंसी (एजेंसी) की जिम्मेदारी है कि वे एसएंडटी अनुदान से संबंधित खातों का नियमित रूप से ऑडिट करें और सीएमपीडीआई को लेखापरीक्षित विवरण की एक प्रति प्रस्तुत करें। हालांकि, यह देखा गया है कि कार्यान्वयन एजेंसियां आवश्यक लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत नहीं कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है। इसके अलावा, दिशानिर्देश यह भी निर्धारित करते हैं कि परियोजना पूर्णता रिपोर्ट के साथ एक लेखापरीक्षित व्यय विवरण या विधिवत प्रमाणित निधि उपयोग प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। यह नोट किया गया कि प्रबंधन द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजना पूर्णता रिपोर्ट के साथ ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।	

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक "ख" के लिए प्रबंधन की टिप्पणी।

अनुलग्नक "ख" का बिंदु संख्या (i) (ख)	प्रबंधन का उत्तर
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए रिकॉर्ड बनाए रखा है। हमें सूचित किया गया है कि प्रबंधन ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार उचित अंतराल पर अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है, और ऐसा सत्यापन विधिवत गठित टीम द्वारा किया गया था। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, इस तरह के सत्यापन के दौरान कोई भौतिक विसंगतियां नोट नहीं की गई थीं। हालांकि, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने देखा कि विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में परिसंपत्तियों की संख्या, जिनमें से कई को वित्तीय वर्ष 2000 से पहले पूंजीकृत किया गया था और व्यक्तिगत रूप से 100.00 रुपये से कम का अवशिष्ट/लिखित मूल्य है, को फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में दिखाया जाना जारी है। ये परिसंपत्तियां भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में दिखाई नहीं देती हैं और उपलब्ध जानकारी के आधार पर, अब अस्तित्व में या सक्रिय उपयोग में नहीं हो सकती हैं। यह इंगित करता है कि जबकि भौतिक सत्यापन किया गया है, अचल संपत्ति रजिस्टर को भौतिक सत्यापन परिणामों के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाया जा सकता है। हमारे विचार में, यह कुछ परिसंपत्तियों के अस्तित्व और निरंतर मान्यता के बारे में चिंता पैदा करता है, और सुझाव देता है कि कंपनी को भारतीय लेखा मानक 16 की आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसी वस्तुओं की अमान्यता के लिए एक विस्तृत मूल्यांकन करना चाहिए - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, विशेष रूप से जहां भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है।	लेखा परीक्षक द्वारा उल्लिखित मदों की अमान्यता का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा और आने वाले वित्तीय वर्ष में इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
अनुलग्नक "ख" का बिंदु संख्या (i) (ग)	प्रबंधन का उत्तर
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए जाते हैं) के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं। हालांकि, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने देखा कि भारत के राजपत्र दिनांक 14 अप्रैल 1979 (चैत्र 24, 1901) के अनुसार, केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान (सीएमपीडीआई) को कुछ अचल संपत्तियों के शीर्षक के साथ निहित किया गया था, जिसमें भूमि, कार्यालय और आवासीय भवन और परिसर शामिल थे जिन्हें लखीपुर और आसनसोल में कोयला बोर्ड कॉलोनी के रूप में जाना जाता है, जिसमें पंप हाउस, रेस्ट हाउस, कोल बोर्ड का कार्यालय और सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान-1 से संबंधित स्टाफ कॉलोनी शामिल है। उपरोक्त संपत्तियों के शीर्षक कर्मों को हमारे सत्यापन के लिए हमारे सामने पेश नहीं किया गया था। तदनुसार, हम इन अचल संपत्तियों के संबंध में शीर्षक की वैधता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	आगे कोई टिप्पणी नहीं।

अनुलग्नक "ख" का बिंदु संख्या (XI)	प्रबंधन का उत्तर
क) भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार की गई कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें न तो कंपनी द्वारा या उस पर धोखाधड़ी का कोई उदाहरण मिला है, वर्ष के दौरान देखा या रिपोर्ट किया गया, न ही हमें मल्लारपुर शिविर, क्षेत्रीय संस्थान -1 में सड़क कर भुगतान के मामले को छोड़कर प्रबंधन द्वारा ऐसे मामले के बारे में सूचित किया गया है, यह ध्यान दिया गया था कि 2021 से 5 नंबर के वाहन के लिए सड़क कर भुगतान के लिए अग्रिम तैयार किया गया था, जिसमें एक्सए अग्रिम को समायोजित करने के लिए प्रस्तुत ट्रेजरी रसीदें थीं। हालांकि, 2021 से परिवार की वेबसाइट पर कर भुगतान की स्थिति को अपडेट नहीं किया गया था। सत्यापन पर, प्रस्तुत ट्रेजरी रसीदों का पता लगाने के लिए गढ़ा हुआ पाया गया और ऑनलाइन पता नहीं लगाया जा सका। मुद्दे को उठाए जाने के बाद, वर्ष 2021 और उसके बाद के भुगतान अंततः जुलाई और अगस्त 2024 में किए गए थे। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि आहरित अग्रिम वास्तविक देय कर से अधिक बढ़ा दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 2024 में 0.02 करोड़ रुपये की वसूली हुई।	आगे कोई टिप्पणी नहीं।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 (एच) में संदर्भित अनुलग्नक "सी" के लिए प्रबंधन की टिप्पणी।

लेखापरीक्षक की राय	प्रबंधन का उत्तर
हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। 31 मार्च 2025, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर।	वर्तमान में उपलब्ध आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पहले से ही मजबूत और पर्याप्त है। सिस्टम में सभी आवश्यक दस्तावेजीकरण और जांच उपलब्ध हैं।
हालांकि, i) कंपनी की जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के जोखिम विश्लेषण और बीमा कवरेज के संबंध में जोखिम शमन सहित विभागीय स्तरों पर प्रक्रिया प्रवाह को शामिल करने, ii) विविध खर्चों के संबंध में नियंत्रण की निगरानी को मजबूत करने, iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की पुष्टि/समायोजन/समायोजन, अन्य वर्तमान और गैर-वर्तमान संपत्ति, व्यापार देय और प्राप्य, अन्य वित्तीय देनदारियों और अन्य वर्तमान और गैर-वर्तमान देनदारियों के संबंध में नियंत्रण की निगरानी को मजबूत करने के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के दस्तावेजीकरण में और सुधार की आवश्यकता है।	

परिशिष्ट - V

Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES

Ground Floor, 36 (179), Sukanta Sarani, Bhadrakali, Hoogly - 712232, West Bengal
Tel.: +91 9867771580, E-mail : raveena@mehta-mehta.com, Visit us : www.mehta-mehta.com
AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

फॉर्म एमआर - 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार}

सेवा में,

सदस्यगण,

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड

गोंडवाना प्लेस, कांके रोड

रांची, झारखंड- 834008

हमने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस प्रकार किया गया कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं, जो इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके अधीन बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन बनाए गए नियम (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम एवं उपनियम;



Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES

Ground Floor, 36 (179), Sukanta Sarani, Bhadrakali, Hoogly - 712232, West Bengal
Tel.: +91 9867771580, E-mail : raveena@mehta-mehta.com, Visit us : www.mehta-mehta.com
AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियम एवं विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-
- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**
 - (2) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;
 - (3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**
 - (4) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2021 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**
 - (5) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**
 - (6) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**
 - (7) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2021 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**
 - (8) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**



Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES

Ground Floor, 36 (179), Sukanta Sarani, Bhadrakali, Hoogly - 712232, West Bengal
Tel.: +91 9867771580, E-mail : raveena@mehta-mehta.com, Visit us : www.mehta-mehta.com
AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की जाँच की है:

- (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;
- (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- (iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2019, जैसा कि भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी और संशोधित किया गया है ('डीपीई दिशानिर्देश');
- (iv) कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून, अर्थात्:
 - 1) कोयला खान अधिनियम, 1952
 - 2) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884
 - 3) कोयला खान नियंत्रण आदेश, 2000 और कोयला खान नियंत्रण नियम, 2004
 - 4) कोयला खान विनियम, 2017
 - 5) मजदूरी भुगतान (खान) नियम, 1956
 - 6) कोयला खान पेंशन योजना, 1998
 - 7) कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम, 1974
 - 8) खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966
 - 9) खान क्रेच नियम, 1961
 - 10) खान बचाव नियम, 1985
 - 11) कोयला खान पिटहेड स्नान नियम, 1946
 - 12) मातृत्व लाभ (खान एवं सर्कस) नियम, 1963
 - 13) विस्फोटक नियम, 2008
 - 14) खनिज रियायत नियम, 2021
 - 15) कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
 - 16) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957
 - 17) असंवितरित मजदूरी भुगतान (खान) नियम, 1989
 - 18) भारतीय विद्वत् अधिनियम, 2003 और भारतीय विद्वत् नियम, 1956
 - 19) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986



Mehta & Mehta

COMPANY SECRETARIES

Ground Floor, 36 (179), Sukanta Sarani, Bhadrakali, Hoogly - 712232, West Bengal
Tel.: +91 9867771580, E-mail : raveena@mehta-mehta.com, Visit us : www.mehta-mehta.com

AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

- 20) खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016
- 21) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और उसके अधीन बनाए गए नियम
- 22) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- 23) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 और उसके अधीन बनाए गए नियम।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, **सिवाय** नीचे उल्लिखित सीमा के:

- 1) कंपनी के बोर्ड में न तो कोई महिला निदेशक थी जैसा कि अधिनियम की धारा 1(149) के तहत आवश्यक है और न ही कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या थी जैसा कि अधिनियम की धारा 4(149) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समीक्षाधीन अवधि के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 के तहत आवश्यक है, इसलिए अधिनियम की धारा 149 की अनुसूची VII के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक वित्तीय वर्ष 25-2024 के दौरान आयोजित नहीं की गई थी।
- 2) कंपनी की लेखा परीक्षा समिति के पास समीक्षाधीन अवधि के दौरान सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 और खंड 4.4 के तहत 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के लिए आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।
- 3) कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के पास समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के लिए अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।
- 4) कंपनी की पारिश्रमिक समिति में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी, जैसा कि सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के तहत अपेक्षित है, इसलिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति निष्क्रिय रही।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में सभी परिवर्तन, उपर्युक्त को छोड़कर, अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में किए गए थे।



Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES

Ground Floor, 36 (179), Sukanta Sarani, Bhadrakali, Hoogly - 712232, West Bengal
Tel.: +91 9867771580, E-mail : raveena@mehta-mehta.com, Visit us : www.mehta-mehta.com
AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यक्रम के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करती हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाईयां की हैं जिनका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है।

- 1) कंपनी ने 5 जुलाई, 2024 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-2023 के लिए %35.694 यानी 1000/- रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 356.9 रुपये यानी 50.97 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश घोषित किया।
- 2) कंपनी के निदेशक मंडल ने 20 अक्टूबर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 25-2024 के लिए %105.042 यानी 1050.42 रुपये प्रति 1000/- रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 150.00 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया।

मेहता एंड मेहता के लिए,

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई विशिष्ट कोड P1996MH007500)



रवीनार अग्रवाल

भागीदार

एसीएस संख्या: 51836 स्थान: कोलकाता

यूडीआईएन: A051836G000679573

सीपी संख्या: 26055 दिनांक: 30.06.2025

पीआर संख्या: 3686/2023



नोट: इस रिपोर्ट को हमारे सम संख्या दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना है, जो 'अनुलग्नक क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES

Ground Floor, 36 (179), Sukanta Sarani, Bhadrakali, Hoogly - 712232, West Bengal
Tel.: +91 9867771580, E-mail : raveena@mehta-mehta.com, Visit us : www.mehta-mehta.com
AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

अनुलग्नक 'क'

सेवा में,

सदस्यगण,

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड

गोंडवाना प्लेस, कांके रोड

रांची, झारखंड- 834008

इस पत्र के साथ हमारी सम तारीख की रिपोर्ट भी पढ़ी जाए।

- 1) सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।
- 2) हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा-परीक्षण पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
- 3) हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
- 4) जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
- 5) कॉर्पोरेट कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
- 6) फॉर्म एमआर-3 में हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी द्वारा दाखिल की गई पुस्तकों, कागजातों, प्रपत्रों, रिपोर्टों और रिटर्न के संबंध में, उक्त विनियमों की आवश्यकताओं का पालन और अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच, उक्त विनियमों के अंतर्गत कंपनी द्वारा विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष दाखिल किए जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों, रिपोर्टों, रिटर्न और दस्तावेजों के निष्पादन और समयबद्धता की जाँच तक सीमित थी। हमने ऐसे प्रपत्रों, रिपोर्टों, रिटर्न और दस्तावेजों की विषय-वस्तु की सत्यता और व्यापकता का सत्यापन नहीं किया है।

Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES

Ground Floor, 36 (179), Sukanta Sarani, Bhadrakali, Hoogly - 712232, West Bengal
Tel.: +91 9867771580, E-mail : raveena@mehta-mehta.com, Visit us : www.mehta-mehta.com
AUTHORISED AGENTS FOR TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT

- 7) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही यह कि प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन कितनी कुशलता या प्रभावशीलता से किया है।

मेहता एंड मेहता के लिए ,

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई विशिष्ट कोड P1996MH007500)



रवीना दुगर अग्रवाल

भागीदार

एसीएस संख्या: 51836

सीपी संख्या: 26055

पीआर संख्या: 3686/2023



स्थान: कोलकाता

दिनांक: 30-06-2025

यूडीआईएन: A051836G000679573

वित्तीय वर्ष 2024-25 की सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा उठाई गई टिप्पणियों के लिए प्रबंधन का उत्तर।

क्र.सं.	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1.	कंपनी के पास न तो अधिनियम की धारा 149(1) के तहत आवश्यक बोर्ड पर एक महिला निदेशक थी और न ही अधिनियम की धारा 149(4) और खंड 3.1.2 के तहत आवश्यक कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या थी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश इसलिए अधिनियम की धारा 149 की अनुसूची VII के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित नहीं की गई थी।	सीएमपीडीआईएल के बोर्ड में वर्तमान में एक महिला निदेशक सहित कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के खंड 31 (वाई) और खंड 31 (जेड) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार एक महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार है।
2.	कंपनी की लेखापरीक्षा समिति के पास समीक्षाधीन अवधि के दौरान सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 और खंड 4.4 के तहत आवश्यक 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।	कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के रूप में, स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति पूरी तरह से भारत सरकार के पास है। इस वैधानिक और प्रशासनिक ढांचे के कारण, कंपनी का ऐसी नियुक्तियों के लिए समय सीमा या प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीएमपीडीआईएल ने कोयला मंत्रालय के सचिव को विशेष रूप से मई 2024, जुलाई 2024, अक्टूबर 2024, जनवरी 2025 और मार्च 2025 के महीनों में, होलिंग कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड को चिह्नित प्रतियों के साथ बार-बार अनुरोध प्रस्तुत किए। इन संचारों ने कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में ऑडिट समिति, सीएसआर समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और अन्य उप-समितियों जैसी अनिवार्य बोर्ड समितियों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया। अंतरिम में, स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, इन समितियों को शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में निरंतरता बनाए रखने के लिए कार्यात्मक निदेशकों और अंशकालिक आधिकारिक निदेशकों के साथ अस्थायी रूप से पुनर्गठित किया गया है, ऐसी नियुक्तियों पर नियमितीकरण लंबित है।
3.	कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के पास समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत आवश्यक 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।	
4.	कंपनी की पारिश्रमिक समिति के पास सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी, इसलिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान निष्क्रिय रही।	

परिशिष्ट - VI

धारा 188 (1) के तहत संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था।

फॉर्म नंबर एओसी-2

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के लिए और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे परंतुक के तहत कुछ निश्चित लेन-देन भी शामिल हैं।

क्र.सं.	विवरण	स्पष्टीकरण
1.	अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण जो एक दूसरे से दूरी के आधार पर नहीं हैं	शून्य
क	संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	
ख	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की प्रकृति	
ग	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि	
घ	मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	
ड	ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	
च	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	
छ	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	
ज	वह तारीख जिस पर धारा 188 के पहले परंतुक के तहत आवश्यक सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था	
2.	एक दूसरे से दूरी के आधार पर सामग्री अनुबंधों या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण	अनुलग्नक - क के अनुसार
क	संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	
ख	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की प्रकृति	
ग	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि	
घ	मूल्य सहित अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो:	
ड	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि यदि कोई हो:	
च	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	

31.03.2025 को समूह के भीतर संबंधित पार्टि लेनदेन।

सरकार से संबंधित इकाई होने के नाते कंपनी को संबंधित पार्टि लेनदेन और नियंत्रण सरकारों और उसी सरकार के तहत किसी अन्य इकाई के साथ बकाया शेष के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं से छूट दी गई है।

भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार, एक ही प्रबंधन के तहत महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के बारे में प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं।

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान लेनदेन की राशि	लेनदेन की प्रकृति
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	173.33	बिक्री
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	88.22	बिक्री
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	193.47	बिक्री
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	265.81	बिक्री
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	542.7	बिक्री
नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	177.28	बिक्री
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	178.12	बिक्री
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (100% होल्डिंग कंपनी)	18.27	बिक्री
	200.97	लाभांश
सकल योग	1838.17	

परिशिष्ट - VII

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

No.CA/CCL/A_Acs/CMPDIL/2024-25/318

कार्यालय, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (कोयला),
पुराना निज़ाम महल, प्रथम तल,
234/4, ए.जे.सी. बोस रोड,
कोलकाता - 700 020



OFFICE OF THE PRINCIPAL
DIRECTOR OF AUDIT (COAL)
OLD NIZAM PALACE,
234/4, A.J.C. BOSE ROAD
KOLKATA - 700020

दिनांक / Date : 04 July 2025

गोपनीय

सेवा में
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड,
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड,
राँची, झारखण्ड - 834 031।

विषय: 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रसारित कर रहा हूँ।

कृपया इसकी प्राप्ति की सूचना अवगत कराया जाए।

आपका विश्वासी



(यशोधरा राय चौधरी)

महानिदेशक एवं एडीएआई)

कोलकाता

संलग्न: यथोक्त।

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 04 जुलाई, 2025

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। 30 अप्रैल 2025 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, उनके द्वारा ऐसा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का एक पूरक लेखापरीक्षा किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

अपने पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं:

क. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क.1 परिसंपत्तियाँ

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (टिप्पणी -3.1)

कंपनी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत, प्रत्यक्ष खरीद द्वारा और कंपनी के नाम पर निहित सरकारी भूमि के हस्तांतरण द्वारा भी फ्रीहोल्ड भूमि अर्जित की है। कोयला मंत्रालय ने (अप्रैल 2022) कोयला कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे पूर्ण स्वामी के रूप में कंपनी के नाम पर भूमि अभिलेखों का म्यूटेशन करवाएँ। सीएमपीडीआईएल के पास 81.72 एकड़ भूमि है जिसका म्यूटेशन नहीं किया गया है।

सीएमपीडीआईएल के नाम पर फ्रीहोल्ड भूमि के म्यूटेशन न होने के संबंध में उपरोक्त तथ्यों का वित्तीय विवरणों के नोट्स में खुलासा नहीं किया गया है। साथ ही, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश के अंतर्गत प्रकटीकरण भी उस सीमा तक अपूर्ण है।

क.2 वित्तीय जानकारी के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी 16) प्रतिबद्धताएं:

अन्य प्रतिबद्धताएं

सीएमपीडीआईएल ने 517.21 करोड़ के विभिन्न राजस्व संविदात्मक कार्यों के कारण निष्पादित की जाने वाली शेष राशि के बारे में विवरण का खुलासा नहीं किया है।

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर भारतीय लेखा मानक के पैराग्राफ 114 (घ) में कहा गया है कि एक इकाई अन्य बातों के साथ-साथ गैर-मान्यता प्राप्त संविदात्मक प्रतिबद्धताओं सहित अन्य प्रकटीकरण का खुलासा करेगी।

उपरोक्त तथ्यों के गैर-प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप भारतीय लेखा मानक -1 की प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के द्वारा



(यशोधरा राय चौधरी)
महानिदेशक एवं एडीएआई
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 04 जुलाई 2025

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सी&एजी के वित्तीय विवरणों द्वारा जारी अंतिम टिप्पणियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया

प्र.भा. सं.	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
1.	A. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ A.1 संपत्ति संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (टिप्पणी -3.1) कंपनी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, प्रत्यक्ष खरीद और सरकारी भूमि के हस्तांतरण के तहत फ्रीहोल्ड भूमि का अधिग्रहण किया जो कंपनी के नाम पर निहित है। कोयला मंत्रालय ने कोयला कंपनियों को कंपनी के नाम पर भूमि रिकॉर्ड को निरपेक्ष मालिक के रूप में उत्परिवर्तित करने का निर्देश (अप्रैल 2022) दिया। सीएमपीडीआईएल के पास 81.72 एकड़ भूमि है जिसके लिए उत्परिवर्तन नहीं किया गया है। सीएमपीडीआईएल के नाम पर फ्रीहोल्ड भूमि के गैर-उत्परिवर्तन के संबंध में उपरोक्त तथ्यों का वित्तीय विवरणों के नोट्स में खुलासा नहीं किया गया है। इसके अलावा, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश के तहत प्रकटीकरण भी उस सीमा तक कम है।	भूमि उत्परिवर्तन के बारे में जानकारी विशेष रूप से भारतीय लेखा मानक या कंपनी अधिनियम की अनुसूची-III के तहत प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, कंपनी ने भूमि के शीर्षक के संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण किया है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्य निर्देशों में टिप्पणी 4 (ii) के तहत व्यापक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कोई भी प्रकटीकरण किया जाना चाहिए कि "अत्यधिक विवरण प्रदान करने के बीच एक संतुलन बनाए रखा जाएगा जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की सहायता नहीं कर सकता है और बहुत अधिक एकत्रीकरण के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं कर सकता है।" वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्य निर्देशों में नोट 4 (ii) का प्रासंगिक उद्धरण यहां उद्धृत किया गया है "(ii) बैलेंस शीट के सामने प्रत्येक आइटम, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और लाभ और हानि का विवरण टिप्पणियों में किसी भी संबंधित जानकारी के लिए क्रॉस-रेफरेंस किया जाएगा। टिप्पणियों सहित वित्तीय विवरण तैयार करने में, अत्यधिक विवरण प्रदान करने के बीच एक संतुलन बनाए रखा जाएगा जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की सहायता नहीं कर सकता है और बहुत अधिक एकत्रीकरण के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं कर सकता है।" प्रक्रियात्मक अनुपालन के रूप में प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा आवश्यक भूमि के उत्परिवर्तन की स्थिति वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता में मूल्य नहीं जोड़ सकती है।

प्र.भा. सं.	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
	A.2 वित्तीय जानकारी के लिए अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी 16) प्रतिबद्धताएं: अन्य प्रतिबद्धताएं सीएमपीडीआईएल ने 517.21 करोड़ के विभिन्न राजस्व संविदात्मक कार्यों के कारण निष्पादित की जाने वाली शेष राशि के बारे में विवरण का खुलासा नहीं किया है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर भारतीय लेखा मानक के पैराग्राफ 114 (डी) में कहा गया है कि एक इकाई अन्य बातों के साथ-साथ गैर-मान्यता प्राप्त संविदात्मक प्रतिबद्धताओं सहित अन्य प्रकटीकरण का खुलासा करेगी। उपरोक्त तथ्यों के गैर-प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप भारतीय लेखा मानक -1 की प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई।	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुसार, विभिन्न प्रकार की प्रतिबद्धताओं के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें पूंजी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं जो शेयरों पर प्रदान नहीं की जाती हैं और अनधिकृत देयता शामिल है। इसके अतिरिक्त, अनुसूची विशेष रूप से वर्णित की जाने वाली ऐसी प्रतिबद्धताओं की प्रकृति के साथ अन्य प्रतिबद्धताओं के प्रकटीकरण को अनिवार्य करती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रभाग-II - भारतीय लेखा मानक अनुसूची-III पर मार्गदर्शन नोट के पैराग्राफ 8.2.14.6 में और स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है। इसमें कहा गया है: “तदनुसार, 'अन्य प्रतिबद्धताओं' के लिए किए जाने वाले आवश्यक प्रकटीकरण में केवल प्रबंधन के पेशेवर निर्णय के आधार पर गैर-रद्द करने योग्य संविदात्मक प्रतिबद्धताएं शामिल होनी चाहिए (अर्थात्, जिसके रद्द होने से इसमें शामिल लाभों से अधिक जुर्माना लगेगा), जो कंपनी के वित्तीय विवरणों को समझने में भौतिक और प्रासंगिक हैं और निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं। वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता। उदाहरणों में बाय-बैक व्यवस्था की प्रकृति में प्रतिबद्धताएं, सहायक कंपनियों और सहयोगियों को निधि देने के लिए प्रतिबद्धताएं, सहायक कंपनियों और उपक्रमों में निवेश का गैर-निपटान, डेरिवेटिव से संबंधित प्रतिबद्धताएं आदि शामिल हो सकती हैं। उपरोक्त के आलोक में, और सामान्य उद्योग अभ्यास के अनुरूप, 'अन्य प्रतिबद्धताओं' श्रेणी के तहत सामान्य राजस्व प्रतिबद्धताओं का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट - VIII

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

सीएमपीडीआईएल, डीपीई के नवीनतम दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करते हुए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएँ चला रहा है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में न्यूनतम अनिवार्य व्यय, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके संशोधनों के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के 2% के आधार पर आवंटित किया जाता है। सीएमपीडीआईएल की सीएसआर नीति इसकी वेबसाइट www.cmpdi.co.in पर अपलोड की गई है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशक पद की प्रकृति	इस वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	इस वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1.	श्री अजय कुमार (डीआईएन-09774347)	अध्यक्ष (30.10.2023 से 02.02.2025) /सदस्य	7	7
2.	श्री मारापल्ली वेंकटेश्वरलु (डीआईएन-10059799)	अध्यक्ष (03.02.2025 से प्रभावी)	1	1
3.	श्री सतीश झा (डीआईएन-10299809)	सदस्य	6	6
4.	श्री अच्युत घटक डीआईएन-08923591	सदस्य	6	6
5.	श्री शंकर नागाचारी (डीआईएन-09729657)	सदस्य	1	1

3. वेब-लिंक उपलब्ध कराएं जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हों।

सीएसआर समिति की संरचना	https://www.cmpdi.co.in/en/c-s-r
सीएसआर नीति	https://www.cmpdi.co.in/en/c-s-r
बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं	https://www.cmpdi.co.in/en/c-s-r

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का कार्यकारी सारांश वेब-लिंक के साथ उपलब्ध कराएं, यदि लागू हो।

कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार सीएमपीडीआईएल पर लागू नहीं।

5.

(रुपये करोड़ में)

क.	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।	489.0600
ख.	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत।	9.7812
ग.	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।	0.0057
घ.	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो।	2.7686
ङ.	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(बी)+(सी)-(डी)].	7.0182

6.

(रुपये करोड़ में)

क.	सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा अन्य दोनों)।	8.8814
ख.	प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि	0.4441
ग.	प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो।	शून्य
घ.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)].	9.3255

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (करोड़ रुपये में)	अव्ययित राशि (रु. में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि।		धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि।		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

(च) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपए करोड़ में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	9.7812
(ii)	*वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि।	12.0942
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	2.3130
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0.0057
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	2.3073

नोट:* इसमें पिछले वर्षों से 2.7686 करोड़ रुपये की अधिक राशि शामिल है।

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रु. में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो	आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹ में)	स्थानांतरण की तिथि	
1.	वित्त वर्ष 2023-24	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	वित्त वर्ष 2022-23	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	वित्त वर्ष 2021-22	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है: नहीं
9. यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं – लागू नहीं

ह०/-

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)

ह०/-

(सीएसआर समिति के अध्यक्ष)

वार्षिक लेखा 2024-25

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

31.03.2025 के अनुसार बैलेंस शीट

(₹ करोड़ में)

संपत्ति	टिप्पणी सं.	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
गैर-चालू संपत्ति			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3.1	240.57	237.73
प्रगति में पूंजीगत कार्य	3.2	8.31	12.47
अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति	3.3	-	-
अमूर्त संपत्ति	3.4	6.38	9.02
विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	3.5	-	-
वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	4.1	-	-
(ii) ऋण	4.2	0.58	0.34
(iii) अन्य वित्तीय संपत्ति	4.6	4.21	4.07
आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	11.2	21.94	17.66
गैर-चालू कर संपत्ति (शुद्ध)	11.1	-	-
अन्य गैर-चालू संपत्ति	6.1	0.21	0.12
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (क)		282.20	281.41
चालू परिसंपत्तियाँ			
इन्वेंट्री	5.1	13.77	14.29
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	4.1	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	4.3	943.68	984.37
(iii) नकद और नकद समकक्ष	4.4	280.17	266.87
(iv) अन्य बैंक शेष	4.5	800.00	330.00
(v) ऋण	4.2	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	175.01	121.46
चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	11.1	39.55	71.27
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	6.2	148.42	101.70
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (ख)		2,400.60	1,889.96
कुल परिसंपत्तियाँ (क+ख)		2,682.80	2,171.37
इक्विटी और देयताएँ			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	7.1	142.80	142.80
अन्य इक्विटी	7.2	1899.05	1448.81
कंपनी के इक्विटीधारकों के लिए इक्विटी		2041.85	1591.61
गैर-नियंत्रक हित	7.3	-	-
कुल इक्विटी (क)		2041.85	1591.61

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

31.03.2025 के अनुसार बैलेंस शीट

(₹ करोड़ में)

देयताएँ	टिप्पणी सं.	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
गैर-वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	8.1	-	-
(ii) लीज़ देयताएँ	8.2	0.86	1.08
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	8.4	75.30	73.14
प्रावधान	9.1	6.08	9.14
आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	11.2	-	-
अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ	10.1	5.23	18.90
कुल गैर-चालू देयताएँ (ख)		87.47	102.26
चालू देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	8.1	-	-
(ii) पट्टा देयताएँ	8.2	0.29	0.23
(iii) व्यापार देयताएँ	8.3	-	-
(A) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल बकाया राशि; और		-	-
(B) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		200.12	104.64
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	8.4	98.69	97.96
अन्य चालू देयताएँ	10.2	140.31	128.31
प्रावधान	9.1	114.07	146.36
वर्तमान कर देयताएँ (शुद्ध)	11.1	-	-
कुल चालू देयताएँ (ग)		553.48	477.50
कुल इक्विटी और देयताएँ (क+ख+ग)		2682.80	2171.37

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणी 1 से 15 और अतिरिक्त टिप्पणी 16, इन विवरणों का एक आवश्यक भाग हैं।

ह./-
(ए. मुंधरा)
कंपनी सचिव

ह./-
(सुदीप दासगुप्ता)
सीएफओ
डीआईएन-10802727

ह./-
(एस. नागाचारी)
निदेशक
डीआईएन-09729657

ह./-
(मनोज कुमार)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-09225497

हमारी संलग्न सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
के.सी. टाक एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000216C

ह./-
(सीए अनिल जैन)
पार्टनर

सदस्यता संख्या : 079005
युडीआईएन- 25079005BMOCKP8577

दिनांक : 30 अप्रैल, 2025
स्थान : राँची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

लाभ और हानि का विवरण 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	31.03.2025 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन से राजस्व (शुल्क के बाद शुद्ध)			
बिक्री	12.1	2102.76	1732.69
अन्य परिचालन राजस्व	12.1	-	-
परिचालन से राजस्व (शुल्क के बाद शुद्ध)		2102.76	1732.69
अन्य आय	12.2	74.77	37.49
कुल आय		2177.53	1770.18
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	13.1	30.63	31.49
व्यापार में स्टॉक की खरीद	13.1(a)		
तैयार माल/कार्य प्रगति पर और व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन	13.2	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	13.3	614.25	642.91
वित्त लागत	13.4	0.09	0.06
मूल्यहास/परिशोधन/क्षति व्यय	13.5	33.48	31.54
अनुबंध व्यय	13.6	-	-
अन्य व्यय	13.7	616.94	331.34
कुल व्यय		1295.39	1037.34
असाधारण मदों और कर से पहले लाभ		882.14	732.84
असाधारण मदें		-	-
कर से पहले लाभ		882.14	732.84
कर व्यय	14.1		
कुल कर व्यय		215.23	229.61
निरंतर परिचालन से अवधि के लिए लाभ		666.91	503.23
बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)		-	-
बंद किए गए परिचालन का कर व्यय		-	-
कर के बाद परिचालन बंद करने से अवधि के लिए लाभ/हानि		-	-
संयुक्त उद्यम/सहयोगी के लाभ/(हानि) में हिस्सा		-	-
अवधि के लिए लाभ		666.91	503.23
अन्य व्यापक आय	15.1		
क (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(20.83)	-13.73
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(5.24)	(3.46)

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

लाभ और हानि का विवरण 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

टिप्पणी सं.	31.03.2025 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 समाप्त वर्ष के लिए
ख (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा (ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
कुल अन्य व्यापक आय	(15.59)	(10.27)
वित्तीय अवधि की कुल व्यापक आय (इसमें अवधि के लाभ/हानि और अन्य व्यापक आय शामिल हैं)	651.32	492.96
लाभ का श्रेय:		
कंपनी के मालिकों	666.91	503.23
गैर-नियंत्रक हित को		
	666.91	503.23
अन्य व्यापक आय जिसके लिए जिम्मेदार हैं:		
कंपनी के मालिक	(15.59)	(10.27)
गैर-नियंत्रक हित		
	(15.59)	(10.27)
कुल व्यापक आय जिसके लिए जिम्मेदार है:		
कंपनी के मालिक	651.32	492.96
गैर-नियंत्रक हित		
	651.32	492.96
प्रति इक्विटी शेयर आय (जारी परिचालन):		
(1) मूलभूत	4,670.24	3,524.02
(2) तनुकृत	4,670.24	3,524.02
प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद परिचालन):		
(1) मूलभूत	-	-
(2) तनुकृत	-	-
प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद और जारी परिचालन):		
(1) मूलभूत	4,670.24	3,524.02
(2) तनुकृत	4,670.24	3,524.02

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणी 1 से 15 और अतिरिक्त टिप्पणी 16, इन विवरणों का एक आवश्यक भाग हैं।

ह./-
(ए. मुंधरा)
कंपनी सचिव

ह./-
(सुदीप दासगुप्ता)
सीएफओ
डीआईएन-10802727

ह./-
(एस. नागाचारी)
निदेशक
डीआईएन-09729657

ह./-
(मनोज कुमार)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-09225497

हमारी संलग्न सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
के.सी. टाक एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 000216C

ह./-
(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 079005
युडीआईएन- 25079005BMOKCP8577

दिनांक : 30 अप्रैल, 2025
स्थान : राँची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

नकदी प्रवाह का विवरण - अप्रत्यक्ष विधि 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
कर से पहले लाभ	882.14	732.84
इसके लिए समायोजन:		
मूल्यहास, परिशोधन और हानि व्यय	33.48	31.54
ब्याज आय	(55.21)	(31.96)
वित्त लागत	0.09	0.06
संपत्ति संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ / हानि	0.02	
देयता और प्रावधान वापस लिखें	(13.89)	(2.91)
भत्ते और प्रावधान	0.79	1.07
बढ़े खाते में डालना	12.29	
विदेशी विनिमय दर भिन्नता	(0.03)	0.01
निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	859.68	730.65
व्यापार प्राप्त	39.90	(162.07)
इन्वेंट्री	0.96	0.75
ऋण और अग्रिम तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(53.93)	(30.18)
अन्य चालू और गैर चालू परिसंपत्तियाँ	(46.81)	3.69
व्यापार देय	95.48	(40.69)
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	2.89	(3.53)
अन्य चालू और गैर चालू देनदारियाँ	11.77	1.02
प्रावधान	(56.24)	(89.36)
परिचालन से उत्पन्न नकदी	853.70	410.28
भुगतान किया गया आयकर	(182.56)	(164.02)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	671.14	246.26
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों और अमूर्त संपत्तियों के लिए भुगतान	(41.90)	(31.87)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री से आय	0.07	
बैंकों के पास जमा/(जमा) की वसूली	(470.00)	(240.00)
निवेश पर प्राप्त ब्याज	55.21	31.96
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(456.62)	(239.91)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
उधारों से प्राप्त आय/चुकोती		
पट्टे की देनदारियों का पुनर्भुगतान (ब्याज सहित)	(0.25)	(0.45)
इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश	(200.97)	(119.00)
वित्तीय गतिविधियों में उपयोग की गई शुद्ध नकदी	(201.22)	(119.45)
नकदी और बैंक बैलेंस में शुद्ध वृद्धि/कमी (क+ख+ग)	13.30	(113.10)
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समकक्ष	266.87	379.97
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष।	280.17	266.87

नकदी और नकदी समकक्षों का समाधान (नोट 4.4 देखें)

नकदी और नकदी समकक्ष के घटक

बैंकों के पास शेष राशि

- जमा खातों में

- चालू खातों में

भारत के बाहर बैंक बैलेंस

चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प

हाथ में नकदी

भारत के बाहर हाथ में नकदी

अन्य

कुल नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 तक

31.03.2024 तक

280.15

266.86

0.01

0.01

0.01

280.17

266.87

1. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य:

31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

विवरण	वित्त पट्टा देयताएं
1 अप्रैल 2023 को आरंभिक शेष राशि	1.70
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह	(0.46)
निम्नलिखित के कारण गैर-नकद परिवर्तन:	
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण	0.01
उधार पर ब्याज	0.06
समायोजन	0.01
31 मार्च 2024 को समापन शेष राशि	1.31

31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए

विवरण	वित्त पट्टा देयताएं
1 अप्रैल 2024 को आरंभिक शेष राशि	1.31
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(0.25)
निम्नलिखित के कारण गैर-नकद परिवर्तन:	
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण	
उधार पर ब्याज	0.09
समायोजन	
31 मार्च 2025 को समापन शेष राशि	1.15

उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक 7 - 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

ह./-
(ए. मुंधरा)
कंपनी सचिव

ह./-
(सुदीप दासगुप्ता)
सीएफओ
डीआईएन-10802727

ह./-
(एस. नागाचारी)
निदेशक
डीआईएन-09729657

ह./-
(मनोज कुमार)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-09225497

हमारी संलग्न सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
के.सी. टाक एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000216C

ह./-
(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 079005
युडीआईएन- 25079005BMOKCP8577

दिनांक : 30 अप्रैल, 2025
स्थान : राँची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए इकिटी में परिवर्तन का विवरण

क. इकिटी शेयर पूंजी

31.03.2025 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2024 तक शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इकिटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2024 तक पुनः घोषित शेष राशि	वर्ष के दौरान इकिटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	शेष राशि 31.03.2025 तक
₹ 1000/- प्रत्येक के 14,28,000 इकिटी शेयर	142.8	0	142.80	-	142.80

31.03.2024 तक

(₹ in Crore)

विवरण	01.04.2023 तक शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इकिटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2023 तक पुनः घोषित शेष राशि	वर्ष के दौरान इकिटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	शेष राशि 31.03.2024 तक
₹ 1000/- प्रत्येक के 14,28,000 इकिटी शेयर	142.8	0	142.80	-	142.80

ख. अन्य इकिटी

31.03.2025 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	ओसीआई - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (कर के बाद शुद्ध)	कुल
	पूंजी मोचन रिजर्व	पूंजी रिजर्व				
01.04.2024 तक शेष राशि	-	-	69.94	1331.1	47.77	1448.81
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-
01.04.2024 तक पुनः घोषित शेष राशि	-	-	69.94	1331.1	47.77	1448.81
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-	33.34	-33.34	-	33.34
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	-	(0.11)	-	-33.34
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	(150.00)	-	-0.11
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(50.97)	-	(150.00)
अंतिम लाभांश	-	-	-	666.91	(15.59)	(50.97)
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	-	-	651.32
बोनस शेयरों का निर्गम	-	-	-	-	-	-
31.03.2025 तक शेष राशि	-	-	103.28	1,763.59	32.18	1,899.05

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए इकिटी में परिवर्तन का विवरण

ख. अन्य इकिटी (जारी)

31.03.2024 तक

विवरण	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	ओसीआई - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (कर के बाद शुद्ध)	कुल
	पूँजी मोचन रिजर्व	पूँजी रिजर्व				
01.04.2023 तक शेष राशि	-	-	44.78	972.03	58.04	1,074.85
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-
01.04.2023 तक पुनः घोषित शेष राशि	-	-	44.78	972.03	58.04	1,074.85
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	25.16	-	-	25.16
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	(25.16)	-	-
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	-	(100.00)	-	(100.00)
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(19.00)	-	(19.00)
अंतिम लाभांश	-	-	-	503.23	(10.27)	492.96
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयरों का निर्गम	-	-	-	-	-	-
31.03.2024 तक शेष राशि	-	-	69.94	1,331.10	47.77	1,448.81

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी इकाई)



सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.1: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/स्थल पुनर्स्थापना की लागत	भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फ़र्निचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहनों	विमान	अन्य खनन अवसंरचना	सर्वेक्षण की गई संपत्तियाँ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:															
1 अप्रैल 2023 तक	1.15	3.14	-	87.06	228.17	1.03	-	24.75	6.04	12.82	-	-	0.83	-	364.99
जोड़	-	-	-	1.97	27.20	0.02	-	3.07	1.72	1.87	-	-	0.39	-	36.24
हटाना/समायोजन	-	-	-	(2.52)	(5.25)	0.06	-	(0.28)	(0.19)	(0.68)	-	-	-	-	-8.86
31 मार्च 2024 तक	1.15	3.14	-	86.51	250.12	1.11	-	27.54	7.57	14.01	-	-	1.22	-	392.37
1 अप्रैल 2024 तक	1.15	3.14	-	86.51	250.12	1.11	-	27.54	7.57	14.01	-	-	1.22	-	392.37
जोड़	-	-	-	1.48	26.35	0.58	-	3.05	0.66	1.81	-	-	-	-	33.93
हटाना/समायोजन	-	(0.09)	-	(0.03)	(3.76)	-	-	(0.14)	(0.01)	(1.49)	-	-	(0.02)	-	-5.54
31 मार्च 2025 तक	1.15	3.05	-	87.96	272.71	1.69	-	30.45	8.22	14.33	-	-	1.20	-	420.76
संचित मूल्यहास, परिशोधन और होन*															
1 अप्रैल 2023 तक	-	0.51	-	14.29	97.20	0.30	-	10.91	3.25	9.07	-	-	-	-	135.53
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.24	-	2.08	20.87	0.15	-	2.25	0.68	0.77	-	-	-	-	27.04
हटाना/समायोजन	-	-	-	(2.46)	(4.63)	0.03	-	(0.25)	(0.17)	(0.45)	-	-	-	-	(7.93)
31 मार्च 2024 तक	-	0.75	-	13.91	113.44	0.48	-	12.91	3.76	9.39	-	-	-	-	154.64
1 अप्रैल 2024 तक	-	0.75	-	13.91	113.44	0.48	-	12.91	3.76	9.39	-	-	-	-	154.64
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.23	-	2.03	23.78	0.21	-	2.26	0.87	0.92	-	-	-	-	30.30
हटाना/समायोजन	-	-0.03	-	-	(3.31)	-	-	(0.13)	(0.01)	(1.27)	-	-	-	-	(4.75)
31 मार्च 2025 तक	-	0.95	-	15.94	133.91	0.69	-	15.04	4.62	9.04	-	-	-	-	180.19
शुद्ध वहन राशि															
31 मार्च 2025 तक	1.15	2.10	-	72.02	138.80	1.00	-	15.41	3.60	5.29	-	-	1.20	-	240.57
31 मार्च 2024 तक	1.15	2.39	-	72.60	136.68	0.63	-	14.63	3.81	4.62	-	-	1.22	-	237.73

टिप्पणियाँ

- उपर्युक्त प्लॉट और मशीनरी में स्टैंड बाय उपकरण और स्टोर और स्पेयर सहित प्लॉट और मशीनरी शामिल हैं जो पीपीई के रूप में मान्यता के लिए मानदंडों को पूरा करते हैं लेकिन अभी तक स्टोर से जारी नहीं किए गए हैं।
- कंपनी की लेखा नीति के अनुसार मूल्यहास प्रदान किया गया है। (टिप्पणी संख्या 2 देखें)
- अन्य भूमि में उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति शामिल है जिसकी राशि 1.72 करोड़ रुपये है और उस पर संचित परिशोधन 31.03.2025 तक 0.78 करोड़ रुपये है।
- समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में लगाया गया मूल्यहास और परिशोधन और क्षति 33.48 करोड़
- भारतीय लेखा मानक के अनुसार, 01.04.2015 को सकल मूल्य में से संचित मूल्यहास को लेनदेन तिथि
- कोयला मंत्रालय [प्रोत्साहन निधि और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निधि] और कोल इंडिया लिमिटेड,

वित्तपोषित परिसंपत्ति वर्ग	(₹ करोड़ में)		
	जोड़कर	वर्ष के लिए मूल्यहास	31-03-2025 तक शुद्ध बही मूल्य
भवन	0.00	0.01	0.18
संयंत्र और उपकरण	0.00	1.40	7.08
फर्नीचर और मरम्मत	0.00		0.06
अमूर्त परिसंपत्ति	0.00	0.14	0.00
कुल	0.00	1.55	7.32

7. संचित हानि में हलचल

	(₹ करोड़ में)		
	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	कुल
1.04.2023 तक	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए शुल्क	0.02	0.04	0.06
हटाना/समायोजन	0.00	0.00	0.00
31.03.2024 तक	0.02	0.04	0.06
1.04.2024 तक	0.02	0.04	0.06
वर्ष के लिए शुल्क	0.02	0.00	0.02
हटाना/समायोजन	0.00	0.00	0.00
31.03.2025 तक	0.04	0.04	0.08

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.1: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

	भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन अवसंरचना/विकास	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:						
1 अप्रैल 2023 तक परिवर्धन	1.98	13.11	-	-	-	15.09
पूँजीकरण/हटाना	0.24 (1.92)	0.02 (0.96)	-	-	-	0.26 (2.88)
31 मार्च 2024 तक	0.30	12.17	-	-	-	12.47
1 अप्रैल 2024 तक परिवर्धन	0.30	12.17	-	-	-	12.47
पूँजीकरण/हटाना	7.53 (0.54)	2.00 (13.15)	-	-	-	9.53 (13.69)
31 मार्च 2025 तक	7.29	1.02	-	-	-	8.31
संचित क्षति						
1 अप्रैल 2023 तक वर्ष के लिए प्रभार विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2024 तक वर्ष के लिए प्रभार विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	-	-	-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि						
31 मार्च 2025 तक	7.29	1.02	-	-	-	8.31
31 मार्च 2024 तक	0.30	12.17	-	-	-	12.47

1. पूंजीगत कार्य-प्रगति की आयु निर्धारण अनुसूची (सकल) :	31-03-2024 तक प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगति पर परियोजनाएँ:				कुल
भवन				
रेडिएशन रखने के लिए भंडारण कक्ष का निर्माण, क्षेत्रीय संस्थान-4		0.04		0.04
सीएमपीडीआई कॉलोनी क्षेत्रीय संस्थान-7 के लिए नई जल आपूर्ति पाइपलाइन		0.11		0.11
ईटीपी के लिए सुरक्षात्मक शेड का निर्माण	0.01			0.01
संयंत्र और उपकरण				-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित:				-
भवन				-
क्षेत्रीय संस्थान-7 के गोपालपुर शिविर के लिए लखनपुर आवासीय भवन			0.14	0.14
संयंत्र और उपकरण				-
सीआईएल आरएंडडी डब्ल्यूआईपी	-	-	12.17	12.17
कुल	0.01	0.15	-	12.47
पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) (सकल)				
2. भौतिक पूंजीगत कार्य-प्रगति हेतु अतिदेय (सकल):	इसे पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगति पर परियोजनाएँ:				
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)				
संयंत्र और उपकरण				
रेलवे साइडिंग				
कुल				

1. पूंजीगत कार्य-प्रगति की आयु निर्धारण अनुसूची (सकल):	31-03-2025 तक प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगति पर परियोजनाएँ:				कुल
बिल्डिंग				
सीएमपीडीआई कॉलोनी क्षेत्रीय संस्थान-7 में नई जल आपूर्ति पाइपलाइन	0.11			0.11
सीएमपीडीआई कॉलोनी में स्कार्पियार्ड का निर्माण	0.05			0.05
गोंडवाना स्कूल मुख्यालय के लिए नया कक्षा कक्ष का निर्माण	0.34			0.34
बीडीडी फ्लोर का नवीनीकरण - सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय	0.84			0.84
सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान-6 कॉलोनी मुख्यालय में कार्टों का निर्माण	4.58			4.58
डब्ल्यूआईपी एसटीसी बिल्डिंग मुख्यालय	0.64			0.64
क्षेत्रीय संस्थान-4 में पॉलीकार्बोनेट शीट की छत के साथ पार्किंग शेड	0.51			0.51
आरसीसी स्टॉर्म वाटर ड्रेन सीएमपीडीआई नागपुर चरण-II क्षेत्रीय संस्थान-4	0.08			0.08
संयंत्र और उपकरण				
सौर ऊर्जा संयंत्र मुख्यालय	0.66			0.66
लिफ्ट_C43 से C53 और B157-B178 फ्रैक्शन ऑटोमेशन मुख्यालय	0.36			0.36
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित:				
भवन				
क्षेत्रीय संस्थान-7 के गोपालपुर शिविर के लिए लखनपुर आवासीय भवन			0.14	0.14
संयंत्र और उपकरण				
कुल योग	8.17	-	-	0.14
				8.31

पूँजी-कार्य-प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) (सकल)	इसे पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
2. सामग्री पूँजी-कार्य-प्रगति पर (सकल) के लिए अतिरिक्त:				
प्रगति पर परियोजनाएँ:				
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)				
संयंत्र और उपकरण				
रेलवे साइडिंग				
कुल				

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.3: गवेषण और मूल्यांकन संसाधन

(₹ करोड़ में)

	गवेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल 2023 तक	-
परिवर्धन	-
हटाना/समायोजन	-
31 मार्च 2024 तक	-
1 अप्रैल 2024 तक	-
परिवर्धन	-
हटाना/समायोजन	-
31 मार्च 2025 तक	-
संचित क्षति	
1 अप्रैल 2023 तक	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हटाना/समायोजन	-
31 मार्च 2024 तक	-
1 अप्रैल 2024 तक	-
वर्ष के लिए विभाग	-
हटाना/समायोजन	-
31 मार्च 2025 तक	-
शुद्ध वहन राशि	
31 मार्च 2025 तक	-
31 मार्च 2024 तक	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.4: अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:			
1 अप्रैल 2023 तक	35.31	-	35.31
परिवर्धन	1.52	-	1.52
हटाना/समायोजन	-0.78	-	-0.78
31 मार्च 2024 तक	36.05	-	36.05
1 अप्रैल 2024 तक	36.05	-	36.05
परिवर्धन	2.08	-	2.08
हटाना/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	38.13	-	38.13
संचित परिशोधन और हानि			
1 अप्रैल 2023 तक	20.97	-	20.97
वर्ष के लिए शुल्क	6.06	-	6.06
हटाना/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	27.03	-	27.03
1 अप्रैल 2024 तक	27.03	-	27.03
वर्ष के लिए विभाग	4.73	-	4.73
हटाना/समायोजन	-0.01	-	-0.01
31 मार्च 2025 तक	31.75	-	31.75
शुद्ध वहन राशि			
31 मार्च 2025 तक	6.38	-	6.38
31 मार्च 2024 तक	9.02	-	9.02

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.5 : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	ईआरपी विकासाधीन
वहन राशि	
1 अप्रैल 2023 तक	-
परिवर्धन	-
कैपिटलाइज़ेशन/डिलीशन	-
31 मार्च 2024 तक	-
1 अप्रैल 2024 तक	-
परिवर्धन	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च 2025 तक	-
संचित हानि	
1 अप्रैल 2023 तक	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च 2024 तक	-
1 अप्रैल 2024 तक	-
वर्ष के लिए विभाग	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च 2025 तक	-
शुद्ध वहन राशि	-
31 मार्च 2025 तक	-
31 मार्च 2024 तक	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.1 : निवेश

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
गैर चालू		
शेयरों में निवेश	-	-
संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी शेयर	-	-
अन्य निवेश	-	-
सुरक्षित बॉन्ड में	-	-
सहकारी शेयरों में	-	-
कुल	-	-
असुचिबद्ध निवेशों की कुल राशि:	-	-
सुचिबद्ध निवेशों की कुल राशि:	-	-
सुचिबद्ध निवेशों का बाजार मूल्य:	-	-
निवेशों के मूल्य में हानि की कुल राशि:	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी 4.1 : जारी..

(₹ करोड़ में)

निवेश

चालू वर्ष

31.03.2025 के अनुसार

31.03.2024 के अनुसार

म्यूचुअल फंड निवेश

यूटीआई म्यूचुअल फंड

-

-

यूटीआई लिक्विड कैश प्लान

-

-

एलआईसी म्यूचुअल फंड

-

-

एसबीआई म्यूचुअल फंड

-

-

केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड

-

-

यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड

-

-

बीओआई एक्सा म्यूचुअल फंड

-

-

कुल

-

-

सुचिबद्ध निवेश का कुल योग:

-

-

असुचिबद्ध निवेश का कुल योग:

-

-

सुचिबद्ध निवेश का बाजार मूल्य:

-

-

निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:

-

-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.2: ऋण

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 के अनुसार

31.03.2024 के अनुसार

गैर चालू

संबंधित पक्षों को दिए गए ऋणों की स्थिति इस प्रकार है:

- सुरक्षित ऋण, जो अच्छे माने जाते हैं
- असुरक्षित ऋण, जो अच्छे माने जाते हैं
- जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है
- और जिनका क्रेडिट खराब हो गया है।

कम : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता 4.2.1

निगमित निकायों और कर्मचारियों को दिए गए ऋण

- सुरक्षित ऋण, जो अच्छे माने जाते हैं
- असुरक्षित ऋण, जो अच्छे माने जाते हैं
- जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है
- और जिनका क्रेडिट खराब हो गया है।

0.58

0.34

-

-

0.58

0.34

घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता

-

-

0.58

0.34

कुल

0.58

0.34

चालू

संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं को दिए गए ऋण

- सुरक्षित ऋण, जो अच्छे माने जाते हैं
- असुरक्षित ऋण, जो अच्छे माने जाते हैं
- जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है
- और जिनका क्रेडिट खराब हो गया है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.2: ऋण

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 के अनुसार

31.03.2024 के अनुसार

घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता 4.2.1

संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण
निगमित निकायों और कर्मचारियों को दिए गए ऋण

- सुरक्षित ऋण, जो अच्छे माने जाते हैं
- असुरक्षित ऋण, जो अच्छे माने जाते हैं
- जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है
- और जिनका क्रेडिट खराब हो गया है।
- संदिग्ध

घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता

कुल

-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.3: व्यापार प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
वर्तमान		
व्यापार प्राप्य		
-सुरक्षित, सुविचारित सामान	-	-
-असुरक्षित, विचारित सामान	943.68	984.37
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
क्रेडिट खराब हुआ है	3.47	2.68
	947.15	987.05
घटाएँ : अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता	3.47	2.68
कुल	943.68	984.37

कंपनी ने व्यापार प्राप्य के क्रेडिट घाटे के लिए भत्ते का निर्धारण करने में प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करके व्यावहारिक समीचीन का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव और भविष्योन्मुखी जानकारी को ध्यान में रखता है। अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता देय प्राप्य की उम्र बढ़ने और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ते में बदलाव का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	2.68	2.58
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त	0.79	0.10
वर्ष के दौरान राइटबैक	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	3.47	2.68

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

31.03.2025 तक

व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
विवरण	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	692.51	122.16	28.23	36.64	67.61	947.15
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण						
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है						
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण						
कुल	692.51	122.16	28.23	36.64	67.61	947.15
अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता					3.47	3.47
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %					5.13%	0.37%
31.03.2024 तक						
व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
विवरण	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	770.95	95.70	44.72	20.08	55.60	987.05
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण						
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है						
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षीण						
कुल	770.95	95.70	44.72	20.08	55.60	987.05
अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता					2.68	2.68
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	0%	0%	0%	4.82%	0.27%

"व्यापार प्राप्य में समूह के भीतर सीआईएल और अनुषंगी कंपनियों से बकाया राशि ₹ 746.36 (पिछले वर्ष ₹ 805.63 करोड़) और उस पर मान्यता प्राप्त भत्ते शून्य (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं। समूह के बाहर से बकाया राशि में ₹ 200.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 181.42 करोड़) और उस पर मान्यता प्राप्त भत्ते ₹ 3.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.68 करोड़) शामिल हैं।"

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ
टिप्पणी - 4.4: नकद और नकद समतुल्य

	31.03.2025 के अनुसार	(₹ करोड़ में) 31.03.2024 के अनुसार
(a) बैंकों में शेष राशि		
- जमा खातों में		
- चालू खातों में	280.15	266.86
(b) भारत के बाहर बैंक शेष राशि	-	-
(c) चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प	0.01	-
(d) हाथ में नकदी		
(e) भारत के बाहर हाथ में नकदी	-	-
(f) अन्य	0.01	0.01
कुल नकदी और नकदी समतुल्य	280.17	266.87

बैंक में शेष 280.15 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 266.86 करोड़ रुपये) में से, निधि से संबंधित बैंक शेष 7.59 करोड़ (पिछले वर्ष 58.04 करोड़ रुपये था) जिसे की निचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

निधियों के नाम	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
एमओसी (प्रचारात्मक + गैर सीआईएल)	1.62	22.66
एमओसी (अनुसंधान एवं विकास)	2.96	2.93
एनएमईटी	0.52	8.84
सीआईएल (अनुसंधान एवं विकास)	2.49	23.61
कुल	7.59	58.04

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 4.5: अन्य बैंक खातों में शेष राशि

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
बैंकों के पास शेष राशि		
- जमा खाते	800.00	330.00
- चालू परियोजनाओं के लिए सीएसआर फंड	-	-
- स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-
- शेयरों की पुनर्खरीद के लिए एस्करो खाता	-	-
- अवैतनिक लाभांश खाते	-	-
- लाभांश खाते	-	-
कुल	800.00	330.00

4.5. अन्य बैंक शेष में जमाराशियां शामिल हैं - विशिष्ट प्रयोजनों के लिए तथा बैंक जमाराशियां, जिनकी रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकदी में वसूली होने की उम्मीद है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ
टिप्पणी - 4.6: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 के अनुसार

31.03.2024 के अनुसार

गैर चालू

सुरक्षा जमा	4.11	3.97
घटाएँ: संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता	0.04	0.04
	4.07	3.93
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमाराशि	0.14	0.14
बैंक के पास जमाराशि		
- स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि योजना	-	-
अन्य जमाराशि और प्राप्य	-	-
घटाएँ: संदिग्ध जमाराशि के लिए भत्ता	-	-
कुल	4.21	4.07
चालू		
सुरक्षा जमा राशि		
घटाएँ : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता		
सीआईएल के साथ चालू खाता शेष	61.58	60.58
आईआईसीएम के साथ शेष राशि	-	-
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
	0.00	0.00
अर्जित ब्याज	30.93	17.92
अन्य जमा और प्राप्य*	82.50	42.96
घटाएँ: संदिग्ध दावों के लिए भत्ता	-	-
	82.50	42.96
कुल	175.01	121.46

4.6.1 सुरक्षा जमा भत्ते में परिवर्तन का विवरण (चालू और गैर-चालू)

	31.03.2025	31.03.2024
वर्ष/अवधि की शुरुआत में शेष राशि	0.04	0.04
वर्ष/अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	0.00	0.00
वर्ष/अवधि के दौरान राइटबैक	0.00	0.00
वर्ष/अवधि के अंत में शेष राशि	0.04	0.04
दावे और अन्य प्राप्य*	31.03.2025	31.03.2024
भारतीय लेखा मानक 115 से प्राप्य - संविदात्मक संपत्ति	69.90	38.42
प्राप्य दावे और अन्य	12.60	4.54
कुल	82.50	42.96

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 5.1 : इन्वेंट्री

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
कोयला (निर्मित वस्तुएँ)		
विकास परियोजनाओं में कोयला		
घटाएँ: मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
(b) भंडार, स्पेयर्स और अन्य सूची	14.50	15.46
घटाएँ: धीमी गति से चलने वाले, स्थिर और अप्रचलित	0.73	1.17
इन्वेंट्री के लिए प्रावधान		
	13.77	14.29

5.1 स्टोर और स्पेयर की सूची में धीमी गति से चलने वाले, स्थिर, और अप्रचलित सामान शामिल हैं। कंपनी की नीति के अनुसार, इन सामानों के लिए मूल्यहास प्रावधान किया जाता है।

धीमी गति से चलने वाले, स्थिर और अप्रचलित स्टोर, स्पेयर और अन्य इन्वेंट्री के मूल्यहास प्रावधान में परिवर्तन का विवरण इस प्रकार है:

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
वित्तीय वर्ष/अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	1.17	0.20
वित्तीय वर्ष/अवधि में मान्यता प्राप्त राशि		0.97
वित्तीय वर्ष/अवधि में अपहचानी गई राशि	0.44	-
वित्तीय वर्ष/अवधि के अंत में शेष राशि	0.73	1.17

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ
टिप्पणी 6.1: अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
(i) पूंजी अग्रिम	0.21	0.12
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	-	-
	0.21	0.12
(ii) पूंजी अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
(क) अन्य जमा और अग्रिम	-	-
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	-	-
	-	-
(ख) संबंधित पक्षों को अग्रिम	-	-
कुल	0.21	0.12

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 6.2: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	0.04	0.04
घटाएँ : संदिग्ध वैधानिक बकाया के लिए भत्ता	-	-
	0.04	0.04
अन्य अग्रिम एवं जमा राशि *	126.58	80.82
घटाएँ : संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिम के लिए भत्ता	0.24	0.25
	126.34	80.57
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	22.04	21.09
	22.04	21.09
कुल	148.42	101.70
टिप्पणी : 6.2		
1) अन्य अग्रिम और जमा*		
	31.03.2025	31.03.2024
अग्रिम भुगतान करें	0.40	0.44
टी.ए.	1.88	1.22
चिकित्सा अग्रिम	0.24	0.55
आयकर पर विरोध**	83.00	66.58
अन्य	41.06	12.03
कुल	126.58	80.82

- ** प्रतिवाद के तहत चुकाया गया आयकर 83 करोड़ रुपये है। इसमें से 0.59 करोड़ रुपये कर वर्ष 2010-11 से संबंधित हैं, 25.12 करोड़ रुपये 2017-18 से संबंधित हैं, 32.44 करोड़ रुपये 2018-19 से संबंधित हैं, 19.13 करोड़ रुपये कर वर्ष 2020-21 से संबंधित हैं, 5.72 करोड़ रुपये कर वर्ष 2021-22 से संबंधित हैं।
- अन्य अग्रिम एवं जमा राशि में विरोध के तहत जमा राशि और सेवा कर मामलों के लिए अभी तक प्राप्त नहीं होने वाली रिफंड राशि ₹7.31 आदि शामिल है।
- * इसमें 2.30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सीएसआर शामिल है

6.2.1 बकाया और संदिग्ध अग्रिमों एवं जमाओं (चालू और गैर-चालू) में हुए परिवर्तनों का विवरण

	31.03.2025	31.03.2024
वित्तीय वर्ष/अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	0.25	0.25
वित्तीय वर्ष/अवधि में मान्यता प्राप्त राशि	-	-
वित्तीय वर्ष/अवधि में उपयोग की गई राशि	0.01	-
वित्तीय वर्ष/अवधि के अंत में शेष राशि	0.24	0.25

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 7.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
अधिकृत		
₹1000/- प्रत्येक के 15,00,000 इक्विटी शेयर	150.00	150.00
	150.00	150.00

जारी किया गया, सदस्यता ली गई और भुगतान किया गया
(कोल इंडिया लिमिटेड, होलिंग कंपनी
और उसके नामांकित व्यक्तियों द्वारा धारित)

₹1,000/- प्रत्येक के 8 इक्विटी शेयर, पूर्णतः नकद
पूर्णतः नकद भुगतान (पिछले वर्ष ₹1,000/- प्रत्येक
के 8 इक्विटी शेयर)

-

-

₹1,000/- प्रत्येक के 1322992 इक्विटी शेयर,
नकद के अलावा प्राप्त प्रतिफल के लिए पूर्णतः भुगतान के
रूप में पूर्णतः भुगतान के रूप में आवंटित

132.30

132.30

₹1000/- प्रत्येक के 105000 इक्विटी शेयर,
ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करके होलिंग कंपनी को
नकद में पूर्णतः भुगतान के रूप में आवंटित

10.50

10.50

कुल

142.80

142.80

1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर

शेयरधारक का नाम

**धारित शेयरों की संख्या
(प्रत्येक का अंकित मूल्य
₹1000)**

**कुल शेयरों का प्रतिशतता
(%)**

कोल इंडिया लिमिटेड

1428000

100%

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 7.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
2 रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:-		
विवरण	शेयर की संख्या	राशि
01.04.2020 को शेष राशि	380,800	38.08
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान परिवर्तन (वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बोनस शेयरों का निर्गमन)	1,047,200	104.72
01.04.2021 को शेष राशि	1,428,000	142.80
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्तन	-	-
01.04.2022 को शेष राशि	1,428,000	142.80
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्तन	-	-
01.04.2023 को शेष राशि	1,428,000	142.80
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान परिवर्तन	-	-
01.04.2024 को शेष राशि	1,428,000	142.80
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2025 को शेष राशि	1,428,000	142.80

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका अंकित मूल्य 1000 रुपये प्रति शेयर है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 7.2: अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
पूंजी मोचन आरक्षित निधि	-	-
पूंजी आरक्षित निधि	-	-
सामान्य आरक्षित निधि	103.28	69.94
प्रतिधारित आय	1,795.77	1,378.87
अन्य व्यापक आय जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
कुल	1,899.05	1,448.81
(क) पूंजी मोचन आरक्षित निधि	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	-	-
वर्ष/अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष/अवधि के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-
(ख) पूंजी आरक्षित निधि	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	-	-
वर्ष/अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष/अवधि के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-
(ग) सामान्य आरक्षित निधि	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	69.94	44.78
वर्ष/अवधि के दौरान वृद्धि	33.34	25.16
वर्ष/अवधि के दौरान समायोजन	-	-
सामान्य आरक्षित निधि में/से स्थानांतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	103.28	69.94
(घ) (i) प्रतिधारित कमाई	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	1,331.10	972.03
वर्ष का लाभ	666.91	503.23
अंतरिम लाभांश	(150.00)	(100.00)
अंतिम लाभांश	(50.97)	(19.00)
वर्ष/अवधि के दौरान समायोजन	(0.11)	-
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	(33.34)	(25.16)
वर्ष के अंत में शेष राशि	1,763.59	1,331.10

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति शेयर ₹1,050.42 का अंतरिम लाभांश दिया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति शेयर ₹700.28 का अंतरिम लाभांश दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति शेयर ₹356.93 का अंतिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2024-25 में भुगतान किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रति शेयर ₹133.05 का अंतिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2023-24 में भुगतान किया गया था।

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

(घ) (ii) अन्य व्यापक आय मर्दे जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	47.77	58.04
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	(15.59)	(10.27)
वर्ष/अवधि के दौरान समायोजन		
वर्ष के अंत में शेष राशि	32.18	47.77

कुल (घ (i) + (ii))

1,795.77

1,378.87

(ङ) अन्य व्यापक आय की मर्दे

(अन्य व्यापक आय मर्दे जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा)

(i) किसी विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय मतभेद

वर्ष के आरंभ में शेष राशि

चालू वर्ष/अवधि के लिए कुल व्यापक आय

वर्ष/अवधि के दौरान समायोजन

वर्ष के अंत में शेष राशि

-

-

(ii) संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा, जिसका लेखा इकिटी पद्धति (कर के बाद शुद्ध) का उपयोग करके किया गया है।

वर्ष/अवधि के आरंभ में शेष राशि

चालू वर्ष/अवधि के लिए कुल व्यापक आय

वर्ष/अवधि के दौरान समायोजन

वर्ष/अवधि के अंत में शेष राशि

-

कुल [(i) + (ii)]

-

-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी 8.1: उधार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
गैर-चालू		
सावधि ऋण		
-बैंकों से	-	-
-अन्य पक्षों से	-	-
संबंधित पक्षों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
चालू		
मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण		
-बैंकों से	-	-
-अन्य पक्षों से	-	-
संबंधित पक्षों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.2: पट्टा देयताएँ

(₹ करोड़ में)

गैर - चालू	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	1.08	0.86
अवधि के दौरान वृद्धि		0.01
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	0.09	0.06
पट्टा देनदारियों का भुगतान/समायोजन	(0.31)	0.15
अवधि के समापन पर शेष राशि	0.86	1.08
 चालू		
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	1.31	0.84
अवधि के दौरान वृद्धि		-
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत		-
पट्टा देयताओं का भुगतान/समायोजन	(1.02)	(0.61)
वर्ष के अंत में शेष राशि	0.29	0.23
कुल योग	1.15	1.31

8.2.1 अछूते आधार पर पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण (गैर-चालू और चालू):

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
1 वर्ष तक	0.27	0.29
1-5 वर्ष	0.71	1.05
5 वर्ष से अधिक	0.37	0.40

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

8.2.2 दिनांक 31.03.2024 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान विलोपन	अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए मूल्यहास/परिशोधन
भूमि	1.36	0.01		1.15	0.22
भवन					
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्स्चर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्तियाँ		-	-	-	-

31.03.2025 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष/अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यहास/परिशोधन
भूमि	1.15			0.93	0.22
भवन					
संयंत्र और उपकरण					
फर्नीचर और फिक्स्चर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्तियाँ		-	-	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

8.2.3 लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियाँ

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	(₹ करोड़ में) 31.03.2024 के अनुसार
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास और परिशोधन व्यय	0.22	0.22
पट्टा देनदारियों पर ब्याज व्यय	0.09	0.06
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय	-	-
बिक्री और लीजबैक लेनदेन से उत्पन्न लाभ या हानि	-	-
कुल	0.31	0.28

8.2.4 नकदी प्रवाह विवरण में पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाह का खुलासा

विवरण	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
वित्तीय पट्टा देनदारियों का भुगतान	0.25	0.45
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकदी बहिर्वाह	-	-
कुल	0.25	0.45

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.3: व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
वर्तमान		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कुल बकाया	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	200.12	104.64
कुल	200.12	104.64

व्यापार देय - सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया

	31.03.2025	31.03.2024
क) मूलधन और ब्याज राशि बकाया है लेकिन अवधि के अंत तक देय नहीं है	शून्य	शून्य
ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, साथ ही अवधि के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	शून्य	शून्य
ग) भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया हो) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
घ) अवधि के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज	शून्य	शून्य
ड.) आगामी वर्षों में भी बकाया और देय शेष ब्याज, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दी जाती।	शून्य	शून्य

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.3: व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 तक

व्यापार देय - सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई					
ii) अन्य	194.02	1.23	0.36	4.51	200.12
iii) विवादित बकाया - एमएसएमई					
iv) विवादित बकाया - अन्य					
बिना बिल वाला बकाया					

31.03.2024 तक

व्यापार देयताओं की आयु निर्धारण अनुसूची	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई					
ii) अन्य	92.20	7.45	4.92	0.07	104.64
iii) विवादित बकाया - एमएसएमई					
iv) विवादित बकाया - अन्य					
बिना बिल वाला बकाया					

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 8.4: अन्य वित्तीय देनदारियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
गैर चालू		
सुरक्षा जमा	75.30	73.14
अन्य	0.00	0.00
कुल	75.30	73.14
 चालू		
सहायक कंपनियों से अधिशेष निधि	-	-
निम्नलिखित के साथ चालू खाता	-	-
-अनुषंगी कंपनियाँ	-	-
-आईआईसीएम	0.20	0.20
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वताएँ	-	-
अवैतनिक लाभांश	-	-
सुरक्षा जमाएँ	22.45	21.35
पूंजीगत व्यय के लिए देय	7.11	13.37
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	64.69	58.95
अन्य	4.24	4.09
कुल	98.69	97.96

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 9.1: प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
गैर-चालू		
कर्मचारी लाभ		
- ग्रेच्युटी*		-
- अवकाश नकदीकरण**		
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ***		4.01
- अन्य कर्मचारी लाभ	6.07	5.12
अन्य प्रावधान		
साइट पुनर्स्थापन/खदान बंद करना	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	-	-
अन्य	0.01	0.01
कुल	6.08	9.14
चालू		
कर्मचारी लाभ		
- ग्रेच्युटी*	9.53	(5.68)
- अवकाश नकदीकरण**	1.64	11.26
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ***	-	6.32
- अन्य कर्मचारी लाभ	102.90	134.46
	114.07	146.36
अन्य प्रावधान	-	-
अन्य		
कुल	114.07	146.36

टिप्पणी :

- 9.1. ग्रेच्युटी की देयता (योजना परिसंपत्तियों का शुद्ध) में भुगतान किए गए लाभ के लिए ग्रेच्युटी ट्रस्ट से
- 9.1.1 प्रावधानों में बदलाव का विवरण (चालू और गैर-चालू)
- ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन।

31.03.2025 के अनुसार	वर्ष की शुरुआत में राशि	वर्ष के दौरान शुल्क	वर्ष के दौरान उपयोग/समायोजित	वर्ष के अंत में शेष राशि
अन्य कर्मचारी लाभ	220.26	96.41	-177.09	139.58

31.03.2025 के अनुसार	वर्ष की शुरुआत में राशि	वर्ष के दौरान शुल्क	वर्ष के दौरान उपयोग/समायोजित	वर्ष के अंत में शेष राशि
अन्य कर्मचारी लाभ	139.58	39.84	-70.45	108.97

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 10.1: अन्य गैर-चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
आस्थगित आय	-	-
अन्य*	5.23	18.90
कुल	5.23	18.90

* इसमें सीआईएल आरएंडडी कैपिटल रिजर्व, प्रमोशनल रीजनल एक्सप्लोरेशन कैपिटल रिजर्व और यूएनडीपी शामिल हैं।

टिप्पणी - 10.2: अन्य चालू देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 के अनुसार
वैधानिक बकाया	94.15	79.99
कोयला आयात के लिए अग्रिम	-	-
ग्राहकों/अन्य लोगों से अग्रिम	5.22	7.74
उपकर समकारी खाता	-	-
*अन्य देयताएँ	40.94	40.58
कुल	140.31	128.31

* अन्य देनदारियों में कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय से प्राप्त धनराशि शामिल है।

10.2.3 प्रबंधन को आशा है कि वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई देनदारियों के अलावा ब्याज सहित कोई अतिरिक्त भविष्य की देनदारियां उत्पन्न नहीं होंगी।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 11.1: कर संपत्ति/देयताएँ

(₹ करोड़ में)

आयकर संपत्ति

वर्ष/अवधि की शुरुआत में शेष राशि
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तन/वापसी
अवधि के समापन पर शेष राशि

31.03.2025 के
अनुसार

31.03.2024 के
अनुसार

339.73

175.70

237.30

164.03

(134.16)

-

442.87

339.73

आयकर देयताएं

वर्ष/अवधि की शुरुआत में शेष राशि
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त
अवधि के दौरान उलटाव/समायोजन
अवधि के समापन पर शेष राशि

268.46

82.53

217.40

185.93

(82.54)

403.32

268.46

अंत में शुद्ध आयकर परिसंपत्ति/(देयताएं)

39.55

71.27

31.03.2025 के
अनुसार

31.03.2024 के
अनुसार

प्रकटित:

गैर-चालू

आयकर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)
आयकर देयताएँ (शुद्ध)

-

-

-

-

चालू

आयकर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)
आयकर देयताएँ (शुद्ध)

39.55

71.27

39.55

71.27

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 11.2: आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	01.04.2024 तक शेष राशि	वर्ष के दौरान लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त/ (उलट)	वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	(₹ करोड़ में) 31.03.2025 तक शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां: (क)				
संदिग्ध अग्रिमों, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान	0.67	0.20		0.87
कर्मचारी लाभ	29.82	4.57		34.39
अन्य	0.06	0.12		0.18
कुल (क)	30.55	4.89	-	35.44
आस्थगित कर देयता: (ख)				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति से संबंधित	12.89	0.61		13.50
अन्य				
कुल (ख)	12.89	0.61	-	13.50
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (आस्थगित कर देयता) (ग=क-ख)				
"परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन डीटीएल(+)/डीटीए(-) (घ)"				
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति (ङ=ग+घ)	17.66	4.28	-	21.94
इस रूप में प्रकट किया गया:				
आस्थगित कर संपत्तियां	35.44			30.55
आस्थगित कर देयता	13.50			12.89
	21.94			17.66
31.03.2025 के अनुसार				
				31.03.2024 के अनुसार

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 12.1: परिचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

31.03.2025 को
समाप्त वर्ष के लिए

31.03.2024 को
समाप्त वर्ष के लिए

क. सेवाओं की बिक्री	2,478.18	2,041.36
घटाएँ: वैधानिक शुल्क	375.42	308.67
शुद्ध बिक्री (क)	2,102.76	1,732.69
ख. अन्य परिचालन राजस्व		
रेत भंडारण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सब्सिडी	-	-
लोडिंग और अतिरिक्त परिवहन शुल्क	-	-
घटाएँ: वैधानिक शुल्क (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	-	-
	-	-
निकासी सुविधा शुल्क	-	-
घटाएँ: वैधानिक शुल्क	-	-
	-	-
सेवाओं से राजस्व	-	-
घटाएँ: वैधानिक शुल्क	-	-
	-	-
अन्य परिचालन राजस्व (ख)	-	-
परिचालन से राजस्व (क+ख)	2,102.76	1,732.69

1) बिक्री में समूह के अंतर्गत सीआईएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों को दी गई सेवाएँ शामिल हैं। कुल राशि ₹1636.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1635.81 करोड़) और उस पर ₹249.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹248.09 करोड़) के शुल्क शामिल हैं; समूह के बाहर की सेवाओं में कुल ₹841.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹405.55 करोड़) और उस पर ₹125.82 करोड़ (पिछले वर्ष ₹60.58 करोड़) के शुल्क शामिल हैं। कुल बिक्री में ₹16.03 करोड़ की अनंतिम बिक्री शामिल है।

2) अनुबंध परिसंपत्तियां - बिल रहित राजस्व (भारतीय लेखा मानक 115 प्रकटीकरण)

31 मार्च 2025 तक, भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार अनुबंध परिसंपत्तियों के अंतर्गत 16.03 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष: 11.88 करोड़ रुपये) (जीएसटी के बिना) का बिल रहित राजस्व मान्यता प्राप्त कर लिया गया है। यह उन पूर्ण निष्पादन दायित्वों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है जहाँ बिलिंग और स्वीकृति लंबित हैं। कानूनी रूप से लागू अनुबंधों के तहत, ऐसे बिल रहित राजस्व पर मार्जिन कंपनी की रूढ़िवादी नीति के अनुरूप लागत पर मान्यता प्राप्त है। कंपनी को अनुबंध की शर्तों और ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर अगले परिचालन चक्र के भीतर इन राशियों का बिल और संग्रह करने की उम्मीद है। अनुबंध परिसंपत्तियों का मूल्यांकन वसूली योग्यता के लिए किया गया था, जिसमें कोई हानि संकेतक नहीं देखा गया। कंपनी क्रेडिट जोखिम और ऐतिहासिक वसूलियों के आधार पर सरलीकृत भारतीय लेखा मानक 109 दृष्टिकोण लागू करती है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी 12.2: अन्य आय

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	(₹ करोड़ में) 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	55.21	31.96
अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय से सीधे संबंधित व्यय को घटाकर)		-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.04	
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	0.04	0.03
पट्टा किराया	-	-
प्रावधान वापस लिखा गया	0.44	-
देयताएं वापस लिखी गईं	13.45	2.91
विविध आय	5.59	2.59
कुल	74.77	37.49
12.2.2 वापस लिखे गए प्रावधानों का विवरण		
निगमों और कर्मचारियों को दिए गए ऋणों के लिए (4.2.1)		
व्यापारिक प्राप्तियों के लिए (4.3.1)		0
वित्तीय जमाओं और प्राप्तियों के लिए (4.6.1)		
कोयला और भंडार सूची के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	0.44	
अन्य गैर-चालू जमाओं और अग्रिमों के लिए (6.1.1)		
अन्य चालू जमाओं और अग्रिमों के लिए (6.2.1)		
अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान	0.44	-

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी 13.1: प्रयुक्त सामग्री की लागत

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	(₹ करोड़ में) 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	-	-
लकड़ी	-	-
तेल और स्नेहक	13.91	14.11
एचईएमएम पुर्जे	0.31	0.36
अन्य उपभोग्य वस्तुएं और पुर्जे	16.41	17.02
कुल	30.63	31.49

टिप्पणी 13.2: तैयार माल, प्रगतिरत कार्य और व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2025	(₹ करोड़ में) समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024
कोयले का आरंभिक स्टॉक	-	-
जोड़ें: आरंभिक स्टॉक का समायोजन	-	-
घटाएँ: कोयले की गिरावट	-	-
कोयले का अंतिम स्टॉक	-	-
घटाएँ: कोयले की गिरावट	-	-
क कोयले की सूची में परिवर्तन	-	-
कार्यशाला में तैयार माल और डब्ल्यूआईपी का प्रारंभिक स्टॉक	-	-
जोड़ें: प्रारंभिक स्टॉक का समायोजन	-	-
घटाएँ: प्रावधान	-	-
कार्यशाला का अंतिम स्टॉक, तैयार माल और डब्ल्यू आई पी	-	-
कम: प्रावधान	-	-
ख कार्यशाला की सूची में परिवर्तन	-	-
प्रेस ओपनिंग जॉब	-	-
i) तैयार माल	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
कम: प्रेस समापन कार्य	-	-
i) तैयार माल	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
ग प्रेस जॉब के समापन स्टॉक की सूची में परिवर्तन	-	-
दवाओं का प्रारंभिक स्टॉक (केंद्रीय अस्पताल)	-	-
कम : दवाओं का अंतिम स्टॉक (केंद्रीय अस्पताल)	-	-
घ दवाओं के स्टॉक की सूची में परिवर्तन	-	-
व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन (क+ख+ग) { हास / (अभिवृद्धि) }	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी 13.3: कर्मचारी लाभ व्यय

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	(₹ करोड़ में) 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	494.20	498.75
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	95.06	122.22
कर्मचारी कल्याण व्यय	24.99	21.94
कुल	614.25	642.91

13.3.1 इसमें भत्ते, बोनस, प्रोत्साहन, प्रदर्शन संबंधी वेतन, ओवरटाइम वेतन, स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क आदि शामिल हैं।

13.3.2 गैर-कार्यपालकों के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एनसीडब्ल्यूए-XI) जून 2023 में लागू कर दिया गया है और संशोधित दर पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है। विवादित मामलों और कुछ अन्य मामलों को छोड़कर बकाया वेतन का भी भुगतान कर दिया गया है।

13.3.3 बीमांकिक मूल्यांकन के अंतर्गत आने वाले लाभों को छोड़कर विभिन्न कर्मचारी लाभों के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण टिप्पणी 9.1.1 में दिए गए हैं।

13.3.4 परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं के संबंध में भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण, जो एक्चुरियल मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, टिप्पणी 9.1 में प्रकट किए गए हैं।

13.3.5 वर्ष के दौरान भविष्य निधि के लिए 42.06 रुपये (पिछले वर्ष 45.70 रुपये), पेंशन निधि के लिए 23.14 रुपये (पिछले वर्ष 25.08 रुपये) और सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए 10.89 रुपये (पिछले वर्ष 10.82 रुपये) व्यय की पहचान की गई।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी 13.4: वित्तीय लागत

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	(₹ करोड़ में) 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज व्यय		
छूट की समाप्ति	0.09	0.06
अन्य उधार लागतें		
कुल	0.09	0.06

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13.5: मूल्यहास/परिशोधन/हानि

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यहास/परिशोधन/हानि		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (टिप्पणी 3.1)	30.30	27.04
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (टिप्पणी 3.2)	-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 3.3)	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 3.4)	4.73	6.06
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 3.5)	-	-
घटाएँ:		
वित्तपोषित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	1.55	1.56
कुल	33.48	31.54

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी 13.6 : संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन शुल्क:		
संयंत्र और उपकरणों का किराया	-	-
अन्य संविदात्मक कार्य	-	-
कुल	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी 13.7 : अन्य खर्चों

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली खर्च	3.60	3.18
मरम्मत और रखरखाव		
- भवन	21.28	17.58
- संयंत्र और उपकरण	15.10	13.33
- अन्य	4.33	3.78
यात्रा व्यय	29.18	21.92
प्रशिक्षण व्यय	2.24	1.75
टेलीफोन और इंटरनेट	4.00	5.56
विज्ञापन एवं प्रचार	2.56	1.94
माल ढुलाई शुल्क		-
विलंब शुल्क		-
सुरक्षा व्यय	24.51	24.36
सीआईएल का सेवा शुल्क	-	-
कानूनी व्यय	0.21	0.33
परामर्श शुल्क*	434.30	193.22
अंडर लोडिंग शुल्क	-	-
बिक्री/त्याग/सर्वेक्षण की गई संपत्तियों पर हानि	0.06	-
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक और व्यय		
- ऑडिट फीस के लिए	0.06	0.08
- कराधान मामलों के लिए	0.01	0.01
- अन्य सेवाओं के लिए	0.04	
- व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.48	0.34
आंतरिक एवं अन्य लेखापरीक्षा व्यय	0.95	0.92
पुनर्वास शुल्क		
पट्टा किराया एवं किराये के शुल्क	24.12	18.65
दरें एवं कर	1.58	1.57
बीमा	0.49	0.50
विनिमय दर भिन्नता पर हानि	0.01	0.04
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय		
साइडिंग रखरखाव शुल्क	-	-
अनुसंधान एवं विकास व्यय	0.03	0.04
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	2.77	2.17
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	9.79	7.66
दान, पुरस्कार एवं अनुदान		-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी 13.7 : अन्य खर्चों

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	(₹ करोड़ में) 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रावधान	0.79	1.07
बढ़े खाते में डालना (पूर्व में मान्य प्रावधानों के बढ़े खाते में डालने के बाद)	12.29	
विविध व्यय	22.16	11.34
कुल	616.94	331.34
13.4.1 प्रावधानों का विवरण		
निगमित निकायों और कर्मचारियों को दिए गए ऋणों के लिए (4.2.1)		
व्यापारिक प्राप्तियों के लिए (4.3.1)	0.79	0.10
वित्तीय जमाओं और प्राप्तियों के लिए (4.6.1)		
कोयला और भंडार सूची के लिए (5.1.1 और 5.1.2)		0.97
अन्य गैर-चालू जमाओं और अग्रिमों के लिए (6.1.1)		
अन्य चालू जमाओं और अग्रिमों के लिए (6.2.1)		
अवधि/वर्ष के दौरान कुल प्रावधान	0.79	1.07

* इसमें कोर ड्रिलिंग, भूभौतिकीय लॉगिंग, बोरहोल परीक्षण और अन्य क्षेत्र-आधारित तकनीकी सेवाओं जैसी विस्तृत अन्वेषण गतिविधियों के लिए एमईसीएल और अन्य ड्रिलिंग पक्षों के साथ अनुबंध शामिल हैं। ये गतिविधियाँ, यद्यपि परिचालनात्मक प्रकृति की हैं, सीएमपीडीआई के भूवैज्ञानिक रिपोर्टिंग, खदान नियोजन और संसाधन मूल्यांकन से संबंधित व्यापक परामर्श कार्यों के अभिन्न अंग हैं।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

13.8.2 सीएसआर व्यय का अनुलग्रक

क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार ब्यौरा (अतिरिक्त व्यय सहित):	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	7.04	5.54
विशेष शिक्षा और रोजगार सहित व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना	1.80	2.78
लैंगिक समानता और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	0.00	0.07
पर्यावरणीय स्थिरता	0.04	0.06
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण		-
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों को लाभ		
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण		
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोष में योगदान		
इनक्यूबेटर या अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में योगदान		
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान		
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ		
स्लम क्षेत्र विकास		
आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं		
प्रशासनिक व्यय	0.44	0.42
देयता राइट बैक		(0.06)
कुल	9.32	8.81

ख. आवश्यक सीएसआर व्यय और सीएसआर व्यय विवरण		
(क) वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ का 2%)।	9.78	7.66
(ख) वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि।	15.72	10.00
(ग) वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर व्यय की गई राशि:		
(i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण		
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए	9.32	8.81
कुल	9.32	8.81

ग. मान्यता प्राप्त सीएसआर व्यय और व्यय किए गए सीएसआर व्यय का मिलान	2024-25	2023-24
सीएसआर व्यय	9.32	8.81
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	2.77	
घटाएँ: आगे ले जाया गया अतिरिक्त	2.30	1.15
जोड़ें: चालू परियोजनाओं पर अप्रयुक्त सीएसआर व्यय		
जोड़ें: चालू सीएसआर के अलावा अन्य पर अप्रयुक्त सीएसआर व्यय		
लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त राशि	9.79*	7.66

* 9.79 करोड़ रुपये में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार 9.78 करोड़ रुपये (अर्थात पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%) और सीएसआर गतिविधि के लिए दिए गए फंड पर प्राप्त 0.01 करोड़ रुपये (कुल मूल्य 56,500 रुपये) ब्याज शामिल है।

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

घ. चल रही परियोजना के अलावा अन्य अप्रयुक्त राशि [धारा 135(5)]	2024-25	2023-24
प्रारंभिक जमा		
6 महीने के भीतर अनुसूची VII के विशिष्ट कोष में जमा किया गया		
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि		
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		

ड. अतिरिक्त व्यय की गई राशि [धारा 135(5)]				
वर्षवार विवरण	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	"वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि"	जमा शेष
2022-23		7.30	8.92	1.62
2023-24		7.66	8.81	1.15
2024-25	2.77	9.79	9.32	2.30

अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अन्य अग्रिम और जमा के लिए फुटनोट देखें

च. अव्ययित चालू परियोजना [धारा 135(6)] (वर्षवार)		2024-25	2023-24
प्रारंभिक जमा	कंपनी के साथ		
	अलग सीएसआर खाते में		
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि			
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	कंपनी के बैंक खाते से		
	अलग सीएसआर खाते में		
जमा शेष	कंपनी के साथ		
	अलग सीएसआर खाते में		

छ. सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान	2024-25	2023-24
प्रारंभिक जमा	1.44	3.16
अवधि के दौरान वृद्धि	0.47	1.44
वर्ष के दौरान समायोजन	1.44	3.16
अंतिम शेष	0.47	1.44

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी 14.1: कर व्यय

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2025	(₹ करोड़ में) समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024
चालू वर्ष	222.64	189.38
पिछले वर्ष	(3.13)	-
कुल वर्तमान कर	219.51	189.38
आस्थगित कर	(4.28)	40.23
कुल	215.23	229.61

कर व्यय और लेखांकन लाभ का समाधान	31.03.25 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.24 को समाप्त वर्ष के लिए
कर से पहले का लाभ	882.14	732.84
25.168% की आयकर दर पर	222.02	184.44
घटाएँ: अनुमत आय पर कर	20.55	13.57
जोड़ें: गैर-कटौती योग्य व्ययों पर कर	16.89	58.74
एमएटी प्रावधानों के अंतर्गत कर समायोजन	-	-
पिछले वर्ष के कर समायोजन	(3.13)	-
लाभ-हानि विवरण में दर्शाए गए आयकर व्यय	215.23	229.61
प्रभावी आयकर दर:	24.40	31.33

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

नोट 15.1: अन्य व्यापक आय

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2025	(₹ करोड़ में) समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024
(क) (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	(20.83) (20.83)	(13.73) (13.73)
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	(5.24) (5.24)	(3.46) (3.46)
कुल (क)	(15.59)	(10.27)
(ख) वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	(15.59)	(10.27)

15.1. यह आंकड़ा ग्रेच्युटी के संबंध में ₹-15.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹-6.30 करोड़) और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए ₹-5.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹-7.43 करोड़) को दर्शाता है।

वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

क. कॉर्पोरेट जानकारी

केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), एक भारत सरकार की कंपनी होने के नाते, परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित की गई थी। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों तथा अन्य बाहरी कंपनियों को भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, जलविज्ञानीय और पर्यावरणीय डेटा सृजन सहित कोयला और खनिज गवेषण में सहायता प्रदान करना था। सीएमपीडीआईएल कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक अनुसूची 'बी' / मिनीरल -श्रेणी-I सीपीएसई है। सीएमपीडीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसका पंजीकृत कार्यालय गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची - 834 031, झारखंड, भारत में स्थित है। 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹ 150.00 करोड़ और ₹ 142.80 करोड़ है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 30 अप्रैल, 2025 को जारी करने के लिए अनुमोदित किए गए थे।

ख. अनुपालन विवरण और हालिया लेखांकन घोषणाएँ

i) अनुपालन का बयान

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (जिन्हें आगे "इंड एस" कहा जाएगा) के अनुसार तैयार किए गए हैं। जारी, अधिसूचित और प्रभावी, ये भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के अधिकृत होने तक प्रभावी रहेंगे और इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से इन पर विचार किया जाएगा।

लेखांकन नीतियां सुसंगत रूप से लागू की जाती हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां किसी नए जारी किए गए लेखांकन मानक को प्रारंभ में अपनाया जाता है या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

ii) नये एवं संशोधित मानकों का अनुप्रयोग

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) समय-समय पर कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के अंतर्गत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। एमसीए ने 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाले किसी भी नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित नहीं किया है।

नोट 2: सामग्री लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत प्रोद्भव आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों

के, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक के अनुसार मापा जाता है।

ऐतिहासिक लागत परंपरा सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा के रूप में निर्धारित की जाती है जिसमें वह संचालित होती है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मानों को दो दशमलव अंकों तक 'करोड़ रुपये' में पूर्णांकित किया जाता है।

2.2. वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है।

किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब:

(क) यह परिसंपत्ति को मान्यता देने की उम्मीद करता है, या अपने सामान्य परिचालन चक्र में इसे बेचने या उपभोग करने का इरादा रखता है;

(ख) यह परिसंपत्ति को मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से रखता है;

(ग) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति को पहचानने की उम्मीद करता है; या

(घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य (जैसा कि भारतीय लेखा मानक 7 में परिभाषित है) है, जब तक कि परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विनिमय या देयता निपटान के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी द्वारा किसी देयता को चालू तब माना जाता है जब:

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता का निपटान करने की उम्मीद करता है;

(ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए दायित्व रखता है;

(ग) दायित्व का निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर किया जाना है; या

(घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, इक्विटी उपकरणों के निर्गम द्वारा इसके निपटान में परिणत हो सकती हैं, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए अपने परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में निर्धारित किया है।

2.3. राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

राजस्व मुख्य रूप से संबंधित सहायक सेवाओं और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होता है। उत्पादों की बिक्री से होने वाली आय को राजस्व के रूप में तब माना जाता है जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, यानी जब उत्पाद ग्राहक को वितरित किए जाते हैं। डिलीवरी तब होती है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया जाता है या वितरित कर दिया जाता है, जैसा भी मामला हो, और नुकसान के जोखिम बिक्री अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनीय प्रतिफल का अनुमान लगाने और प्रदान करने के लिए किया जाता है, सबसे संभावित विधि का उपयोग करते हुए, और राजस्व को केवल उस सीमा तक पहचाना जाता है, जब यह अत्यधिक संभावित हो कि कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। प्रतिफल की राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है क्योंकि बिक्री अनुबंधों के अनुसार भुगतान की शर्तें एक वर्ष से कम होती हैं।

कंपनी के पास भविष्य की अवधि में ग्राहकों को उत्पाद आपूर्ति करने के लिए कई दीर्घकालिक अनुबंध हैं। आम तौर पर, राजस्व को चालान के आधार पर पहचाना जाता है, क्योंकि बेची गई प्रत्येक इकाई एक अलग प्रदर्शन दायित्व है, और इसलिए ग्राहक से विचार का अधिकार सीधे हमारे आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन से मेल खाता है।

ब्याज

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है, जो वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को प्रारंभिक पहचान पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर सटीक रूप से छूट देती है।

अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित वसूली पर ब्याज सहित) के संबंध में राजस्व को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब अंतिम वसूली के संबंध में तार्किक सुनिश्चितता हो और राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि इस बात का उचित आश्वासन न मिल जाए कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी तथा इस बात की उचित निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त हो जाएगा।

सरकारी अनुदान को लाभ और हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी संबंधित व्यय या लागतों को मान्यता देती है, जिसके लिए अनुदान की सहायता ली जाती है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात परिसंपत्तियों के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को सामान्य शीर्षक 'अन्य आय' के अंतर्गत लाभ या हानि विवरण के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान/सहायता, जो पहले से किए गए व्यय या हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में या कंपनी को भविष्य में संबंधित लागतों के बिना तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्त होती है, उसे उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, जिसमें वह प्राप्त होती है।

प्रवर्तक के योगदान के रूप में सरकारी अनुदान या अनुदान को सीधे "पूंजी रिजर्व" में मान्यता दी जाती है जो "शेयरधारक निधि" का हिस्सा बनती है।

2.5 पट्टे

एक अनुबंध पट्टा कहलाता है, या पट्टा में निहित होता है, यदि अनुबंध, प्रतिफल के बदले में, एक निश्चित अवधि के लिए किसी चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। यदि अनुबंध में प्रतिफल के बदले में किसी समयावधि के लिए पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, तो अनुबंध पट्टा कहलाता है या उसमें पट्टा होता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या: (i) अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) कंपनी के पास पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ हैं और (iii) कंपनी के पास परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

प्रारंभिक तिथि पर, पट्टेदार को लागत पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को तथा उस तिथि को न चुकाए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मान्यता देनी होगी, बशर्ते कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके, किए गए पट्टा भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि को कम करके तथा किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधनों को दर्शाने के लिए वहन राशि को पुनः मापकर मापा जाता है।

लीज़ देयता को शुरू में भविष्य के लीज़ भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लीज़ भुगतानों को लीज़ में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन लीज़ की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि क्या वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी, तो लीज़ देयताओं को संबंधित उपयोग संपत्ति

के अधिकार के अनुरूप समायोजन के साथ पहले से मापा जाता है। लीज़ देयता और ROU परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और लीज़ भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लीज़ देयता दायित्वों को "वित्तीय देयताएँ" शीर्षक के अंतर्गत अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करते हुए किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यहास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है, यदि पट्टा अवधि के अंत तक पट्टाधारक को परिसंपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर देता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टाधारक खरीद विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टाधारक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यहास आरंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टा अवधि के अंत में से जो भी पहले हो, तक करेगा।

2.5.2 कंपनी पट्टेदार के रूप में

परिसंपत्तियों को या तो वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे पर दिया जाता है

वित्त पट्टा: यदि कोई पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करता है, तो उसे वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रारंभ में, वित्त पट्टे के तहत रखी गई परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त आय को पट्टे की अवधि में मान्यता दी जाती है, जो पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर वापसी की निरंतर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न पर आधारित होती है।

ऑपरेटिंग लीज़: एक लीज़ जिसे वित्तीय लीज़ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, एक ऑपरेटिंग लीज़ है। कंपनी ऑपरेटिंग लीज़ पर दी गई परिसंपत्तियों के मामले में लीज़ भुगतान को स्ट्रेट लाइन बेसिस पर आय के रूप में मान्यता देती है।

2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और मूल्यहास

पीपीई की किसी वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

पीपीई को शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत के आधार पर मापा जाता है, जिसमें आवश्यकतानुसार डीकमीशनिंग या बहाली लागत शामिल होती है। भूमि की लागत में वे व्यय शामिल होते हैं जो सीधे भूमि अधिग्रहण से संबंधित होते हैं, जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले मुआवजा आदि।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यहास और किसी भी संचित हानि को घटाकर उसकी लागत पर ले जाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत में शामिल हैं:

- (क) इसका क्रय मूल्य, जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसीयोग्य क्रय कर शामिल हैं, व्यापार छूट और रियायतें घटाने के बाद।
- (ख) परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कोई भी लागत।
- (ग) वस्तु को नष्ट करने और हटाने तथा उस स्थान को बहाल करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, जिसके लिए इकाई या तो वस्तु के अधिग्रहण के समय या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग सूची तैयार करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए करने के परिणामस्वरूप दायित्व वहन करती है।
- (घ) अर्हक परिसंपत्तियों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए गए उधार पर ब्याज को परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के प्रत्येक भाग की लागत, जो उस वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का अलग से मूल्यहास किया जाता है। हालांकि, मूल्यहास प्रभार निर्धारित करने में पीपीई के एक मद के महत्वपूर्ण भाग (भागों) को एक ही उपयोगी जीवन और मूल्यहास विधि के साथ समूहीकृत किया जाता है।

'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवाओं की लागतों को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय की जाती हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण भागों को बदलने की बाद की लागत को उस वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे; और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए गए भागों की वहन राशि को नीचे उल्लिखित मान्यता समाप्ति नीति के अनुसार मान्यता समाप्ति कर दी जाती है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को प्रतिस्थापन के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे; और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण की लागत की कोई भी शेष वहन राशि (भौतिक भागों से अलग) को मान्यता नहीं दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की किसी वस्तु की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब निपटान हो जाता है या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता। इससे होने वाला कोई भी लाभ या हानि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की ऐसी अमान्यता को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास, फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन बेसिस पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:



संपत्ति

अन्य भूमि (पट्टे पर ली गई भूमि सहित)

भवन (सड़कों सहित)

दूरसंचार

संयंत्र और उपकरण

कंप्यूटर और लैपटॉप

कार्यालय उपकरण

फ़र्निचर व फिक्सचर

वाहनों

उपयोगी जीवन

परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि, जो भी कम हो

3-60 वर्ष

3-9 साल

1-15 वर्ष

3 वर्ष

3-5 वर्ष

10 वर्ष

8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवन उस अवधि को सबसे अच्छी तरह दर्शाते हैं जिसके दौरान प्रबंधन को परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

कुछ परिसंपत्ति मदों जैसे अन्य भूमि, साइट पुनर्स्थापना परिसंपत्ति, अन्य खनन अवसंरचना, सर्वेक्षण की गई परिसंपत्तियों को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, जोड़ने/निपटाने के माह के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

"अन्य भूमि" के मूल्य में कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम, 2013, सरकारी भूमि का दीर्घकालिक हस्तांतरण आदि के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि शामिल है, जिसका परिशोधन परियोजना की शेष अवधि के आधार पर किया जाता है; और पट्टाधारित भूमि के मामले में ऐसा परिशोधन पट्टा अवधि या परियोजना की शेष अवधि, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

वे परिसंपत्तियां जो पूर्णतः मूल्यहासित हो चुकी हैं, तथा सक्रिय उपयोग से हटा ली गई हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र उपकरण के अंतर्गत अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षित परिसंपत्तियों के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है, तथा उनकी हानि के लिए जांच की जाती है।

भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन

कंपनी ने लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य जारी रखने का चुनाव किया (इंड एस में परिवर्तन की तिथि पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त इसकी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए, जिसे पिछले GAAP के अनुसार मापा गया है)

2.7

अमूर्त संपत्तियां और परिशोधन

अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर आरंभिक मान्यता पर मापा जाता है। लागत में संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय शामिल होता है। आरंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत में से किसी भी संचित मान्यता प्राप्त और संचित हानि हानि को घटाकर रखा जाता है।

अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की एक मद को निपटान पर या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता समाप्त कर दी जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया जाता है।

अमूर्त संपत्तियों के उपयोगी जीवन को या तो सीमित या अनिश्चित के रूप में आकलित किया जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है और जब भी ऐसा संकेत मिलता है कि अमूर्त संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो उनका मूल्यहास के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। संपत्ति में निहित भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित उपयोगी जीवन या अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने के लिए उचित माना जाता है, और उन्हें लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन, अमूर्त परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अमूर्त संपत्ति

एसएपी/ईआरपी

अन्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर

उपयोगी जीवन

6 साल

लाइसेंस अवधि

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उसकी क्षति के लिए जांच की जाती है।

शोध पर व्यय को व्यय के रूप में तब जोड़ा जाता है जब वह व्यय होता है। विकास पर व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन रखने का इरादा रखती है।

2.8 परिसंपत्तियों की क्षति (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई के उपयोग में मूल्य और निपटान की लागत को घटाकर उसके उचित मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है और इसे एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति ऐसी नकदी प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य परिसंपत्तियों या कंपनी की परिसंपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र हो, ऐसी स्थिति में वसूली योग्य राशि उस नकदी पैदा करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी क्षति के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग-अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है तथा हानि की क्षति को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.9 वित्तीय उपकरण

वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

2.9.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

2.9.1.1 प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, साथ ही लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार में विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित

समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है (नियमित तरीके से व्यापार) को व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, यानी, वह तिथि जिस पर कंपनी परिसंपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है। हालाँकि, व्यापार प्राप्य जिसमें एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है, उसे लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

2.9.1.2 अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण, व्युत्पन्न और इक्विटी उपकरण (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी उपकरण

2.9.1.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण

एक 'ऋण साधन' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

- क) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना है, और
- ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। हानि से होने वाली हानियों को लाभ या हानि में शामिल किया जाता है।

2.9.1.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन

एक 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

- क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और
- ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण लिखतों को प्रारंभ में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। हालाँकि, कंपनी ब्याज आय, हानि हानि और प्रतिवर्तन और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ और हानि (पी एंड एल) में मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण लिखत धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.9.1.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण साधन

एफवीटीपीएल, ऋण लिखतों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण लिखत, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी किसी ऐसे ऋण लिखत को नामित करने का चुनाव कर सकती है जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करता हो, जैसा कि एफवीटीपीएल में है। हालाँकि, ऐसा चुनाव केवल तभी अनुमत है जब ऐसा करने से माप या मान्यता संबंधी असंगति (जिसे 'लेखा विसंगति' कहा जाता है) कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। कंपनी ने किसी भी ऋण लिखत को एफवीटीपीएल के रूप में नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को पी एंड एल में सभी परिवर्तनों को मान्यता देते हुए उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.9.1.2.4 सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक को पहली बार अपनाना) के अनुसार , संक्रमण की तिथि पर पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि को अनुमानित लागत माना जाता है। इसके बाद, सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

भारतीय लेखा मानक 28 के पैरा 10 में निर्धारित इक्विटी पद्धति के अनुसार किया जाता है।

2.9.1.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में आने वाले अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

कंपनी उचित मूल्य में बाद में होने वाले परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी यह चुनाव उपकरण-दर-उपकरण आधार पर करती है। यह वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है।

एफवीटीओसीआई में वर्गीकृत किसी इक्विटी उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। लाभ-हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का बाद में कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी में स्थानांतरित कर सकती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांश को लाभ-हानि विवरण में "अन्य आय" के रूप में मान्यता दी जाती है, जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी उपकरणों को पी एंड एल में सभी परिवर्तनों को मान्यता देते हुए उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.9.1.3 अमान्य करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों वाली कंपनी का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से तब अमान्य कर दिया जाता है (अर्थात बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है) जब:

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या
- कंपनी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या 'पास-श्रु' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना किसी देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण कर लिया है; और या तो (क) कंपनी परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या ख) कंपनी उसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और लाभों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही उन्हें बरकरार रखा है, लेकिन उसने परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।

जब कंपनी किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या पास-श्रु व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब उसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही उन्हें बरकरार रखा है, और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया है, तो कंपनी कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबद्ध देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी के अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी के रूप में निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि और कंपनी द्वारा चुकाए जाने वाले प्रतिफल की अधिकतम राशि के बीच के निम्नतम स्तर पर मापा जाता है।

2.9.1.4 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और ऋण जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

- क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं जैसे, ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक बैलेंस
- ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और एफवीटीओसीआई के अनुसार मापी जाती हैं
- ग) भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य
- घ) व्यापार प्राप्य या नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो भारतीय लेखा मानक 115 के दायरे में आने वाले लेनदेन से उत्पन्न होता है

कंपनी निम्नलिखित पर हानि क्षति भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है:

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य; तथा
- भारतीय लेखा मानक 116 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न सभी पट्टा प्राप्ति

सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक पहचान से ही, आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देता है।

2.9.2 वित्तीय देयताएं

2.9.2.1 प्रारंभिक पहचान और माप

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण और उधार शामिल हैं। सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, तथा ऋणों, उधारों और देयताओं के मामले में, प्रत्यक्ष रूप से देय लेनदेन लागतों को घटाकर मान्यता दी जाती है।

2.9.2.2 अनुवर्ती माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

2.9.2.2.1 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियाँ और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को ट्रेडिंग के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी ट्रेडिंग के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखे गए दायित्वों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.9.2.2.2 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में पहचाना जाता है जब देनदारियों को मान्यता से हटा दिया जाता है और साथ ही प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी पहचाना जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग हैं। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

2.9.2.3 अमान्य करना

वित्तीय दायित्व तब अमान्य हो जाता है जब दायित्व के अंतर्गत दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की अमान्यता और एक नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। किसी वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व के भाग) की वहन राशि, जिसे समाप्त कर दिया गया है या किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया है और भुगतान किए गए प्रतिफल, जिसमें हस्तांतरित कोई भी गैर-नकद परिसंपत्ति या ग्रहण की गई देनदारियां शामिल हैं, के बीच का अंतर लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त होगा।

2.9.2.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण इंस्ट्रूमेंट हैं, पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव होता है। व्यवसाय मॉडल में बदलाव अक्सर नहीं होने की उम्मीद है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसाय मॉडल में बदलाव का निर्धारण करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे बदलाव बाहरी पक्षों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में बदलाव तब होता है जब कंपनी अपने संचालन के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि शुरू करती है या करना बंद कर देती है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है, तो यह पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से लागू करती है जो व्यवसाय मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद की अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ, हानि (क्षति लाभ या हानि सहित) या ब्याज को फिर से नहीं बताती है।

निम्न तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण और उनके हिसाब का तरीका दर्शाती है

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन उपचार
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को पी&एल में मान्यता दी जाती है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई सकल वहन राशि बन जाती है। इआइआर की गणना नई सकल वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। पुनर्वर्गीकरण के कारण इआइआर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन उपचार
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई परिशोधित लागत वहन राशि बन जाती है। हालाँकि, ओसीआई में संचयी लाभ या हानि को उचित मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। परिणामस्वरूप, परिसंपत्ति को इस तरह मापा जाता है जैसे कि इसे हमेशा परिशोधित लागत पर मापा जाता था।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई वहन राशि बन जाती है। किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी है। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर पी&एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.9.2.5 वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने, परिसंपत्तियों की वसूली करने और देयताओं का एक साथ निपटान करने का इरादा है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को समेकित बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है।

2.9.2.6 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

उचित मूल्य वह मूल्य है जो वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

कंपनी उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है, जो ऐसे माप के लिए प्रयुक्त इनपुट के अवलोकन की क्षमता पर निर्भर करता है:

- (क) स्तर 1: इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं।
- (ख) स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हैं।
- (ग) स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अवलोकनीय इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

कंपनी के पास उचित मूल्यों के मापन के संबंध में एक स्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है, जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापनों की देखरेख की समग्र जिम्मेदारी है, जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट, मूल्यांकन समायोजन और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करती है जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.9.3 नकद और नकद समकक्ष

बैलेंस शीट में नकदी और नकदी समतुल्य में बैंकों में और हाथ में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के उद्देश्य के लिए, नकदी और नकदी समतुल्य में नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के शुद्ध क्योंकि उन्हें कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.10 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और स्थगित कर का योग दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है। कर योग्य लाभ "आयकर से पहले लाभ" से भिन्न होता है जैसा कि लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में रिपोर्ट किया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की ऐसी मदें शामिल नहीं हैं जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और इसमें ऐसी मदें भी शामिल नहीं हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताओं को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर सद्भावना से या किसी ऐसे लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यावसायिक संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है और न ही लेखांकन लाभ को।

सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देनदारियों को मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर को उलटने पर नियंत्रण करने में सक्षम है और यह संभावना है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं होगा। ऐसे निवेशों और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि अस्थायी अंतरों के लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होंगे।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि परिसंपत्ति के सभी या भाग को वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अपरिचित आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या भाग को वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें देयता का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है, जो कर दर (और कर कानूनों) पर आधारित होती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा के अनुसार होंगे।

चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जिस स्थिति में, चालू और आस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां चालू कर या आस्थगित कर किसी व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, वहां कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है, जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो, तथा जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देनदारियां एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य इकाइयों पर लगाए गए आयकरों से संबंधित हों, जहां शेष राशि का निपटान शुद्ध आधार पर करने का इरादा हो।

2.11 कर्मचारी लाभ

2.11.1 अल्पकालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ वे कर्मचारी लाभ हैं (समाप्ति लाभों के अलावा) जिनका भुगतान उस वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के बारह महीने से पहले पूर्ण रूप से किया जाना अपेक्षित होता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.11.2 रोजगार के बाद के लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.11.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजना एक रोजगार-पश्चात लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग से बनाए गए फंड में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.11.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक रोजगार-पश्चात लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण परिभाषित लाभ योजनाएँ हैं (लाभों पर अधिकतम सीमा के साथ)। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाकर की जाती है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पिछली अवधि में अपनी सेवा के बदले में अर्जित की है। लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटाया जाता है, यदि कोई हो। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित है, जिनकी परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों के करीब हैं और जो उसी मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं जिसमें लाभ का भुगतान किए जाने की उम्मीद है।

एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट दर, परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दरें, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि के बारे में धारणा बनाना शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, ऐसे अनुमान अनिश्चितताओं के अधीन हैं। प्रत्येक बैलेंस शीट पर एक एक्चुररी द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके गणना की जाती है। जब गणना के परिणामस्वरूप कंपनी को लाभ होता है, तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति योजना से किसी भी भविष्य की वापसी या योजना में भविष्य के योगदान में कमी के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है। कंपनी को एक आर्थिक लाभ तब उपलब्ध होता है जब यह योजना के जीवनकाल के दौरान या योजना देनदारियों के निपटान पर प्राप्त किया जा सकता है।

शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन, जिसमें योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज को छोड़कर) और परिसंपत्तियों की अधिकतम सीमा (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) के प्रभावों पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ और हानि शामिल है, को अन्य व्यापक आय में तुरंत मान्यता दी जाती है। कंपनी वार्षिक अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर को तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर लागू करके अवधि के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है, योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए। परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित शुद्ध ब्याज व्यय और अन्य व्यय लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त हैं।

जब योजना के लाभों में सुधार किया जाता है, तो कर्मचारियों द्वारा पूर्व सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को लाभ और हानि विवरण में तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.11.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, रोजगार-पश्चात लाभ और सेवा समाप्ति लाभ को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे मदें शामिल हैं, जिनका निपटान वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, की समाप्ति के बारह महीने बाद तक पूर्ण रूप से होने की उम्मीद नहीं है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का शुद्ध योग लाभ या हानि विवरण में पहचाना जाता है:

- क. सेवा लागत
- ख. शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज
- ग. शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का पुनः मापन

2.12 विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्राओं में किए गए लेन-देन को लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के निपटान पर या मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को उन दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तित करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर परिवर्तित किया गया था, उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक वस्तुओं का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

2.13 इन्वेंट्री

2.13.1 स्टोर, स्पेयर्स और अन्य इन्वेंट्री

अन्य इन्वेंटरी सहित भंडार और अतिरिक्त सामान के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत पद्धति के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और स्पेयर्स के लिए 100% की दर से प्रावधान किया जाता है, तथा 5 वर्षों तक स्थानांतरित न किए गए स्टोर और स्पेयर्स के लिए 50% की दर से प्रावधान किया जाता है।

2.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है, वहां प्रावधान दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर बताए जाते हैं।

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए उन्हें समायोजित किया जाता है।

जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर-दूर तक न हो। संभावित दायित्व, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर-दूर तक न हो।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संभावित परिसंपत्तियाँ हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास वित्तीय विवरणों में उचित रूप से परिलक्षित हो।

2.15 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर तनु आय की गणना कर के बाद लाभ को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है और साथ ही उन इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या भी जो सभी तनु संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे।

2.16 निर्णय, अनुमान और मान्यताएँ

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को ऐसे अनुमान, निर्णय और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करते हैं। इन वित्तीय विवरणों में जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों और धारणाओं के उपयोग से जुड़ी लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन अनुमान अवधि दर अवधि बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमान में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि महत्वपूर्ण हैं, तो उनके प्रभावों का खुलासा वित्तीय विवरणों के नोट्स में किया जाता है।

2.16.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है:

वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

2.16.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण

लेखांकन नीतियों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वित्तीय विवरणों में लेन-देन, अन्य घटनाओं और उन स्थितियों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी शामिल हो, जिन पर वे लागू होती हैं। जब उन्हें लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हो, तो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

किसी लेनदेन, अन्य घटना या स्थिति पर विशिष्ट रूप से लागू होने वाले भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के अभाव में, प्रबंधन ने लेखांकन नीति को विकसित करने और लागू करने में अपने विवेक का उपयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है:

क. उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक और

ख. वित्तीय विवरण विश्वसनीय हैं और:

(i) इकाई की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करें; (ii) लेनदेन, अन्य घटनाओं और स्थितियों के आर्थिक सार को प्रतिबिंबित करें, न कि केवल कानूनी रूप को; (iii) तटस्थ हों, अर्थात् पूर्वाग्रह से मुक्त हों; (iv) विवेकपूर्ण हों; और (v) सभी भौतिक मामलों में सुसंगत आधार पर पूर्ण हों

निर्णय लेने में प्रबंधन अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों का संदर्भ लेता है और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है:

(क) समान और संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताएं; और

(ख) फ्रेमवर्क में परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय के लिए परिभाषाएं, मान्यता मानदंड और माप अवधारणाएं।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं और उनके अभाव में अन्य मानक-निर्धारक निकायों की घोषणाओं पर विचार करता है, जो लेखांकन मानकों को विकसित करने के लिए समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं, अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग प्रथाओं पर विचार करता है, इस सीमा तक कि ये भारतीय लेखांकन मानक और लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के साथ संघर्ष नहीं करते हैं, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में कहा गया है।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है (ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन और विकास उत्पादन चरण कई दशकों तक चलने वाली लीज़ अवधि में फैले विभिन्न स्थलाकृतिक और भू-खनन भूभाग पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तनों के लिए प्रवण होते हैं), जिसकी लेखांकन नीतियां अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग प्रथाओं के आधार पर विकसित हुई हैं और पिछले कई दशकों में इसके लगातार आवेदन के कारण विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदित हैं। विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन और मानकों की अनुपस्थिति में कुछ विशिष्ट क्षेत्र जो विकास की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के अनुरूप लेखांकन नीतियों को विकसित करने का प्रयास जारी रखती है और इसमें किसी भी विकास को ऊपर और अधिक विशेष रूप से भारतीय लेखा मानक 8 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भावी रूप से हिसाब में लिया जाएगा।

2.16.1.2 माह्दा

भारतीय लेखा मानक उन मदों पर लागू होता है जो महत्वपूर्ण हैं। प्रबंधन यह तय करने में विवेक का उपयोग करता है कि वित्तीय विवरणों में व्यक्तिगत मदें या मदों का समूह महत्वपूर्ण हैं या नहीं। महत्वपूर्णता का निर्धारण मदों की प्रकृति या परिमाण या दोनों के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या किसी सूचना को छोड़ना या गलत तरीके से प्रस्तुत करना या अस्पष्ट करना व्यक्तिगत रूप से या अन्य सूचनाओं के साथ मिलकर उन निर्णयों को प्रभावित कर सकता है जो प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखा मानक की अनुपालन आवश्यकता निर्धारित करने के लिए भी महत्वपूर्णता के विवेक का उपयोग करता है। इसके अलावा, कंपनी को कानून द्वारा अपेक्षित होने पर अलग से महत्वहीन मदों को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

दिनांक 01.04.2019 से पूर्व अवधियों से संबंधित चालू वर्ष में पाई गई त्रुटियों/चूक को महत्वहीन माना जाएगा तथा चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाएगा, यदि ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कुल मिलाकर कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार परिचालन से प्राप्त कुल राजस्व (वैधानिक शुल्कों को छोड़कर) के 1% से अधिक न हों।

2.16.2 अनुमान और मान्यताएँ

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएँ, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित हैं। कंपनी ने अपनी धारणाएँ और अनुमान वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर आधारित किए। हालाँकि, भविष्य के विकास के बारे में मौजूदा परिस्थितियाँ और धारणाएँ, बाज़ार में होने वाले बदलावों या ऐसी परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब वे धारणाओं में परिलक्षित होते हैं।

अनुमान, निर्णय और संबंधित धारणाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग जिसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय और लेखांकन अनुमान की आवश्यकता होती है, जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं का उपयोग नीचे बताया गया है:

2.16.2.1 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

हानि का संकेत तब मिलता है, जब किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, जो उसके उचित मूल्य में से निपटान की लागत घटाकर और उसके उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, होती है। हानि के परीक्षण के उद्देश्य से कंपनी अलग-अलग खानों को अलग-अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग में मूल्य की गणना DCF मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के बजट से प्राप्त होते हैं और इसमें पुनर्गठन गतिविधियाँ शामिल नहीं होती हैं, जिनके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश जो परीक्षण किए जा रहे CGU की परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। वसूली योग्य राशि DCF मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ अपेक्षित भविष्य के नकदी-प्रवाह और एक्सट्रपलेशन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील होती है।

2.16.2.2 आयकर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर घाटे के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध घाटे का उपयोग किया जा सकता है। संभावित समय और भविष्य के कर योग्य मुनाफे के स्तर के साथ-साथ भविष्य की कर नियोजन रणनीतियों के आधार पर, मान्यता प्राप्त करने योग्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.16.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजना और अन्य रोजगार-पश्चात चिकित्सा लाभों की लागत और दायित्वों का वर्तमान मूल्य एक्चुरियल मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक्चुरियल मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है।

मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन के लिए सबसे अधिक विषयगत पैरामीटर छूट दर है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन रोजगार के बाद के लाभ दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में सरकारी बांड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। ये मृत्यु दर तालिकाएँ जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में अंतराल पर ही बदलती हैं।

2.16.2.4 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार किसी परियोजना के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति का पूंजीकरण किया

जाता है। लागतों का आरंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर जब कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे मंजूरी दी जाती है।

टिप्पणी – 16: वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी:

1. उचित मूल्य मापन

क. श्रेणी के अनुसार वित्तीय उपकरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिनके उचित मूल्य का खुलासा किया जाता है।	31 मार्च 2025		31 मार्च 2024	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ एफवीटीपीएल				
निवेश :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वरीयता शेयरों				
-इक्विटी अवयव				
-ऋण अवयव				
-अन्य निवेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऋण	शून्य	0.58	शून्य	0.34
जमा और प्राप्य	शून्य	179.22	शून्य	125.53
व्यापार प्राप्तियों	शून्य	943.68	शून्य	984.37
नकद और नगदी समकक्ष	शून्य	280.17	शून्य	266.87
अन्य किनारा शेष	शून्य	800.00	शून्य	330.00
वित्तीय देयताएं				
उधार लेना और पट्टा	शून्य	1.15	शून्य	1.31
व्यापार देय	शून्य	200.12	शून्य	104.64
सुरक्षा जमा और बयाना राशि	शून्य	97.75	शून्य	94.49
अन्य देयताएं	शून्य	76.24	शून्य	76.61

ख. उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका उन वित्तीय साधनों के उचित मूल्य निर्धारण में किए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जो (क) उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त और मापे गए हैं और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए हैं और जिनके उचित मूल्य वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त इनपुट की विश्वसनीयता का संकेत देने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के अंतर्गत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ	31 मार्च 2025		31 मार्च 2024	
	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ एफवीटीपीएल				
निवेश :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आपसी फंड/आईसीडी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय देयताएं				
यदि कोई वस्तु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(₹ करोड़ में)

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिनके उचित मूल्य का खुलासा किया जाता है।	31 वीं मार्च 2025		31 मार्च 2024	
	लेवल 2	स्तर 3	लेवल 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ एफवीटीपीएल				
निवेश :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वरीयता शेयरों				
-इक्विटी अवयव				
-ऋण अवयव				
-अन्य निवेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऋण	शून्य	0.58	शून्य	0.34
जमा और प्राप्त	शून्य	179.22	शून्य	125.53
व्यापार प्राप्तियों	शून्य	943.68	शून्य	984.37
नकद और नगदी समकक्ष	शून्य	280.17	शून्य	266.87
अन्य बैंक अधिशेष	शून्य	800.00	शून्य	330.00
वित्तीय देयताएं				
उधारी	शून्य	1.15	शून्य	1.31
व्यापार देय	शून्य	200.12	शून्य	104.64
सुरक्षा जमा और बयाना राशि	शून्य	97.75	शून्य	94.49
अन्य देयताएं	शून्य	76.24	शून्य	76.61

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

स्तर 2: सक्रिय बाज़ार में कारोबार न करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकनीय बाज़ार आँकड़ों का अधिकतम उपयोग करती हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करती हैं। यदि किसी साधन के उचित मूल्य निर्धारण के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय हैं, तो उस साधन को स्तर 2 में शामिल किया जाता है। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर समापन शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके किया

जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह स्तर 3 में शामिल निवेश, सुरक्षा जमा और अन्य देनदारियों के मामले में है।

ग. उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में शामिल हैं:

म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में उपकरणों के उद्भूत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग।

घ. महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप उपलब्ध नहीं है।

ड.. परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

- व्यापार प्राप्त, अल्पावधि जमा, नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार देयताओं की अग्रणीत राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण, उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।
- कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखना आवश्यक है। प्रत्येक मील के पथर के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकना कंपनी के हितों की रक्षा करने के लिए है, ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल होने से। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के रूप में माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी एक विधि का चयन करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणाएँ बनाती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियाँ:

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय राशियाँ शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन को समर्थन देने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्त राशियाँ, और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित हैं और वित्तीय जोखिमों

की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनसे सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट उन जोखिम स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे इकाई को सामना करना पड़ता है और यह बताता है कि इकाई जोखिम का प्रबंधन कैसे करती है और वित्तीय विवरणों में बचाव लेखांकन का क्या प्रभाव पड़ता है।

जोखिम	इससे उत्पन्न जोखिम	माप	प्रबंध
ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य वित्तीय परिसंपत्ति परिशोधित लागत पर मापी जाती है	आयु विश्लेषण/ क्रेडिट विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भावी वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जो भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित नहीं हैं	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकदी और नकदी समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है, साथ ही अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियां भी प्रदान करता है।

क. ऋण जोखिम : ऋण जोखिम तब उत्पन्न होता है जब कोई प्रतिपक्ष संविदात्मक दायित्वों का पालन करने में चूक करता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि होती है। प्रतिपक्ष द्वारा व्यापार प्राप्तियों के चूक जोखिम का प्रबंधन प्रतिभूति जमा, अग्रिम, बैंक गारंटी आदि जैसे वित्तीय आश्वासनों द्वारा किया जाता है।

ख. अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान: कंपनी संदिग्ध/ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण जोखिम हानि के लिए आजीवन अपेक्षित ऋण हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा प्रावधान करती है। नोट - 4.3, व्यापार प्राप्य देखें

महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

ऊपर बताए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट चुनने में विवेक का उपयोग करती है, जो कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों पर आधारित है।

ग. तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना है और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी का राजकोष प्रतिबद्ध ऋण लाइनों के अंतर्गत उपलब्धता

बनाए रखकर वित्तपोषण में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति (जिसमें अप्रयुक्त उधार सुविधाएं शामिल हैं) और नकदी एवं नकदी समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है।

कोल इंडिया लिमिटेड के बैंक उधारों को बैंकों के संघ के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के कोयले, भंडार और स्पेयर पार्ट्स के स्टॉक तथा बही ऋणों के विरुद्ध प्रभार सृजित करके सुरक्षित किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास उपलब्ध कुल कार्यशील पूंजी ऋण सीमा ₹430.00 करोड़ है, जिसमें से निधि आधारित सीमा ₹140.00 करोड़ और गैर-निधि आधारित सीमा ₹290.00 करोड़ है। व्यवस्था के विवरण के लिए j-अन्य महत्वपूर्ण मामले देखें।

घ. बाज़ार जोखिम

क. विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है, जो ऐसी मुद्रा में मूल्यांकित होती हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (INR) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी के पास एक नीति है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ख. नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम।

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमाराशियों से उत्पन्न होता है, ब्याज दर में परिवर्तन के कारण कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम का सामना करना पड़ता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमाराशियों को निश्चित दर पर बनाए रखने की है। कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

पूंजी प्रबंधन

चूंकि यह कंपनी एक सरकारी इकाई है, इसलिए यह अपनी पूंजी का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025	31.03.2024
इक्विटी शेयर पूंजी	142.80	142.80
लंबी अवधि के ऋण	शून्य	शून्य

3. कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (इंड एस-19)

परिभाषित लाभ योजनाएँ:

क. ग्रेच्युटी

कंपनी ग्रेच्युटी, एक रोजगार-पश्चात परिभाषित लाभ योजना ("ग्रेच्युटी योजना") प्रदान करती है, जो पात्र कर्मचारियों को कवर करती है। ग्रेच्युटी भुगतान कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है, जो कंपनी से अलग होने के समय ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के संशोधित प्रावधानों पर विचार करते हुए अधिकतम ₹ 20 लाख तक होता है। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जिसमें योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक्चुअरी द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजन और एक्चुरियल मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनर्मापन लाभ और हानि को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं, सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में।

ग्रेच्युटी योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। एलआईसी सेवा के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में एक बीमा कवरेज (जीवन बीमा राशि- "एलसीएसए") भी प्रदान करता है, जो अंतिम आहरित वेतन के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति तिथि पर देय अनुमानित ग्रेच्युटी राशि में कमी की भरपाई करता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 20 लाख है।

ख. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ – अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना है जिसे सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई) के रूप में जाना जाता है, जो अधिकारियों, उनके जीवनसाथियों और पूरी तरह से आर्थिक रूप से आश्रित दिव्यांग बच्चे (बच्चों) को कंपनी के अस्पताल/सूचीबद्ध अस्पतालों या बाह्य रोगी/घर में केवल भारत में किसी भी विकलांगता के कम से कम 40% से पीड़ित होने पर सीलिंग लिमिट के अधीन चिकित्सा प्रदान करती है, जो कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर अलग किए जाने या सामान्य कोयला कैडर के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति या समय-समय पर तैयार और लागू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण होती है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। सेवानिवृत्त अधिकारियों, जीवनसाथियों और आश्रित दिव्यांग बच्चे (बच्चों) के लिए पूरे जीवनकाल के दौरान संयुक्त रूप से या अलग-अलग प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये योजना के लिए देयता की पहचान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

ग. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ – कर्मचारी (सीपीआरएमएस-एनई)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी गैर-अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई-एनई) प्रदान कर रही है, ताकि गैर-अधिकारियों और उनके जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) को कंपनी अस्पताल/सूचीबद्ध अस्पतालों या बाह्य रोगी/घरेलू में चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा सके, जो कि छत की सीमा के अधीन है, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या कंपनी द्वारा चिकित्सा

आधार पर अलग किए जाने या समय-समय पर तैयार और लागू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति या 57 वर्ष या उससे अधिक की आयु में कंपनी से इस्तीफा देने या जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चे(बच्चों) की मृत्यु पर। सेवानिवृत्त गैर-अधिकारियों और जीवनसाथी को संयुक्त रूप से या अलग-अलग साथ में पूरे जीवनकाल के दौरान प्रतिपूर्ति की जाने वाली अधिकतम राशि 8 लाख रुपये है, योजना के लिए देयता की पहचान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

परिभाषित अंशदान योजनाएँ

क. भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर पूर्व-निर्धारित दरों पर भविष्य निधि और पेंशन निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, अर्थात मूल वेतन का 12% और 7% और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता क्रमशः भविष्य निधि और पेंशन निधि में। इन निधियों को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में एक अलग वैधानिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) कहा जाता है। अवधि के लिए निधि में योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख. सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अपने अधिकारियों को नौकरी के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे "सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना -2007" (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को इस उद्देश्य के लिए गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। कंपनी का दायित्व ट्रस्ट में मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक राशि का योगदान नहीं करना है, जिसमें भविष्य निधि, ग्रेजुटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - कार्यकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं है। मूल और महंगाई भत्ते का 6.99% वर्तमान नियोक्ता योगदान लाभ और हानि के विवरण में लगाया जा रहा है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क. अवकाश नकदीकरण

कंपनी अपने अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों की अर्ध-भुगतान छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्ध-वार्षिक आधार पर आनुपातिक रूप से अर्जित और जमा की जाती है। सेवा के दौरान, 75% ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों की ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। सेवा की अवधि के दौरान संचित एचपीएल को नकदीकरण के लिए अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ नकदीकरण के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्प्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। कर्मचारियों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित होता है और वर्तमान में कामगार प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित छुट्टी का नकदीकरण पाने के हकदार हैं और मृत्यु, सेवानिवृत्ति, सुपरएनुएशन और वीआरएस के कारण सेवा बंद होने पर, शेष छुट्टी या 150 दिन जो भी कम हो, नकदीकरण के लिए अनुमत है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों का भुगतान सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद किया जाना अपेक्षित है।

इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतानों के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। लाभों की छूट रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाज़ार प्रतिफल का उपयोग करके की जाती है, जिसकी शर्तें संबंधित दायित्व की शर्तों के लगभग बराबर होती हैं। इस योजना का वित्तपोषण भारतीय जीवन बीमा निगम की योग्य बीमा पॉलिसियों द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

ख. जीवन कवर योजना (एलसीएस)

सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, समूह के पास "कोल इंडिया लिमिटेड की जीवन बीमा योजना" (LCS) नामक एक जीवन बीमा योजना है, जो सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कवर करती है। सेवाकाल में मृत्यु होने पर, इस योजना के अंतर्गत नामांकित व्यक्तियों को ₹1,25,000 (अधिकारी) और ₹1,56,250 (कर्मचारी) की राशि 01.06.2023 से भुगतान की जाती है। लाभ की अपेक्षित लागत तब निर्धारित की जाती है जब कोई ऐसी घटना घटती है जिसके कारण योजना के अंतर्गत लाभ देय होता है।

ग. निपटान भत्ते

वेतन समझौते के एक हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद उनकी सेवानिवृत्ति पर सेटलमेंट-इन भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

घ. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सीआईएल समूह के अधिकारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना से बचाने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है, जिसे "कोल इंडिया एग्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (जीपीएआईएस) के नाम से जाना जाता है। जीपीएआईएस दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। इस योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान सीआईएल द्वारा किया जाता है।

ङ. यात्रा भत्ता योजना

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, गैर-कार्यकारी कर्मचारी 4 वर्ष के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए क्रमशः 10000/- रुपये और 15000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तपोषण स्थिति निम्नानुसार है:

(i) वित्त पोषित		(ii) अविक्त पोषित	
➤ उपदान		➤ लाइफ कवर स्कीम	
➤ अवकाश नकदीकरण		➤ सेटलमेंट भत्ता	
➤ सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - अधिकारी(सीपीआरएमएसई)		➤ समूह निजी दुर्घटना बीमा	
➤ सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - कर्मचारी (सीपीआरएमएस - एनई)		➤ छुट्टी यात्रा रियायत	

एक्चुअरी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर कुल देयता, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

सिर	प्रारंभिक एक्चुरियल देयता 01.04.2023	वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता	प्रारंभिक बीमांकिक देयता 31.03.2024	वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता	समापन बीमांकिक देयता 31.03.2025
उपदान	155.00	6.50	161.50	4.56	166.06
अवकाश अधिकारी	84.62	10.16	94.78	-0.76	94.02
अवकाश कर्मचारी	24.00	5.4	29.40	3.15	32.55
निपटान भत्ता अधिकारी	3.85	0.09	3.94	0.07	4.01
निपटान भत्ता कर्मचारी	0.44	-0.02	0.42	-0.01	0.41
अवकाश यात्रा रियायत	2.46	-0.01	2.45	1.2	3.65
चिकित्सा लाभ अधिकारी	62.12	4.40	66.52	1.90	68.42
चिकित्सा लाभ कर्मचारी	26.20	1.24	27.44	3.32	30.76
कुल	358.69	27.76	386.45	13.43	399.88

(iii) एक्चुअरी के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

31.03.2025 तक ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1:

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	क. लाभ और हानि (पी एंड एल)	31.03.2025
4.46	वर्तमान सेवा लागत	4.95
6.17	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	0.00
-	कटौती लागत / (क्रेडिट)	0.00
-	निपटान लागत / (क्रेडिट)	0.00
10.64	सेवा लागत	4.95
(0.65)	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	-0.55
-	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00
9.99	P&L में मान्यता प्राप्त लागत	4.40

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	ख: अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	31.03.2025
1.57	डीबीओ अनुभव के कारण एक्चुरियल (लाभ)/हानि	7.61
4.85	डीबीओ धारणा में परिवर्तन के कारण एक्चुरियल (लाभ)/हानि	7.38
6.42	अवधि के दौरान होने वाली एक्चुरियल (लाभ)/हानि	14.98
(0.13)	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम	0.20
6.30	ओसीआई में मान्यता प्राप्त एक्चुरियल (लाभ)/ हानि	15.18

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	ग: परिभाषित लाभ लागत	31.03.2025
10.64	सेवा लागत	4.95
(0.65)	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	-0.55
6.30	ओसीआई में मान्यता प्राप्त एक्चुरियल (लाभ)/ हानि	15.18
-	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00
16.28	परिभाषित लाभ लागत	19.59

(₹ करोड़ में)

31.03.2023	घ: वर्तमान में मान्यताएं	31.03.2024
7.30%	छूट की दर	7.00%
अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%	वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%

तालिका 2 :

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	क: निवल बैलेंस शीट स्थिति का विकास	31.03.2025
(161.50)	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	-166.06
167.18	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	156.53
5.68	वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	-9.53
-	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	0.00
5.68	शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-9.53

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	ख: शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का समाधान	31.03.2025
(4.17)	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	5.68
(10.64)	सेवा लागत	-4.95
0.65	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	0.55
(6.30)	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	-15.18
26.14	नियोक्ता योगदान	4.37
-	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	0.00
-	अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)	0.00
-	विनिवेश	0.00
-	समाप्ति लाभ की लागत	0.00
5.68	वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-9.53

31.03.2024	ग: मान्यताएं:	31.03.2025
7.00%	छूट की दर	6.60%
अधिकारी: 9%	वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी: 9%
कर्मचारी: 6.25%		कर्मचारी: 6.25%

तालिका 3:

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	क: परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन	31.03.2025
155.00	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	161.50
4.46	वर्तमान सेवा लागत	4.95
10.54	डीबीओ पर ब्याज लागत	10.40
-	कटौती (क्रेडिट)/ लागत	0.00

31.03.2024	क: परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन	31.03.2025
-	निपटान (ऋण)/ लागत	0.00
6.17	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	0.00
-	अधिग्रहण (क्रेडिट)/ लागत	0.00
1.57	एक्चुरियल (लाभ)/हानि - अनुभव	7.61
-	एक्चुरियल (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय मान्यताएँ	0.00
4.86	एक्चुरियल (लाभ)/हानि - वित्तीय मान्यताएं	7.38
-	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए जाने वाले लाभ	0.00
(21.10)	योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-25.78
161.50	अवधि के अंत में डीबीओ	166.06

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	ख: परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2025
150.83	पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	167.18
-	अधिग्रहण समायोजन	0.00
11.18	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	10.95
26.14	नियोक्ता योगदान	4.37
0.13	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)	-0.20
(21.10)	भुगतान किये गये लाभ	-25.78
167.18	वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	156.53

तालिका 4: अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

(₹ करोड़ में)

क. समाप्त वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
31 मार्च, 2026	17.48
31 मार्च, 2027	12.87
31 मार्च, 2028	10.93
31 मार्च, 2029	10.50
31 मार्च, 2030	6.97
31 मार्च 2031 से 31 मार्च 2035	34.98
10 वर्ष से अधिक	345.11
ख. 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	5.11
ग. परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	12 Years
घ. 31 मार्च 2025 को अर्जित लाभ दायित्व	109.43

क. समाप्त वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
ड. 31 मार्च 2025 तक योजना परिसंपत्ति की जानकारी	
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ (केन्द्रीय एवं राज्य)	0.00%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड (सार्वजनिक क्षेत्र के बांड सहित)	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
संपत्ति	0.00%
नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
बीमा योजनाएँ - पारंपरिक उत्पाद	100.00%
बीमा योजनाएँ - यूलिप उत्पाद	0.00%
अन्य	0.00%
कुल	100.00%
च. 31 मार्च 2025 तक वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता का ब्यौरा	
वर्तमान में दायित्व	16.93
गैर-वर्तमान देयता	149.13
31 मार्च 2025 तक देयता	166.06

तालिका 5: संवेदनशीलता विश्लेषण

प्रकटीकरण आइटम

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 तक आधार मान्यताओं पर डीबीओ	166.06
छूट की दर	
31 मार्च 2025 तक छूट दर	6.60%
छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	-9.13
प्रतिशत प्रभाव	-6%
छूट दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	10.08
प्रतिशत प्रभाव	6%

वेतन वृद्धि दर	
31 मार्च 2025 तक वेतन वृद्धि दर	अधिकारी: 9%; कर्मचारी: 6.25%
वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	3.45
प्रतिशत प्रभाव	2%
वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण DBO पर प्रभाव	-3.98
प्रतिशत प्रभाव	-2%

31.03. 2025 तक अवकाश लाभ योजना का बीमांकिक मूल्यांकन IND AS 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1:

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	क. लाभ और हानि (पी एंड एल)	
17.52	वर्तमान सेवा लागत	19.38
3.63	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	0.00
-	कटौती लागत / (क्रेडिट)	0.00
-	निपटान लागत / (क्रेडिट)	0.00
21.15	सेवा लागत	19.38
(0.34)	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	-0.10
8.94	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-3.40
29.75	पी&एल में मान्यता प्राप्त लागत	15.87

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	ख: अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	31.03.2025
4.61	डीबीओ अनुभव के कारण एक्चुरियल (लाभ)/हानि	-11.78
4.37	डीबीओ धारणा में परिवर्तन के कारण एक्चुरियल (लाभ)/हानि	6.78
8.97	अवधि के दौरान होने वाली एक्चुरियल (लाभ)/हानि	-5.01
(0.03)	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम	1.60
-	ओसीआई में मान्यता प्राप्त एक्चुरियल (लाभ)/ हानि	0.00

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	ग: परिभाषित लाभ लागत	
21.15	सेवा लागत	19.38
-0.34	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	-0.10
-	ओसीआई में मान्यता प्राप्त एक्चुरियल (लाभ)/ हानि	0.00
8.94	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	-3.40
29.75	परिभाषित लाभ लागत	15.87

31.03.2023	घ: मान्यताएं:	31.03.2024
7.30%	छूट की दर	7.00%
अधिकारी: 9%	वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी: 9%
कर्मचारी: 6.25%		कर्मचारी: 6.25%

तालिका 2:

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	क: नेट बैलेंस शीट स्थिति का विकास	31.03.2025
(124.18)	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	-126.56
112.92	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	124.92
(11.26)	वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	-1.64
-	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	0.00
(11.26)	शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-1.64

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	ख: शुद्ध बैलेंस शीट स्थिति का समाधान	31.03.2025
(9.27)	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-11.26
(21.15)	सेवा लागत	-19.38
0.34	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	0.10
(8.94)	एक्चुरियल (हानि)/ लाभ	3.40
27.76	नियोक्ता योगदान	25.49
-	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	0.00
-	अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)	0.00
-	विनिवेश	0.00
-	समाप्ति लाभ की लागत	0.00
(11.26)	वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-1.64

31.03.2024	ग: मान्यताएं:	31.03.2025
7.00%	छूट की दर	6.60%
अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%	वेतन वृद्धि की दर	कार्यकारी: 9% गैर-कार्यकारी: 6.25%

तालिका 3:

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	क : परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन	31.03.2025
108.63	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	124.18
17.52	वर्तमान सेवा लागत	19.38
7.14	डीबीओ पर ब्याज लागत	7.99
-	कटौती (क्रेडिट)/ लागत	0.00
-	निपटान (ऋण)/ लागत	0.00
3.63	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	0.00
-	अधिग्रहण (क्रेडिट)/ लागत	0.00
4.61	एक्चुरियल (लाभ)/हानि - अनुभव	-11.78
-	एक्चुरियल (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय मान्यताएँ	0.00
4.36	एक्चुरियल (लाभ)/हानि - वित्तीय मान्यताएं	6.78
-	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए जाने वाले लाभ	0.00
(21.71)	योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-19.98
124.18	अवधि के अंत में डीबीओ	126.56

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	ख : परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2025
99.39	पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	112.92
-	अधिग्रहण समायोजन	0.00
7.47	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	8.10
27.74	नियोक्ता योगदान	25.49
0.03	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)	-1.60
(21.71)	भुगतान किये गये लाभ	-19.98
112.92	वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	124.92

तालिका 4: अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

(₹ करोड़ में)

क. समाप्त वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
31 मार्च, 2026	10.21
31 मार्च, 2027	6.13
31 मार्च, 2028	7.98
31 मार्च, 2029	6.17
31 मार्च, 2030	5.12
31 मार्च 2031 से 31 मार्च 2035	24.27
10 वर्ष से अधिक	334.33
ख. 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	23.21
ग. परिभाषित लाभ दायित्व की भारत औसत अवधि	15 Years
घ. 31 मार्च 2025 को अर्जित लाभ दायित्व	52.96
ड. 31 मार्च 2025 तक योजना परिसंपत्ति की जानकारी	
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ (केन्द्रीय एवं राज्य)	0.00%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड (सार्वजनिक क्षेत्र के बांड सहित)	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
संपत्ति	0.00%
नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
बीमा योजनाएँ - पारंपरिक उत्पाद	100.00%
बीमा योजनाएँ - यूलिप उत्पाद	0.00%
अन्य	0.00%
कुल	100.00%
च. 31 मार्च 2025 तक वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता का ब्यौरा	
वर्तमान में दायित्व	9.88
गैर-वर्तमान देयता	116.68
31 मार्च 2025 तक देयता	126.56

तालिका 5 : संवेदनशीलता विश्लेषण

प्रकटीकरण आइटम

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 तक आधार मान्यताओं पर डीबीओ	126.56
छूट की दर	
31 मार्च 2025 तक छूट दर	6.60%
छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	-8.39
प्रतिशत प्रभाव	-7%
छूट दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	9.32
प्रतिशत प्रभाव	7%

वेतन वृद्धि दर	
31 मार्च 2025 तक वेतन वृद्धि दर	अधिकारी:9% कर्मचारी: 6.25%
वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	9.13
प्रतिशत प्रभाव	7%
वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	-8.30
प्रतिशत प्रभाव	-7%

31.03.2025 तक सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन IND AS 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1:

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	क. लाभ और हानि (पी एंड एल)	31.03.2025
1.65	वर्तमान सेवा लागत	1.64
-	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	0.00
-	कटौती लागत / (क्रेडिट)	0.00
-	निपटान लागत / (क्रेडिट)	0.00
1.65	सेवा लागत	1.64
0.39	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	0.05
-	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00
2.04	पी&एल में मान्यता प्राप्त लागत	1.69

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	ख: अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	31.03.2025
4.02	डीबीओ अनुभव के कारण एक्चुरियल (लाभ)/हानि	1.67
2.83	डीबीओ धारणा में परिवर्तन के कारण एक्चुरियल (लाभ)/हानि	4.06
6.86	अवधि के दौरान होने वाली एक्चुरियल (लाभ)/हानि	5.72
0.58	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (अधिक)/छूट दर से कम	-0.08
7.43	ओसीआई में मान्यता प्राप्त एक्चुरियल (लाभ)/ हानि	5.64

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	ग: परिभाषित लाभ लागत	31.03.2025
1.65	सेवा लागत	1.64
0.39	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	0.05
7.43	ओसीआई में मान्यता प्राप्त एक्चुरियल (लाभ)/ हानि	5.64
-	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00
9.47	परिभाषित लाभ लागत	7.33

31.03.2023	घ: मान्यताएं:	31.03.2024
7.30%	छूट की दर	7.00%
0.00%	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0.00%

तालिका 2:

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	क: नेट बैलेंस शीट स्थिति का विकास	31.03.2025
(93.96)	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	-99.18
83.63	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	100.73
(10.33)	वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	1.55
-	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	0.00
(10.33)	शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	1.55

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	ख: नेट बैलेंस शीट स्थिति का समाधान	31.03.2025
(9.84)	पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	-10.33
(1.65)	सेवा लागत	-1.64
(0.39)	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	-0.05
(7.43)	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	-5.64
8.99	नियोक्ता योगदान	19.21
-	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	0.00
-	अधिग्रहण क्रेडिट/ (लागत)	0.00
-	विनिवेश	0.00
-	समाप्ति लाभ की लागत	0.00
(10.33)	वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	1.55

31.03.2024	ग: मान्यताएं:	31.03.2025
7.00%	छूट की दर	6.60%
0.00%	वेतन वृद्धि की दर	0.00%

तालिका 3:

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	क: परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन	31.03.2025
88.32	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	93.96
1.65	वर्तमान सेवा लागत	1.64
6.12	डीबीओ पर ब्याज लागत	6.28
-	कटौती (क्रेडिट)/ लागत	0.00
-	निपटान (ऋण)/ लागत	0.00
-	पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	0.00
-	अधिग्रहण (क्रेडिट)/ लागत	0.00
4.02	एक्चुरियल (लाभ)/हानि - अनुभव	1.67
-	एक्चुरियल (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय मान्यताएँ	0.00
2.84	एक्चुरियल (लाभ)/हानि - वित्तीय मान्यताएं	4.06
-	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए जाने वाले लाभ	0.00
(8.99)	योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	-8.42
93.96	वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	99.18

(₹ करोड़ में)

31.03.2024	ख: परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2025
78.48	पूर्व अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	83.63
-	अधिग्रहण समायोजन	0.00
5.73	योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	6.23
8.99	नियोक्ता योगदान	19.21
(0.58)	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक/(कम)	0.08
(8.99)	भुगतान किये गये लाभ	-8.42
83.63	वर्तमान अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	100.73

तालिका 4: अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी

(₹ करोड़ में)

क. समाप्त वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
31 मार्च, 2026	6.97
31 मार्च, 2027	7.23
31 मार्च, 2028	7.36
31 मार्च, 2029	7.47
31 मार्च, 2030	7.56
31 मार्च 2031 से 31 मार्च 2035	37.79
10 वर्ष से अधिक	159.70
परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	11 Years
31 मार्च 2025 को अर्जित लाभ दायित्व	99.18

तालिका 5: संवेदनशीलता विश्लेषण

प्रकटीकरण आइटम

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 तक आधार मान्यताओं पर डीबीओ	99.18
छूट की दर	
31 मार्च 2025 तक छूट दर	6.60%
छूट दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	-5.02
प्रतिशत प्रभाव	-5.0%
छूट दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	5.54
प्रतिशत प्रभाव	6.0%

क) आकस्मिक देयताएं (भारतीय लेखा मानक-37)

कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (जहां भी लागू हो, ब्याज सहित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्यौरा	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और अन्य	सीपीएसई	अन्य	कुल
1	01.04.2023 को खुलने की तिथि	191.39			11.00	202.39
2	अवधि के दौरान वृद्धि	2.03			-	2.03
3	इस अवधि के दौरान निपटाए गए दावे	-			-	-
	क. प्रारंभिक शेष राशि से	1.19			6.83	8.02
	ख. समाप्त अवधि के दौरान अतिरिक्त	-			-	-
	ग. समाप्त अवधि के दौरान निपटाए गए कुल दावे (ए+बी)	1.19			6.83	8.02
4	31.03.2024 को समापन	192.203			4.17	196.40

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्यौरा	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और अन्य स्थानीय निकाय	सीपीएसई	अन्य	कुल
1	01.04.2024 को खुलने की तिथि	192.23			4.17	196.40
2	अवधि के दौरान वृद्धि				2.21	2.21
3	इस अवधि के दौरान निपटाए गए दावे					
	ए. प्रारंभिक शेष राशि से				1.20	1.20
	बी. समाप्त अवधि के दौरान अतिरिक्त					
	सी. समाप्त अवधि के दौरान निपटाए गए कुल दावे (ए+बी)				1.20	1.20
4	31.03.2025 को समापन	192.23			5.18	197.41

आकस्मिक देयता

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 तक राशि करोड़ रुपये में	31.03.2024 तक राशि करोड़ रुपये में
1.	केंद्र सरकार		
	आयकर	123.20	123.20
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क		
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर		
	केंद्रीय बिक्री कर		
	सेवा कर	69.03	69.03
	अन्य, (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	कुल	192.23	192.23

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 तक राशि करोड़ रुपये में	31.03.2024 तक राशि करोड़ रुपये में
2.	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण		
	रॉयल्टी		
	पर्यावरण मंजूरी		
	बिक्री कर/वैट		
	प्रवेश कर		
	बिजली शुल्क		
	एमएडीए		
	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	कुल		
3.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम		
	मध्यस्थता कार्यवाही		
	कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर		
	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	कुल		
4.	अन्य: (यदि कोई हो)		
	विविध	5.18	4.17
	कुल	5.18	4.17
	कुल योग	197.41	196.40

* कंपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में कर अधिकारियों द्वारा उठाई गई मांगों का विरोध कर रही है, जो वर्तमान में विवादित हैं और विभिन्न अपीलीय मंचों के समक्ष लंबित हैं। 31 मार्च 2025 तक, ब्याज और दंड को छोड़कर, आकस्मिक देनदारियों का खुलासा कर दिया गया है। ब्याज, जहाँ लागू हो, संबंधित आदेशों की तिथि से रिपोर्टिंग तिथि तक, वर्तमान में अनिश्चित है और अंतिम निर्णय पर इसका हिसाब लगाया जाएगा।

** पूलड कंसोर्टियम व्यवस्था के भाग के रूप में कंपनी की वर्तमान परिसंपत्तियों पर बनाए गए प्रभार के बारे में विवरण के लिए, व्यवस्था के विवरण के लिए j-अन्य महत्वपूर्ण मामले देखें।

ख) प्रतिबद्धताएं (इंड एस-37)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
अन्य के लिए प्रावधान न किए गए पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	69.81	14.99
पट्टा प्रतिबद्धता	1.36	1.56

ग) आकस्मिक संपत्तियाँ:

आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्ट होता है जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं होतीं। व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान, कई अनुसुलझे दावे वर्तमान में लंबित हैं। ऐसे दावों के संबंध में आर्थिक लाभ के अंतर्वाह को संबंधित घटनाओं और परिस्थितियों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता।

घ.) गारंटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
कंपनी ने बैंक गारंटी दी है, जिसके लिए कंपनी की चालू परिसंपत्तियों पर फ्लोटिंग चार्ज है।	0.14	0.14

ड.) प्रति शेयर आय (इंडएस 33)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयरधारकों को देय कर के पश्चात शुद्ध लाभ रुपए (करोड़ में)	666.91	503.23
बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1428000	1428000
रुपये में प्रति शेयर मूल और तनु आय (अंकित मूल्य 1000/- रुपये प्रति शेयर)	4670.24	3524.02

च.) संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (इंड एस-24)

संबंधित पक्षों की सूची

i)	सहयोगी कंपनियाँ	ii)	रोजगारोत्तर लाभ निधि एवं अन्य:
1	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	1	कोल इंडिया कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड
2	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	2	कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)
3	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	3	कोल इंडिया सुपरएनुएशन बेनिफिट फंड ट्रस्ट
4	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	4	कर्मचारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना संशोधित
5	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	5	सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट
6	नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)		
7	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)		
8	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) - होल्डिंग कंपनी		

iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

31-03-2025

नाम	पद का नाम	प्रभावी तिथि से
श्री मनोज कुमार	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	04.10.2021
श्री बी. वीरा रेड्डी	अंशकालिक सरकारी निदेशक	24.02.2022 से 31.08.2024 तक
श्री मुकेश अग्रवाल	अंशकालिक सरकारी निदेशक	17.10.2024
श्री अजितेश कुमार	अंशकालिक सरकारी निदेशक	27.12.2023 से 31.12.2024 तक
श्री मारापल्ली वेंकटेश्वरलु	अंशकालिक सरकारी निदेशक	01.01.2025

नाम	पद का नाम	प्रभावी तिथि से
श्री शंकर नागाचारी	निदेशक (तकनीकी)	02.09.2022
श्री अजय कुमार	निदेशक (तकनीकी)	26.10.2022
श्री सतीश झा	निदेशक (तकनीकी)	01.09.2023 19.12.2024 तक
श्री अच्युत घटक	निदेशक (तकनीकी)	01.10.2023 से 23.01.2025 तक
श्री एस.बी. तिवारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.11.2023 से 30.09.2024 तक
श्री सुदीप दासगुप्ता	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.10.2024
श्री अभिषेक मूंदड़ा	कंपनी सचिव	18.02.2016

iv) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ		
a)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान	4.29	4.27
b)	स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस	-	-
ii)	नौकरी के बाद मिलने वाले लाभ	0.72	0.76
iii)	अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.13	1.75
iv)	टर्मिनेशन लाभ	-	-
v)	शेयर आधारित भुगतान	-	-
	कुल	5.14	6.78

* 31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक से अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी जैसे केएमपी के लिए परिभाषित लाभों के बीमांकिक मूल्यांकन को बाहर रखा गया है।

टिप्पणी: इसके अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अनुसार ₹ 2000 प्रति माह के भुगतान पर 1000 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कार का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

v) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ बकाया अधिशेष

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई भी व्यापार या अन्य प्राप्य राशि अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ

संयुक्त रूप से देय नहीं है। न ही किसी भी फर्म या निजी कंपनी से कोई व्यापार या अन्य प्राप्य राशि देय है जिसमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य हो। इसके अलावा, संबंधित पक्षों (निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य) को कोई ऋण नहीं दिया गया है।

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों का नाम	संबंधित पक्षों को ऋण	संबंधित पक्षों से ऋण	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	पट्टा किराया आय	सहायक कंपनियों द्वारा जमा की गई धनराशि पर ब्याज	आई आई सी एम शुल्क	कोई अन्य (बिक्री)	डिविडेंट का भुगतान	चालू खाता शेष (देय/प्राप्य)	बकाया शेष राशि (देय/प्राप्य)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)								173.33			160.87
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)								88.22			50.93
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)								193.47			137.53
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)								265.81			87.58
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)								542.75			192.30
नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)								177.28			32.04
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)								178.12			65.18
*कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)								18.27	200.97**	61.58	19.93

*कंपनी ने वर्ष के दौरान सीआईएल द्वारा प्राप्त कंसोर्टियम क्रेडिट सुविधा के किसी भी हिस्से का लाभ नहीं उठाया है। हालाँकि, इस सुविधा के समर्थन में इसकी वर्तमान संपत्तियाँ संपात्तिक के रूप में प्रदान की गई हैं। अधिक जानकारी के लिए, व्यवस्था के विवरण के लिए j-अन्य महत्वपूर्ण मामले देखें।

** वित्त वर्ष 2024-25 में, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹50.97 करोड़ के अंतिम लाभांश के अतिरिक्त, ₹150.00 करोड़ का अंतरिम लाभांश वितरित किया।

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों का नाम	संबंधित पक्षों को ऋण	संबंधित पक्षों से ऋण	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	पट्टा किराया आय	सहायक कंपनियों द्वारा जमा की गई धनराशि पर ब्याज	आई आई सी एम शुल्क	कोई अन्य (बिक्री)	डिविडेंट का भुगतान	चालू खाता शेष (देय/प्राप्य)	बकाया शेष राशि (देय/प्राप्य)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)								126.28			102.25
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)								89.09			53.07
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)								237.02			127.56
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)								225.35			68.85
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)								550.97			324.87
नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)								197.96			29.47
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)								191.32			77.96
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)								17.81	119.00	60.58	21.61

* वित्त वर्ष 2023-24 में, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹19.00 करोड़ के अंतिम लाभांश के अतिरिक्त ₹100.00 करोड़ का अंतरिम लाभांश वितरित किया।

छ. विखंडित राजस्व जानकारी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वस्तुओं या सेवाओं के प्रकार		
-कोयला		
-अन्य	2102.76	1732.69
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कुल राजस्व	2102.76	1732.69
ग्राहकों के प्रकार		
-बिजली क्षेत्र	21.40	20.27
-गैर-विद्युत क्षेत्र	2081.36	1712.42
-अन्य या सेवाएँ (सीएमपीडीआईएल)	-	-
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कुल राजस्व	2102.76	1732.69
अनुबंध के प्रकार		
-एफएसए	-	-
-ई नीलामी	-	-
-अन्य	2102.76	1732.69
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कुल राजस्व	2102.76	1732.69
कुल मुनाफा	2102.76	1732.69
सीआईएल समूह	1386.65	1387.72
पराया	716.11	344.97
माल या सेवा का समय		
-किसी समय पर स्थानांतरित माल	-	-
-समय के साथ स्थानांतरित माल	-	-
-किसी समय पर स्थानांतरित की गई सेवा	2102.76	1732.69
-समय के साथ स्थानांतरित की गई सेवा	-	-
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कुल राजस्व	2102.76	1732.69

(ज) अनुपात

i.) वर्तमान अनुपात

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	भिन्नता
4.34	3.96	0.38

चालू अनुपात एक तरलता अनुपात है जो अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए मौजूदा संसाधनों को मापता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की जाती है।

ii) इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	भिन्नता
36.71%	35.83%	0.88%

इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है जिसकी गणना पीएटी को औसत शेयरधारकों की इक्विटी से विभाजित करके की जाती है। जहाँ औसत शेयरधारकों की इक्विटी = (प्रारंभिक इक्विटी + समापन इक्विटी)/2. अन्य इक्विटी में पूंजी रिजर्व शामिल नहीं है।

iii) व्यापार प्राप्य अनुपात

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	भिन्नता
2.17	1.91	0.26

प्राप्य टर्नओवर अनुपात एक लेखा माप है जिसका उपयोग किसी कंपनी की अपने प्राप्य खातों या ग्राहकों द्वारा बकाया राशि को इकट्ठा करने में प्रभावशीलता को मापने के लिए किया जाता है। प्राप्य खातों का टर्नओवर = शुद्ध ऋण बिक्री/औसत व्यापार प्राप्य

iv) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	भिन्नता
1.14	1.23	-0.09

नेट कैपिटल टर्नओवर वह माप है जो व्यवसाय में नियोजित पूंजी के उपयोग के संबंध में संगठन की दक्षता को इंगित करता है और इसकी गणना उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की मात्रा से विभाजित शुद्ध बिक्री के अनुपात के रूप में की जाती है।
नेट कैपिटल टर्नओवर अनुपात = शुद्ध बिक्री / कार्यशील पूंजी

शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री में से बिक्री रिटर्न घटाकर की जाएगी।

कार्यशील पूंजी की गणना चालू परिसंपत्तियों में से चालू देनदारियों को घटाकर की जाएगी।

v) शुद्ध लाभ अनुपात

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	भिन्नता
31.72%	29.04%	2.68%

यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है।

शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री

शुद्ध लाभ कर के पश्चात होगा।

शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री में से बिक्री रिटर्न घटाकर की जाएगी।

vi) नियोजित पूंजी पर रिटर्न

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	भिन्नता
40.36%	43.93%	-3.57%

नियोजित पूंजी पर रिटर्न किसी कंपनी के प्रबंधन की ऋण धारकों और इक्विटी धारकों दोनों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए उतनी ही कुशलता से पूंजी का उपयोग किया जाएगा।

आरओसीई = ब्याज और कर से पहले की कमाई / नियोजित पूंजी

नियोजित पूंजी = मूर्त निवल संपत्ति + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता

i) लेखांकन नीति में अद्यतनीकरण:

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए अद्यतनीकरण के अनुरूप, वित्त वर्ष 2024-25 में लेखा नीति में अद्यतनीकरण किया गया है। ये परिवर्तन बेहतर समझ के लिए किए गए हैं। और कंपनी के वित्तीय विवरण की बेहतर प्रस्तुति।

क्रम सं.	पिछली लेखा नीति (31 मार्च, 2024)	अद्यतन लेखा नीति (31 मार्च, 2025)	परिवर्तन
1.	नोट 1 बी: अनुपालन विवरण और हालिया लेखा घोषणा i) अनुपालन विवरण ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (जिन्हें आगे "इंड एस" कहा जाएगा) के अनुसार तैयार किए गए हैं। जारी, अधिसूचित और प्रभावी किए गए इंड एस वित्तीय विवरणों के अधिकृत होने तक प्रभावी रहेंगे और इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उन पर विचार किया जाएगा। लेखांकन नीतियां सुसंगत रूप से लागू की जाती हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां किसी नए जारी किए गए लेखांकन मानक को प्रारंभ में अपनाया जाता है या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है।	नोट 1 बी: अनुपालन विवरण और हालिया लेखा घोषणा i) अनुपालन विवरण ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (जिन्हें आगे "इंड एस" कहा जाएगा) के अनुसार तैयार किए गए हैं। जारी, अधिसूचित और प्रभावी किए गए इंड एस वित्तीय विवरणों के अधिकृत होने तक प्रभावी रहेंगे और इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उन पर विचार किया जाएगा। लेखांकन नीतियां सुसंगत रूप से लागू की जाती हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां किसी नए जारी किए गए लेखांकन मानक को प्रारंभ में अपनाया जाता है या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ii) नये एवं संशोधित मानकों का अनुप्रयोग: कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) समय-समय पर कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के अंतर्गत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। एमसीए ने 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाले किसी भी नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित नहीं किया है।	"ii) नए और संशोधित मानकों का अनुप्रयोग: कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) समय-समय पर कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। एमसीए ने 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाले किसी भी नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित नहीं किया है। उपरोक्त खंड को नवीनतम लेखा नीति में शामिल किया गया है।

क्रम सं.	पिछली लेखा नीति (31 मार्च, 2024)	अद्यतन लेखा नीति (31 मार्च, 2025)	परिवर्तन
2.	नोट 2.3 राजस्व मान्यता ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व राजस्व मुख्यतः संबंधित सहायक सेवाओं और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होता है। उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व की पहचान तब की जाती है जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात् जब उत्पाद ग्राहक को वितरित कर दिए जाते हैं। वितरण तब होता है जब उत्पादों को, जैसा भी मामला हो, विशिष्ट स्थान पर भेज दिया जाता है या वितरित कर दिया जाता है, और हानि के जोखिम बिक्री अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसकी कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनशील प्रतिफल का अनुमान लगाने और उसके लिए प्रावधान करने के लिए, सबसे संभावित विधि का उपयोग करके किया जाता है, और राजस्व की पहचान केवल उस सीमा तक की जाती है जहाँ यह अत्यधिक संभावित हो कि कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है क्योंकि बिक्री अनुबंधों के अनुसार भुगतान की शर्तें एक वर्ष से कम होती हैं। कंपनी के पास भविष्य में ग्राहकों को उत्पाद आपूर्ति करने के लिए कई दीर्घकालिक अनुबंध हैं। आम तौर पर, राजस्व की पहचान चालान के आधार पर की जाती है, क्योंकि बेची गई प्रत्येक इकाई एक अलग निष्पादन दायित्व है, और इसलिए ग्राहक से प्रतिफल का अधिकार सीधे हमारे अब तक पूरे किए गए निष्पादन से मेल खाता है।	नोट 2.3 राजस्व मान्यता ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व राजस्व मुख्य रूप से संबंधित सहायक सेवाओं और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होता है। उत्पादों की बिक्री से राजस्व तब पहचाना जाता है जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, जब उत्पाद ग्राहक को वितरित किए जाते हैं। डिलीवरी तब होती है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया जाता है या वितरित कर दिया जाता है, जैसा भी मामला हो, और नुकसान के जोखिम बिक्री अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस विचार को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनीय विचार का अनुमान लगाने और प्रदान करने के लिए किया जाता है, और राजस्व को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहाँ यह अत्यधिक संभावित है कि कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। विचार की राशि में एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है क्योंकि बिक्री अनुबंधों के अनुसार भुगतान शर्तें एक वर्ष से कम हैं। कंपनी के पास भविष्य में ग्राहकों को उत्पाद आपूर्ति करने के लिए कई दीर्घकालिक अनुबंध हैं। आम तौर पर, राजस्व की पहचान चालान के आधार पर की जाती है, क्योंकि बेची गई प्रत्येक इकाई एक अलग निष्पादन दायित्व है, और इसलिए ग्राहक से प्रतिफल का अधिकार सीधे हमारे अब तक पूरे किए गए निष्पादन से मेल खाता है। ब्याज किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है, जो वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को प्रारंभिक पहचान पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर सटीक रूप से छूट देती है। अन्य दावे अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित वसूली पर ब्याज सहित) के संबंध में राजस्व को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब अंतिम वसूली के संबंध में उचित निश्चितता हो और राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।	"ब्याज" किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है, जो वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को प्रारंभिक पहचान पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर सटीक रूप से छूट देती है। अन्य दावे अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित वसूली पर ब्याज सहित) के संबंध में राजस्व को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब अंतिम वसूली के संबंध में उचित निश्चितता हो और राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके। उपरोक्त धाराएं नवीनतम लेखा नीति में शामिल कर ली गई हैं।

क्रम सं.	पिछली लेखा नीति (31 मार्च, 2024)	अद्यतन लेखा नीति (31 मार्च, 2025)	परिवर्तन
3.	नोट 2.4 सरकार से अनुदान सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि इस बात का उचित आश्वासन न मिल जाए कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी तथा इस बात की उचित निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त हो जाएगा। सरकारी अनुदानों को लाभ-हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी संबंधित व्ययों या लागतों को मान्यता देती है, जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान का इरादा होता है। आय से संबंधित अनुदान (अर्थात् परिसंपत्तियों के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को सामान्य शीर्षक 'अन्य आय' के अंतर्गत लाभ या हानि विवरण के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी अनुदान/सहायता जो पहले से किए गए व्यय या हानि के मुआवजे के रूप में या कंपनी को भविष्य में संबंधित लागतों के बिना तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्त होती है, उसे उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें वह प्राप्त होती है। सरकारी अनुदान या प्रमोटर के योगदान के रूप में दिए गए अनुदान को सीधे "पूंजी रिजर्व" में मान्यता दी जाती है, जो "शेयरधारक निधि" का हिस्सा बनता है।	नोट 2.4 सरकार से अनुदान सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि इस बात का उचित आश्वासन न मिल जाए कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी तथा इस बात की उचित निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त हो जाएगा। सरकारी अनुदानों को लाभ-हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी संबंधित व्ययों या लागतों को मान्यता देती है, जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान का इरादा होता है। परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। आय से संबंधित अनुदान (अर्थात् परिसंपत्तियों के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को सामान्य शीर्षक 'अन्य आय' के अंतर्गत लाभ या हानि विवरण के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी अनुदान/सहायता जो पहले से किए गए व्यय या हानि के मुआवजे के रूप में या कंपनी को भविष्य में संबंधित लागतों के बिना तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्त होती है, उसे उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें वह प्राप्त होती है। सरकारी अनुदान या प्रमोटर के योगदान के रूप में दिए गए अनुदान को सीधे "पूंजी रिजर्व" में मान्यता दी जाती है, जो "शेयरधारक निधि" का हिस्सा बनता है।	" परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।" उपरोक्त खंड को नवीनतम लेखा नीति में शामिल किया गया है।

क्रम सं.	पिछली लेखा नीति (31 मार्च, 2024)	अद्यतन लेखा नीति (31 मार्च, 2025)	परिवर्तन
4.	नोट 2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और मूल्यहास फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है: संपत्ति का उपयोगी जीवन अन्य भूमि (पट्टे पर ली गई भूमि सहित) : परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि, जो भी कम हो भवन (सड़क सहित) : 3-60 वर्ष दूरसंचार: 3-9 वर्ष रेलवे साइडिंग: 15 वर्ष संयंत्र और उपकरण: 1-40 वर्ष कंप्यूटर और लैपटॉप: 3 वर्ष कार्यालय उपकरण: 3-5 वर्ष फर्नीचर और फिक्स्चर: 10 वर्ष वाहन: 8-10 वर्ष तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दी गई उपयोगी अवधि उस अवधि को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है जिसके दौरान प्रबंधन परिसंपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। इसलिए, परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग में निर्धारित उपयोगी अवधि से भिन्न हो सकती है। कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी मौजूदा परिसंपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत सक्षम परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।	नोट 2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और मूल्यहास फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है: संपत्ति का उपयोगी जीवन अन्य भूमि (पट्टे पर ली गई भूमि सहित) : परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि, जो भी कम हो भवन (सड़क सहित) : 3-60 वर्ष दूरसंचार: 3-9 वर्ष रेलवे साइडिंग: 15 वर्ष संयंत्र और उपकरण: 1-15 वर्ष कंप्यूटर और लैपटॉप: 3 वर्ष कार्यालय उपकरण: 3-5 वर्ष फर्नीचर और फिक्स्चर: 10 वर्ष वाहन: 8-10 वर्ष तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दी गई उपयोगी अवधि उस अवधि को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है जिसके दौरान प्रबंधन परिसंपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। इसलिए, परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग में निर्धारित उपयोगी अवधि से भिन्न हो सकती है।	संयंत्र और उपकरण: 1-15 वर्ष “कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी मौजूदा परिसंपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत सक्षम परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।” उपरोक्त खंड को नवीनतम लेखांकन नीतियों से हटा दिया गया है।

क्रम सं.	पिछली लेखा नीति (31 मार्च, 2024)	अद्यतन लेखा नीति (31 मार्च, 2025)	परिवर्तन
5.	नोट 2.7 अमूर्त संपत्तियां अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता के आधार पर मापा जाता है। लागत में संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी व्यय शामिल होता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत में से किसी भी संचित मान्यताप्राप्त और संचित हानि हानि को घटाकर रखा जाता है। अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद को निपटान के समय या उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न होने पर अमान्य कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति की अमान्यता से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और परिसंपत्ति की अमान्यता के समय लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है। पूँजीकृत विकास लागतों को छोड़कर, आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों को पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि के लाभ या हानि विवरण और अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया गया है।	नोट 2.7 अमूर्त संपत्तियां और परिशोधन अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता के आधार पर मापा जाता है। लागत में संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी व्यय शामिल होता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत में से किसी भी संचित मान्यताप्राप्त और संचित हानि हानि को घटाकर रखा जाता है। अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद को निपटान के समय या उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न होने पर अमान्य कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति की अमान्यता से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और परिसंपत्ति की अमान्यता के समय लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है। पूँजीकृत विकास लागतों को छोड़कर, आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों को पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि के लाभ या हानि विवरण और अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया गया है।	"सीमित जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ या हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन अमूर्त परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है: अमूर्त संपत्ति का उपयोगी जीवन एसएपी/इआरपी : 6 वर्ष अन्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर: लाइसेंस अवधि" उपरोक्त खंड को नवीनतम लेखा नीति में शामिल किया गया है।

क्रम सं.	पिछली लेखा नीति (31 मार्च, 2024)	अद्यतन लेखा नीति (31 मार्च, 2025)	परिवर्तन
	अमूर्त आस्तियों का उपयोगी जीवन परिमित या अनिश्चित के रूप में आकलित किया जाता है। परिमित जीवन वाली अमूर्त आस्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधन किया जाता है और जब भी इस बात का संकेत मिलता है कि अमूर्त आस्तियों की हानि हो सकती है, तो उनकी हानि का आकलन किया जाता है। परिमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त आस्तियों के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन पद्धति की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या आस्तियों में निहित भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तनों को, आवश्यकतानुसार, परिशोधन अवधि या पद्धति को संशोधित करने के लिए माना जाता है, और उन्हें लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उसकी क्षति के लिए जांच की जाती है। अनुसंधान पर व्यय, जब भी हो, व्यय में शामिल किया जाता है। विकास पर व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हों और कंपनी विकास कार्य पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग या बिक्री करने के लिए पर्याप्त संसाधन रखने का इरादा रखती हो।	अमूर्त आस्तियों का उपयोगी जीवन परिमित या अनिश्चित के रूप में आकलित किया जाता है। परिमित जीवन वाली अमूर्त आस्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधन किया जाता है और जब भी इस बात का संकेत मिलता है कि अमूर्त आस्तियों की हानि हो सकती है, तो उनकी हानि का आकलन किया जाता है। परिमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त आस्तियों के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन पद्धति की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या आस्तियों में निहित भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तनों को परिशोधन अवधि या पद्धति में, आवश्यकतानुसार, संशोधन करने के लिए माना जाता है, और उन्हें लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों के रूप में माना जाता है। परिमित जीवन वाली अमूर्त आस्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ या हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। अमूर्त आस्तियों का परिशोधन, अमूर्त आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है: अमूर्त संपत्ति का उपयोगी जीवन एसएपी/इआरपी : 6 वर्ष अन्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर: लाइसेंस अवधि अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उसकी क्षति के लिए जांच की जाती है। अनुसंधान पर व्यय, जब भी हो, व्यय में शामिल किया जाता है। विकास पर व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हों और कंपनी विकास कार्य पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग या बिक्री करने के लिए पर्याप्त संसाधन रखने का इरादा रखती हो।	

जैसा कि ऊपर बताया गया है, लेखांकन नीति में संशोधन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्टता बढ़ाने के लिए किया गया है। इन अद्यतनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

ज.) अन्य महत्वपूर्ण मामले:

कंसोर्टियम सुविधा और संपार्श्विक व्यवस्था:

होल्टिंग कंपनी, सीआईएल ने स्वयं और अपनी सहायक कंपनियों के लाभ के लिए बैंकों के एक संघ द्वारा स्वीकृत कुल ₹430 करोड़ (जिसमें ₹140 करोड़ निधि-आधारित और ₹290 करोड़ गैर-निधि-आधारित सीमाएँ शामिल हैं) की एक कंसोर्टियम नकद ऋण सुविधा का लाभ उठाया है। यह सुविधा एक संयुक्त ऋण व्यवस्था के रूप में संरचित है और सीआईएल और/या उसकी

सहायक कंपनियों द्वारा, परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर, स्वीकृत सीमा के भीतर, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, इसका लाभ उठाया जा सकता है।

यद्यपि सीएमपीडीआई ने वर्ष के दौरान इस सुविधा से कोई राशि प्राप्त नहीं की है, फिर भी इसकी वर्तमान परिसंपत्तियों को इस सुविधा के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया है। परिणामस्वरूप, समूह की अन्य संस्थाओं द्वारा चूक की स्थिति में सीएमपीडीआई पर वित्तीय दायित्व आ सकता है।

सीआईएल, जहाँ लागू हो, कंसोर्टियम के ऋणदाताओं को तिमाही चालू परिसंपत्ति विवरण प्रस्तुत करता है। सीआईएल समेकित स्तर पर ऋण और तरलता जोखिमों की केंद्रीय निगरानी करता है।

ट.) क) विविध जानकारी

इन वित्तीय विवरणों में निहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ सूचनात्मक प्रकटीकरण के साधन और कंपनी की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों से केवल उन्हीं नीतियों और टिप्पणियों का खुलासा किया है, जो आवश्यक प्रकटीकरण को उचित रूप से प्रस्तुत करती हैं।

ख) अन्य

- i. बेनामी संपत्ति: बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- ii. बैंकों या वित्तीय संस्थानों के पास दाखिल रिटर्न या विवरण: कंपनी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल तिमाही रिटर्न/वर्तमान परिसंपत्तियों का विवरण आम तौर पर लेखा पुस्तकों के अनुरूप होता है।
- iii. जानबूझकर चूककर्ता: कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- iv. स्ट्रॉक ऑफ कंपनियों के साथ संबंध: कंपनी ने हटाई गई कंपनियों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है।
- v. कंपनी रजिस्ट्रार के पास शुल्कों का पंजीकरण या संतुष्टि: कंपनी द्वारा वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए कोई शुल्क या संतुष्टि लंबित नहीं है।
- vi. कंपनियों की कई परतों का अनुपालन: कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- vii. व्यवस्था की अनुमोदित योजना(ओं) का अनुपालन: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार वर्ष के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्था की कोई योजना अनुमोदित नहीं की गई।
- viii. उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग: (ए) कंपनी ने इस समझ के साथ किसी भी संस्था (मध्यस्थ) को कोई निधि अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं की है कि मध्यस्थ कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष (अंतिम लाभार्थी) को उधार देगा या निवेश करेगा। (बी) कंपनी ने इस समझ के साथ किसी भी संस्था से कोई निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने

गए अन्य संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगी।

- ix. क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा: कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- x. अघोषित आय: कंपनी का ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।
- xi. इन वित्तीय विवरणों में निहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ सूचनात्मक प्रकटीकरण के साधन और कंपनी की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों से केवल उन्हीं नीतियों और टिप्पणियों का खुलासा किया है, जो आवश्यक प्रकटीकरण को उचित रूप से प्रस्तुत करती हैं।
- xii. मौजूदा संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि। व्यवसाय के सामान्य क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों पर वसूली का मूल्य उस राशि से कम नहीं होगा जिस पर उन्हें बैलेंस शीट में बताया गया है।
- xiii. शेष पुष्टिकरण: कंपनी के पास बैंकों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। बैंक खातों और बैंकों व वित्तीय संस्थानों से लिए गए उधारों के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। अन्य पक्षों के संबंध में, समाधान किया जाता है और शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र/ईमेल भी समय-समय पर भेजे जाते हैं। ऐसी कुछ शेष राशियाँ पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान के बाद उसका हिसाब लगाया जाएगा, तथा परिणामों पर इसका कोई भौतिक प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।
- xiv. खंड रिपोर्टिंग : कंपनी का मुख्य व्यापार है कंसल्टेंसी सेवाएं। सभी गतिविधियाँ का कंपनी घूमना आस-पास मुख्य व्यवसाय। इस प्रकार, कंपनी के लिए कोई अलग रिपोर्ट योग्य खंड नहीं हैं।
- xv. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है, ताकि उन्हें तुलनीय बनाया जा सके।
- xvi. नोट - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 11 बैलेंस शीट का हिस्सा हैं और 12 से 13 लाभ और हानि विवरण का हिस्सा हैं। नोट - 16 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है।
- xvii. वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागू हालिया लेखांकन घोषणाएँ:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में कई संशोधन जारी

किए हैं, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाले विभिन्न भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। इन संशोधनों में इंड एस 117 - इंड एस 101, 103, 105, 107, 109, 115 में परिणामी संशोधनों के साथ बीमा अनुबंधों की शुरूआत; इंड एस 116 में संशोधन - कुछ बीमा कंपनियों के लिए इंड एस 104 के पट्टे और निरंतरता शामिल हैं। कंपनी ने इन संशोधनों का मूल्यांकन किया है और पाया है कि इनके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

- xviii. सीएमपीडीआई की वर्तमान परिसंपत्तियों [अर्थात् संयंत्र और मशीनरी से संबंधित नहीं भंडार और पुर्जे (उपभोज्य भंडार और पुर्जे) (वित्तीय विवरणों की सूची नोट-5.1 देखें), प्राप्य बिल और पुस्तक ऋण (वित्तीय विवरणों की व्यापार प्राप्य नोट-4.3 देखें)], अन्य सभी चल संपत्तियों (ऐसी चल संपत्तियों को छोड़कर, जिन्हें एसबीआई कंसोर्टियम द्वारा समय-समय पर अपने विवेक से अनुमति दी जा सकती है), वर्तमान और भविष्य दोनों पर 430 करोड़ रुपये का प्रभार बनाया गया है। नोट 1 से 16 तक के लिए हस्ताक्षरित

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के लिए

ह./-
(ए. मुंधरा)
कंपनी सचिव

ह./-
(सुदीप दासगुप्ता)
सीएफओ
डीआईएन-10802727

ह./-
(एस. नागाचारी)
निदेशक
डीआईएन-09729657

ह./-
(मनोज कुमार)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-09225497

हमारी संलग्न सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
के.सी. टाक एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000216C

ह./-
(सीए अनिल जैन)
पार्टनर

सदस्यता संख्या : 079005
युडीआईएन- 25079005BMOKCP8577

दिनांक : 30 अप्रैल, 2025
स्थान : राँची



**सेंद्रल माइन प्लानिंग एंड
डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड**

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)

एक मिनी रल कंपनी (कैट - 1)

आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची - 834008

www.cmpdi.co.in

सीआईएन : यू14292जेएच1975जीओआई001223

